

राजीव गाँधी के प्रधानमंत्रित्वकाल (1984 - 1989) में भारत का पड़ोसी देशों से सम्बन्ध

डॉक्टर ऑफ फिलास्फी
की उपाधि हेतु
प्रस्तुत शोध-प्रबन्ध

प्रस्तुत कर्ता
केशरी नन्दन मिश्र
प्रवक्ता
हेमवती नन्दन बहुगुणा
राजकीय महाविद्यालय नैनी
इलाहाबाद



निदेशक
डा० हेरम्ब चतुर्वेदी
रीडर
मध्य/आधु इतिहास विभाग
इलाहाबाद विश्वविद्यालय
इलाहाबाद

मध्यकालीन एव आधुनिक इतिहास विभाग
इलाहाबाद विश्वविद्यालय
इलाहाबाद

2000

प्राक्कथन

इलाहाबाद विश्वविद्यालय की डी० फिल० उपाधि हेतु प्रस्तुत शोध प्रबन्ध “राजीव गाँधी के प्रधान मन्त्रित्व काल (1984-1989) में भारत का पड़ोसी देशों से सम्बन्ध” के अन्तर्गत एक महत्वपूर्ण काल का अध्ययन है क्योंकि यह सक्रमण काल था। भारतीय राजनीतिक नेतृत्व स्वातन्त्रोत्तर पीढ़ी के हाथ में पहली बार गया था अतः स्वाभाविक रूप से यह पीढ़ी विभाजन तथा अन्य समस्याओं को नये दृष्टिकोण से देखने को उत्सुक थी। इसी काल में सूचना क्रांति का प्रस्फुटन हो रहा था तथा विश्व सिकुड़ता सा नजर आ रहा था ऐसे में पड़ोसियों के साथ पारस्परिक सम्बन्धों को पुनः परिभाषित करना अपरिहार्य हो गया था।

इस रोचक एवम् महत्वपूर्ण विषय के चयन के लिए मैं अपने निदेशक डा० हेरम्ब चतुर्वेदी व विभागाध्यक्ष प्रो० श्रीमती रेखा जोशी का सदैव आभारी रहूँगा। मैं अपने निदेशक डा० हेरम्ब चतुर्वेदी के प्रति बार-बार सम्मान प्रकट करता हूँ, जिनके कुशल एव स्नेहिल निर्देशन में इस शोध प्रबन्ध को पूर्ण करने में महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वाह किया। मैं अपने निदेशक की पत्नी श्रीमती आभा चतुर्वेदी के प्रति आभार प्रकट करता हूँ जिनका स्नेह मुझे हमेशा मिलता रहा और जिन्होंने इस शोध प्रबन्ध को पूर्ण करने के लिए सदैव प्रेरित किया।

मैं कांग्रेस अध्यक्षा माननीया श्रीमती सोनिया गाँधी तथा सांसद मणिशकर अय्यर का हृदय से आभार प्रकट करता हूँ जिन्होंने समय-समय पर अति उपयोगी पुस्तकों को उपलब्ध कराया।

मैं अपने अग्रज डा० रामचन्द्र मिश्र (सहायक निदेशक, उच्च शिक्षा) को शत शत नमन करता हूँ जिनके स्नेह व उत्साहवर्धन ने इस शोध प्रबन्ध को पूर्ण करने के लिए मुझे प्रेरणा व शक्ति प्रदान की।

मैं डा० अजय शकर पाण्डे (सचिव, नेडा) तथा विनय शकर पाण्डे (एस०डी०एम० गौरीगज) के प्रति आभार प्रकट करने के लिए किन शब्दों का प्रयोग करूँ, मैं नहीं जानता, परन्तु इतना अवश्य है कि उनका सहयोग इस शोध प्रबन्ध के पूर्ण होने में अविस्मरणीय है।

मैं अपनी सौम्य पत्नी श्रीमती अन्नो मिश्रा के प्रति आभार प्रकट करता हूँ जो सदैव शोध-प्रबन्ध को पूर्ण करने में सहायता प्रदान करने के साथ-साथ प्रेरित करती रही। विशेष रूप से मैं अपने बेटे अर्चित शिवम् के प्रति आभारी हूँ जिसकी पढाई के प्रति उचित ध्यान न दे सका, अपितु निरन्तर शान्त रहने को भी विवश किया।

मैं श्री एस०एन० श्रीवास्तव (सयुक्त सचिव, लोक सेवा आयोग) का विशेष आभारी हूँ जिन्होंने अपना सहयोग विशेष रूप से मुझे प्रदान किया।

मैं अपने परम मित्रों श्री रमाकान्त शुक्ल, राजा दिनेश सिंह, श्री सिद्धाशरण पाण्डे तथा श्री कमलाकान्त मिश्र को जीवन पर्यन्त विस्मृत नहीं कर सकता जिनके प्रेरणात्मक सहयोग ने इस शोध प्रबन्ध को पूर्ण करने में योगदान किया।

मै राष्ट्रीय पुस्तकालय कलकत्ता, पुस्तकालय इलाहाबाद विश्वविद्यालय इलाहाबाद, केन्द्रीय पुस्तकालय इलाहाबाद, जी० बी० पन्त शोध सस्थान इलाहाबाद के पुस्तकालय, इलाहाबाद संग्रहालय के पुस्तकालय, राजीव गाँधी फाउन्डेशन, नई दिल्ली, उत्तर प्रदेश सचिवालय के पुस्तकालय, क्षेत्रीय अभिलेखागार इलाहाबाद, हे० न० ब० राजकीय महाविद्यालय आदि के पुस्तकालयाध्यक्षों के प्रति आभार प्रकट करता हूँ, जिन्होंने मुझे शोध कार्य हेतु पुस्तकें उपलब्ध कराईं।

अन्त में मै नितिन प्रिन्टर्स 1 मनमोहन पार्क, पुराना कटरा, इलाहाबाद के प्रबन्धक सुहैल अहमद के प्रति आभार प्रकट करता हूँ जिन्होंने व्यक्तिगत रुचि के साथ इस शोध प्रबन्ध को तैयार कराने में महती भूमिका निभाई।

साभार

केशरी नन्दन मिश्र

“शोध छात्र”

मध्य / आधुनिक इतिहास विभाग,

इलाहाबाद विश्वविद्यालय

इलाहाबाद

विषय प्रवर्ग।

स्वर्गीय श्री राजीव गांधी का काल विदेश नीति के क्षेत्र में अपने समकालीन परिप्रेक्ष्य के साथ-साथ एवं उपग्रह क्रान्तियों के कारण अध्ययन को जटिल एवं दिलचस्प बना देता है। स्वयं राजीव गांधी एक नवीन पुर्नजागरण का प्रतिनिधित्व करते थे जिन्होंने अपने माता-पिता को स्वतंत्रता संग्राम में जूझते हुए देखा था, किन्तु स्वयं एक स्वतन्त्रोत्तर भारत में जन्मी या पली-पोषी पीढ़ी का नेतृत्व करते थे। अतः परम्परा के साथ-साथ एक नवीन दिशा बोध उनके व्यक्तित्व एवं कृतित्व में स्पष्टतः परिलक्षित होती है। अतः यह अध्ययन भारत में परम्परा और नवीनता के समन्वय का अच्छा प्रतीक है।

सुविधा की दृष्टि से इस शोध प्रबंध का विभाजन नौ अध्यायों में किया गया है।

सर्वप्रथम^① प्रथम अध्याय में भारतीय विदेश नीति के मौलिक सिद्धान्तों की चर्चा की गयी है। जैसे कि असलग्नता साधनों की पवित्रता का सिद्धान्त, उपनिवेशवाद तथा सम्राज्यवाद विरोधी सिद्धान्त, जातिवाद एवं नस्लवाद विरोधी सिद्धान्त तथा पंचशील का महत्वपूर्ण सिद्धान्त। भारतीय विदेश नीति का वास्तविक निर्माण पं० जवाहर लाल नेहरू ने 1947 में कैसे किया यह भी इसी अध्याय के अर्न्तगत विश्लेषित करने का प्रयास किया गया है। साथ ही उत्तर नेहरू युग में स्वर्गीय लाल बहादुर शास्त्री एवं स्वर्गीय श्रीमती इन्दिरा गांधी के नेतृत्व में भारतीय विदेश नीति के अग्रिम चरणों का

विश्लेषणात्मक अध्ययन किया गया है । तत्पश्चात् जनता सरकार कालीन राष्ट्रीय सहमति की विदेश नीति पर भी कुछ प्रकाश डाला गया है ।

② दूसरे अध्याय में श्री राजीव गांधी के काल में भारतीय राजनीतिज्ञों द्वारा अन्तराष्ट्रीय रंगमंच पर किये गए निर्णयो क्रियान्वयनो तथा अदा की गयी भूमिका का अध्ययन किया गया है। इसके अन्तर्गत सर्वप्रथम संयुक्त राष्ट्रसंघ तथा उसके अन्तर्गत आने वाली संस्थाओं का भारतीय योगदान में मूल्यांकन किया गया है । गुटनिरपेक्षता भारतीय विदेश नीति का अविभाज्य अंग रही है अतः गुटनिरपेक्ष आन्दोलन तथा श्री राजीव गांधी भी अध्ययन के एक महत्वपूर्ण बिन्दु है । राजीव गांधी के काल में CHOGM तथा सार्क (SAARC) जैसे दो संगठनों में भी भारतीय योगदान तथा भूमिका की चर्चा करे बिना पड़ोसियों के साथ सम्बन्धों का वाढमय पूर्ण नहीं होता है । अतः यह अध्ययन बहुत महत्वपूर्ण है ।

③ जहाँ तक श्री राजीव गांधी के प्रधानमन्त्रित्व काल की पड़ोसियों के साथ नीति का प्रश्न है तीसरे अध्याय में सर्वप्रथम भारत-चीन के पारस्परिक सम्बन्धों पर प्रकाश डालने का प्रयास किया गया है । इस काल में चीन के साथ एक सकारात्मक पहल हुई अवश्य दिखती है हालांकि इसके तात्कालिक ठोस परिणाम तो

दृष्टिगोचर नहीं होते किन्तु एक निश्चित दिशाबोध एव सुस्पष्ट आधार निर्मित हो सका। नवम्बर 1986 तथा नवम्बर 1987 में दोनों देशों के मध्य पारस्परिक वार्ताओं के दौर चले। इन्हीं के परिणामस्वरूप मई 1988 को भारत और चीन के मध्य प्रथम पंचवर्षीय सांस्कृतिक सन्धि सम्भव हो सकी। अन्ततः श्री राजीव गांधी जी की पांच दिवसीय चीन यात्रा के दौरान 22 दिसम्बर को भारत तथा चीन के नागरिक उड्डयन सेवाओं, विज्ञान व प्राद्योगिकी तथा सांस्कृतिक विनमय के लिए तीन समझौतों पर हस्ताक्षर भी किये गए। 23 दिसम्बर 1988 को चीन यात्रा समाप्ति पर जारी संयुक्त विज्ञप्ति में दोनों देशों ने पंचशील के आधारभूत सिद्धान्तों के तहत सौहार्दपूर्ण सम्बन्धों की स्थापना तथा सीमा विवाद समेत समस्त समस्याओं के समाधान हेतु सकारात्मक प्रयास का आश्वासन भी दिया।

चौथे अध्याय में भारत-नेपाल तथा भारत-भूटान के मध्य पारस्परिक सम्बन्धों का सिंहावलोकन किया गया है। स्वर्गीय श्री राजीव गांधी ने नेपाल के साथ अच्छे सम्बन्धों के अनेक प्रयास किए जिसमें जुलाई 1986 की भारतीय राष्ट्रपति की नेपाल यात्रा तथा 1987 में काठमांडू में आयोजित सार्क सम्मेलन में दोनों देशों के नेताओं का एक मंच पर आना आदि महत्वपूर्ण थे, किन्तु बदलते चीन-नेपाल समीकरणों के चलते इस दौर में भारत-नेपाल के पारस्परिक सम्बन्धों पर प्रतिकूल प्रभाव भी पड़ा तथा मैत्री एव

परागमन की सन्धि को लेकर हुए विवाद ने कटुता को जन्म दिया । इसी प्रकार भारत-भूटान के सम्बन्धों के बदलते समीकरणों की व्याख्या करना आवश्यक हो जाता है । 1985 में भारत के सैद्धान्तिक विरोध के बावजूद भूटान द्वारा अणु प्रसार सन्धि पर हस्ताक्षर तथा 1988 में भूटान-चीन समझौता में दो ऐसे प्रकरण थे जिनसे स्थानीय शक्ति सन्तुलन परिवर्तित होता था । अतः दोनों बार तनाव को कम करने के नियत से भारतीय प्रधानमंत्री ने 1985 तथा 1988 में भूटान की यात्रा की । भारत-भूटान मैत्री का प्रतीक चूखा जल विद्युत परियोजना अक्टूबर 1988 में भारतीय राष्ट्रपति द्वारा उदघाटित हुई । अतः स्वर्गीय श्री राजीव गांधी जी सम्बन्धों में कटु व्यवहार को दूर करने में सफल रहे ।

⑤

प्रस्तावित शोध प्रबन्ध के पाचवें अध्याय में श्री राजीव गाँधी के काल में भारत-पाकिस्तान सम्बन्धों का विश्लेषणात्मक अध्ययन किया गया है क्योंकि अपने उतार-चढ़ाव के कारण इस काल में भी इन देशों के सम्बन्ध अपने आप में महत्वपूर्ण हो जाते हैं। इस पूरे काल में दोनों राष्ट्रों के नेताओं के साथ-साथ अनेक स्तरों पर पारस्परिक वार्ताएँ होती रही। भारत-पाक सम्बन्धों में जैसा कि सदैव होता आया है एक तरफ वार्ताओं का दौर चलता रहा तो दूसरी ओर सीमाओं पर सैनिक मुठभेड़ों का क्रम वदस्तूर जारी रहा। इसी दौर में पाकिस्तान में सत्ता परिवर्तन भी हुआ और श्रीमती बेनजीर द्वारा सत्ता संभालते

ही दोनों देशों के युवा नेताओं द्वारा ऐसे गतिशील प्रयास किये गये जो दोनों देशों के स्वतंत्रोत्तर पीढ़ी के मानसिकता के परिचायक थे । वे परम्परागत शत्रुओं के प्रायः विस्मृत कर आगे मैत्रीपूर्ण संबंधों के इच्छुक थे।

छठे अध्याय में अब तक के सर्वाधिक विवादित विषय भारत-श्रीलंका संबंध का तटस्थ, वैज्ञानिक एवं पूर्णता के साथ अध्ययन किया गया है। भारत तथा श्रीलंका संबंधों की वास्तविकता क्या थी, एवं भारत की श्रीलंका के प्रति नीति एवं पारस्परिक संबंध कितने सार्थक व सफल थे, इन बिन्दुओं पर गहन दृष्टि डाली गई है। विशेष तौर से २९ जुलाई १९८७ के भारत-श्रीलंका के उस समझौते का सूक्ष्म अध्ययन किया गया जिसके अंतर्गत भारत ने भारतीय शांति सस्थापक सेना (आई पी के एफ) के ३० ००० सैनिकों को श्रीलंका भेजा था।

सातवें अध्याय में कुछ अन्य पड़ोसी देशों के साथ भारतीय संबंधों की चर्चा की गई है। पूर्वी पड़ोसी देश ^{अथवा} बर्मा/म्यांमार में सैनिक शासन के विरोध में चल रहे प्रजातांत्रिक आन्दोलन की पृष्ठभूमि में भारत-बर्मा पारस्परिक सम्बन्धों का अध्ययन दिलचस्प हो जाता है क्योंकि स्पष्ट रूप से प्रजातांत्रिक भारत का झुकाव आन्दोलनकारियों की ओर था। इस अध्याय में हिन्द महासागर क्षेत्र की घटनाओं को

लेकर भारतीय विदेश नीति का मूल्यांकन किया गया है। हिन्द महासागर भारतीय रक्षा सामरिक एवं व्यावसायिक तीनों दृष्टियों से महत्वपूर्ण है अतः उसको लेकर इस काल में किए गए चिन्तन पर भी प्रकाश डालना अपरिहार्य हो जाता है।

⑧ आठवें अध्याय में भारत के साथ बांग्लादेश के सम्बन्धों की विवेचना की गयी है। बांग्लादेश के भारत के साथ सम्बन्ध विशेष सवेदनशील रहे हैं। क्योंकि इस देश की स्थापना भारत के प्रयास से ही हुई थी। इस अध्याय में बांग्लादेश के साथ भारत के सम्बन्धों की ऐतिहासिक विवेचना करते हुए राजीव गांधी के कार्यकाल में उसके सकारात्मक और नकारात्मक पहलुओं पर गहन रुचि डाली गयी है। साराशतः फरक्का विवाद मूरद्वीप का विवाद अवैध आब्रजन तथा सीमा विवाद आदि बिन्दुओं पर विशेष बल दिया गया है।

नवा अध्याय सम्पूर्ण शोध पत्र का निचोड़ है तथा इसे उपसंहार शीर्षक से सज्जानित किया गया है। इस अध्याय में श्री राजीव गांधी के पड़ोसी देशों के साथ सम्बन्धों की सफलता एवं असफलता को बेबाक दृष्टि से समग्रता के साथ मूल्यांकित किया गया है। यही नहीं चूँकि श्री राजीव गांधी की सम्पूर्ण विदेश नीति का 'रिफ्लेक्शन' ^{अथवा प्रभाव} पड़ोसी देशों के साथ सम्बन्धों पर पड़ा है अतः इस अध्याय में श्री राजीव गांधी की विदेश नीति पर सम्पूर्णता के साथ निष्कर्षात्मक टिप्पणियाँ प्रस्तुत की गयी हैं।

पड़ोसी देशों के साथ राजीव गांधी के सम्बन्धों पर निष्कर्षात्मक निर्णय देने के पूर्व यह आवश्यक था कि इन देशों के साथ राजीव गांधी के पूर्व काल में सम्बन्धों की पृष्ठभूमि को समझ लिया जाय । यही कारण है कि प्रत्येक अध्याय के प्रारम्भ में सम्बन्धित देश के साथ भारत के ऐतिहासिक सम्बन्धों की पर्याप्त विवेचना की गई है।

अन्ततः इस अध्ययन के लिए जहाँ सामग्री का अभाव था वही दूसरी ओर निकट अतीत की घटना होने के कारण इसमें प्रायः वस्तुनिष्ठ मूल्यांकन का अभाव पड़ा । हमें उस काल के समस्त दैनिक समाचार पत्रों के साथ प्रमुख शोध पत्रिकाएँ व अन्य पत्रिकाओं का अध्ययन करना पड़ा । वही भारत की ससद की कार्यवाहियों का अध्ययन भी अपरिहार्य था । स्वर्गीय श्री राजीव गांधी तथा तमाम भारत के पड़ोसी देशों पर लिखे गये ग्रन्थों से भी सहायता लेनी पड़ी । उपरोक्त सामग्री किसी एक छत के नीचे सहज उपलब्ध नहीं थी अतः शोधकर्ता को राष्ट्रीय पुस्तकालय कलकत्ता, राष्ट्रीय अभिलेखागार नई दिल्ली लोकसभा राज्यसभा तथा केन्द्रीय सचिवालय के पुस्तकालयों (दिल्ली) में अध्ययन करना पड़ा वही नेहरू मेमोरियल म्यूजियम तथा लाइब्रेरी इन्दिरा गांधी राष्ट्रीय कला केन्द्र तथा राजीव गांधी फाउण्डेशन आदि स्थानों में भी शोध सामग्री एकत्रित करने हेतु जाना पड़ा । मैं इन सभी संस्थानों के अधिकारियों एवं कर्मचारियों द्वारा प्रदान की गयी सहायता के लिए हृदय से आभारी हूँ ।

અધ્યાય - ૧

आज सूचना क्रांति ने 'ग्लोबल विलेज' की अवधारणा को साकार कर दिया है। देशों की दूरियाँ कम हो रही हैं दुनिया सिमट रही है। सूचना प्रौद्योगिकी या कम्प्यूटर ने इण्टरनेट, ई-मेल ई-कामर्स जैसी तमाम विधायें इजाद की हैं। भारत को कम्प्यूटर युग में ले जाने का सपना राजीव गांधी का था। भारत में राजीव गांधी इन्फार्मेशन टेक्नालॉजी के पुरस्कर्ता थे।

सूचना प्रौद्योगिकी और उदारीकरण से ग्लोबलाइजेशन (वैश्वीकरण) को बल मिला है। तेजी से बदलते हुए विश्व परिदृश्य में यह आवश्यक हो गया है कि हमारे सम्बन्ध अपने पड़ोसियों से मैत्रीपूर्ण एवं हितैषी के हों। इस सदर्भ में यह स्पष्ट कर देना समीचीन प्रतीत होता है कि भारत सदा से ही 'वसुधैव कुटुम्बकम्' का पोषक और पूरक रहा है। दल छद्म से परे हमारी विदेश नीति सदा से ही सुस्पष्ट एवं पारदर्शी ही है। जॉन डन ने कहा है कोई भी द्वीप बनकर नहीं रह सकता है^{अतः} स्वाभाविक है कि पड़ोसी देशों से भारत के बेहतर सम्बन्ध आज के युग की मांग हैं।

राजीव गांधी स्वातंत्रोत्तर भारत में जन्मी या पली पोसी नयी पीढ़ी का प्रतिनिधित्व करते थे। विज्ञान और प्रौद्योगिकी मानसिकता की पृष्ठभूमि में उनकी विदेश नीति नवोन्मेषक, अत्याधुनिक और प्रासंगिक थी¹। प्रस्तावित शोध प्रबन्ध राजीव गांधी के प्रधानमन्त्रित्व काल में भारत का पड़ोसी देशों से सम्बन्ध के सागोपाग और सूक्ष्म

विश्लेषण के लिये यह आवश्यक है कि भारतीय विदेश नीति के उन मूलभूत सिद्धांतों का विवेचन कर लिया जाय जिनके आलोक में हम आगे राजीव गांधी की विदेश नीति का मूल्यांकन करेंगे ।

भारतीय विदेश नीति के नीति निर्धारक तत्व व सिद्धान्तों का आधार है-विश्व शांति गुटनिरपेक्षता निरस्त्रीकरण का समर्थन साम्राज्यवाद उपनिवेशवाद व नस्लवाद का विरोध, अफ्रीका-एशियाई एकता का आह्वान और संयुक्त राष्ट्र सभ के सिद्धान्तों में आस्था । यही भारतीय विदेश नीति की नींव के पत्थर समझे जा सकते हैं । भारतीय विदेश नीति के प्रमुख सिद्धांतों का विश्लेषण निम्नांकित बिन्दुओं के तहत किया जा सकता है-

प्रथम बिन्दु है विश्व शान्ति | स्वतंत्र भारत के प्रथम प्रधानमंत्री प० जवाहर लाल नेहरू ने भारतीय संस्कृति और सभ्यता के अनुकूल विश्व बंधुत्व की अवधारणा को साकार करने के लिए विश्व शांति की नीति अपनायी। विश्व शान्ति में नेहरू की आस्था सिर्फ इस लिये नहीं थी कि वह बुद्ध और अशोक के देश में जन्मे थे या अहिंसक महात्मा गाँधी के पटु शिष्य थे²। नेहरू में व्यक्तिगत साहस की कोई कमी नहीं थी । उनके जीवन के अनेक प्रकरण उन्हें दुस्साहसी ही बताते हैं । विश्व शान्ति के प्रति उनका आकर्षण उस व्यक्तिगत अनुभव से उपजा था, जिसमें उन्होंने यूरोप के समृद्ध-सम्पन्न देशों को युद्ध की आग में झुलसते और बर्बाद होते देखा था । जिस समय भारत आजाद हुआ उस समय सारा विश्व द्वितीय महायुद्ध के ध्वंस

का बोझ उठा रहा था । नेहरू जी इस बात को भलीभाँति समझते थे कि यदि विश्व शान्ति अक्षत नहीं रखी जा सकी तो अफ्रीका और एशिया के अनगिनत देशों को आजाद होने का मौका नहीं मिलेगा³ । जब तक बड़ी शक्तियाँ संघर्षरत रहेगी उन्हें सामरिक दृष्टि से साम्राज्यवादी रणनीति के अनुसार अपने-अपने प्रभाव क्षेत्र बनाने ही होंगे । इन प्रभाव क्षेत्रों के अन्तर्गत आने वाले छोटे राष्ट्र-विपन्न समाज ऐसी हालत में स्वाधीनता की कल्पना ही नहीं कर सकते । नेहरू जी ने यह बात बहुत पहले आत्मसात कर ली थी कि विकास और विनाश के बीच गहरा अन्तर-संबंध है। जब तक विश्व पर युद्ध के बादल मंडराते रहेगे, तब तक विकासशील-नवोदित राष्ट्रों के लिए राष्ट्र निर्माण के साधन सुलभ नहीं हो सकते⁴ । नेहरू यूरोप में महायुद्ध तथा अफ्रीका-एशियाई देशों में गृहयुद्ध के अपने निजी अनुभवों से यह बात भलीभाँति समझते थे कि युद्ध का दबाव अन्य सभी सामाजिक प्राथमिकताओं को पीछे धकेल देता है वह मनुष्य के पार्श्विक पक्ष को उकसाता-उभारता है तथा अधिनायक को बढ़ावा देता है। फासीवाद-नाजीवाद का उदय प्रथम विश्वयुद्ध के मलबे के बिना सम्भव नहीं था । परमाणु अस्त्रों के अविष्कार ने नेहरू जी के शान्तिवादी चिन्तन को और पुष्ट किया । भारत की स्वाधीनता को सार्थक बनाने तथा विकास की गति तेज रखने के लिये विश्व शान्ति अनिवार्य थी, इसीलिये नेहरू जी ने अपने विदेश नीति नियोजन में विश्वशान्ति को प्राथमिकता दी ।

द्वितीय बिन्दु है गुटनिरपेक्षता किसी उभरते हुए राष्ट्र की विदेश नीति के ढांचे की विकास प्रक्रिया तथा मौजूदा अंतर्राष्ट्रीय पद्धतियों के साथ उसके समायोजन का निरीक्षण अपने आपमें अत्यंत आकर्षक होता है। विदेश नीति के आयाम विभिन्न कारकों से प्रभावित होते हैं, जैसे विभिन्न राज्यों का सूक्ष्म विश्लेषणात्मक मानचित्रण, संरचनात्मक बाधाओं की अनुभूति निर्णयकर्ताओं का व्यक्तित्व, सूचना अर्जन प्रणाली का आधारीक नमूना और राजनीतिक वैधता का सामाजिक आर्थिक मनोवैज्ञानिक विश्लेषण⁵। रोजनों के शब्दों में राज्य की कार्यवाही का स्वरूप उन लक्ष्यों द्वारा निर्धारित होता है जिनकी ओर वह उन्मुख होती है। ऐसा कुछ तो उन साधनों के द्वारा होता है जो उनका पोषण करने के लिये उपलब्ध होते हैं और कुछ उस संगठनात्मक एवं बौद्धिक प्रक्रिया के द्वारा होता है जिसके माध्यम से उस कार्यवाही का चयन किया गया था⁶। किसी भी शासन प्रणाली की विदेश नीति की चर्चा करते समय राष्ट्रीय हित की धारणा की चर्चा करना बहुत उपयुक्त होगा। हैस जे मारगेन्थो राष्ट्रीय हित संबंधी धारणा की तुलना सामान्य कल्याण और सम्यक प्रक्रिया जैसी सविधान की भारी भरकम उदघोषणा से करते हैं। उनके अनुसार इस धारणा के अनेक अर्थ हो सकते हैं जिनका निर्धारण उन राजनैतिक परम्पराओं और समग्र सांस्कृतिक सदर्भ के आधार पर होता है जिनकी परिधि में कोई राष्ट्र अपनी नीतियों का निरूपण करता है। किसी भी विदेश नीति का

विश्लेषण तीन चरणों के आधार पर किया जा सकता है सकल्पना विषय वस्तु, और कार्यान्वयन⁷ । सकल्पना का सबध वाछनीय एव व्यावहारिक लक्ष्यों के युक्तिपूर्ण मूल्यांकन से होता है विषयवस्तु में मूल्यांकन का परिणाम और प्रतिफलन अतर्निहित होता है और कार्यान्वयन का सबध राज्य के समन्वय तंत्र और उन तत्वों से होता है जिनके माध्यम से राज्य अन्य देशों से अपने सबध निर्मित करता है । उन्हीं सदर्थों में हमें भारत की गुट निरपेक्ष नीति के मुख्य अभिप्राय प्रयोज्यता सुसंगति की जाच और विश्लेषण करना होगा⁸।

भारत की विदेश नीति के प्रमुख लक्ष्य हैं - अंतराष्ट्रीय शांति एवं सुरक्षा को कायम रखना और उसका सबर्धन करना, सभी उपनिवेशों के निवासियों के आत्मनिर्णय के अधिकार को बढावा देना, रगभेद का विरोध और समानता पर आधारित समाज की स्थापना का समर्थन, अंतराष्ट्रीय विवादों और झगडों का शांतिपूर्ण निपटारा अफ्रीकी-एशियाई देशों का समर्थन आणविक निशस्त्रीकरण तथा नवीन अंतराष्ट्रीय आर्थिक व्यवस्था की स्थापना और इन सभी लक्ष्यों की प्राप्ति सयुक्त राष्ट्र की व्यवस्था में रहकर करना⁹ । गुटनिरपेक्ष नीति के निरूपण पर विशेषकर उसके आरम्भिक काल में, साम्राज्यवाद-विरोधी उस संघर्ष का और उसके द्वारा घोषित आदर्शों एवं मान्यताओं का प्रत्यक्ष प्रभाव पड़ा जिसका नेतृत्व गांधी ने किया था । समय के साथ-साथ गुटनिरपेक्ष नीति का विश्लेषण करते समय ऐसी मान्यताओं के प्रभाव को दृष्टि से ओझल नहीं किया जा

सकता जैसे राजनीतिक एव सत्ता का आदर्शवादी दृष्टिकोण, एशियावाद, सिद्धांततः पश्चिमी जनतंत्र प्रणाली और साम्यवाद दोनों का खंडन और अंतर्राष्ट्रीय संधि के प्रति आदर्शवादी दृष्टिकोण¹⁰ ।

गुट निरपेक्षता की अवधारणा विश्वशान्ति की स्थापना के लिये एक महत्वपूर्ण पहल थी । द्वितीय महायुद्ध के बाद युद्ध विराम तो हो गया परन्तु शान्ति नहीं लौटी । मित्र राष्ट्रों में फूट पड़ गयी और शीतयुद्ध का आविर्भाव हुआ परमाणु अस्त्रों के आविष्कार के बाद पारम्परिक शक्ति सन्तुलन का स्थान आतंक के सन्तुलन ने ले लिया⁸। यहाँ सिर्फ इतना रेखांकित करना यथेष्ट होगा कि द्वितीय विश्व युद्ध के बाद अन्तर्राष्ट्रीय स्थिति बेहद तनाव पूर्ण एव जोखिम भरी हो गयी थी। नेहरू जी ने बेहद समझदारी के साथ नवोदित राष्ट्रों के सामने गुट निरपेक्ष नीति अपनाने का सुझाव रखा । जाहिर है कि गुट निरपेक्षता का अर्थ निष्क्रिय उदासीनता तटस्थताया अवसरवादिता नहीं था। अपनी स्वाधीनता को मुखर कर स्व-विवेक के अनुसार अपने राष्ट्र हित के अनुकूल विकल्प चुनना असली गुट-निरपेक्षता थी। इस नीति पर डटे रहना कट्टरपन नहीं, बल्कि साहस का काम था¹¹ ।

नेहरू जी ने यह बात आरम्भ में ही स्पष्ट कर दी थी कि उनका इरादा अपने देश को महाशक्तियों के दगल से अलग बचाकर रखने का है और क्रमशः शान्ति के क्षेत्र में विस्तार का । उन्होंने यह भी स्पष्ट कर दिया था कि भारत की कोई भी महात्वाकांक्षा तीसरे खेमे के गठन और उसके मुखिया के रूप में उभरने का अर्थ किसी

न किसी महाशक्ति का शिविरानुचर बनना ही हो सकता है और ऐसा करना कठिनाई से अर्जित आजादी को गवाना होता है¹² । नेहरू जी ने कभी यह समझने- समझाने की नादानी नहीं की कि गुट निरपेक्षता का अर्थ निष्क्रिय रहना है। इसके अतिरिक्त गुट निरपेक्षता के कारण भारत जैसा नवोदित राष्ट्र दोनो खेमो में आर्थिक सहायता ग्रहण कर सकता था। आरम्भ में भले ही तत्कालीन सोवियत शासक स्टालिन और अमरीकी विदेश सचिव डलेस ने गुट निरपेक्षता को उपहास का विषय समझा, किन्तु कोरिया और हिन्द चीन के अनुभव के बाद उनके द्वारा भारत की ईमानदारी पर प्रश्न-चिन्ह लगाना सम्भव नहीं रहा। नेहरू जी ने गुट-निरपेक्ष आन्दोलन के बहाने मिश्र कम्पूचिया इण्डोनेशिया और युगोस्लाविया जैसे देशों से सम्बन्ध घनिष्ट कर अफ्रीका-एशियाई भाईचारे और विश्व बन्धुत्व के भाव को पुष्ट किया¹³ । जब साम्राज्यवाद व उपनिवेशवाद के विरुद्ध मुहिम छेड़ना जरूरी समझा गया, तब गुट निरपेक्षता का मन्त्र बेहद उपयोगी सिद्ध हुआ। इसीलिए शिशिर गुप्त जैसे विद्वानों ने टिप्पणी की है कि शायद गुट निरपेक्षता को भारतीय विदेश नीति का एक प्रमुख सिद्धान्त कहने की अपेक्षा इसे विदेश नीति के उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए अपनायी गयी रणनीति कहना अधिक समीचीन है।

तीसरा बिन्दु है निशस्त्रीकरण जिस तरह गुट निरपेक्षता विश्व शान्ति से जुड़ी हुई थी, उसी तरह निशस्त्रीकरण का मुद्दा गुट

निरपेक्षता से गुँथा हुआ था। जब तक शस्त्रास्त्रों की अन्धी दौड़ जारी थी, तब तक विश्व शान्ति को निरापद नहीं समझा जा सकता था¹⁴। शस्त्रीकरण की प्रक्रिया अनिवार्यतः युद्ध की मानसिकता को पुष्ट करती थी जिसमें सैनिक संगठन शत्रु की घेराबन्दी जोर अजमाइश आदि से बचना कठिन था। परमाणु अस्त्रों के आविष्कार ने शस्त्रीकरण की समस्या के और भी खतरनाक आयाम उद्घाटित किये थे। कई लोगों का यह भी मानना है कि नेहरू जी के लिए विश्व शान्ति और निशस्त्रीकरण अलग-अलग मुद्दे नहीं थे। नेहरू जी ने हर उपलब्ध अन्तर्राष्ट्रीय मंच से निशस्त्रीकरण का संदेश प्रसारित किया। इसके खातिर वह अपने आत्मीय मित्रों से टकराने में भी कभी कतराये नहीं। गुट निरपेक्ष देशों के बेलग्रेड शिखर सम्मलेन (1961) में सुकार्णों के साथ उनकी मुठभेड़ निशस्त्रीकरण बनाम नव-उपनिवेशवाद को लेकर ही हुई थी¹⁵। कुछ अन्य विद्वानों का यह भी मानना है कि संयुक्त राष्ट्र संघ में नेहरू जी की आस्था इसीलिए गहरी थी क्योंकि वह समझते थे कि बिना व्यावहारिक सामूहिक सुरक्षा व्यवस्था के सम्प्रभु राष्ट्र स्वेच्छा से शस्त्र त्याग नहीं करने वाले। नेहरू जी का निशस्त्रीकरण के प्रति आकर्षण किसी दुर्बलता से नहीं उपजा था। न्यायसंगत विषय पर आत्मरक्षा के लिए शस्त्र प्रयोग से नेहरू जी को कोई हिचकिचाहट नहीं होती थी। गोवा कश्मीर और चीन के प्रसंग इसका अच्छा उदाहरण प्रस्तुत करते हैं।

चौथा बिन्दु है साम्राज्यवाद उपनिवेशवाद व रगभेद का विरोध विश्व शांति, गुटनिरपेक्षता व निरस्त्रीकरण की पक्षधरता के बावजूद नेहरू द्वारा निर्धारित भारतीय विदेश नीति के सिद्धान्तों में साम्राज्यवाद उपनिवेशवाद व नश्लवाद का कटु विरोध शामिल था । सतही दृष्टि से इसमें भले ही विरोधाभास जान पड़े, लेकिन वास्तव में ऐसा नहीं था । नेहरू जी ने यह बात बहुत पहले स्पष्ट कर दी थी कि विश्व शान्ति को सबसे बड़ा संकट साम्राज्यवाद उपनिवेशवाद एवं नश्लवाद से है¹⁶ । नेहरू जी का ऐतिहासिक अध्ययन और राजनीतिक अनुभव उन्हें यह बात भी भलीभाँति आत्मसात करवा चुका था कि नश्लवाद और उपनिवेशवाद बिना साम्राज्यवादी समर्थन के टिके नहीं रह सकते । भारतीय अनुभव के कारण नेहरू जी वास्तव में इस संघर्ष का शांतिपूर्ण परामर्श द्वारा समाधान चाहते थे, परन्तु आवश्यकता पड़ने पर सशस्त्र जन-मुक्ति संग्राम को भारतीय समर्थन देने में उन्हें संकोच नहीं होता था ।

पाचवा बिन्दु है अफ्रो एशियाई एकता नेहरू जी ने यह बात बहुत पहले अच्छी तरह गँठ बाँध ली थी । संसार के सभी विपन्न और वंचित राष्ट्रों और समाजों के हित एक समान हैं । साम्राज्यवाद, उपनिवेशवाद व नश्लवाद का विरोध हो या गुट निरपेक्षवाद आन्दोलन के संचालन द्वारा विश्व शांति और निरस्त्रीकरण को आगे बढ़ाने का सवाल इसके लिए अफ्रो-एशियाई एकता की पुष्टि

परमाश्यक थी । इस प्रकार नेहरू द्वारा अफ्रो-एशियाई भाईचारे की बात उठाना महज भावावेश नहीं बल्कि एक तर्कसगत कदम था ।

छठा बिन्दु है सयुक्त राष्ट्र सघ में आस्था सयुक्त राष्ट्र सघ के प्रति नेहरू जी का आर्कषण किसी आदर्शवाद नादानी से प्रेरित नहीं था बल्कि सिद्धान्तों के व्यवहार में रूपान्तरण की सम्भावना के कारण उपजा था¹⁷ । नेहरू जी निहायत यथार्थवादी ढंग से जानते थे कि वीटो के कारण दो महाशक्तियों के बीच जिच की स्थिति पैदा हो जाने से स० रा० सघ में भारत जैसे गुट निरपेक्ष देश को रचनात्मक भूमिका निभाने का मौका मिल सकता है और सदस्य देशों की जमात में अफ्रो-एशियाई देशों की वृद्धि होने के साथ इस मंच का उपयोग विश्व शान्ति की स्थापना, निशस्त्रीकरण के प्रसार और साम्राज्यवाद उपनिवेशवाद व नश्लवाद के विरुद्ध संघर्ष के लिए बखूबी किया जा सकता है ।

अब हम आते हैं राजीव गाँधी के पूर्व स्वतंत्र भारत की विदेश नीति पर । विभिन्न चरणों में भारतीय विदेश नीति में निरन्तरता और परिवर्तन की दोनों धाराएँ साथ-साथ चलती रही हैं । आजादी के बाद भारत ने जहाँ उपनिवेशवाद, साम्राज्यवाद व रंगभेद और बड़ी शक्तियों की गुटबाजी का कड़ा विरोध किया, वहीं १९६२ के बाद भारतीय विदेश नीति की प्राथमिकताएँ और जोर कुछ अन्य मसलों पर केन्द्रित हो गया । कुछ और वर्षों बाद नई विश्व अर्थव्यवस्था की

तलाश समुद्री कानून सम्मेलन, उत्तर दक्षिण सवाद दक्षिण-दक्षिण सवाद और परमाणु निशस्त्रीकरण जैसे मसले विश्व राजनीति में छा गये। जाहिर है कि भारत इनके प्रति मौन नहीं रह सकता था। इसके अतिरिक्त पड़ोसी देशों के साथ भारत के सम्बन्ध भी अनेक बार काफी तनावग्रस्त हुए। इन सभी बातों का अध्ययन विभिन्न भारतीय प्रधान मन्त्रियों के शासन काल के दौरान अपनायी गई विदेश नीति के विश्लेषण से करना उचित होगा।

नेहरू कालीन विदेश नीति

नेहरू की विदेश नीति के प्रमुख सिद्धान्त स्वाधीनता संग्राम के दिनों में ही सुनिश्चित हो गये थे। व्यावहारिक रूप में इनको औपचारिक ढंग से पंचशील के नाम से परिभाषित किया गया। भले ही भारत व चीन के बीच पंचशील समझौते पर हस्ताक्षर अप्रैल १९५४ में किया गया, परन्तु १९४७ से लेकर १९५४ तक भारत के अन्तर्राष्ट्रीय क्रियाकलाप इसी आधार पर संचालित व समायोजित होते रहे¹⁸।

पंचशील के पाँच सिद्धान्त निम्नवत हैं-

- १ सभी राष्ट्र एक दूसरे की प्रादेशिक अखण्डता व सम्प्रभुता का सम्मान करें।
- २ कोई राज्य दूसरे राज्य पर आक्रमण न करे और दूसरों की राष्ट्रीय सीमाओं का अतिक्रमण न करे।
- ३ कोई राज्य दूसरे राज्य के आन्तरिक मामलों में हस्तक्षेप न करे।

४ प्रत्येक राज्य एक दूसरे के साथ समानता का व्यवहार करे तथा पारस्परिक हित में सहयोग प्रदान करे अर्थात् न कोई देश बड़ा है और न ही छोटा ।

५ सभी राष्ट्र शान्तिपूर्ण सह-अस्तित्व के सिद्धान्त में विश्वास करें तथा इसी सिद्धान्त के आधार पर एक-दूसरे के साथ शान्तिपूर्वक रहे और अपनी पृथक सत्ता एवं स्वतन्त्रता बनाये रखे ।

कुछ विद्वानों का मानना है कि पंचशील योजना नेहरू जी की आदर्शवादी रूमानियत का उदाहरण भर थी, और कुछ नहीं । परन्तु वास्तविकता की अनदेखी नहीं की जानी चाहिए कि पंचशील की राजनयिक रणनीति भारतीय राष्ट्रीय हितों की यथार्थवादी कसौटी पर खरी उतरती है । भारत का विभाजन आजादी के साथ हो गया और पाकिस्तानी रजाकारों ने कश्मीर को हथियाने के लालच में भारतीय सीमा का अतिक्रमण किया । यह अघोषित युद्ध लगभग दो वर्ष तक चलता रहा । १९४७ में सारा भारतीय भू-भाग एक साथ स्वतन्त्र नहीं हुआ । रजवाड़ों की स्थिति सदिग्ध थी और गोवा, दमन दीव चन्द्रनगर व पाण्डिचेरी जैसे इलाके अंग्रेजों से इतर दूसरी औपनिवेशिक शक्तियों के आधिपत्य में थे।

इसके शीघ्र बाद एक और महत्वपूर्ण परिवर्तन हुआ । १९४९ में चीन में साम्यवादियों ने सरकार का गठन किया और १९५० में तिब्बत को मुक्त कराने का प्रयास शुरू किया । इसके साथ ही ब्रिटिश साम्राज्यवादी शासन काल में सीमांकित किया गया सारा

हिमालयी भू-भाग सीमान्त विवादास्पद बन गया¹⁹ । ऐसी परिस्थिति में यदि नेहरू जी ने नवोदित राष्ट्रों की सम्प्रभुता की रक्षा, भौगोलिक सीमाओं के सम्मान और आन्तरिक मामलों में हस्तक्षेप से बचने के पक्ष में अन्तर्राष्ट्रीय जनमत तैयार करने की चेष्टा की तो इसे आदर्शवादी कतई नहीं समझा जा सकता । समस्याओं के शान्तिपूर्ण समाधान की प्रस्तावना के बिना सह-अस्तित्व की बात सोची भी नहीं जा सकती थी । पंचशील योजना में यह बात अन्तर्निहित थी कि इसका अभिगम सिर्फ प्रतिरक्षात्मक नहीं बल्कि रचनात्मक भी है । पंचशील समझौते में साझीदार पक्षों के लिए लाभप्रद उभयपक्षीय सहकार के लक्ष्य तय करना नेहरू जी की दूरदर्शिता थी ।

पंचशील के बारे में विदेशी और भारतीय विद्वानों के मत स्पष्टतः दो ध्रुवों के बीच झूलते हैं । कुछ विद्वानों का मानना है कि पंचशील की बात उठाना नेहरू जी की दुर्बलताजनित विवशता थी । सैनिक शक्ति और आर्थिक साधनों के अभाव में वह और कुछ कर भी नहीं सकते थे। जयन्तनुज वन्द्योपाध्याय जैसे कुछेक विद्वान अपवाद हैं जो मानते हैं कि नेहरू जी ने जान बूझकर यह जोखिमभरा कदम उठाया, ताकि अन्तर्राष्ट्रीय राजनीति को नई दिशा दी जा सके ²⁰। दूसरी ओर लॉर्न काविक और नेविल मैक्सवेल सरीखे लेखक हैं जिनकी समझ में पंचशील एक धूर्ततापूर्ण पाखण्ड था, जिसका एकमात्र उद्देश्य भारत को सैनिक दृष्टि से शक्तिशाली बनाने के लिए कुछ मोहलत जुटाना था । वैसे इन दोनों बातों में

कोई बुनियादी अन्तरविरोध नहीं है। आर्थिक और सैनिक उपकरणों के अभाव में यदि बाडुग सम्मेलन १९५५ के अवसर पर नेहरू जी ने भारत को अदभूत प्रतिष्ठा दिला दी थी तो उसके आधार में पंचशील की सफलता ही थी।

बाडुग सम्मेलन के बारे में मजेदार बात यह है कि अफ्रो-एशियाई देशों के इस जमघट का आयोजन भारत के सुझाव पर नहीं किया गया था। कोलम्बो परियोजना में शामिल पश्चिमी खेमे के पक्षधर राष्ट्रों ने इसकी पहल की परन्तु नेहरू जी और कृष्णा मेनन ने समझदारी दिखाते हुए इसे नवोदित राष्ट्रों की स्वाधीनता और गुट-निरपेक्षता का प्रतीक बना दिया²¹। आज कई दशक बाद बाडुग सम्मेलन की सीमाओं और असफलताओं का छिद्रान्वेषण सहज है। परन्तु नेहरू जी ने शीत युद्ध के सकटों से जूझते हुए जिस तरह सैनिक गठबन्धनों को निरस्त करने का प्रयास किया, वह प्रशंसनीय था। ऐसा सोचना ठीक नहीं कि नेहरू जी ने सिर्फ शब्दाडम्बर या वक्तृता से तीसरी दुनिया का नेतृत्व हथियाने के लिए किया। बाडुग सम्मेलन के आयोजन के पहले कोरिया में अपनी निष्पक्ष मध्यस्थता और हिन्द - चीन में युद्ध विराम के लिए सक्रियता से भारत ने अपनी पात्रता प्रमाणित कर दी थी। नासिर सुकार्णो आदि के साथ व्यक्तिगत स्तर पर सार्थक सवाद का सूत्रपात भी बाडुग सम्मेलन से ही सम्भव हुआ²²।

बाडुग सम्मेलन का एक और दृष्टि से अन्तर्राष्ट्रीय महत्व है । इस सम्मेलन में हिस्सेदारी के बाद ही चीन की साम्यवादी सरकार का मानवीय पक्ष अन्य देशों के सामने आया और उसको वाछित स्वीकृति मिल सकी । इस सम्मेलन में अपनाये गये प्रस्तावों का अध्ययन करने पर यह बात स्पष्ट होती है कि पचशील समझौते की ही तरह इस बार भी नेहरू जी ने आदर्श और यथार्थ का सन्तुलन बैठाने की कोशिश की थी²³ । उनका प्रमुख प्रयत्न यही कि अधिकाधिक अफ्रो-एशियाई देशों को ब्रिटिश ससदीय प्रणाली से प्रेरित सभा-सम्मेलनीय राजनय में शामिल किया जा सके ताकि भविष्य में उठने वाले विवादों के शान्तिपूर्ण समाधान की सम्भावना बची रहे । बाडुग सम्मेलन की उपलब्धि सही थी कि दोनों महाशक्तियों को यह बात स्पष्टतः समझायी जा सकी कि अफ्रो-एशियाई देशों का उनसे कोई जन्मजात बैर सैद्धान्तिक विचारधारा या नस्ल के आधार पर नहीं है । पाकिस्तान और सीलोन (अब श्रीलंका) के साथ भारतीय प्रतिनिधियों की नोक-झोंक भले ही होती रही परन्तु बाडुग में ही उस अफ्रो-एशियाई गुट का गठन हुआ, जिसने संयुक्त राष्ट्र सभ में इनकी हस्ती को महत्वपूर्ण बनाया । बाडुग भावना के बिना गुट-निरपेक्ष आन्दोलन का बेगवान बनना कठिन होता²⁴ ।

परन्तु इससे यह समझना उचित नहीं कि नेहरू जी की विदेश-नीति तर्क सगत और दूरदर्शी होने के कारण सभी प्रकार

की दुर्बलताओं से मुक्त थी। नेहरू जी सदैव इस बात को अनदेखा करते रहे कि अधिकतर अफ्रो-एशियाई नेताओं का स्वभाव और सस्कार उससे भिन्न है और यह जरूरी नहीं कि वे हमेशा बदली परिस्थिति में अन्तर्राष्ट्रीय राज्य विषयक उनकी सभी स्थापनाओं को लाभप्रद उपयोगी उपदेश के रूप में ग्रहण करते रहे। बाडुग सम्मेलन के सस्मरण लिखते वक्त नासिर और चाऊ एन लाई दोनों ने यह स्वीकार किया है कि नेहरू जी हमेशा इस तरह आचरण करते थे जैसे वह उनके भाई या पथ प्रदर्शक हों। दोनों नेताओं को यह बात अपमानजनक लगती रही थी ²⁵। इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता कि नेहरू जी की विदेश नीति और राजनय व्यक्ति-केन्द्रित थे और व्यक्तिगत समीकरण बदलने पर विदेश नीति और राजनय बहुत सीमित प्रभाव वाले रह जाते थे। बेलग्रेड सम्मेलन में सुकार्णो और नेहरू जी के बीच टकराव के बाद पुरानी स्थिति कभी लौटाई नहीं जा सकी।

नेहरू जी की एक और कमजोरी थी। वह अपनी पसन्द-नापसन्द को छिपा कर नहीं रख सकते थे। उनकी आस्था समाजवादी जनतंत्र में थी। वह राजशाही सामन्तवाद तथा सैनिक शासन को प्रति क्रियावादी समझते थे। नेपाल तथा पाकिस्तान के साथ उनका व्यवहार इसी कारण कभी सहज नहीं हो सका। श्रीलंका के प्रधानमंत्री जोन कोटनेवाला ने यह एक बार सटीक टिप्पणी की थी कि भारत जैसा बड़ा राष्ट्र गुट-निरपेक्षता की

विलासिता भोग सकती है परन्तु छोटे राष्ट्रों के सामने यह सुविधापूर्ण मार्ग उपलब्ध नहीं । आचारण में व्यावहारिक होने के बावजूद घोषणाओं के स्तर पर सैद्धान्तिक शुद्धि का दुराग्रह नेहरू जी की विश्वसनीयता और भारतीय विदेश नीति का प्रभाव कम करता रहा⁵ । समस्याओं के शान्तिपूर्ण निपटारे की बात करते वक्त नेहरू जी कश्मीर में जनमत संग्रह के अपने आश्वासन के निरन्तर टालते रहने के लिये बाध्य हुये । वह गोवा की मुक्ति के लिये बल-प्रयोग के बाद कथनी और करनी में दोहरे मानदण्डों के लिये भी बाध्य हुये । इसी तरह भारत चीन सम्बन्धों की गलतफहमी एक बड़ी सीमा तक इस बात से पैदा हुई कि जहाँ नेहरू जी एक ओर स्वयं को स्वतंत्र भारत के प्रगतिशील प्रधानमंत्री के रूप में पेश करते थे वही देश की भौगोलिक सीमा के बारे में औपनिवेशिक उत्तराधिकार को अक्षत रखने के लिये वह बचनबद्ध थे । नेहरूकालीन भारतीय विदेश-नीति की सबसे बड़ी विशेषता यही पुरानी और नयी परम्परा तथा अन्तर्द्वन्द्व थी । महाशक्तियों और पड़ोसियों के साथ १९४७ से १९६४ तक भारत के राजनयिक सम्बन्धों के उतार चढ़ाव में इसका तनाव स्पष्ट प्रतिबिम्बित होता है ।

अब हम आते हैं शास्त्रीकालीन विदेश नीति पर । १९६४ में नेहरू जी की मृत्यु के बाद लाल बहादुर शास्त्री ने देश की बागडोर संभाली । शास्त्री जी का व्यक्तित्व अपने पूर्ववर्ती प्रधानमंत्री नेहरू जी से इतना भिन्न था कि कई लोगों के मन में यह शक पैदा होना

स्वाभाविक था कि विदेश-नीति नियोजन और निर्धारण के मामले में शास्त्री जी असमर्थ रहेंगे। न तो उनकी शिक्षा-दीक्षा विदेश में हुई थी और न ही प्रधानमंत्री बनने के पहले उन्होंने अन्तर्राष्ट्रीय मामलों में कोई विशेष रुचि दर्शायी थी। इसी कारण जब शास्त्रीकालीन भारतीय विदेश नीति का विश्लेषण किया जाता है तो नेहरू युगीन विदेश नीति के साथ उसका फर्क दर्शाने का लोभ सवरण कम ही लोग कर पाते हैं²⁶। शास्त्रीकालीन विदेश नीति के सदर्भ में अक्सर यह कहा जाता है कि उन्होंने निरर्थक आदर्शवाद को सार्थक यथार्थवाद से विस्थापित किया और शान्ति प्रेमी होने के वावजूद राष्ट्र-हित के संरक्षण-संवर्धन के लिए सैनिक उपकरणों की उपयोगिता को स्वीकार किया। उनके कार्य काल का विशेष अध्ययन करने वाले प्रोफेसर एल०पी० सिंह का मानना है कि भले ही उन्होंने भारतीय विदेश नीति के क्षितिज संकुचित किये, किन्तु उन्हें कुल मिलाकर भौतिक सूझ से वंचित नहीं समझा जा सकता और न ही उनके योगदान को नगण्य माना जा सकता।

शास्त्रीय युग की भारतीय विदेश नीति में दो प्रमुख स्मारक बिन्दु हैं -

- १ पाकिस्तान के साथ सैनिक मुठभेड़ के बाद ताश्कन्द समझौता और
- २ श्रीलंका की प्रधानमंत्री श्रीमती सिरीमाओ भण्डारनायके के साथ परामर्श के बाद नागरिकता-विहीन प्रवासी तमिलों के बारे में शान्तिपूर्ण समाधान। जहाँ एक ओर कच्छ के रण में और उसके बाद पाकिस्तान के साथ युद्ध में शास्त्री जी ने यह स्पष्ट किया कि वह

शान्ति प्रिय ओर शान्तिपूर्ण सह-अस्तित्व के नाम पर भारतीय राष्ट्रीय हित की बलि देने को तैयार नहीं है वही श्रीलंका के साथ समझौते से उन्होंने अन्य छोटे पड़ोसी देशों को इस बारे में आश्वस्त भी किया कि भारत का कोई इरादा बल प्रयोग द्वारा उन पर हावी होने का नहीं था । मैत्रीपूर्ण सम्बन्धों की स्थापना के लिए वह रियायतें देने को प्रस्तुत थे । नेहरू जी की तरह अपनी अन्तर्राष्ट्रीय छवि या अह को बरकरार रखने की कोई समस्या शास्त्री जी के सामने नहीं थी ।

शास्त्री जी की विदेश नीति के बारे में दो-तीन विन्दु उल्लेखनीय हैं । एक तो उन्होंने प्रधानमंत्री सचिवालय का गठन कर अपने सलाहकारों की एक नई टोली जुटायी। इससे विदेश मंत्रालय के अवमूल्यन की प्रक्रिया चाहे-अनचाहे शुरू हुई। इसके अतिरिक्त परमाणु नीति के मामले में शास्त्री जी ने ऐसा निर्णय लिया कि सामरिक विकल्प को त्यागा न जा सके²⁷ । ताशकन्द सम्मेलन में दौरा पड़ने से शास्त्री जी की मृत्यु हो गयी । गुट-निरपेक्ष आन्दोलन राष्ट्रमण्डलीय राजनय अफ्रो-एशियाई भाईचारे आदि के क्षेत्र में निजी छाप छोड़ने का कोई अवसर उसे नहीं मिला। यह भी स्मरणीय है कि १९६४-६६ में भारत भयंकर दुर्भिक्ष से ग्रस्त था और अपमानजनक ढंग से विदेशों से खाद्यान्नके आयात पर निर्भर था। ऐसी परिस्थिति में अन्तर्राष्ट्रीय रंगमंच पर भारत की भूमिका कतई प्रमुख नहीं हो सकती थी । इसे शास्त्रीजी की एक बड़ी उपलब्धि समझा जाना चाहिए कि १९६२ के घाव को भरने का काम उन्होंने

अपने छोटे से कार्यकाल में बखूबी किया ।

जहाँ तक इन्दिरागांधी कालीन विदेश नीति का सम्बन्ध है

जनवरी १९६६ में शास्त्रीजी के निधन के बाद इन्दिरा गांधी प्रधानमंत्री बनी । जिस तरह की भ्रान्तियाँ शास्त्रीजी के बारे में फैली हैं उसी तरह तर्कहीन अतिसरलीकरण इन्दिरा गांधी की विदेश नीति और राजनय के बारे में भी प्रचलित है। पत्रकारों और जीवनीकारों की कृपा से श्रीमती गांधी की छवि लौह महिला और रणचण्डी वाली प्रसिद्ध हुई है। लोगों के मन में आज भी या तो १९७१ के बंगलादेश मुक्ति अभियान की याद ताजा है या मई १९७४ में पोखरण में परमाणु विस्फोट और जून १९७५ में आपातकाल की घोषणा की । यदि चुन-चुनकर ऐसे उदाहरण पेश किये जायें तो श्रीमती गांधी को अति यथार्थवादी प्रमाणित करना कठिन नहीं होगा। इसी तरह के प्रयत्न श्रीमती गांधी के अन्तर्मुखी स्वभाव उनके पारिवारिक एकाकीपन एवं मानसिक असुरक्षा के भाव को उनके अन्तर्राष्ट्रीय आचरण के साथ जोड़ने के लिए किये जाते हैं²⁸ । ऐसा नहीं कि यह विश्लेषण श्रीमती गांधी के आलोचक विरोधी ही करते रहे हैं बल्कि श्रीमती गांधी के साथ सहानुभूति रखने वाले विद्वान भी इस भ्रान्ति के शिकार हुए हैं। उदाहरणार्थ इन्दिरा गाँधी की विदेश नीति का विस्तार से विश्लेषण प्रस्तुत करने वाली लेखिका सुरजीत मानसिंह की पुस्तक का शीर्षक ही 'India's Search for Power' अर्थात् 'भारत शक्ति के तलाश में' है। यदि अध्येता

सतर्कता न बरते तो इस निष्कर्ष तक अनायास पहुँचा जा सकता है कि श्रीमती गांधी ने ही सर्वप्रथम पारम्परिक शक्ति सन्तुलन के आधार पर राष्ट्र हित संपादन का कार्य किया। जैसा कि ऊपर कहा जा चुका है कि काश्मीर, पाकिस्तान गोवा आदि के सन्दर्भ में नेहरू और शास्त्रीजी का आचरण भी आर्दशवादी नहीं समझा जा सकता है²⁹।

श्रीमती गांधी के सन्दर्भ में यह टिप्पणी अधिक सार्थक लगती है कि उनकी विदेश नीति का अमूर्त वैचारिक पक्ष कहीं अधिक मुखर था। तीसरी दुनिया का खाद्यान्न संकट हो या पर्यावरण के संरक्षण का प्रश्न श्रीमती गांधी का उद्बोधन-आह्वान सिर्फ भारतीय जनता के लिये ही नहीं, बल्कि समग्र विश्व के लिए होता था। इसी तरह यह भी कहा जा सकता है कि पड़ोसी देशों और परमाणु नीति के सन्दर्भ में वह उसी दिशा में आगे बढ़ी जिस तरफ कदम पहले ही उठाये चुके थे। श्रीमती गांधी को अपनी घोषणाओं-वक्तव्यों में क्रान्तिकारी प्रगतिशील मुद्रा ग्रहण करना अच्छा लगता था, परन्तु व्यवहार में नेहरू जी की सुझायी गुट-निरपेक्ष नीति में किंचित मात्र परिवर्तन या संशोधन की जरूरत नहीं समझी।

श्रीमती गांधी की विदेश नीति का अध्ययन करते समय इस तथ्य की अनदेखी नहीं की जानी चाहिये कि उन्होंने कठिनतम चुनौतियों से जूझते हुए भारत को अन्तर्राष्ट्रीय राजनय का केन्द्र बिन्दु बनाये रखने में सफलता प्राप्त की। १९६६ से १९६९-७० तक कांग्रेस पार्टी में उनकी अपनी स्थिति निरापद नहीं थी और भारत

विकट आर्थिक समस्याओं से जूझ रहा था। रुपये का अवमूल्यन प्रिवीपर्स की समाप्ति बैंको का राष्ट्रीयकरण कांग्रेस का विभाजन, बिहार में अकाल का सामना आदि चुनौतियाँ उन्हें अपने कार्यकाल के पहले चरण में पूरी तरह व्यस्त रखे रहीं। बंगला देश प्रकरण में पराक्रमी प्रदर्शन और १९७१ के चुनाव में अभूतपूर्व सफलता के बाद थोड़े ही समय के लिये वैदेशिक मामलों में एकाग्रचित होने का अवसर मिला। १९७२ में शिमला समझौता सम्पन्न हुआ तो १९७३-७५ में जयप्रकाश नारायण के नेतृत्व में उनके राजनैतिक अस्तित्व की चुनौती देने वाला व्यापक जन-आन्दोलन शुरू हुआ। इसकी परिणति जून १९७५ में आपातकाल की घोषणा और अन्ततः मार्च १९७७ के संसदीय आम चुनाव में श्रीमती गांधी की हार में हुई।

जहाँ तक जनता सरकार की विदेश नीति का सम्बन्ध है इसकी रूपरेखा मार्च १९७७ में मोरारजी देसाई के नेतृत्व में जनता पार्टी के शासन की बागडोर सम्भालने से बनी। जिन परिस्थितियों में जनता सरकार का गठन हुआ उसमें गांधी ही नहीं, बल्कि नेहरू वंश के प्रति रोष-आक्रोश का स्वर तेज था। आपात काल की तानाशाही की दुस्वप्न जैसी स्मृति जनता के मन में थी। जनता सरकार के नेता श्रीमती इन्दिरा गांधी की सभी नीतियों को बदलने के लिये व्यग्र थे। फिर भी नए विदेश मंत्री अटल बिहारी वाजपेयी ने कार्यभार सम्भालने के बाद यह घोषणा की कि वह नेहरू की

विदेश नीति के अनुसार ही आचरण करेंगे । कहने को भले ही उन्होंने खालिस गुट निरपेक्षता की बात की परन्तु इसका प्रमुख अभिप्राय यह दर्शाना था कि इन्दिरा गांधी ही अपने पिता के मार्ग से विचलित हुई थी । पड़ोसी देशों के साथ सम्बन्धों के क्षेत्र में जरूरत से ज्यादा रियायती व नरम रुख अपनाना जनता सरकार के लिये शायद इसलिये जरूरी हुआ कि उसके विदेश मंत्री बाजपेयी की अब तक छवि आक्रामक हिन्दु राष्ट्रवादी वाली थी ³⁰ । जनता सरकार का गठन विभिन्न वैचारिक रुझानों वाले राजनीतिक दलों को मिलाकर हुआ था । इसी कारण किसी स्पष्ट अन्तर्राष्ट्रीय परिपेक्ष्य या सैद्धान्तिक संरोकार की अपेक्षा उनसे नहीं की जा सकती थी । यह स्वभाविक था कि नौकरशाही का महत्व विदेश नीति नियोजन के क्षेत्र में बढ़ा ।

अन्तर्राष्ट्रीय मामलों में जनता सरकार के वरिष्ठ सदस्यों की अनुभवहीनता भी भारत के लिये हानिप्रद सिद्ध हुई । तत्कालीन अमरीकी राष्ट्रपति कार्टर की भारत यात्रा १९७८ के दौरान मोरारजी देसाई के साथ उपजी गलतफहमी और जनता सरकार (चरण सिंह के नेतृत्व में) के दूसरे विदेश मंत्री श्याम नन्दन मिश्र की विदेश यात्राएँ इसका उदाहरण हैं । जहाँ एक ओर गृहमन्त्री चरण सिंह इसे गौरव का विषय समझते थे कि उन्हें दीन दुनिया की कोई खबर नहीं रहती वहीं उन्हें बिना किसी प्रमाण के अपने मन्त्रिमण्डल के एक सहयोगी को विदेशी गुप्तचर बताने में कोई सकोच नहीं हुआ । इसी

तरह प्रधानमन्त्री मोरारजी देसाई शान्ति प्रेमी थे परन्तु इतने नहीं कि सिद्धान्तों के लिये वह राष्ट्र के सामरिक हित बलि कर देते । परमाणु नीति के मामले में एकपक्षीय घोषणाएँ या पाकिस्तान में भुट्टो की कानूनी हत्या की भर्त्सना न करना उनकी निरपेक्षता ही प्रकट करते हैं³¹ ।

अनेक बार जनता सरकार की विदेश नीति का अध्ययन - विश्लेषण करते वक्त परिवर्तन एवं निरन्तरता की बात कही जाती है । यह कहना अधिक सटीक होगा कि ढाई वर्ष का यह समय एक तरह का व्यवधान काल था । यह एक ऐसा अन्तराल था जिसमें सुचिन्तित विदेश नीति के दर्शन नहीं होते³² । अन्तर्राष्ट्रीय घटनाक्रम के प्रति अपनी इच्छानुसार व्यक्ति विशेष की प्रत्यावर्तित क्रियाएँ ही देखने को मिलती रहीं ।

श्रीमती इन्दिरा की वापसी और विदेश नीति १९८० के आम चुनाव में श्रीमती इन्दिरा गांधी की अत्यन्त नाटकीय ढंग से अभूतपूर्व विजय हुई । परन्तु जहाँ से व्यवधान पड़ा था, वहीं से छूटा काम आगे बढ़ाने का प्रश्न नहीं उठता था । जनता सरकार के कार्यकाल में श्रीमती इन्दिरा गांधी को अपने अनेक मित्रों को परखने का अवसर मिला³³ । इसके अतिरिक्त अपनी वापसी के बाद उनके मन में निश्चय ही इस बात का अहसास गहरा हुआ कि नियति ने उन्हें कुछ ऐतिहासिक उपलब्धियों के लिये चुना है । इस दूसरे कार्यकाल

के विषय में यह कहा जा सकता है कि एक साथ मोहभग के बाद श्रीमती इन्दिरा गांधी की विदेश नीति में अति यथार्थवादी और आदर्शवादी महत्वाकांक्षाओं का सम्मिश्रण देखने को मिलता है । सयोगवश ही सही , मार्च १९८३ में गुटनिरपेक्ष आन्दोलन का नेतृत्व ग्रहण करने के साथ श्रीमती इन्दिरा गांधी अन्तर्राष्ट्रीय नेताओं की पहली वरिष्ठ श्रेणी में आ गयी । भारत की अन्तर्राष्ट्रीय प्रतिष्ठा और राजनयिक प्रभाव में उनके जीवन पर्यन्त कोई क्षय नहीं हुआ ³⁴।

पाद टिप्पणिया

- 1 Times of India 24 5 1991 (Editorial)
- 2 Appadorai, A Domestic Roots of India's Foreign Policy Page-76
- 3 Arnold Wolfer's International Encyclopaedia of the Social Sciences Page 124
- 4 Appadorai, A Domestic Roots of India's Foreign Policy Page 94
- 5 An article by Kamalkant Panda, Motilal Nehru College
- 6 James N. Rosenau(ed.) International Politics and Foreign Policy: A Reader in Research and Theory (New York, 1969)p 17
- 7 Hans J. Morgenthau Dilemmas of Politics (Chicago 1958)
- 8 Gopal Krishna (One party dominance) Development and trends Page 127
- 9 Quoted in Servepalli Gopal 'J.L. Nehru: A Biography' Page 69
- 10 Braine B. Will India Stay in the Common Wealth? Page 99
- 11 Chipman W. India's Foreign Policy Page-54
- 12 Suffimal Dutt With Nehru in the Foreign Policy Page 116
- 13 Arnold Wolfer's International Encyclopedia of the Social Sciences Page-201
- 14 Durgadas India and the world Page -176
- 15 Durgadas India and the world Page 104
- 16 Dutt, V P India's Foreign Policy Page 97
- 17 सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय भारत सरकार द्वारा प्रकाशितसंदर्भ 'ग्रंथ इण्डिया १९८७' से
- 18 Times of India 24 8 1991 (Editorial)
- 19 Arnold Wolfer's International Encyclopedia of the Social Sciences Page-236
- 20 Appadorai, A Domestic Roots of India's Foreign Policy Page-197
- 21 Burke S.M. Mainsprings of Indian and Pakistan Foreign Policies Page 198
- 22 Arnold Wolfer's International Encyclopedia of the Social Sciences Page 287
- 23 Appadorai, A Domestic Roots of India's Foreign Policy Page-207
- 24 Burke S.M. Mainsprings of Indian and Pakistan Foreign Policies Page 234
- 25 Arora, S.K. American Foreign Policy Towards India Page-97
- 26 Berkes, R.N. and Bedi, M.S. The Diplomacy of India Indian Foreign Policy in the United Nations Page 232

- 27 Braine B Will India Stay in the Common Wealth? Page-164
- 28 Burke S M Mainsprings of Indian and Pakistan Foreign Policies Page 94
- 29 Rajni Kothari 'The Congress System in India From Party System and
Election Studies Page 77
- 30 Statesman 4 1 1978
- 31 Indian Express Editorial 7 July 1979
- 32 Chipman W India s Foreign Policy Page 116
- 33 Dainik Hindustan 13 12 1980
- 34 Dutt V P India s Foreign Policy Page 201

અધ્યાય - ૨

द्वितीय अध्याय मे हम राजीव गाधी के काल मे भारतीय राजनीतिज्ञो द्वारा समय-समय पर अन्तर्राष्ट्रीय मंचो पर किये गये निर्णयो उनके क्रियान्वनो तथा अदा की गई भूमिका का विवेचन करेगे ।

इन्दिरा गाधी की दुखद हत्या के कारण विश्व शान्ति निरस्त्रीकरण और विकास का अग्रणी समर्थक हमारे बीच से चला गया परन्तु जितने आसान और सुव्यवस्थित ढंग से राजीव गाधी को प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया और उसके बाद जिस तरीके से स्वतन्त्र निष्पक्ष और शांतिपूर्ण ढंग से चुनाव हुए तथा राजीव गाधी की अध्यक्षता मे नई सरकार ने पदभार सम्भाला उससे सम्पूर्ण विश्व को यह स्पष्ट प्रमाण प्राप्त हो गया कि भारतीय लोकतान्त्रिक प्रणाली कितनी परिपक्व तथा मजबूत हो चुकी है¹ ।

श्री गाधी ने एक शान्ति दूत की हैसियत से देश की सीमाओं से बाहर जाकर अपनी हर मजिल और हर पड़ाव पर जो कुछ किया अपने जो प्रभाव छोडे उनकी समीक्षा से पहले, आइये हम उनके उन सकल्यो और सद्भावो की झाकी से परिचित हो ले जो उनकी विश्व यात्रा मे उनकी झोली के सबल रहे। यानी उनके विचार और इरादे ।

श्री गाँधी ने २० अप्रैल १९८८ को लोकसभा मे भारत की विदेश नीति के सन्दर्भ मे अपने विचार प्रकट करते हुए कहा था -
“पिछले दो-तीन वर्षो से, विशेषकर अन्तर्राष्ट्रीय सम्बन्धो मे विश्व मे

बड़ी तेजी से बदलाव हो रहे हैं। नये दृष्टिकोण विकसित हो रहे हैं सोच के नये ढंग निकल रहे हैं। इन सबसे संचार के सभी देशों के सामने नई चुनौतियाँ खड़ी हो जायेगी, खासतौर से भारत सरीखे देशों के सामने जो अन्तर्राष्ट्रीय मामलों में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। इस तरह के हालात में कोई भी अपने अतीत में ही डूबा नहीं रह सकता। हमें लचीला रूख अपनाना ही होगा साथ ही हमें अपने उन आधारभूत सिद्धान्तों और नैतिक अवधारणाओं पर भी अटल रहना होगा जिन पर हमारी विदेश नीति टिकी हुई है²।”

श्री गाँधी ने भारत के शान्ति प्रयासों को विश्व के अन्य देशों द्वारा मिलने वाले समर्थन को रेखांकित करते हुए उन्होंने कहा -

“जब हमने अपनी विदेश नीति को नैतिकता के साथ जोड़ा तो उस समय हमें अव्यावहारिक माना गया लेकिन आज ऐसा नहीं है, अब विश्व अहिंसा आणविक हथियारों से मुक्ति और निरस्त्रीकरण के महत्व को समझने लगा है³।”

हमारे ‘बसुधैव कुटुम्बकम्’ के सनातन सिद्धान्त को विश्व में प्राप्त हो रही आम सहमति पर हर्ष व्यक्त करते हुए श्री राजीव गांधी ने कहा था- “आज विश्व यह स्वीकार करने लगा है कि तब तक हमारा सही और पूर्ण विकास नहीं हो सकता, जब तक सच्चाई महाशक्तियों के हितों और प्रभावों के बोझ तले दबी रहेगी। मानव जाति एक है। ‘बसुधैव कुटुम्बकम्’ के हमारे सिद्धान्त पर पूर्ण विश्व में आम सहमति होती जा रही है। जो हमारे शान्तिपूर्ण सह-

अस्तित्व के सिद्धान्त के प्रति शकालु थे आज वही राष्ट्र भय दिखाने की नीति छोड़कर शान्तिपूर्ण सह-अस्तित्व की बात कर रहे हैं। पण्डित जवाहर लाल नेहरू जी ने हमारी विदेश नीति को मजबूत आधारशिला पर खड़ा किया था। आज विश्व भी हमारी ही विचारधारा में शामिल होता जा रहा है⁴।”

परमाणु शस्त्र विहीन विश्व के लिए दिल्ली घोषणा श्री गाँधी ने विश्व को परमाणु शस्त्र विहीन करने की अपील करने वाली दिल्ली घोषणा की चर्चा करते हुए कहा था - “इसका एक सशक्त प्रमाण सामने ही है जब अभी हाल ही में, नवम्बर १९८६ में नई दिल्ली घोषण-पत्र में अहिंसा और आणविक निरस्त्रीकरण के सिद्धान्तों के प्रति निष्ठा दुहराई गई। आणविक शस्त्रों के विकास पर रोक लगाने की बात से ही हमारी नीतियों के प्रति उनका झुकाव साफ झलकता है⁵।”

इस सफलता के मूल में उपस्थित पाँच महाद्वीप, छ राष्ट्र की पहल की याद दिलाते हुए श्री गाँधी ने कहा था -

मई १९८४ में इन्दिरा जी की छत्रछाया में छ राष्ट्रों द्वारा पहल की गयी। ऐसा उस समय किया गया, जब महाशक्तियों के बीच सम्बन्ध नाममात्र के थे तब किसी ने भी नहीं सोचा था कि तनाव इस प्रकार दूर हो जायेगा। लेकिन उन्होंने जो प्रयास किये विश्व में उचित वातावरण बनाने और निरस्त्रीकरण की दिशा में रत, उन सभी देशों की अनवरत कोशिशों के फलस्वरूप आई एन एफ सन्धि पर

हस्ताक्षर हुए। उन्ही के शब्दों में पहली बार आणविक हथियारों का विघटन हुआ। हम देख रहे हैं कि पहली बार एक सही अन्तर्राष्ट्रीय लोकतांत्रिक व्यवस्था विकसित हो रही है और दो महाशक्तियों की विभाजन रेखा अब लुप्त होती जा रही है⁶।

श्री गाँधी ने आशाजनक वातावरण की चर्चा के बावजूद कुछ नये सभावित खतरों के प्रति चेतावनी भी दी -

“यही समय है जब हमें एक ऐसे विश्व के निर्माण की दिशा में मुड़ना होगा जहाँ आणविक हथियार न हों, निस्स्त्रीकरण हो चुका हो और हमें ऐसे सभी नये खतरों से अपना बचाव करना होगा जो हमें दुबारा हथियारों की होड़ में घसीट ले सकते हैं। आणविक हथियारों से भी परे, हमें यह भी देखना होगा कि कहीं कोई ऐसा साधन तो नहीं बन रहा जिससे सम्पूर्ण मानव जाति का विनाश हो सकता है। हम इस बात के प्रति भी सचेत रहे कि हथियारों की होड़ के साथ कहीं कोई और नई दिशाएँ तो नहीं जुड़ रही हैं⁷।”

श्री गाँधी ने एक भयकरतम आसन्न खतरे के प्रति आगाह करते हुए कहा था- “हमें यह भी देखना होगा कि कहीं उच्च स्तर के वे पारम्परिक हथियार तो विकसित नहीं हो रहे, जिन्हें अपने पाँच महाद्वीपीय प्रयास में सर्जिकल हथियारों की सज़ा दी है। इस विधा का प्रयोग बड़े प्रभावशाली ढंग से, देशों के नेतृत्व को बिना कोई बड़ा नुकसान किये, समाप्त करने के लिए किया जाता है, ताकि घोर अव्यवस्था फैल जाय⁸।”

श्री गाँधी ने अन्तर्राष्ट्रीय सहयोग की दिशा में नही व्यवस्था के महत्व की आवश्यकता पर जोर देते हुए कहा - “अब समय आ गया है कि हमें सोचना पड़ेगा कि हम किस तरह इन बातों पर नियंत्रण पाकर सही रास्ता अपना सकें। अन्तर्राष्ट्रीय सहयोग के एक नये ढाँचे की आवश्यकता है। एक ऐसी वास्तविक प्रभावशाली एवं पुनर्गठित संयुक्त राष्ट्र संघ व्यवस्था की आवश्यकता है जिसमें अन्तर्राष्ट्रीय लोकतंत्र और सार्वभौमिक समानता को मान्यता प्राप्त हो। एक ऐसे अन्तर्राष्ट्रीय सहयोग की आवश्यकता है जो यह मानकर चले कि सम्पूर्ण मानव जाति एक परिवार के समान है, जहाँ सबके हित आपस में इतने जुड़े हुए हों कि एक हिस्से में हो रही वृद्धि एवं विकास दूसरे हिस्से में स्थिरता लाये। एक ऐसी विश्व व्यवस्था की जरूरत है, जो गाँधी जी और नेहरू जी की अन्तर्दृष्टि एवं मूल्यों पर आधारित हो^१ ।”

जवाहर लाल नेहरू और इन्दिरा गांधी द्वारा अपनायी गयी विदेश नीति के सिद्धान्तों और मूल दृष्टिकोणों के प्रति अपनी वचनबद्धता को दोहराते हुए राजीव गाँधी ने कहा था - “शान्ति के लिए कार्य करने में हमारा सदैव विश्वास रहा है। हमारी नीति आपसी आदान-प्रदान तथा परस्पर लाभ के आधार पर सभी देशों के साथ मित्रता बनाये रखने की है। न्याय समानता तथा आपसी सहयोग पर आधारित नई आर्थिक व्यवस्था और गुटनिरपेक्षता के प्रति हमारी बचनबद्धता अडिग है। इसका तात्पर्य है कि- शान्ति तथा विकास के

दो देशों के प्रति घोर निष्ठा। हम राष्ट्रों की स्वतंत्रता की रक्षा करने और एक दूसरे के मामलों में दखलान्दाजी न करने और अहस्तक्षेप के सिद्धान्तों में विश्वास करते हैं¹⁰ । ”

श्री राजीव गांधी की विदेश नीति विषयक विचारों का और खुलासा ससद में उनके द्वारा दिये गये वक्तव्य से हो जाता है -

“भारत की विदेश नीति पिछले ३७ वर्षों से कसौटी पर कसी और जाची जा चुकी है। इन ३७ वर्षों के दौरान न केवल भारत अपितु समूचे विश्व भर में यह माना गया है कि हमारी विदेश नीति अत्यन्त सशक्त और सार्थक है। भारत में जब सत्ता परिवर्तन हुआ था उस समय भी उन लोगों के लिए हमारी विदेश नीति में परिवर्तन कर पाना संभव नहीं हो पाया था। इसका कारण यह था कि हमारी विदेश नीति देश की जरूरतों के अनुरूप तैयार की गई थी । ”

किसी देश की विदेश नीति की सफलता या विफलता इस बात पर निर्भर करती है कि उस देश का विश्व स्तर के संगठनों में कितना सम्मान है और संसार के अन्य देशों में उसका कितना मान है। आज किसी देश को इसमें सन्देह नहीं हो सकता कि भारत विदेश नीति में न केवल भारत को नेतृत्व प्रदान किया है अपितु १०० से अधिक गुटनिरपेक्ष राष्ट्रों का पथप्रदर्शन भी किया है।

हमारी विदेश नीति का एक महत्वपूर्ण आधार स्तम्भ विश्व शान्ति है। शान्ति का मार्ग गांधी जी के अहिंसा से प्रशस्त होता है जो कि एक व्यापक अर्थात् विश्व स्तरीय अवधारणा है। कांग्रेस

गांधीवादी नीति का अनुगमन करती रही है और आज का भारत भी इसी का अनुपालन कर रहा है। इस प्रक्रिया में सहायता पहुंचाने के लिए हमने जो कदम उठाये हैं दिल्ली में होने वाला छ राष्ट्रों का सम्मेलन उनमें से एक कदम था। दिल्ली घोषणा इसी सम्मेलन की देन थी। जिसको ससार भर में व्यापक रूप से स्वीकार किया गया था। परमाणु हथियारों वाले देशों के लोग भी इस घोषणा पत्र से प्रभावित हुए। इसने बड़े बड़े शक्तिशाली जनमत को बदला है और उसे प्रभावित किया है।

गत दो या तीन वर्षों के दौरान विश्व में विशेषकर अन्तर्राष्ट्रीय सम्बन्धों में बड़ी तेजी से परिवर्तन हुआ है। नये दृष्टिकोणों का विकास हो रहा है और नये-नये विचार उभरकर सामने आ रहे हैं तथा इसके परिणामस्वरूप विश्व के सभी देशों के लिए चुनौतियाँ पैदा होना स्वाभाविक है। विशेषकर भारत जैसे देश के लिए, जो अन्तर्राष्ट्रीय मामलों में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। ऐसी स्थिति में, किसी को भी अतीत के दलदल में नहीं फंसा रहना चाहिए अपितु लचीला मार्ग अपनाना चाहिए। किन्तु इसके साथ-साथ हमें अपने उन मूल सिद्धान्तों को नहीं छोड़ना चाहिए, जिनपर हमारी विदेश नीति आधारित है¹¹।

राजीव गांधी की विदेश नीति के बारे में श्री के. आर. नारायण के विचार महत्वपूर्ण हैं। राजीव गांधी के ३ जनवरी १९८५ को, भारत के प्रधानमन्त्री के रूप में कार्यभार ग्रहण करने के तुरंत

पश्चात उन्होंने कहा था- “देश की बागडोर नई पीढ़ी के हाथ में आ गई है । साथ प्रतिशत मतदाता चालीस वर्ष से कम आयु के हैं । उन्हें इस बात की भी जानकारी थी कि विश्व में नयापन आ गया है यह भी कि इसमें बुनियादी परिवर्तन आ गया है और यह तेजी से बदलता जा रहा है । किन्तु शीघ्र ही उन्हें इस बात का पता चल गया कि इन महत्वपूर्ण परिवर्तन में से अधिकांश अनिवार्यतः भारत की विदेश नीति के नियामक पंडित जवाहर लाल नेहरू के दृष्टिकोण के अनुरूप थे जिन्होंने इसकी कल्पना की थी तथा इसे मूर्तरूप देने को प्रयास किया था ।” इसलिये उन्होंने आगे कहा था- “उन्हीं सिद्धान्तों को पुनः उपयोग में लाना आवश्यक है । इसलिये नये सिरे से विचार करने की आवश्यकता है । इस प्रकार राजीव गांधी की विदेश नीति परिवर्तन के साथ निरंतरता का अथवा निरंतरता में मौलिकता का एक अच्छा उदाहरण प्रस्तुत करता है । उन्होंने नये दृष्टिकोण से भाषा में नवीनता के साथ तथा गतिशीलता की भावना के साथ जवाहर लाल नेहरू के मूल दृष्टिकोण तथा नीतियों का अनुसरण किया तथा विश्व में उभर रहे शीत युद्ध रहित एक नये विश्व का निर्माण करने के लिये जागरूक रहकर प्रयास किया, एक नये विश्व का सपना देखा और उसके लिये कार्य किया, किन्तु इसे वे प्राप्त नहीं कर सके या वास्तविक रूप में परिणित नहीं कर सके¹² ।”

राजीव गांधी को अपने पूर्ववर्ती प्रधान मंत्रियों की तरह पता था कि भारत का आर्थिक दृष्टि से निर्माण तथा इसकी रक्षा वैज्ञानिक और प्रौद्योगिकीय क्षमताओं का इस विशाल और जटिल देश की राजनीतिक और मनोवैज्ञानिक एकता के आधार पर विकास विश्व मंच पर किसी सार्थक भूमिका को निभाने के लिये एक अपरिहार्य शर्त है। इसलिये वे देश को आर्थिक रूप से निर्भर बनाने तथा इसे २१वीं सदी में ले जाने के बास्तेनिरन्तर बात करते थे। परन्तु उन्हें ज्ञात था जैसा कि उन्होंने अपने प्रथम भाषण में १२ नवम्बर १९८४ को कहा था- “राष्ट्र निर्माण की सबसे पहली पूर्वापेक्षा शांति है पड़ोसी देशों के साथ शांति तथा विश्व में शांति। अपने सक्षिप्त परन्तु बेहतरीन राजनैतिक जीवन में उनके लिए शांति एक मुख्य मुद्दा था जिसे उन्होंने उत्साह और उद्देश्यपूर्ण कार्यवाही करके स्थापित करने की कोशिश की थी।”

प्रधान मंत्री के तौर पर उनका पहला अन्तराष्ट्रीय सम्मेलन नई दिल्ली में छ राष्ट्रों के पांच महाद्वीपों का शिखर सम्मेलन था जिसे उनकी माता इंदिरा गांधी द्वारा शुरू किया गया था। राजीव ने कहा था कि यह सम्मेलन इतिहास के निराशपूर्ण मोड़ पर हो रहा है। इस दिल्ली शिखर सम्मेलन में एक घोषणा जारी की गयी थी। इस घोषणा में परमाणु शस्त्रों के उत्पादन और विकास पर रोक लगाने का अनुरोध किया गया था जो कि परमाणु शस्त्रों को पूर्णतया समाप्त करने के उद्देश्य को पूरा करने की तरफ पहला

एशिया महाद्वीप में ब्रिटिश उपनिवेशवाद की समाप्ति के साथ एक नये सघर्ष की शुरुआत हुई जिसके परिणामस्वरूप इस क्षेत्र से शान्ति शब्द का लोप ही हो गया यह सघर्ष है दो पड़ोसी देशों का सघर्ष जिसे भारत पाक सघर्ष के नाम से जाना जाता है । भारत विभाजन के समय की घृणा और अविश्वास ने दोनों ही देशों को आज तक युद्ध की तैयारी में लगाये रखा । प्रारम्भ से ही दोनों देशों की सेनाएँ एक दूसरे के आमने सामने न केवल तैनात रही अपितु तीन बड़े युद्ध हुए और एक छोटी सी चिनगारी से किसी भी दिन चौथा युद्ध शुरू हो जाये तो आश्चर्य नहीं । पाकिस्तान की दुराग्रहपूर्ण विदेश नीति पर प्रकाश डालते हुए श्री राजीव गांधी ने कहा था-
“पाकिस्तान के विदेश नीति का आधार भारत विरोध रहा है । पाकिस्तान का निर्माण मुस्लिम लीग की हिन्दुओं के प्रति घृणा की नीति का फल है इसलिए पाकिस्तान के शासकों के लिए यह आवश्यक हो गया कि वे भारत विरोध की नीति अपनाएँ क्योंकि यदि वे ऐसा नहीं करते रहे तो उसके जन्म का आधार नष्ट हो जाता है । कश्मीर का प्रश्न इस नीति की प्रमुख अभिव्यक्ति है कश्मीर को प्राप्त करने के लिए कभी अमेरिका और ब्रिटेन का पिछलग्गू बने रहने की नीति तो कभी चीन की चापलूसी यही संकेत देती है कि पाकिस्तान का भारत विरोध हमेशा बना रहेगा । ”

जनवरी १९८८ में स्टाकहोम में जब छ राष्ट्रों की पुन बैठक हुई थी तो महाशक्तियों को सामरिक महत्व के अपने हथियारों में १९८८ के पहले छ माह के दौरान ५० प्रतिशत की कटौती करने का सुझाव दिया गया था तथा संयुक्त राष्ट्र व्यवस्था के अर्न्तगत एक समेकित बहुउद्देशीय जाच व्यवस्था करने का भी सुझाव दिया गया था । शिखर सम्मेलन ने परम्परागत हथियारों में भी भारी कटौती करने का सुझाव दिया था यह महत्वपूर्ण बात है कि बाद में महाशक्तियों के बीच किये गये निरस्त्रीकरण समझौते राजीव गांधी तथा उनके अन्य पाच सहयोगी देशों द्वारा छ राष्ट्रों के शिखर सम्मेलन में रखे गये प्रस्तावों के आधार पर ही किये गये। इस बारे में नवम्बर १९८८ के शुरू में राजीव गांधी और मिखाइल गोर्बाचोव द्वारा जारी की गयी 'दिल्ली घोषणा' याद करने योग्य है जिसके माध्यम से निरस्त्रीकरण प्रयासों को एक नये सैद्धान्तिक एवं व्यावहारिक आयाम दिये गये। इसके माध्यम से राजीव के अनुसार भारतीय संसद परमाणु शस्त्र मुक्त और शांतिप्रिय विश्व की स्थापना की दिशा में आम कल्पना को साकार करने के कार्य में सम्मिलित हो गयी । गांधी जी के शांति प्रिय विश्व सिद्धान्त को पहली बार एक महत्वपूर्ण अन्तर्राष्ट्रीय दस्तावेज में स्थान मिला। राजीव ने दावा किया था कि गांधी जी और लेनिन के आदर्श दिल्ली घोषणा में समाहित हुए हैं और विश्व समुदाय द्वारा इसकी आम स्वीकृति हेतु उन्होंने इसकी सन्तुति की।

राजीव गांधी के निरस्त्रीकरण के प्रयास उस वक्त उच्चतम सीमा पर पहुच गए जब उन्होंने सयुक्त राष्ट्र सघ के विशेष सत्र मे परमाणु शस्त्रो को २० वर्षो के अदर पूरी तरह से समाप्त करने सबधी निरस्त्रीकरण कार्यकारी योजना प्रस्तुत की थी। यह अभी भी शायद कुछ सशोधनो के साथ भारत की परमाणु शस्त्र निरस्त्रीकरण नीति का मुख्य अवलम्ब है और शायद इस विषय पर अब तक की प्रस्तुत सबसे अधिक विस्तृत और वास्तविक योजना है। उन्होंने कहा कि हमारा प्रस्ताव है कि प्रथम चरण मे १९९५ मे समाप्त होने वाली परमाणु अस्त्र वाले राष्ट्रो को सन २०१० तक सभी परमाणु शस्त्रो को कम करने और सभी ऐसे राष्ट्रो जिनके पास परमाणु अस्त्र नहीं है परमाणु अस्त्रो की देहरी पार न करने देने हेतु किए गए वायदो को कानूनी स्वरूप देगा, इस सूत्र से विश्व परमाणु शस्त्र निरस्त्रीकरण की आवश्यकता तथा आज भारत द्वारा अनुभव की जा रही निरस्त्रीकरण की कुछ समस्याओ की कमी पूरी हो जाती है।

राजीव गांधी ने सयुक्त राष्ट्र सघ मे भारत की स्थिति स्पष्ट करते हुए कहा था कि, हम इस तर्क को स्वीकार नहीं कर सकते है कि कुछ राष्ट्रो को मानव जाति के अस्तित्व पर प्रश्न चिन्ह लगाते हुए अपने सुरक्षोपाय करने का अधिकार है न ही ये स्वीकार्य है कि जिनके पास परमाणु शस्त्र है वे सभी नियत्रणो से परे है जबकि वे राष्ट्र जिनके पास परमाणु शस्त्र नहीं है, उनकी इस बात के लिए जाच की जाती है कि वे इन शस्त्रो का उत्पादन न करे।

शांति और निरस्त्रीकरण भारत द्वारा स्वतंत्रता के बाद से ही अपनाई गई गुट निरपेक्ष नीति के केन्द्रीय उद्देश्यों में से एक था। शस्त्र युद्ध के बाद विश्व में नई नीति की प्रासंगिकता को राजीव जी ने समझा था और नेहरू जी की गुटनिरपेक्षता और शांतिपूर्ण सह-अस्तित्व के सन्दर्भ में उन्होंने उस नीति के पालन और उसमें नई वास्तविकताओं के आधार पर परिवर्तित और परिवर्तनशील विश्व के अनुरूप रचनात्मक संशोधन किए। हारारे में और उसके बाद बेलग्रेड में गुट निरपेक्ष आन्दोलन को इस बात की आवश्यकता महसूस हुई कि सुस्थापित नीति के मूल उद्देश्यों का अनुसरण किया जाय और साथ ही नए विश्व की नई वास्तविकताओं का दृढ़तापूर्वक सामना किया जाए। हारारे और बेलग्रेड दोनों में ही राजीव ने वहाँ हुई चर्चाओं में प्रमुख रूप से अपना योगदान दिया। बेलग्रेड में हुए सम्मेलन में राजीव ने उसके परम्परागत उद्देश्यों को ऐसा नया रूप दिया कि सतत परिवर्तनशील मानवजाति के भविष्य की समस्याओं के अनुरूप हो जाये। विश्व स्तर पर हो रही गतिविधियों के सन्दर्भ में एक नैतिक शक्ति के रूप में उन्होंने तटस्थता की भूमिका पर बल दिया जिसका सीधा प्रहार नामीबिया की आजादी पर पड़ने वाला था और जिससे उपनिवेशवाद एवं नस्लवाद के रूप में रंगभेद के समाप्त होने की संभावना थी और साथ ही उन्होंने गुट-निरपेक्षता को शासन करने और प्रभुत्व की खोज की। उस नीति की प्रतिशक्ति के रूप में प्रस्तुत किया जो अभी तक अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में व्याप्त थी। 'पृथ्वी

सरक्षण कोष' का विशिष्ट प्रस्ताव देकर उन्होने पर्यावरणीय समस्याओ पर विशेष बल देने का प्रस्ताव दिया और इस प्रकार उन्होने तटस्थता के सन्दर्भ में एक नई सकल्पना दी जिसका पृथ्वी और मानव जाति के भविष्य पर महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ेगा ।

राजीव गांधी ने रंगभेद की नीति के विरुद्ध जो संघर्ष किया उसका उल्लेख अवश्य किया जाना चाहिए। राष्ट्र मण्डल सम्मेलनों में उन्होने दक्षिण अफ्रीका के विरुद्ध लगे प्रतिबंधों को जारी रखने की वकालत की। मार्गरेट थैचर जैसे उग्र व्यक्तित्व के साथ बातचीत करते समय उन्होने जो वाक्चातुर्य और कूटनीतिक कौशल दिखाया उससे उनकी प्रतिष्ठा और अधिक बढ़ गयी। नसाऊ और लन्दन दोनों ही स्थानों पर हुए सम्मेलनों में लौह महिला मार्गरेट थैचर अलग-थलग पड़ गई। किन्तु उन्होने अपने आकर्षण और राजनीतिक दक्षता के द्वारा श्रीमती थैचर का सम्मान और सदभाव अक्षुण्ण बनाए रखा। उन्होने रंगभेद पर इस महत्वपूर्ण चरण में निर्णयात्मक भूमिका निभाई। रंगभेद, उपनिवेशवाद और जातिभेद के विरुद्ध संघर्ष में जिस अफ्रीका कोष का प्रस्ताव राजीव गांधी ने किया वह दूसरा महत्वपूर्ण प्रस्ताव था । नामीबिया के संबंध में राजीव गांधी की भूमिका इतनी महत्वपूर्ण थी कि नामीबिया सरकार ने अपने स्वतंत्रता समारोह में उन्हें उस समय विशेष अतिथि के रूप में आमंत्रित किया जबकि वे विपक्ष के नेता मात्र थे ।

राजीव गांधी की विदेश नीति विश्व के व्यापक कार्यकलापों के

बारे में पहले से ही नहीं बनायी गयी थी बल्कि पड़ोसी देशों की कठिन और दुरुह समस्याओं को लेकर भी बनायी गयी थी। दक्षिण एशिया में मूल सिद्धान्तों और राष्ट्रीय हितों के साथ समझौता किये बिना ही उन्होंने मेल-मिलाप मैत्री और सहयोग के लिए प्रयास किया। उन्होंने दक्षेस संगठन को नयी प्रेरण दी। उन्होंने जिया उल हक और बेनजीर भूटो दोनों के साथ न केवल सरकारी किन्तु व्यक्तिगत सम्बन्ध भी स्थापित किये। एक दूसरे के परमाणु प्रतिष्ठानों पर आक्रमण न करने सबंधी पाकिस्तान के साथ किया गया समझौता विश्वास पैदा करने वाला प्रमुख उपाय था और परमाणु प्रश्न के निपटारे की संभावनाये दोनों पड़ोसियों के बीच सबंध बिगड़ने का कारण इसमें अन्तर्ग्रस्त था। राजीव गांधी की चीन यात्रा कुल मिलाकर एक ऐतिहासिक कदम था जिससे एशिया के दो महान देशों के बीच लम्बे समय से बिगड़े सबंधों में सुधार आया। उसी ऐतिहासिक यात्रा के आधार पर आज चीन के साथ भावी सबंध बनाये जा रहे हैं। श्रीलंका के सबंध में दुर्भाग्यपूर्ण कार्यों के होते हुए भी, श्रीलंका में तमिलों को कोई बड़ी स्वायत्ता मिल सकने में शका है और श्री राजीव गांधी जयवर्धने समझौते में उसकी एकता और अखण्डता में अधिक विश्वसनीय गारन्टी है।

महाशक्तियों के साथ व्यवहार में राजीव ने अन्तर्राष्ट्रीय सबंधों के प्रति गहरी समझबूझ दिखायी। वह समझते थे कि शीत युद्ध के समाप्त होने से भारत को अमेरिका और पूर्व सोवियत संघ के साथ

निकट और सार्थक सम्बन्ध स्थापित करने के अवसर प्राप्त होंगे। उन्होंने भारत के साहस तथा विश्वास और इसके हितों को ध्यान में रखकर मित्रता की पेशकश की। इस सदर्भ में बात उल्लेखनीय है कि भारत के युवा प्रधानमंत्री ने सहज रूप से और समानता के स्तर पर राष्ट्रपति श्री रोनाल्ड रीगन और महासचिव श्री मिखाइल गोर्बाचोव से वार्ता की। उन्होंने इन दोनों महाशक्तियों के साथ गहरे और व्यापक सम्बन्ध स्थापित करने के लिए अमेरिका और भूतपूर्व सोवियत संघ के साथ अनेक समझौतों पर हस्ताक्षर किए। साथ ही उन्होंने जापान, एशियाई देशों तथा यूरोपीय आर्थिक समुदाय के साथ निकट सम्बन्धों के महत्त्व की अवहेलना नहीं की। उन्होंने भारत की परम्पराएँ - जो उन्हें विरासत में मिली थी, और अन्तर्राष्ट्रीय स्थिति की वास्तविकता - जैसा कि उन्होंने समझी था के अनुसार विश्व के प्रति अपना दृष्टिकोण बनाया।

विश्व के प्रति अपने दृष्टिकोण में उन्होंने भारत पर मुख्य रूप से ध्यान दिया। भारत की राजनैतिक एकता को तथा इसकी आर्थिक प्रौद्योगिकीय और सैन्य दृष्टि से मजबूत कराने की आवश्यकता महसूस की जैसे कि जवाहर लाल नेहरू और इंदिरा गांधी की विज्ञान और प्रौद्योगिकी पर केवल भारत के विकास के साधन रूप में ही प्रमुख रूप से बल नहीं दिया बल्कि अपनी विदेश नीति और राजनयिकता के एक महत्वपूर्ण पहलू के रूप में इसका प्रचार भी किया।

उन्होंने अपनी विदेश नीति और कूटनीति में महाशक्तियों के साथ तथा दक्षिण के विकासशील देशों में वैज्ञानिक और प्रौद्योगिकीय सहयोग के उद्देश्यों को प्राथमिकता के रूप में अपनाया। इस प्रकार “भारत के प्रधान मंत्री के संक्षिप्त और उज्ज्वल काल के दौरान राजीव गांधी द्वारा प्रतिपादित विदेश नीति में आदर्श और आराध्य सिद्धान्तों तथा तीक्ष्ण व्यवहार्य विषयवस्तु और प्रौद्योगिकीय तर्कों का सही पुट था ¹³।”

अब हम लेते हैं गुटनिरपेक्ष आंदोलन, निरस्त्रीकरण तथा आर्थिक मामलों में राजीव गांधी की भूमिका को अनेक राष्ट्रों की उपनिवेशवाद से मुक्ति होने पर भारत की गुटनिरपेक्ष नीति को बड़े पैमाने पर स्वीकृति मिली। पहला गुटनिरपेक्ष सम्मेलन १९६१ में बेलग्राद में हुआ जिसमें २५ देशों ने भाग लिया था। बेलग्राद शांति घोषणा की काफी अधिक प्रतिक्रिया हुई। इस सम्मेलन में गुटनिरपेक्ष देशों के बीच समय समय पर होने वाले विचारों के आदान-प्रदान और विचार-विमर्श की उपादेयता को सिद्ध कर दिया। इसके बाद अन्य और देश भी गुटनिरपेक्ष आंदोलन में सम्मिलित हुए हैं, और इसकी वर्तमान संख्या १०० तक पहुँच गयी है। इसके अतिरिक्त कुछ दर्जन देश पर्यवेक्षक और अतिथि के रूप में भी सम्बद्ध हैं। सदस्य संख्या में वृद्धि होने के बावजूद इस आंदोलन ने शांति, निरस्त्रीकरण, विकास और स्वतंत्रता के पक्ष में अपना मूल स्वर बनाए रखा है। कुछ मामूली मतभेदों के बावजूद गुटनिरपेक्ष राष्ट्रों के बीच एकता और आंदोलन

को व्यापक समर्थन और स्वीकृति प्राप्त हुई है। गुटनिरपेक्ष आंदोलन में भारत की भूमिका का अनुमान इसी बात से लगाया जा सकता है कि मार्च १९८३ में गुटनिरपेक्ष शिखर सम्मेलन का आयोजन नई दिल्ली में किया गया और भारत को इसका अध्यक्ष चुना गया। सितम्बर १९८६ में जिम्बाब्वे को गुटनिरपेक्ष आंदोलन की अध्यक्षता सौंप दिए जाने के बाद भी आंदोलन में भारत की भूमिका और गतिविधियों ने अपने लिए ऊंचा स्थान रखा है। भारत ने गुटनिरपेक्ष आंदोलन के भीतर के प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों पर जनमत बनाए रखने के अपने प्रयास जारी रखे और इसने अन्य गुट निरपेक्ष देशों के निकट सहयोग से कार्य किया। इसने कोनट्राडोरा प्रक्रिया के लिए आंदोलन और ग्वाटेमाला संधि में उल्लिखित क्षेत्रीय शांति की पहल के प्रति अपनी एकजुटता और समर्थन व्यक्त किया¹⁴। भारत ने आंदोलन द्वारा विश्व के आर्थिक मुद्दों, विशेषकर गुटनिरपेक्ष और अन्य विकासशील देशों से संबंधित मुद्दों के संबंध में सक्रिय भूमिका निभाने पर जोर दिया है ताकि बहुआयामी आर्थिक सहयोग के संबंध में उनकी स्थिति सुदृढ़ हो सके।

जहां तक निरस्त्रीकरण का संबंध है भारत ने समय-समय पर परमाणु हथियारों का कड़ा विरोध किया और पूर्ण निरस्त्रीकरण का समर्थन किया है। भारत परमाणु ऊर्जा के शांतिपूर्ण उपयोग के लिए भी पूरी तरह प्रतिबद्ध है लेकिन वह उन प्रयासों या उपायों का विरोध करता है जो परमाणु ऊर्जा के शांतिपूर्ण उपयोग के बारे में

भारत के कार्यक्रम के आड़े आते हैं। भारत ने विशेष रूप से अमरीका और सोवियत संघ के बीच परमाणु हथियारों में कमी करने के लिए जेनेवा वार्ता शुरू करने का स्वागत किया क्योंकि निरस्त्रीकरण के लिए कारगर कदम उठाने की प्रमुख जिम्मेदारी परमाणु शक्तिओं की है। प्रधानमंत्री राजीव गांधी ने न्यूयार्क में संयुक्त राष्ट्र की स्थापना की ४०वीं वर्षगांठ के अवसर पर अधिवेशन को सम्बोधित करते हुए कहा था कि परमाणु सैनिकवाद के पागलपन से दुनिया को मुक्त करने की आवश्यकता है। मनुष्य को अपनी सृजन क्षमता का प्रयोग विनाश के लिए नहीं बल्कि सबर्धन के लिए करना चाहिए। उन्होंने जनवरी १९८५ में छह राष्ट्रों के शिखर सम्मेलन में जारी दिल्ली घोषणा के उद्देश्यों को फिर दोहराया। इस शिखर सम्मेलन में अर्जेंटीना ग्रीस भारत मैक्सिको, स्वीडन और तजानिया के नेताओं ने सभी तरह के परमाणु परीक्षणों पर १२ महीने की रोक लगाने का अनुरोध किया था तथा इस बारे में जाँच प्रक्रिया के लिए सुविधाओं का प्रस्ताव किया था। छह राष्ट्रों के इन नेताओं की बैठक मैक्सिको में छह अगस्त १९८६ को फिर हुई। सभी तरह के परमाणु परीक्षणों पर रोक लगाने^{की} आवश्यकता पर जोर देते हुए इन नेताओं ने परमाणु हथियार सम्पन्न महाशक्तियों से अनुरोध किया कि वे परमाणु परीक्षणों पर रोक लगाने और इसके लिए समुचित परमाणु प्रबंध के लिए ठोस प्रस्ताव रखें¹⁵।

सितम्बर १९८६ में हारारे में गुटनिरपेक्ष देशों के राष्ट्राध्यक्षों का

आठवाँ शिखर सम्मेलन हुआ जिसमें निरस्त्रीकरण के लिए गुटनिरपेक्ष आंदोलन की वचनबद्धता को पुनः दुहराया गया और दोनों महाशक्तियों से अनुरोध किया गया कि वे परमाणु युद्ध को छिड़ने से रोकने के लिए तुरन्त कारगर कदम उठाए। भारत ने तीन मुख्य बहुपक्षीय निरस्त्रीकरण मंचों अर्थात्- निरस्त्रीकरण सम्मेलन, संयुक्त राष्ट्र निरस्त्रीकरण आयोग और संयुक्त राष्ट्र जनरल असेम्बली की पहली समिति में प्रमुख भूमिका निभाई। ऐसा भारत की इस अडिग आस्था के अनुरूप किया गया कि इस आणविक युग में निरस्त्रीकरण केवल शांति के लिए ही नहीं बल्कि मानव जाति के अस्तित्व के लिए भी आवश्यक है¹⁶। भारत ने बहुपक्षीय दबाव की वैधता पर यह दोहराते हुए जोर दिया कि परमाणविक निवारण के माध्यम एकपक्षीय सुरक्षा की खोज के स्थान पर परमाणु निरस्त्रीकरण के जरिए विश्व सुरक्षा की खोज की जाए।

परमाणविक और सामान्य निरस्त्रीकरण के जेहाद में भारत ने छह-राष्ट्रीय पहल के पांच अन्य देशों के साथ २२ जनवरी १९८८ को सोवियत संघ और अमेरिका के बीच आई एन एफ संधि का स्वागत किया और इसे ऐतिहासिक कदम बताया¹⁷। उनकी स्टाकहोम घोषणा में वार्ता पुनः आरम्भ होने का स्वागत किया गया और इनकी जांच तथा इस क्षेत्र में समझौतों की मांग की गई।

नौ जून १९८८ को निरस्त्रीकरण पर संयुक्त राष्ट्र महासभा के तीसरे विशेष सत्र को सम्बोधित करते हुए तत्कालीन प्रधानमंत्री

राजीव गांधी ने सयुक्त राष्ट्र को एक कार्य योजना आरम्भ करने के लिए कहा था जिससे सभी मौजूदा परमाणु शक्तियों वाले देशों द्वारा २०१० ई तक विश्व के सभी परमाणविक हथियार समाप्त कर दिए जाए¹⁸। उन्होंने प्रस्ताव किया कि यह कार्य योजना तीन चरणों में परिचालित की जाए जिसके परिणामस्वरूप न केवल परमाणविक खतरे समाप्त हो सकेंगे बल्कि एक नई सयुक्त राष्ट्र गहन विश्व सुरक्षा प्रणाली स्थापित होगी जिससे एक नया न्यायपूर्ण समाज और समरूपी विश्व नियम सुनिश्चित किया जा सकेगा¹⁹। प्रधानमंत्री के विस्तृत प्रस्ताव में शताब्दी के अंत तक एक एकल बहुपक्षी सत्यापन प्रणाली की स्थापना की मांग की गई ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि विश्व में कहीं भी नए परमाणविक हथियार नहीं बनाए जा रहे हैं। उन्होंने राष्ट्रपति रीगन के प्रस्तावित विशेष प्रतिरक्षा पहल का उल्लेख करते हुए यह घोषणा की- परमाणविक दौड़ को ऐसी कार्रवाई के सबंध में विलम्बन संधि के बिना समाप्त नहीं किया जा सकता अथवा रोका नहीं जा सकता।

अब हम लेते हैं आर्थिक मामले और राजीव गांधी द्वारा उनको निबटाने के प्रयासों को हाल के वर्षों में मामूली से विस्तार के साथ विश्व-अर्थव्यवस्था सकट के कगार पर है। उत्पादकता में कमी इसी से स्पष्ट है कि उत्पादन की दर १९८५ में ३ प्रतिशत से घटकर २८ प्रतिशत रह गई। व्यापार १९८६ में चार प्रतिशत उत्पादकता पर ही चलता रहा, वस्तुओं के मूल्यों में और कमी आई,

विकासशील देशों के नए ऋण घट गए और ऋण अदायगी और भी कठिन हो गई। हाल के आकड़ों से पता चलता है कि विकासशील देशों का कुल ऋण १९८६ के अंत तक ११ ट्रिलियन अमरीकी डालर हो गया है।

विकासशील देशों को पूंजी उपलब्धता में जारी रूकावट के फलस्वरूप वित्तीय वर्ष १९८६ में लगभग कुल ३००० करोड़ अमरीकी डालर मूल्य के ससाधनों का दक्षिण से उत्तर को शुद्ध अंतरण हुआ। सरकारी विकास सहायता अंतर्राष्ट्रीय रूप से सहमत स्तर ०.७ प्रतिशत के आधे से भी कम रही। कई विकासशील देशों की प्रति व्यक्ति आय में कमी हुई और सामूहिक रूप से विकासशील देशों की सकल स्थानीय उत्पादन १९८५ में ४.२ प्रतिशत से घटकर १९८६ में ३.६ प्रतिशत हो गई। संरक्षणवाद निरन्तर बढ़ता ही रहा है। हालांकि सरकारों ने बार-बार घोषणाएं और बहुपक्षीय व्यापार वार्ताएं के नए दौर शुरू करने की सधिया की हैं। अमीर और गरीब देशों के बीच परस्पर निर्भरता को अब अधिक मान्यता मिल रही है और इसके बढ़ने के प्रमाण भी हैं। तथापि, विकसित देशों के बीच परस्पर विकास धीमा हुआ है।

नई दिल्ली और हरारे में हुए सातवें और आठवें गुटनिरपेक्ष शिखर सम्मेलनों में बहुपक्षीय सहयोग के माध्यम से उत्पादकता और विकास के प्रति एक ठोस और व्यावहारिक दृष्टिकोण और विकास के प्रति बहुपेक्षावाद से खिचाव रोकने का प्रस्ताव किया गया था।

साथ ही इनमें नए अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक सहयोग की प्राप्ति के लिए दीर्घकालीन सरचनात्मक सुधारों का भी प्रस्ताव किया गया। मुद्रा, वित्त ऋण व्यापार प्रौद्योगिकी तथा विकास की अंतर्राष्ट्रीय और अतर्सम्बन्धी प्रणालियों में सुधार आवश्यक है। प्रमुख औद्योगिक देशों की मैक्रो-एकानामिक नीतियों के विश्व अर्थव्यवस्था में माग में वृद्धि करने तथा उत्पादकता को बढ़ाने के उद्देश्य से सामंजस्य स्थापित करने और सहयोग करने की आवश्यकता है। अक्टूबर १९८७ के राष्ट्रमंडल शिखर सम्मेलन में विश्व व्यापार पर की गई घोषणा को अपनाया गया जिसमें यह उल्लेख किया गया कि नई बहुपक्षीय व्यापार वार्ताओं में विकासशील देशों पर विशेष रूप से विचार किया जाए।

भारत ने विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी की नई खोजों को अनुकूल बनाने और विकसित करने की दक्षिण की क्षमताएँ बढ़ाने में सुविधा प्रदान करने के उद्देश्य से नई दिल्ली में हुए गुटनिरपेक्ष एवं आगे होने वाले ग्रुप-७७ सम्मेलनों के माध्यम से पहल की है। भारत ने शांति को बढ़ावा देने एवं जीवन-स्तर बेहतर बनाने के लिए, विशेषकर विकासशील देशों के लिए इन वैज्ञानिक और प्रौद्योगिकीय विकास कार्यों के परिणामों का लाभ उठाने हेतु अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बटवारे की नई प्रक्रिया आरम्भ करने के लिए संयुक्त राष्ट्र में पहल की। विज्ञान और प्रौद्योगिकी के लिए संयुक्त राष्ट्र अंतर्राष्ट्रीय समिति के अगस्त १९८७ में हुए नार्वे सत्र में भारतीय पहल पर आम सहमति

द्वारा एक प्रस्ताव पारित किया गया जिसमें अनुसंधान, सूचना एवं प्रशिक्षण प्रौद्योगिकी, पूर्व सूचना और नए तथा अविषयगत विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी नेस्ट के आकलन के आपसी विकास और सहयोग के लिए कार्यक्रमों परियोजनाओं की मांग की गई थी ²⁰।

सामूहिक आत्म निर्भरता और आर्थिक स्वतंत्रता की प्राप्ति और विश्व अर्थव्यवस्था तथा एक नए अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक सहयोग की स्थापना के प्रयासों के एक महत्वपूर्ण भाग के रूप में अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक संबंधों में विकासशील देशों की भूमिका बढ़ाने के लिए उनमें आपसी सहयोग गुटनिरपेक्ष आंदोलन एवं ग्रुप-७७ का एक प्रमुख उद्देश्य बन गया है। विकास कार्यों के लिए दक्षिण के एक स्वतंत्र आयोग की स्थापना से महत्वपूर्ण आर्थिक विषयों पर लाभदायी निवेश प्राप्त हो सकता है। इस आयोग ने दो से पांच अक्टूबर १९८७ तक अपनी पहली बैठक में औपचारिक रूप से अपना कार्याारम्भ कर दिया है ²¹ ।

विकासशील देशों के आपसी सहयोग से संबंधित सभी मुद्दों और प्रतिविधियों की समीक्षा करने के लिए जून १९८७ में गुटनिरपेक्ष मंत्रियों की बैठक प्यागयोग में हुई। बैठक के परिणामों के महत्वपूर्ण पहलुओं में प्रमुख नई दिल्ली में गुटनिरपेक्ष विज्ञान और प्रौद्योगिकी केन्द्र आरम्भ किए जाने का निर्णय और भारत द्वारा नई एवं उच्च वैज्ञानिक तथा प्रौद्योगिकी के लिए की गई पहल का सत्यापन और उसका स्वागत।

- ४ प्रत्येक राज्य एक दूसरे के साथ समानता का व्यवहार करे तथा पारस्परिक हित में सहयोग प्रदान करे अर्थात् न कोई देश बड़ा है और न ही छोटा ।
- ५ सभी राष्ट्र शान्तिपूर्ण सह-अस्तित्व के सिद्धान्त में विश्वास करें तथा इसी सिद्धान्त के आधार पर एक-दूसरे के साथ शान्तिपूर्वक रहे और अपनी पृथक सत्ता एवं स्वतन्त्रता बनाये रखे ।

कुछ विद्वानों का मानना है कि पंचशील योजना नेहरू जी की आदर्शवादी रुमानियत का उदाहरण भर थी और कुछ नहीं । परन्तु वास्तविकता की अनदेखी नहीं की जानी चाहिए कि पंचशील की राजनयिक रणनीति भारतीय राष्ट्रीय हितों की यथार्थवादी कसौटी पर खरी उतरती है । भारत का विभाजन आजादी के साथ हो गया और पाकिस्तानी रजाकारों ने कश्मीर को हथियाने के लालच में भारतीय सीमा का अतिक्रमण किया । यह अघोषित युद्ध लगभग दो वर्ष तक चलता रहा । १९४७ में सारा भारतीय भू-भाग एक साथ स्वतंत्र नहीं हुआ । रजवाड़ों की स्थिति सदिग्ध थी और गोवा, दमन दीव चन्द्रनगर व पाण्डिचेरी जैसे इलाके अंग्रेजों से इतर दूसरी औपनिवेशिक शक्तियों के आधिपत्य में थे।

इसके शीघ्र बाद एक और महत्वपूर्ण परिवर्तन हुआ । १९४९ में चीन में साम्यवादियों ने सरकार का गठन किया और १९५० में तिब्बत को मुक्त कराने का प्रयास शुरू किया । इसके साथ ही ब्रिटिश साम्राज्यवादी शासन काल में सीमांकित किया गया सारा

हिमालयी भू-भाग सीमान्त विवादास्पद बन गया¹⁹। ऐसी परिस्थित में यदि नेहरू जी ने नवोदित राष्ट्रों की सम्प्रभुता की रक्षा भौगोलिक सीमाओं के सम्मान और आन्तरिक मामलों में हस्तक्षेप से बचने के पक्ष में अन्तर्राष्ट्रीय जनमत तैयार करने की चेष्टा की तो इसे आदर्शवादी कतई नहीं समझा जा सकता। समस्याओं के शान्तिपूर्ण समाधान की प्रस्तावना के बिना सह-अस्तित्व की बात सोची भी नहीं जा सकती थी। पंचशील योजना में यह बात अन्तर्निहित थी की इसका अभिगम सिर्फ प्रतिरक्षात्मक नहीं बल्कि रचनात्मक भी है। पंचशील समझौते में साझीदार पक्षों के लिए लाभप्रद उभयपक्षीय सहकार के लक्ष्य तय करना नेहरू जी की दूरदर्शिता थी।

पंचशील के बारे में विदेशी और भारतीय विद्वानों के मत स्पष्टतः दो ध्रुवों के बीच झूलते हैं। कुछ विद्वानों का मानना है कि पंचशील की बात उठाना नेहरू जी की दुर्बलताजनित विवशता थी। सैनिक शक्ति और आर्थिक ससाधनों के अभाव में वह और कुछ कर भी नहीं सकते थे। जयन्तनुज वन्द्योपाध्याय जैसे कुछेक विद्वान अपवाद हैं, जो मानते हैं कि नेहरू जी ने जान बूझकर यह जोखिमभरा कदम उठाया, ताकि अन्तर्राष्ट्रीय राजनीति को नई दिशा दी जा सके²⁰। दूसरी ओर लॉर्न काविक और नेविल मैक्सवेल सरीखे लेखक हैं जिनकी समझ में पंचशील एक धूर्ततापूर्ण पाखण्ड था, जिसका एकमात्र उद्देश्य भारत को सैनिक दृष्टि से शक्तिशाली बनाने के लिए कुछ मोहलत जुटाना था। वैसे इन दोनों बातों में

कोई बुनियादी अन्तरविरोध नहीं है । आर्थिक और सैनिक उपकरणों के अभाव में यदि बाडुग सम्मेलन १९५५ के अवसर पर नेहरू जी ने भारत को अदभूत प्रतिष्ठा दिला दी थी तो उसके आधार में पंचशील की सफलता ही थी ।

बाडुग सम्मेलन के बारे में मजेदार बात यह है कि अफ्रो-एशियाई देशों के इस जमघट का आयोजन भारत के सुझाव पर नहीं किया गया था । कोलम्बो परियोजना में शामिल पश्चिमी खेमे के पक्षधर राष्ट्रों ने इसकी पहल की परन्तु नेहरू जी और कृष्णा मेनन ने समझदारी दिखाते हुए इसे नवोदित राष्ट्रों की स्वाधीनता और गुट-निरपेक्षता का प्रतीक बना दिया²¹ । आज कई दशक बाद बाडुग सम्मेलन की सीमाओं और असफलताओं का छिद्रान्वेषण सहज है । परन्तु नेहरू जी ने शीत युद्ध के सकटों से जूझते हुए जिस तरह सैनिक गठबन्धनों को निरस्त करने का प्रयास किया वह प्रशंसनीय था । ऐसा सोचना ठीक नहीं कि नेहरू जी ने सिर्फ शब्दाडम्बर या वक्तृता से तीसरी दुनिया का नेतृत्व हथियाने के लिए किया । बाडुग सम्मेलन के आयोजन के पहले कोरिया में अपनी निष्पक्ष मध्यस्थता और हिन्द - चीन में युद्ध विराम के लिए सक्रियता से भारत ने अपनी पात्रता प्रमाणित कर दी थी । नासिर सुकार्णो आदि के साथ व्यक्तिगत स्तर पर सार्थक सवाद का सूत्रपात भी बाडुग सम्मेलन से ही सम्भव हुआ²²।

बाडुग सम्मेलन का एक और दृष्टि से अन्तर्राष्ट्रीय महत्व है । इस सम्मेलन में हिस्सेदारी के बाद ही चीन की साम्यवादी सरकार का मानवीय पक्ष अन्य देशों के सामने आया और उसको वांछित स्वीकृति मिल सकी । इस सम्मेलन में अपनाये गये प्रस्तावों का अध्ययन करने पर यह बात स्पष्ट होती है कि पचशील समझौते की ही तरह इस बार भी नेहरू जी ने आदर्श और यथार्थ का सन्तुलन बैठाने की कोशिश की थी²³ । उनका प्रमुख प्रयत्न यही कि अधिकाधिक अफ्रो-एशियाई देशों को ब्रिटिश ससदीय प्रणाली से प्रेरित सभा-सम्मेलनीय राजनय में शामिल किया जा सके ताकि भविष्य में उठने वाले विवादों के शान्तिपूर्ण समाधान की सम्भावना बची रहे । बाडुग सम्मेलन की उपलब्धि सही थी कि दोनों महाशक्तियों को यह बात स्पष्टतः समझायी जा सकी कि अफ्रो-एशियाई देशों का उनसे कोई जन्मजात बैर सैद्धान्तिक विचारधारा या नस्ल के आधार पर नहीं है । पाकिस्तान और सीलोन (अब श्रीलंका) के साथ भारतीय प्रतिनिधियों की नोक-झोंक भले ही होती रही, परन्तु बाडुग में ही उस अफ्रो-एशियाई गुट का गठन हुआ जिसने संयुक्त राष्ट्र सभ में इनकी हस्ती को महत्वपूर्ण बनाया । बाडुग भावना के बिना गुट-निरपेक्ष आन्दोलन का बेगवान बनना कठिन होता²⁴ ।

परन्तु इससे यह समझना उचित नहीं कि नेहरू जी की विदेश-नीति तर्क सगत और दूरदर्शी होने के कारण सभी प्रकार

की दुर्बलताओं से मुक्त थी। नेहरू जी सदैव इस बात को अनदेखा करते रहे कि अधिकतर अफ्रो-एशियाई नेताओं का स्वभाव और सस्कार उससे भिन्न है और यह जरूरी नहीं कि वे हमेशा बदली परिस्थिति में अन्तर्राष्ट्रीय राज्य विषयक उनकी सभी स्थापनाओं को लाभप्रद उपयोगी उपदेश के रूप में ग्रहण करते रहे। बाडुग सम्मेलन के सस्मरण लिखते वक्त नासिर और चारु एन लाई दोनों ने यह स्वीकार किया है कि नेहरू जी हमेशा इस तरह आचरण करते थे जैसे वह उनके भाई या पथ प्रदर्शक हों। दोनों नेताओं को यह बात अपमानजनक लगती रही थी ²⁵। इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता कि नेहरू जी की विदेश नीति और राजनय व्यक्ति-केन्द्रित थे और व्यक्तिगत समीकरण बदलने पर विदेश नीति और राजनय बहुत सीमित प्रभाव वाले रह जाते थे। बेलग्रेड सम्मेलन में सुकार्णो और नेहरू जी के बीच टकराव के बाद पुरानी स्थिति कभी लौटाई नहीं जा सकी।

नेहरू जी की एक और कमजोरी थी। वह अपनी पसन्द-नापसन्द को छिपा कर नहीं रख सकते थे। उनकी आस्था समाजवादी जनतंत्र में थी। वह राजशाही सामन्तवाद तथा सैनिक शासन को प्रति क्रियावादी समझते थे। नेपाल तथा पाकिस्तान के साथ उनका व्यवहार इसी कारण कभी सहज नहीं हो सका। श्रीलंका के प्रधानमंत्री जोन कोटनेवाला ने यह एक बार सटीक टिप्पणी की थी कि भारत जैसा बड़ा राष्ट्र गुट-निरपेक्षता की

विलासिता भोग सकती है परन्तु छोटे राष्ट्रों के सामने यह सुविधापूर्ण मार्ग उपलब्ध नहीं । आचारण में व्यावहारिक होने के बावजूद घोषणाओं के स्तर पर सैद्धान्तिक शुद्धि का दुराग्रह नेहरू जी की विश्वसनीयता और भारतीय विदेश नीति का प्रभाव कम करता रहा⁵ । समस्याओं के शान्तिपूर्ण निपटारे की बात करते वक्त नेहरू जी कश्मीर में जनमत संग्रह के अपने आश्वासन के निरन्तर टालते रहने के लिये बाध्य हुये । वह गोवा की मुक्ति के लिये बल-प्रयोग के बाद कथनी और करनी में दोहरे मानदण्डों के लिये भी बाध्य हुये । इसी तरह भारत चीन सम्बन्धों की गलतफहमी एक बड़ी सीमा तक इस बात से पैदा हुई कि जहाँ नेहरू जी एक ओर स्वयं को स्वतंत्र भारत के प्रगतिशील प्रधानमंत्री के रूप में पेश करते थे, वही देश की भौगोलिक सीमा के बारे में औपनिवेशिक उत्तराधिकार को अक्षत रखने के लिये वह बचनबद्ध थे । नेहरूकालीन भारतीय विदेश-नीति की सबसे बड़ी विशेषता यही पुरानी और नयी परम्परा तथा अन्तर्द्वन्द्व थी । महाशक्तियों और पड़ोसियों के साथ १९४७ से १९६४ तक भारत के राजनयिक सम्बन्धों के उतार चढ़ाव में इसका तनाव स्पष्ट प्रतिबिम्बित होता है ।

अब हम आते हैं शास्त्रीकालीन विदेश नीति पर । १९६४ में नेहरू जी की मृत्यु के बाद लाल बहादुर शास्त्री ने देश की बागडोर संभाली । शास्त्री जी का व्यक्तित्व अपने पूर्ववर्ती प्रधानमंत्री नेहरू जी से इतना भिन्न था कि कई लोगों के मन में यह शक पैदा होना

स्वाभाविक था कि विदेश-नीति नियोजन और निर्धारण के मामले में शास्त्री जी असमर्थ रहेगे। न तो उनकी शिक्षा-दीक्षा विदेश में हुई थी और न ही प्रधानमंत्री बनने के पहले उन्होंने अन्तर्राष्ट्रीय मामलों में कोई विशेष रुचि दर्शायी थी। इसी कारण जब शास्त्रीकालीन भारतीय विदेश नीति का विश्लेषण किया जाता है तो नेहरू युगीन विदेश नीति के साथ उसका फर्क दर्शाने का लोभ सवरण कम ही लोग कर पाते हैं²⁶ । शास्त्रीकालीन विदेश नीति के सदर्भ में अक्सर यह कहा जाता है कि उन्होंने निरर्थक आदर्शवाद को सार्थक यथार्थवाद से विस्थापित किया और शान्ति प्रेमी होने के बावजूद राष्ट्र-हित के संरक्षण-संवर्धन के लिए सैनिक उपकरणों की उपयोगिता को स्वीकार किया । उनके कार्य काल का विशेष अध्ययन करने वाले प्रोफेसर एल०पी० सिंह का मानना है कि भले ही उन्होंने भारतीय विदेश नीति के क्षितिज संकुचित किये किन्तु उन्हें कुल मिलाकर भौतिक सूझ से वंचित नहीं समझा जा सकता और न ही उनके योगदान को नगण्य माना जा सकता ।

शास्त्रीय युग की भारतीय विदेश नीति में दो प्रमुख स्मारक बिन्दु हैं -

- १ पाकिस्तान के साथ सैनिक मुठभेड़ के बाद ताश्कन्द समझौता, और
- २ श्रीलंका की प्रधानमंत्री श्रीमती सिरीमाओ भण्डारनायके के साथ परामर्श के बाद नागरिकता-विहीन प्रवासी तमिलों के बारे में शान्तिपूर्ण समाधान । जहाँ एक ओर कच्छ के रण में और उसके बाद पाकिस्तान के साथ युद्ध में शास्त्री जी ने यह स्पष्ट किया कि वह

शान्ति प्रिय ओर शान्तिपूर्ण सह-अस्तित्व के नाम पर भारतीय राष्ट्रीय हित की बलि देने को तैयार नहीं है वही श्रीलंका के साथ समझौते से उन्होंने अन्य छोटे पड़ोसी देशों को इस बारे में आश्वस्त भी किया कि भारत का कोई इरादा बल प्रयोग द्वारा उन पर हावी होने का नहीं था। मैत्रीपूर्ण सम्बन्धों की स्थापना के लिए वह रियायतें देने को प्रस्तुत थे। नेहरू जी की तरह अपनी अन्तर्राष्ट्रीय छवि या अहं को बरकरार रखने की कोई समस्या शास्त्री जी के सामने नहीं थी।

शास्त्री जी की विदेश नीति के बारे में दो-तीन विन्दु उल्लेखनीय हैं। एक तो उन्होंने प्रधानमंत्री सचिवालय का गठन कर अपने सलाहकारों की एक नई टोली जुटायी। इससे विदेश मंत्रालय के अवमूल्यन की प्रक्रिया चाहे-अनचाहे शुरू हुई। इसके अतिरिक्त परमाणु नीति के मामले में शास्त्री जी ने ऐसा निर्णय लिया कि सामरिक विकल्प को त्यागा न जा सके²⁷। ताशकन्द सम्मेलन में दौरा पड़ने से शास्त्री जी की मृत्यु हो गयी। गुट-निरपेक्ष आन्दोलन राष्ट्रमण्डलीय राजनय अफ्रो-एशियाई भाईचारे आदि के क्षेत्र में निजी छाप छोड़ने का कोई अवसर उसे नहीं मिला। यह भी स्मरणीय है कि १९६४-६६ में भारत भयंकर दुर्भिक्ष से ग्रस्त था और अपमानजनक ढंग से विदेशों से खाद्यान्नके आयात पर निर्भर था। ऐसी परिस्थिति में अन्तर्राष्ट्रीय रंगमंच पर भारत की भूमिका कतई प्रमुख नहीं हो सकती थी। इसे शास्त्रीजी की एक बड़ी उपलब्धि समझा जाना चाहिए कि १९६२ के घाव को भरने का काम उन्होंने

अपने छोटे से कार्यकाल में बखूबी किया ।

जहां तक इन्दिरागांधी कालीन विदेश नीति का सम्बन्ध है

जनवरी १९६६ में शास्त्रीजी के निधन के बाद इन्दिरा गांधी प्रधानमंत्री बनी । जिस तरह की भ्रान्तियां शास्त्रीजी के बारे में फैली हैं उसी तरह तर्कहीन अतिसरलीकरण इन्दिरा गांधी की विदेश नीति और राजनय के बारे में भी प्रचलित है। पत्रकारों और जीवनीकारों की कृपा से श्रीमती गांधी की छवि लौह महिला और रणचण्डी वाली प्रसिद्ध हुई है। लोगों के मन में आज भी या तो १९७१ के बंगलादेश मुक्ति अभियान की याद ताजा है या मई १९७४ में पोखरण में परमाणु विस्फोट और जून १९७५ में आपातकाल की घोषणा की । यदि चुन-चुनकर ऐसे उदाहरण पेश किये जायें तो श्रीमती गांधी को अति यथार्थवादी प्रमाणित करना कठिन नहीं होगा। इसी तरह के प्रयत्न श्रीमती गांधी के अन्तर्मुखी स्वभाव, उनके पारिवारिक एकाकीपन एवं मानसिक असुरक्षा के भाव को उनके अन्तराष्ट्रीय आचरण के साथ जोड़ने के लिए किये जाते हैं²⁸ । ऐसा नहीं कि यह विश्लेषण श्रीमती गांधी के आलोचक विशेषी ही करते रहे हैं, बल्कि श्रीमती गांधी के साथ सहानुभूति रखने वाले विद्वान भी इस भ्रान्ति के शिकार हुए हैं। उदाहरणार्थ इन्दिरा गाँधी की विदेश नीति का विस्तार से विश्लेषण प्रस्तुत करने वाली लेखिका सुरजीत मानसिंह की पुस्तक का शीर्षक ही 'India's Search for Power' अर्थात् 'भारत शक्ति के तलाश में' है। यदि अध्येता

सतर्कता न बरते तो इस निष्कर्ष तक अनायास पहुँचा जा सकता है कि श्रीमती गांधी ने ही सर्वप्रथम पारम्परिक शक्ति सतुलन के आधार पर राष्ट्र हित संपादन का कार्य किया। जैसा कि ऊपर कहा जा चुका है कि काश्मीर पाकिस्तान गोवा आदि के सन्दर्भ में नेहरू और शास्त्रीजी का आचरण भी आदर्शवादी नहीं समझा जा सकता है²⁹।

श्रीमती गांधी के सन्दर्भ में यह टिप्पणी अधिक सार्थक लगती है कि उनकी विदेश नीति का अमूर्त वैचारिक पक्ष कहीं अधिक मुखर था। तीसरी दुनिया का खाद्यान्न संकट हो या पर्यावरण के संरक्षण का प्रश्न श्रीमती गांधी का उद्बोधन-आह्वान सिर्फ भारतीय जनता के लिये ही नहीं बल्कि समग्र विश्व के लिए होता था। इसी तरह यह भी कहा जा सकता है कि पड़ोसी देशों और परमाणु नीति के सन्दर्भ में वह उसी दिशा में आगे बढ़ी, जिस तरफ कदम पहले ही उठाये चुके थे। श्रीमती गांधी को अपनी घोषणाओं-वक्तव्यों में क्रान्तिकारी, प्रगतिशील मुद्रा ग्रहण करना अच्छा लगता था, परन्तु व्यवहार में नेहरू जी की सुझायी गुट-निरपेक्ष नीति में किंचित मात्र परिवर्तन या संशोधन की जरूरत नहीं समझी।

श्रीमती गांधी की विदेश नीति का अध्ययन करते समय इस तथ्य की अनदेखी नहीं की जानी चाहिये कि उन्होंने कठिनतम चुनौतियों से जूझते हुए भारत को अन्तर्राष्ट्रीय राजनय का केन्द्र बिन्दु बनाये रखने में सफलता प्राप्त की। १९६६ से १९६९-७० तक कांग्रेस पार्टी में उनकी अपनी स्थिति निरापद नहीं थी और भारत

विकट आर्थिक समस्याओं से जूझ रहा था। रुपये का अवमूल्यन प्रिवीपर्स की समाप्ति बैंको का राष्ट्रीयकरण, कांग्रेस का विभाजन बिहार में अकाल का सामना आदि चुनौतियाँ उन्हें अपने कार्यकाल के पहले चरण में पूरी तरह व्यस्त रखे रहीं। बंगला देश प्रकरण में पराक्रमी प्रदर्शन और १९७१ के चुनाव में अभूतपूर्व सफलता के बाद थोड़े ही समय के लिये वैदेशिक मामलों में एकाग्रचित होने का अवसर मिला। १९७२ में शिमला समझौता सम्पन्न हुआ तो १९७३-७५ में जयप्रकाश नारायण के नेतृत्व में उनके राजनैतिक अस्तित्व की चुनौती देने वाला व्यापक जन-आन्दोलन शुरू हुआ। इसकी परिणति जून १९७५ में आपातकाल की घोषणा और अन्ततः मार्च १९७७ के ससदीय आम चुनाव में श्रीमती गांधी की हार में हुई।

जहाँ तक जनता सरकार की विदेश नीति का सम्बन्ध है इसकी रूपरेखा मार्च १९७७ में मोरारजी देसाई के नेतृत्व में जनता पार्टी के शासन की बागडोर सम्भालने से बनी। जिन परिस्थितियों में जनता सरकार का गठन हुआ, उसमें गांधी ही नहीं, बल्कि नेहरू वंश के प्रति रोष-आक्रोश का स्वर तेज था। आपात काल की तानाशाही की दुस्वप्न जैसी स्मृति जनता के मन में थी। जनता सरकार के नेता श्रीमती इन्दिरा गांधी की सभी नीतियों को बदलने के लिये व्यग्र थे। फिर भी नए विदेश मन्त्री अटल बिहारी वाजपेयी ने कार्यभार सम्भालने के बाद यह घोषणा की कि वह नेहरू की

विदेश नीति के अनुसार ही आचरण करेंगे । कहने को भले ही उन्होंने खालिस गुट निरपेक्षता की बात की परन्तु इसका प्रमुख अभिप्राय यह दर्शाना था कि इन्दिरा गांधी ही अपने पिता के मार्ग से विचलित हुई थी । पड़ोसी देशों के साथ सम्बन्धों के क्षेत्र में जरूरत से ज्यादा रियायती व नरम रुख अपनाना जनता सरकार के लिये शायद इसलिये जरूरी हुआ कि उसके विदेश मंत्री बाजपेयी की अब तक छवि आक्रामक हिन्दु राष्ट्रवादी वाली थी ³⁰ । जनता सरकार का गठन विभिन्न वैचारिक रुझानों वाले राजनीतिक दलों को मिलाकर हुआ था । इसी कारण किसी स्पष्ट अन्तर्राष्ट्रीय परिपेक्ष्य या सैद्धान्तिक संरोकार की अपेक्षा उनसे नहीं की जा सकती थी । यह स्वभाविक था कि नौकरशाही का महत्व विदेश नीति नियोजन के क्षेत्र में बढ़ा ।

अन्तर्राष्ट्रीय मामलों में जनता सरकार के वरिष्ठ सदस्यों की अनुभवहीनता भी भारत के लिये हानिप्रद सिद्ध हुई । तत्कालीन अमेरिकी राष्ट्रपति कार्टर की भारत यात्रा १९७८ के दौरान मोरारजी देसाई के साथ उपजी गलतफहमी और जनता सरकार (चरण सिंह के नेतृत्व में) के दूसरे विदेश मंत्री श्याम नन्दन मिश्र की विदेश यात्राएँ इसका उदाहरण हैं । जहाँ एक ओर गृहमन्त्री चरण सिंह इसे गौरव का विषय समझते थे कि उन्हें दीन दुनिया की कोई खबर नहीं रहती वही उन्हें बिना किसी प्रमाण के अपने मन्त्रिमण्डल के एक सहयोगी को विदेशी गुप्तचर बताने में कोई सकोच नहीं हुआ । इसी

तरह प्रधानमन्त्री मोरारजी देसाई शान्ति प्रेमी थे परन्तु इतने नहीं कि सिद्धान्तों के लिये वह राष्ट्र के सामरिक हित बलि कर देते। परमाणु नीति के मामले में एकपक्षीय घोषणाएँ या पाकिस्तान में भुट्टो की कानूनी हत्या की भर्त्सना न करना उनकी निरपेक्षता ही प्रकट करते हैं³¹।

अनेक बार जनता सरकार की विदेश नीति का अध्ययन - विश्लेषण करते वक्त परिवर्तन एवं निरन्तरता की बात कही जाती है। यह कहना अधिक सटीक होगा कि ढाई वर्ष का यह समय एक तरह का व्यवधान काल था। यह एक ऐसा अन्तराल था जिसमें सुचिन्तित विदेश नीति के दर्शन नहीं होते³²। अन्तर्राष्ट्रीय घटनाक्रम के प्रति अपनी इच्छानुसार व्यक्ति विशेष की प्रत्यावर्तित क्रियाएँ ही देखने को मिलती रही।

श्रीमती इन्दिरा की वापसी और विदेश नीति १९८० के आम चुनाव में श्रीमती इन्दिरा गांधी की अत्यन्त नाटकीय ढंग से अभूतपूर्व विजय हुई। परन्तु जहाँ से व्यवधान पड़ा था वही से छूटा काम आगे बढ़ाने का प्रश्न नहीं उठता था। जनता सरकार के कार्यकाल में श्रीमती इन्दिरा गांधी को अपने अनेक मित्रों को परखने का अवसर मिला³³। इसके अतिरिक्त अपनी वापसी के बाद उनके मन में निश्चय ही इस बात का अहसास गहरा हुआ कि नियति ने उन्हें कुछ ऐतिहासिक उपलब्धियों के लिये चुना है। इस दूसरे कार्यकाल

के विषय में यह कहा जा सकता है कि एक साथ मोहभग के बाद श्रीमती इन्दिरा गांधी की विदेश नीति में अति यथार्थवादी और आदर्शवादी महत्वाकांक्षाओं का सम्मिश्रण देखने को मिलता है । संयोगवश ही सही मार्च १९८३ में गुटनिरपेक्ष आन्दोलन का नेतृत्व ग्रहण करने के साथ श्रीमती इन्दिरा गांधी अन्तराष्ट्रीय नेताओं की पहली वरिष्ठ श्रेणी में आ गयी । भारत की अन्तराष्ट्रीय प्रतिष्ठा और राजनयिक प्रभाव में उनके जीवन पर्यन्त कोई क्षय नहीं हुआ ³⁴।

पाद टिप्पणिया

- 1 Times of India 24 5 1991 (Editorial)
- 2 Appadorai A Domestic Roots of India s Foreign Policy Page 76
- 3 Arnold Wolfer s International Encyclopaedia of the Social Sciences Page 124
- 4 Appadorai A Domestic Roots of India s Foreign Policy Page 94
- 5 An article by Kamalkant Panda Motilal Nehru College
- 6 James N Rosenau(ed) International Politics and Foreign Policy A Reader in Research and Theory (New York, 1969)p 17
- 7 Hans J Morgenthau Dilemmas of Politics (Chicago 1958)
- 8 Gopal Krishna (One party tominance) Development and trends Page 127
- 9 Quoted in Servepalli Gopal J L Nehru A Biography Page 69
- 10 Braine B Will India Stay in the Common Wealth? Page-99
- 11 Chipman W India s Foreign Policy Page 54
- 12 Suffimal Dutt With Nehru in the Foreign Policy Page 116
- 13 Arnold Wolfer s International Encyclopedia of the Social Sciences Page 201
- 14 Durgadas India and the world Page 176
- 15 Durgadas India and the world Page 104
- 16 Dutt V P India s Foreign Policy Page 97
- 17 सूचना एव प्रसारण मंत्रालय भारत सरकार द्वारा प्रकाशितसदर्म 'ग्रंथ इण्डिया १९८७ से
- 18 Times of India 24 8 1991 (Editorial)
- 19 Arnold Wolfer s International Encyclopedia of the Social Sciences Page 236
- 20 Appadorai, A Domestic Roots of India's Foreign Policy Page-197
- 21 Burke S M Mainsprings of Indian and Pakistan Foreign Policies Page 198
- 22 Arnold Wolfer's International Encyclopedia of the Social Sciences Page 287
- 23 Appadorai A Domestic Roots of India's Foreign Policy Page 207
- 24 Burke S M Mainsprings of Indian and Pakistan Foreign Policies Page 234
- 25 Arora, S K American Foreign Policy Towards India Page-97
- 26 Berkes, R N and Bedi, M S The Diplomacy of India Indian Foreign Policy in the United Nations Page 232

- 27 Braine B Will India Stay in the Common Wealth? Page 164
- 28 Burke S M Mainsprings of Indian and Pakistan Foreign Policies Page-94
- 29 Rajni Kothari The Congress System in India From Party System and
Election Studies Page-77
- 30 Statesman 4 1 1978
- 31 Indian Express Editorial 7 July 1979
- 32 Chipman W India s Foreign Policy Page 116
- 33 Dainik Hindustan 13 12 1980
- 34 Dutt V P India s Foreign Policy Page 201

અધ્યાય - ૨

द्वितीय अध्याय में हम राजीव गांधी के काल में भारतीय राजनीतिज्ञों द्वारा समय-समय पर अन्तर्राष्ट्रीय मंचों पर किये गये निर्णयों उनके क्रियान्वयनों तथा अदा की गई भूमिका का विवेचन करेंगे ।

इन्दिरा गांधी की दुःखद हत्या के कारण विश्व शान्ति निरस्त्रीकरण और विकास का अग्रणी समर्थक हमारे बीच से चला गया परन्तु जितने आसान और सुव्यवस्थित ढंग से राजीव गांधी को प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया और उसके बाद जिस तरीके से स्वतन्त्र निष्पक्ष और शांतिपूर्ण ढंग से चुनाव हुए तथा राजीव गांधी की अध्यक्षता में नई सरकार ने पदभार सम्भाला उससे सम्पूर्ण विश्व को यह स्पष्ट प्रमाण प्राप्त हो गया कि भारतीय लोकतान्त्रिक प्रणाली कितनी परिपक्व तथा मजबूत हो चुकी है¹ ।

श्री गांधी ने एक शान्ति दूत की हैसियत से देश की सीमाओं से बाहर जाकर अपनी हर मजिल और हर पड़ाव पर जो कुछ किया अपने जो प्रभाव छोड़े उनकी समीक्षा से पहले, आइये हम उनके उन सकल्यों और सदभावों की झांकी से परिचित हो लें जो उनकी विश्व यात्रा में उनकी झोली के सबल रहे। यानी उनके विचार और इरादे ।

श्री गाँधी ने २० अप्रैल १९८८ को लोकसभा में भारत की विदेश नीति के सन्दर्भ में अपने विचार प्रकट करते हुए कहा था - “पिछले दो-तीन वर्षों से, विशेषकर अन्तर्राष्ट्रीय सम्बन्धों में, विश्व में

बड़ी तेजी से बदलाव हो रहे हैं। नये दृष्टिकोण विकसित हो रहे हैं, सोच के नये ढंग निकल रहे हैं। इन सबसे संचार के सभी देशों के सामने नई चुनौतियाँ खड़ी हो जायेगी खासतौर से भारत सरीखे देशों के सामने जो अन्तर्राष्ट्रीय मामलों में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। इस तरह के हालात में कोई भी अपने अतीत में ही डूबा नहीं रह सकता। हमें लचीला रूख अपनाना ही होगा साथ ही हमें अपने उन आधारभूत सिद्धान्तों और नैतिक अवधारणाओं पर भी अटल रहना होगा जिन पर हमारी विदेश नीति टिकी हुई है²।”

श्री गाँधी ने भारत के शान्ति प्रयासों को विश्व के अन्य देशों द्वारा मिलने वाले समर्थन को रेखांकित करते हुए उन्होंने कहा -

“जब हमने अपनी विदेश नीति को नैतिकता के साथ जोड़ा तो उस समय हमें अव्यावहारिक माना गया, लेकिन आज ऐसा नहीं है अब विश्व अहिंसा आणविक हथियारों से मुक्ति और निरस्त्रीकरण के महत्व को समझने लगा है³।”

हमारे ‘बसुधैव कुटुम्बकम्’ के सनातन सिद्धान्त को विश्व में प्राप्त हो रही आम सहमति पर हर्ष व्यक्त करते हुए श्री राजीव गांधी ने कहा था- “आज विश्व यह स्वीकार करने लगा है कि तब तक हमारा सही और पूर्ण विकास नहीं हो सकता, जब तक सच्चाई महाशक्तियों के हितों और प्रभावों के बोझ तले दबी रहेगी। मानव जाति एक है। ‘बसुधैव कुटुम्बकम्’ के हमारे सिद्धान्त पर पूर्ण विश्व में आम सहमति होती जा रही है। जो हमारे शान्तिपूर्ण सह-

अस्तित्व के सिद्धान्त के प्रति शकालु थे आज वही राष्ट्र भय दिखाने की नीति छोड़कर शान्तिपूर्ण सह-अस्तित्व की बात कर रहे हैं। पण्डित जवाहर लाल नेहरू जी ने हमारी विदेश नीति को मजबूत आधारशिला पर खड़ा किया था। आज विश्व भी हमारी ही विचारधारा में शामिल होता जा रहा है⁴।”

परमाणु शस्त्र विहीन विश्व के लिए दिल्ली घोषणा श्री गाँधी ने विश्व को परमाणु शस्त्र विहीन करने की अपील करने वाली दिल्ली घोषणा की चर्चा करते हुए कहा था - “इसका एक सशक्त प्रमाण सामने ही है जब अभी हाल ही में, नवम्बर १९८६ में, नई दिल्ली घोषण-पत्र में अहिंसा और आणविक निरस्त्रीकरण के सिद्धान्तों के प्रति निष्ठा दुहराई गई। आणविक शस्त्रों के विकास पर रोक लगाने की बात से ही हमारी नीतियों के प्रति उनका झुकाव साफ झलकता है⁵।”

इस सफलता के मूल में उपस्थित पाँच महाद्वीप, छ राष्ट्र की पहल की याद दिलाते हुए श्री गाँधी ने कहा था -

मई १९८४ में इन्दिरा जी की छत्रछाया में छ राष्ट्रों द्वारा पहल की गयी। ऐसा उस समय किया गया, जब महाशक्तियों के बीच सम्बन्ध नाममात्र के थे तब किसी ने भी नहीं सोचा था कि तनाव इस प्रकार दूर हो जायेगा। लेकिन उन्होंने जो प्रयास किये विश्व में उचित वातावरण बनाने और निरस्त्रीकरण की दिशा में रत उन सभी देशों की अनवरत कोशिशों के फलस्वरूप आई एन एफ सन्धि पर

हस्ताक्षर हुए। उन्ही के शब्दों में पहली बार आणविक हथियारों का विघटन हुआ। हम देख रहे हैं कि पहली बार एक सही अन्तर्राष्ट्रीय लोकतांत्रिक व्यवस्था विकसित हो रही है और दो महाशक्तियों की विभाजन रेखा अब लुप्त होती जा रही है⁶।

श्री गाँधी ने आशाजनक वातावरण की चर्चा के बावजूद कुछ नये सम्भावित खतरों के प्रति चेतावनी भी दी -

“यही समय है जब हमें एक ऐसे विश्व के निर्माण की दिशा में मुड़ना होगा, जहाँ आणविक हथियार न हों, निरस्त्रीकरण हो चुका हो और हमें ऐसे सभी नये खतरों से अपना बचाव करना होगा जो हमें दुबारा हथियारों की होड़ में घसीट ले सकते हैं। आणविक हथियारों से भी परे हमें यह भी देखना होगा कि कहीं कोई ऐसा साधन तो नहीं पनप रहा, जिससे सम्पूर्ण मानव जाति का विनाश हो सकता है। हम इस बात के प्रति भी सचेत रहे कि हथियारों की होड़ के साथ कहीं कोई और नई दिशाएँ तो नहीं जुड़ रही हैं⁷।”

श्री गाँधी ने एक भयकरतम आसन्न खतरे के प्रति आगाह करते हुए कहा था- “हमें यह भी देखना होगा कि कहीं उच्च स्तर के वे पारम्परिक हथियार तो विकसित नहीं हो रहे जिन्हें अपने पाँच महाद्वीपीय प्रयास में सर्जिकल हथियारों की सज़ा दी है। इस विधा का प्रयोग बड़े प्रभावशाली ढंग से देशों के नेतृत्व को बिना कोई बड़ा नुकसान किये, समाप्त करने के लिए किया जाता है, ताकि घोर अव्यवस्था फैल जाय⁸।”

श्री गाँधी ने अन्तर्राष्ट्रीय सहयोग की दिशा में नही व्यवस्था के महत्व की आवश्यकता पर जोर देते हुए कहा - “अब समय आ गया है कि हमें सोचना पड़ेगा कि हम किस तरह इन बातों पर नियंत्रण पाकर सही रास्ता अपना सकें। अन्तर्राष्ट्रीय सहयोग के एक नये ढाँचे की आवश्यकता है। एक ऐसी वास्तविक प्रभावशाली एवं पुनर्गठित संयुक्त राष्ट्र संघ व्यवस्था की आवश्यकता है जिसमें अन्तर्राष्ट्रीय लोकतंत्र और सार्वभौमिक समानता को मान्यता प्राप्त हो। एक ऐसे अन्तर्राष्ट्रीय सहयोग की आवश्यकता है, जो यह मानकर चले कि सम्पूर्ण मानव जाति एक परिवार के समान है जहाँ सबके हित आपस में इतने जुड़े हुए हों कि एक हिस्से में हो रही वृद्धि एवं विकास दूसरे हिस्से में स्थिरता लाये। एक ऐसी विश्व व्यवस्था की जरूरत है, जो गाँधी जी और नेहरू जी की अन्तर्दृष्टि एवं मूल्यों पर आधारित हो^१ । ”

जवाहर लाल नेहरू और इन्दिरा गांधी द्वारा अपनायी गयी विदेश नीति के सिद्धान्तों और मूल दृष्टिकोणों के प्रति अपनी वचनबद्धता को दोहराते हुए राजीव गाँधी ने कहा था - “शान्ति के लिए कार्य करने में हमारा सदैव विश्वास रहा है। हमारी नीति आपसी आदान-प्रदान तथा परस्पर लाभ के आधार पर सभी देशों के साथ मित्रता बनाये रखने की है। न्याय, समानता तथा आपसी सहयोग पर आधारित नई आर्थिक व्यवस्था और गुटनिरपेक्षता के प्रति हमारी वचनबद्धता अडिग है। इसका तात्पर्य है कि- शान्ति तथा विकास के

दो देशों के प्रति घोर निष्ठा। हम राष्ट्रों की स्वतंत्रता की रक्षा करने और एक दूसरे के मामलों में दखलान्दाजी न करने और अहस्तक्षेप के सिद्धान्तों में विश्वास करते हैं¹⁰ । ”

श्री राजीव गांधी की विदेश नीति विषयक विचारों का और खुलासा संसद में उनके द्वारा दिये गये वक्तव्य से हो जाता है -

“भारत की विदेश नीति पिछले ३७ वर्षों से कसौटी पर कसी और जाची जा चुकी है। इन ३७ वर्षों के दौरान न केवल भारत अपितु समूचे विश्व भर में यह माना गया है कि हमारी विदेश नीति अत्यन्त सशक्त और सार्थक है। भारत में जब सत्ता परिवर्तन हुआ था उस समय भी उन लोगों के लिए हमारी विदेश नीति में परिवर्तन कर पाना संभव नहीं हो पाया था। इसका कारण यह था कि हमारी विदेश नीति देश की जरूरतों के अनुरूप तैयार की गई थी । ”

किसी देश की विदेश नीति की सफलता या विफलता इस बात पर निर्भर करती है कि उस देश का विश्व स्तर के संगठनों में कितना सम्मान है और संसार के अन्य देशों में उसका कितना मान है। आज किसी देश को इसमें सन्देह नहीं हो सकता कि भारत विदेश नीति में न केवल भारत को नेतृत्व प्रदान किया है अपितु १०० से अधिक गुटनिरपेक्ष राष्ट्रों का पथप्रदर्शन भी किया है।

हमारी विदेश नीति का एक महत्वपूर्ण आधार स्तम्भ विश्व शान्ति है। शान्ति का मार्ग गांधी जी के अहिंसा से प्रशस्त होता है जो कि एक व्यापक अर्थात् विश्व स्तरीय अवधारणा है। कांग्रेस

गांधीवादी नीति का अनुगमन करती रही है और आज का भारत भी इसी का अनुपालन कर रहा है। इस प्रक्रिया में सहायता पहुंचाने के लिए हमने जो कदम उठाये हैं दिल्ली में होने वाला छ राष्ट्रों का सम्मेलन उनमें से एक कदम था। दिल्ली घोषणा इसी सम्मेलन की देन थी। जिसको ससार भर में व्यापक रूप से स्वीकार किया गया था। परमाणु हथियारों वाले देशों के लोग भी इस घोषणा पत्र से प्रभावित हुए। इसने बड़े बड़े शक्तिशाली जनमत को बदला है और उसे प्रभावित किया है।

गत दो या तीन वर्षों के दौरान विश्व में विशेषकर अन्तर्राष्ट्रीय सम्बन्धों में बड़ी तेजी से परिवर्तन हुआ है। नये दृष्टिकोणों का विकास हो रहा है और नये-नये विचार उभरकर सामने आ रहे हैं तथा इसके परिणामस्वरूप विश्व के सभी देशों के लिए चुनौतियाँ पैदा होना स्वाभाविक है। विशेषकर भारत जैसे देश के लिए, जो अन्तर्राष्ट्रीय मामलों में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। ऐसी स्थिति में किसी को भी अतीत के दलदल में नहीं फंसा रहना चाहिए अपितु लचीला मार्ग अपनाना चाहिए। किन्तु इसके साथ-साथ हमें अपने उन मूल सिद्धान्तों को नहीं छोड़ना चाहिए, जिनपर हमारी विदेश नीति आधारित है¹¹।

राजीव गांधी की विदेश नीति के बारे में श्री के आर नारायण के विचार महत्वपूर्ण हैं। राजीव गांधी के ३ जनवरी १९८५ को, भारत के प्रधानमंत्री के रूप में कार्यभार ग्रहण करने के तुरंत

पश्चात उन्होंने कहा था- “देश की बागडोर नई पीढ़ी के हाथ में आ गई है । साठ प्रतिशत मतदाता चालीस वर्ष से कम आयु के हैं । उन्हें इस बात की भी जानकारी थी कि विश्व में नयापन आ गया है, यह भी कि इसमें बुनियादी परिवर्तन आ गया है और यह तेजी से बदलता जा रहा है । किन्तु शीघ्र ही उन्हें इस बात का पता चल गया कि इन महत्वपूर्ण परिवर्तन में से अधिकांश अनिवार्यतः भारत की विदेश नीति के नियामक पंडित जवाहर लाल नेहरू के दृष्टिकोण के अनुरूप थे जिन्होंने इसकी कल्पना की थी तथा इसे मूर्तरूप देने को प्रयास किया था ।” इसलिये उन्होंने आगे कहा था- “उन्हीं सिद्धान्तों को पुनः उपयोग में लाना आवश्यक है । इसलिये नये सिरे से विचार करने की आवश्यकता है । इस प्रकार राजीव गांधी की विदेश नीति परिवर्तन के साथ निरंतरता का अथवा निरंतरता में मौलिकता का एक अच्छा उदाहरण प्रस्तुत करता है । उन्होंने नये दृष्टिकोण से भाषा में नवीनता के साथ तथा गतिशीलता की भावना के साथ जवाहर लाल नेहरू के मूल दृष्टिकोण तथा नीतियों का अनुसरण किया तथा विश्व में उभर रहे शीत युद्ध रहित एक नये विश्व का निर्माण करने के लिये जागरूक रहकर प्रयास किया, एक नये विश्व का सपना देखा और उसके लिये कार्य किया किन्तु इसे वे प्राप्त नहीं कर सके या वास्तविक रूप में परिणित नहीं कर सके¹² । ”

राजीव गांधी को अपने पूर्ववर्ती प्रधान मंत्रियों की तरह पता था कि भारत का आर्थिक दृष्टि से निर्माण तथा इसकी रक्षा वैज्ञानिक और प्रौद्योगिकीय क्षमताओं का इस विशाल और जटिल देश की राजनीतिक और मनोवैज्ञानिक एकता के आधार पर विकास विश्व मंच पर किसी सार्थक भूमिका को निभाने के लिये एक अपरिहार्य शर्त है। इसलिये वे देश को आर्थिक रूप से निर्भर बनाने तथा इसे २१वीं सदी में ले जाने के बारे में निरन्तर बात करते थे। परन्तु उन्हें ज्ञात था जैसा कि उन्होंने अपने प्रथम भाषण में १२ नवम्बर, १९८४ को कहा था- “राष्ट्र निर्माण की सबसे पहली पूर्वापेक्षा शांति है, पड़ोसी देशों के साथ शांति तथा विश्व में शांति। अपने सक्षिप्त परन्तु बेहतरीन राजनैतिक जीवन में उनके लिए शांति एक मुख्य मुद्दा था जिसे उन्होंने उत्साह और उद्देश्यपूर्ण कार्यवाही करके स्थापित करने की कोशिश की थी।”

प्रधान मंत्री के तौर पर उनका पहला अन्तराष्ट्रीय सम्मेलन नई दिल्ली में छह राष्ट्रों के पांच महाद्वीपों का शिखर सम्मेलन था जिसे उनकी माता इंदिरा गांधी द्वारा शुरू किया गया था। राजीव ने कहा था कि यह सम्मेलन इतिहास के निराशपूर्ण मोड़ पर हो रहा है। इस दिल्ली शिखर सम्मेलन में एक घोषणा जारी की गयी थी। इस घोषणा में परमाणु शस्त्रों के उत्पादन और विकास पर रोक लगाने का अनुरोध किया गया था जो कि परमाणु शस्त्रों को पूर्णतया समाप्त करने के उद्देश्य को पूरा करने की तरफ पहला

एशिया महाद्वीप में ब्रिटिश उपनिवेशवाद की समाप्ति के साथ एक नये सघर्ष की शुरुआत हुई जिसके परिणामस्वरूप इस क्षेत्र से शान्ति शब्द का लोप ही हो गया यह सघर्ष है दो पड़ोसी देशों का सघर्ष जिसे भारत पाक सघर्ष के नाम से जाना जाता है । भारत विभाजन के समय की घृणा और अविश्वास ने दोनों ही देशों को आज तक युद्ध की तैयारी में लगाये रखा । प्रारम्भ से ही दोनों देशों की सेनाएँ एक दूसरे के आमने सामने न केवल तैनात रही अपितु तीन बड़े युद्ध हुए और एक छोटी सी चिनगारी से किसी भी दिन चौथा युद्ध शुरू हो जाये तो आश्चर्य नहीं । पाकिस्तान की दुराग्रहपूर्ण विदेश नीति पर प्रकाश डालते हुए श्री राजीव गांधी ने कहा था- “पाकिस्तान के विदेश नीति का आधार भारत विरोध रहा है । पाकिस्तान का निर्माण मुस्लिम लीग की हिन्दुओं के प्रति घृणा की नीति का फल है इसलिए पाकिस्तान के शासकों के लिए यह आवश्यक हो गया कि वे भारत विरोध की नीति अपनाएँ क्योंकि यदि वे ऐसा नहीं करते रहे तो उसके जन्म का आधार नष्ट हो जाता है । कश्मीर का प्रश्न इस नीति की प्रमुख अभिव्यक्ति है कश्मीर को प्राप्त करने के लिए कभी अमेरिका और ब्रिटेन का पिछलग्गू बने रहने की नीति तो कभी चीन की चापलूसी यही संकेत देती है कि पाकिस्तान का भारत विरोध हमेशा बना रहेगा । ”

जनवरी १९८८ में स्टोकहोम में जब छ राष्ट्रों की पुन बैठक हुई थी तो महाशक्तियों को सामरिक महत्व के अपने हथियारों में १९८८ के पहले छ माह के दौरान ५० प्रतिशत की कटौती करने का सुझाव दिया गया था तथा संयुक्त राष्ट्र व्यवस्था के अर्न्तगत एक समेकित बहुउद्देशीय जाच व्यवस्था करने का भी सुझाव दिया गया था । शिखर सम्मेलन ने परम्परागत हथियारों में भी भारी कटौती करने का सुझाव दिया था यह महत्वपूर्ण बात है कि बाद में महाशक्तियों के बीच किये गये निरस्त्रीकरण समझौते राजीव गांधी तथा उनके अन्य पांच सहयोगी देशों द्वारा छ राष्ट्रों के शिखर सम्मेलन में रखे गये प्रस्तावों के आधार पर ही किये गये। इस बारे में नवम्बर १९८८ के शुरू में राजीव गांधी और मिखाइल गोर्बाचोव द्वारा जारी की गयी 'दिल्ली घोषणा' याद करने योग्य है, जिसके माध्यम से निरस्त्रीकरण प्रयासों को एक नये सैद्धान्तिक एवं व्यावहारिक आयाम दिये गये। इसके माध्यम से राजीव के अनुसार भारतीय संसद परमाणु शस्त्र मुक्त और शांतिप्रिय विश्व की स्थापना की दिशा में आम कल्पना को साकार करने के कार्य में सम्मिलित हो गयी । गांधी जी के शांति प्रिय विश्व सिद्धान्त को पहली बार एक महत्वपूर्ण अन्तर्राष्ट्रीय दस्तावेज में स्थान मिला। राजीव ने दावा किया था कि गांधी जी और लेनिन के आदर्श दिल्ली घोषणा में समाहित हुए हैं और विश्व समुदाय द्वारा इसकी आम स्वीकृति हेतु उन्होंने इसकी सन्तुति की।

राजीव गांधी के निरस्त्रीकरण के प्रयास उस वक्त उच्चतम सीमा पर पहुच गए जब उन्होंने सयुक्त राष्ट्र सघ के विशेष सत्र मे परमाणु शस्त्रो को २० वर्षो के अदर पूरी तरह से समाप्त करने सबधी निरस्त्रीकरण कार्यकारी योजना प्रस्तुत की थी। यह अभी भी शायद कुछ सशोधनो के साथ भारत की परमाणु शस्त्र निरस्त्रीकरण नीति का मुख्य अवलम्ब है और शायद इस विषय पर अब तक की प्रस्तुत सबसे अधिक विस्तृत और वास्तविक योजना है। उन्होंने कहा कि हमारा प्रस्ताव है कि प्रथम चरण मे १९९५ मे समाप्त होने वाली परमाणु अस्त्र वाले राष्ट्रो को सन २०१० तक सभी परमाणु शस्त्रो को कम करने और सभी ऐसे राष्ट्रो जिनके पास परमाणु अस्त्र नहीं है परमाणु अस्त्रो की देहरी पार न करने देने हेतु किए गए वायदो को कानूनी स्वरूप देगा इस सूत्र से विश्व परमाणु शस्त्र निरस्त्रीकरण की आवश्यकता तथा आज भारत द्वारा अनुभव की जा रही निरस्त्रीकरण की कुछ समस्याओ की कमी पूरी हो जाती है।

राजीव गांधी ने सयुक्त राष्ट्र सघ मे भारत की स्थिति स्पष्ट करते हुए कहा था कि हम इस तर्क को स्वीकार नहीं कर सकते है कि कुछ राष्ट्रो को मानव जाति के अस्तित्व पर प्रश्न चिन्ह लगाते हुए अपने सुरक्षोपाय करने का अधिकार है न ही ये स्वीकार्य है कि जिनके पास परमाणु शस्त्र है वे सभी नियंत्रणो से परे है जबकि वे राष्ट्र जिनके पास परमाणु शस्त्र नहीं है उनकी इस बात के लिए जाच की जाती है कि वे इन शस्त्रो का उत्पादन न करे।

शांति और निरस्त्रीकरण भारत द्वारा स्वतंत्रता के बाद से ही अपनाई गई गुट निरपेक्ष नीति के केन्द्रीय उद्देश्यों में से एक था। शस्त्र युद्ध के बाद विश्व में नई नीति की प्रासंगिकता को राजीव जी ने समझा था और नेहरू जी की गुटनिरपेक्षता और शांतिपूर्ण सह-अस्तित्व के सन्दर्भ में उन्होंने उस नीति के पालन और उसमें नई वास्तविकताओं के आधार पर परिवर्तित और परिवर्तनशील विश्व के अनुरूप रचनात्मक संशोधन किए। हरे में और उसके बाद बेलग्रेड में गुट निरपेक्ष आन्दोलन को इस बात की आवश्यकता महसूस हुई कि सुस्थापित नीति के मूल उद्देश्यों का अनुसरण किया जाय और साथ ही नए विश्व की नई वास्तविकताओं का दृढ़तापूर्वक सामना किया जाए। हरे और बेलग्रेड दोनों में ही राजीव ने वहाँ हुई चर्चाओं में प्रमुख रूप से अपना योगदान दिया। बेलग्रेड में हुए सम्मेलन में राजीव ने उसके परम्परागत उद्देश्यों को ऐसा नया रूप दिया कि सतत परिवर्तनशील मानवजाति के भविष्य की समस्याओं के अनुरूप हो जाये। विश्व स्तर पर हो रही गतिविधियों के सन्दर्भ में एक नैतिक शक्ति के रूप में उन्होंने तटस्थता की भूमिका पर बल दिया, जिसका सीधा प्रहार नामीबिया की आजादी पर पड़ने वाला था और जिससे उपनिवेशवाद एवं नस्लवाद के रूप में रंगभेद के समाप्त होने की संभावना थी और साथ ही उन्होंने गुट-निरपेक्षता को शासन करने और प्रभुत्व की खोज की। उस नीति की प्रतिशक्ति के रूप में प्रस्तुत किया जो अभी तक अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में व्याप्त थी। ‘पृथ्वी

सरक्षण कोष' का विशिष्ट प्रस्ताव देकर उन्होंने पर्यावरणीय समस्याओं पर विशेष बल देने का प्रस्ताव दिया और इस प्रकार उन्होंने तटस्थता के सन्दर्भ में एक नई सकल्पना दी जिसका पृथ्वी और मानव जाति के भविष्य पर महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ेगा ।

राजीव गांधी ने रंगभेद की नीति के विरुद्ध जो संघर्ष किया उसका उल्लेख अवश्य किया जाना चाहिए। राष्ट्र मण्डल सम्मेलनों में उन्होंने दक्षिण अफ्रीका के विरुद्ध लगे प्रतिबंधों को जारी रखने की वकालत की। मार्गरेट थैचर जैसे उग्र व्यक्तित्व के साथ बातचीत करते समय उन्होंने जो वाक्चातुर्य और कूटनीतिक कौशल दिखाया उससे उनकी प्रतिष्ठा और अधिक बढ़ गयी। नसाऊ और लन्दन दोनों ही स्थानों पर हुए सम्मेलनों में लौह महिला मार्गरेट थैचर अलग-थलग पड़ गई। किन्तु उन्होंने अपने आकर्षण और राजनीतिक दक्षता के द्वारा श्रीमती थैचर का सम्मान और सदभाव अक्षुण्ण बनाए रखा। उन्होंने रंगभेद पर इस महत्वपूर्ण चरण में निर्णयात्मक भूमिका निभाई। रंगभेद उपनिवेशवाद और जातिभेद के विरुद्ध संघर्ष में जिस अफ्रीका कोष का प्रस्ताव राजीव गांधी ने किया वह दूसरा महत्वपूर्ण प्रस्ताव था । नामीबिया के संघर्ष में राजीव गांधी की भूमिका इतनी महत्वपूर्ण थी कि नामीबिया सरकार ने अपने स्वतंत्रता समारोह में उन्हें उस समय विशेष अतिथि के रूप में आमंत्रित किया, जबकि वे विपक्ष के नेता मात्र थे ।

राजीव गांधी की विदेश नीति विश्व के व्यापक कार्यक्रमों के

बारे में पहले से ही नहीं बनायी गयी थी, बल्कि पड़ोसी देशों की कठिन और दुरूह समस्याओं को लेकर भी बनायी गयी थी। दक्षिण एशिया में मूल सिद्धान्तों और राष्ट्रीय हितों के साथ समझौता किये बिना ही उन्होंने मेल-मिलाप, मैत्री और सहयोग के लिए प्रयास किया। उन्होंने दक्षिण सगठन को नयी प्रेरण दी। उन्होंने जिया उल हक और बेनजीर भूटो दोनों के साथ न केवल सरकारी किन्तु व्यक्तिगत सम्बन्ध भी स्थापित किये। एक दूसरे के परमाणु प्रतिष्ठानों पर आक्रमण न करने संबंधी पाकिस्तान के साथ किया गया समझौता विश्वास पैदा करने वाला प्रमुख उपाय था और परमाणु प्रश्न के निपटारे की संभावनाएँ दोनों पड़ोसियों के बीच संबंध बिगड़ने का कारण इसमें अन्तर्गुप्त था। राजीव गांधी की चीन यात्रा कुल मिलाकर एक ऐतिहासिक कदम था जिससे एशिया के दो महान देशों के बीच लम्बे समय से बिगड़े संबंधों में सुधार आया। उसी ऐतिहासिक यात्रा के आधार पर आज चीन के साथ भावी संबंध बनाये जा रहे हैं। श्रीलंका के संबंध में दुर्भाग्यपूर्ण कार्यों के होते हुए भी, श्रीलंका में तमिलों को कोई बड़ी स्वायत्ता मिल सकने में शका है और श्री राजीव गांधी जयवर्धने समझौते में उसकी एकता और अखण्डता में अधिक विश्वसनीय गारन्टी है।

महाशक्तियों के साथ व्यवहार में राजीव ने अन्तर्राष्ट्रीय संबंधों के प्रति गहरी समझबूझ दिखायी। वह समझते थे कि शीत युद्ध के समाप्त होने से भारत को अमेरिका और पूर्व सोवियत संघ के साथ

निकट और सार्थक सम्बन्ध स्थापित करने के अवसर प्राप्त होंगे। उन्होंने भारत के साहस तथा विश्वास और इसके हितों को ध्यान में रखकर मित्रता की पेशकश की। इस सन्दर्भ में बात उल्लेखनीय है कि भारत के युवा प्रधानमंत्री ने सहज रूप से और समानता के स्तर पर राष्ट्रपति श्री रोनाल्ड रीगन और महासचिव श्री मिखाइल गोर्बाचोव से वार्ता की। उन्होंने इन दोनों महाशक्तियों के साथ गहरे और व्यापक सम्बन्ध स्थापित करने के लिए अमेरिका और भूतपूर्व सोवियत संघ के साथ अनेक समझौतों पर हस्ताक्षर किए। साथ ही उन्होंने जापान एशियाई देशों तथा यूरोपीय आर्थिक समुदाय के साथ निकट सम्बन्धों के महत्त्व की अवहेलना नहीं की। उन्होंने भारत की परम्पराएँ - जो उन्हें विरासत में मिली थी और अन्तर्राष्ट्रीय स्थिति की वास्तविकता - जैसा कि उन्होंने समझी था के अनुसार विश्व के प्रति अपना दृष्टिकोण बनाया।

विश्व के प्रति अपने दृष्टिकोण में उन्होंने भारत पर मुख्य रूप से ध्यान दिया, भारत की राजनैतिक एकता को तथा इसकी आर्थिक प्रौद्योगिकीय और सैन्य दृष्टि से मजबूत कराने की आवश्यकता महसूस की जैसे कि जवाहर लाल नेहरू और इंदिरा गांधी की विज्ञान और प्रौद्योगिकी पर केवल भारत के विकास के साधन रूप में ही प्रमुख रूप से बल नहीं दिया बल्कि अपनी विदेश नीति और राजनयिकता के एक महत्वपूर्ण पहलू के रूप में इसका प्रचार भी किया।

उन्होंने अपनी विदेश नीति और कूटनीति में महाशक्तियों के साथ तथा दक्षिण के विकासशील देशों में वैज्ञानिक और प्रौद्योगिकीय सहयोग के उद्देश्यों को प्राथमिकता के रूप में अपनाया। इस प्रकार “भारत के प्रधान मंत्री के संक्षिप्त और उज्ज्वल काल के दौरान राजीव गांधी द्वारा प्रतिपादित विदेश नीति में आदर्श और आराध्य सिद्धान्तों तथा तीक्ष्ण व्यवहार्य विषयवस्तु और प्रौद्योगिकीय तर्कों का सही पुट था ¹³।”

अब हम लेते हैं गुटनिरपेक्ष आंदोलन निरस्त्रीकरण तथा आर्थिक मामलों में राजीव गांधी की भूमिका को अनेक राष्ट्रों की उपनिवेशवाद से मुक्ति होने पर भारत की गुटनिरपेक्ष नीति को बड़े पैमाने पर स्वीकृति मिली। पहला गुटनिरपेक्ष सम्मेलन १९६१ में बेलग्राद में हुआ, जिसमें २५ देशों ने भाग लिया था। बेलग्राद शांति घोषणा की काफी अधिक प्रतिक्रिया हुई। इस सम्मेलन में गुटनिरपेक्ष देशों के बीच समय समय पर होने वाले विचारों के आदान-प्रदान और विचार-विमर्श की उपादेयता को सिद्ध कर दिया। इसके बाद अन्य और देश भी गुटनिरपेक्ष आंदोलन में सम्मिलित हुए हैं और इसकी वर्तमान संख्या १०० तक पहुंच गयी है। इसके अतिरिक्त कुछ दर्जन देश पर्यवेक्षक और अतिथि के रूप में भी सम्बद्ध हैं। सदस्य संख्या में वृद्धि होने के बावजूद इस आंदोलन ने शांति, निरस्त्रीकरण, विकास और स्वतंत्रता के पक्ष में अपना मूल स्वर बनाए रखा है। कुछ मामूली मतभेदों के बावजूद गुटनिरपेक्ष राष्ट्रों के बीच एकता और आंदोलन

को व्यापक समर्थन और स्वीकृति प्राप्त हुई है। गुटनिरपेक्ष आंदोलन में भारत की भूमिका का अनुमान इसी बात से लगाया जा सकता है कि मार्च १९८३ में गुटनिरपेक्ष शिखर सम्मेलन का आयोजन नई दिल्ली में किया गया और भारत को इसका अध्यक्ष चुना गया। सितम्बर, १९८६ में जिम्बाब्वे को गुटनिरपेक्ष आंदोलन की अध्यक्षता सौंप दिए जाने के बाद भी आंदोलन में भारत की भूमिका और गतिविधियों ने अपने लिए ऊंचा स्थान रखा है। भारत ने गुटनिरपेक्ष आंदोलन के भीतर के प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों पर जनमत बनाए रखने के अपने प्रयास जारी रखे और इसने अन्य गुट निरपेक्ष देशों के निकट सहयोग से कार्य किया। इसने कोनट्राडोरा प्रक्रिया के लिए आंदोलन और ग्वाटेमाला संधि में उल्लिखित क्षेत्रीय शांति की पहल के प्रति अपनी एकजुटता और समर्थन व्यक्त किया¹⁴। भारत ने आंदोलन द्वारा विश्व के आर्थिक मुद्दों विशेषकर गुटनिरपेक्ष और अन्य विकासशील देशों से संबंधित मुद्दों के संबंध में सक्रिय भूमिका निभाने पर जोर दिया है ताकि बहुआयामी आर्थिक सहयोग के संबंध में उनकी स्थिति सुदृढ़ हो सके।

जहां तक निरस्त्रीकरण का संबंध है भारत ने समय-समय पर परमाणु हथियारों का कड़ा विरोध किया और पूर्ण निरस्त्रीकरण का समर्थन किया है। भारत परमाणु ऊर्जा के शांतिपूर्ण उपयोग के लिए भी पूरी तरह प्रतिबद्ध है, लेकिन वह उन प्रयासों या उपायों का विरोध करता है जो परमाणु ऊर्जा के शांतिपूर्ण उपयोग के बारे में

भारत के कार्यक्रम के आड़े आते हैं। भारत ने विशेष रूप से अमरीका और सोवियत संघ के बीच परमाणु हथियारों में कमी करने के लिए जेनेवा वार्ता शुरू करने का स्वागत किया क्योंकि निरस्त्रीकरण के लिए कारगर कदम उठाने की प्रमुख जिम्मेदारी परमाणु शक्तियों की है। प्रधानमंत्री राजीव गांधी ने न्यूयार्क में संयुक्त राष्ट्र की स्थापना की ४०वीं वर्षगांठ के अवसर पर अधिवेशन को सम्बोधित करते हुए कहा था कि परमाणु सैनिकवाद के पागलपन से दुनिया को मुक्त करने की आवश्यकता है। मनुष्य को अपनी सृजन क्षमता का प्रयोग विनाश के लिए नहीं बल्कि सबर्धन के लिए करना चाहिए। उन्होंने जनवरी १९८५ में छह राष्ट्रों के शिखर सम्मेलन में जारी दिल्ली घोषणा के उद्देश्यों को फिर दोहराया। इस शिखर सम्मेलन में अर्जेंटीना, ग्रीस भारत मैक्सिको स्वीडन और तजानिया के नेताओं ने सभी तरह के परमाणु परीक्षणों पर १२ महीने की रोक लगाने का अनुरोध किया था तथा इस बारे में जाँच प्रक्रिया के लिए सुविधाओं का प्रस्ताव किया था। छह राष्ट्रों के इन नेताओं की बैठक मैक्सिको में छह अगस्त १९८६ को फिर हुई। सभी तरह के परमाणु परीक्षणों पर रोक लगाने^{की} आवश्यकता पर जोर देते हुए इन नेताओं ने परमाणु हथियार सम्पन्न महाशक्तियों से अनुरोध किया कि वे परमाणु परीक्षणों पर रोक लगाने और इसके लिए समुचित परमाणु प्रबंध के लिए ठोस प्रस्ताव रखें¹⁵।

सितम्बर १९८६ में हरारे में गुटनिरपेक्ष देशों के राष्ट्राध्यक्षों का

आठवाँ शिखर सम्मेलन हुआ जिसमें निरस्त्रीकरण के लिए गुटनिरपेक्ष आंदोलन की वचनबद्धता को पुनः दुहराया गया और दोनों महाशक्तियों से अनुरोध किया गया कि वे परमाणु युद्ध को छिड़ने से रोकने के लिए तुरन्त कारगर कदम उठाए। भारत ने तीन मुख्य बहुपक्षीय निरस्त्रीकरण मंचों अर्थात्- निरस्त्रीकरण सम्मेलन, संयुक्त राष्ट्र निरस्त्रीकरण आयोग और संयुक्त राष्ट्र जनरल असेम्बली की पहली समिति में प्रमुख भूमिका निभाई। ऐसा भारत की इस अडिग आस्था के अनुरूप किया गया कि इस आणविक युग में निरस्त्रीकरण केवल शांति के लिए ही नहीं बल्कि मानव जाति के अस्तित्व के लिए भी आवश्यक है¹⁶। भारत ने बहुपक्षीय दबाव की वैधता पर यह दोहराते हुए जोर दिया कि परमाणविक निवारण के माध्यम एकपक्षीय सुरक्षा की खोज के स्थान पर परमाणु निरस्त्रीकरण के जरिए विश्व सुरक्षा की खोज की जाए।

परमाणविक और सामान्य निरस्त्रीकरण के जेहाद में भारत ने छह-राष्ट्रीय पहल के पांच अन्य देशों के साथ २२ जनवरी १९८८ को सोवियत संघ और अमेरिका के बीच आई एन एफ संधि का स्वागत किया और इसे ऐतिहासिक कदम बताया¹⁷। उनकी स्टाकहोम घोषणा में वार्ता पुनः आरम्भ होने का स्वागत किया गया और इनकी जांच तथा इस क्षेत्र में समझौतों की मांग की गई।

नौ जून १९८८ को निरस्त्रीकरण पर संयुक्त राष्ट्र महासभा के तीसरे विशेष सत्र को सम्बोधित करते हुए तत्कालीन प्रधानमंत्री

राजीव गांधी ने सयुक्त राष्ट्र को एक कार्य योजना आरम्भ करने के लिए कहा था जिससे सभी मौजूदा परमाणु शक्तियों वाले देशों द्वारा २०१० ई तक विश्व के सभी परमाणविक हथियार समाप्त कर दिए जाए¹⁸। उन्होंने प्रस्ताव किया कि यह कार्य योजना तीन चरणों में परिचालित की जाए जिसके परिणामस्वरूप न केवल परमाणविक खतरे समाप्त हो सकेंगे बल्कि एक नई सयुक्त राष्ट्र गहन विश्व सुरक्षा प्रणाली स्थापित होगी, जिससे एक नया न्यायपूर्ण समाज और समरूपी विश्व नियम सुनिश्चित किया जा सकेगा¹⁹। प्रधानमन्त्री के विस्तृत प्रस्ताव में शताब्दी के अंत तक एक एकल बहुपक्षी सत्यापन प्रणाली की स्थापना की मांग की गई ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि विश्व में कहीं भी नए परमाणविक हथियार नहीं बनाए जा रहे हैं। उन्होंने राष्ट्रपति रीगन के प्रस्तावित विशेष प्रतिरक्षा पहलू का उल्लेख करते हुए यह घोषणा की- परमाणविक दौड़ को ऐसी कार्रवाई के सबंध में विलम्बन संधि के बिना समाप्त नहीं किया जा सकता अथवा रोका नहीं जा सकता।

अब हम लेते हैं आर्थिक मामले और राजीव गांधी द्वारा उनको निबटाने के प्रयासों को हाल के वर्षों में मामूली से विस्तार के साथ विश्व-अर्थव्यवस्था संकट के कगार पर है। उत्पादकता में कमी इसी से स्पष्ट है कि उत्पादन की दर १९८५ में ३ प्रतिशत से घटकर २८ प्रतिशत रह गई। व्यापार १९८६ में चार प्रतिशत उत्पादकता पर ही चलता रहा, वस्तुओं के मूल्यों में और कमी आई

विकासशील देशों के नए ऋण घट गए और ऋण अदायगी और भी कठिन हो गई। हाल के आकड़ों से पता चलता है कि विकासशील देशों का कुल ऋण १९८६ के अंत तक ११ ट्रिलियन अमरीकी डालर हो गया है।

विकासशील देशों को पूंजी उपलब्धता में जारी रुकावट के फलस्वरूप वित्तीय वर्ष १९८६ में लगभग कुल ३००० करोड़ अमरीकी डालर मूल्य के ससाधनों का दक्षिण से उत्तर को शुद्ध अंतरण हुआ। सरकारी विकास सहायता अंतर्राष्ट्रीय रूप से सहमत स्तर ०.७ प्रतिशत के आधे से भी कम रही। कई विकासशील देशों की प्रति व्यक्ति आय में कमी हुई और सामूहिक रूप से विकासशील देशों की सकल स्थानीय उत्पादन १९८५ में ४.२ प्रतिशत से घटकर १९८६ में ३.६ प्रतिशत हो गई। संरक्षणवाद निरन्तर बढ़ता ही रहा है। हालांकि सरकारों ने बार-बार घोषणाएं और बहुपक्षीय व्यापार वार्ताएं के नए दौर शुरू करने की सधिया की हैं। अमीर और गरीब देशों के बीच परस्पर निर्भरता को अब अधिक मान्यता मिल रही है और इसके बढ़ने के प्रमाण भी हैं। तथापि विकासित देशों के बीच परस्पर विकास धीमा हुआ है।

नई दिल्ली और हारारे में हुए सातवे और आठवे गुटनिरपेक्ष शिखर सम्मेलनों में बहुपक्षीय सहयोग के माध्यम से उत्पादकता और विकास के प्रति एक ठोस और व्यावहारिक दृष्टिकोण और विकास के प्रति बहुपक्षवाद से खिचाव रोकने का प्रस्ताव किया गया था।

साथ ही इनमें नए अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक सहयोग की प्राप्ति के लिए दीर्घकालीन सरचनात्मक सुधारों का भी प्रस्ताव किया गया। मुद्रा वित्त ऋण, व्यापार प्रौद्योगिकी तथा विकास की अंतर्राष्ट्रीय और अतर्सम्बन्धी प्रणालियों में सुधार आवश्यक है। प्रमुख औद्योगिक देशों की मैक्रो-एकानामिक नीतियों के विश्व अर्थव्यवस्था में मांग में वृद्धि करने तथा उत्पादकता को बढ़ाने के उद्देश्य से सामंजस्य स्थापित करने और सहयोग करने की आवश्यकता है। अक्टूबर १९८७ के राष्ट्रमंडल शिखर सम्मेलन में विश्व व्यापार पर की गई घोषणा को अपनाया गया जिसमें यह उल्लेख किया गया कि नई बहुपक्षीय व्यापार वार्ताओं में विकासशील देशों पर विशेष रूप से विचार किया जाए।

भारत ने विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी की नई खोजों को अनुकूल बनाने और विकसित करने की दक्षिण की क्षमताएँ बढ़ाने में सुविधा प्रदान करने के उद्देश्य से नई दिल्ली में हुए गुटनिरपेक्ष एवं आगे होने वाले ग्रुप-७७ सम्मेलनों के माध्यम से पहल की है। भारत ने शांति को बढ़ावा देने एवं जीवन-स्तर बेहतर बनाने के लिए, विशेषकर विकासशील देशों के लिए, इन वैज्ञानिक और प्रौद्योगिकीय विकास कार्यों के परिणामों का लाभ उठाने हेतु अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बटवारे की नई प्रक्रिया आरम्भ करने के लिए संयुक्त राष्ट्र में पहल की। विज्ञान और प्रौद्योगिकी के लिए संयुक्त राष्ट्र अंतर्राष्ट्रीय समिति के अगस्त, १९८७ में हुए नार्वे सत्र में भारतीय पहल पर आम सहमति

द्वारा एक प्रस्ताव पारित किया गया जिसमें अनुसंधान सूचना एवं प्रशिक्षण प्रौद्योगिकी पूर्व सूचना और नए तथा अविषयगत विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी नेस्ट के आकलन के आपसी विकास और सहयोग के लिए कार्यक्रमों परियोजनाओं की माग की गई थी ²⁰।

सामूहिक आत्म निर्भरता और आर्थिक स्वतंत्रता की प्राप्ति और विश्व अर्थव्यवस्था तथा एक नए अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक सहयोग की स्थापना के प्रयासों के एक महत्वपूर्ण भाग के रूप में अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक संबंधों में विकासशील देशों की भूमिका बढ़ाने के लिए उनमें आपसी सहयोग, गुटनिरपेक्ष आंदोलन एवं ग्रुप-७७ का एक प्रमुख उद्देश्य बन गया है। विकास कार्यों के लिए दक्षिण के एक स्वतंत्र आयोग की स्थापना से महत्वपूर्ण आर्थिक विषयों पर लाभदायी निवेश प्राप्त हो सकता है। इस आयोग ने दो से पांच अक्टूबर १९८७ तक अपनी पहली बैठक में औपचारिक रूप से अपना कार्यारम्भ कर दिया है ²¹ ।

विकासशील देशों के आपसी सहयोग से संबंधित सभी मुद्दों और प्रतिविधियों की समीक्षा करने के लिए जून १९८७ में गुटनिरपेक्ष मंत्रियों की बैठक प्यागयोग में हुई। बैठक के परिणामों के महत्वपूर्ण पहलुओं में प्रमुख नई दिल्ली में गुटनिरपेक्ष विज्ञान और प्रौद्योगिकी केन्द्र आरम्भ किए जाने का निर्णय और भारत द्वारा नई एवं उच्च वैज्ञानिक तथा प्रौद्योगिकी के लिए की गई पहल का सत्यापन और उसका स्वागत।

विकासशील देशों में आपसी सहयोग की भावना में अफ्रीका एशिया और लैटिन अमेरिकी देशों में विश्व के अन्य विकासशील देशों के साथ सहयोग बढ़ाने के प्रति भारत की कटिबद्धता को विदेश मन्त्रालय द्वारा चलाई जा रही भारतीय तकनीकी एवं आर्थिक सहयोग के अतर्गत सहायता की द्विपक्षीय योजना में अभिव्यक्ति मिली। सहायता के इस द्विपक्षीय कार्यक्रम से अन्य बहुपक्षीय योजनाओं जैसे कि कोलम्बो योजना और विशेष राष्ट्रमंडल अफ्रीकी सहायता कार्यक्रमों की अनुपूर्ति हुई है। सन १९६४ में आरम्भ किए गये आइटेक कार्यक्रम में जो कि निरन्तर वर्षानुकूल फैला है अब अफ्रीका एशिया और लैटिन अमेरिका के ७० से अधिक देश शामिल हैं और इसका बजट परिव्यय २० करोड़ रुपये से अधिक हो गया है।

भारत की महत्वपूर्ण भूमिका के परिणामस्वरूप ही, संयुक्त राष्ट्र महासभा के ४३वें अधिवेशन से पूर्व हुई ७७ के समूह और गुटनिरपेक्ष देशों की मंत्री स्तरीय बैठकों में घोषणाएँ पारित की जा सकीं। दूसरी समिति में मुख्यतः बाहरी ऋण सफट एवं सम्बद्ध मसलों पर्यावरण संबंधी मामलों और ७७ के समूह के इस प्रस्ताव पर चर्चा हुई कि विकासशील देशों में उत्पादन और विकास को पुनः सक्रिय किए जाने के लिए महासभा का एक विशेष अधिवेशन बुलाया जाए। खेद की बात है कि ऋण संबंधी सकल्प पर लगातार दूसरे वर्ष, संयुक्त राज्य अमेरिका ने विरोधी वोट डाला, जबकि जापान ने इसमें भाग नहीं लिया। भारत ने पर्यावरण संबंधी सकल्प

पर जनमत तैयार करने में एक सक्रिय भूमिका निभाई। इस वर्ष की एक प्रमुख उपलब्धि प्रदूषण रोकने के लिए विकसित देशों की मुख्य जिम्मेदारी पर समझौता करा लेना था²²।

भारत १९८८ के दौरान एकासोक संगठन का सदस्य था और उसने दूसरे नियमित सत्र में सक्रिय भूमिका निभाई। पर्यावरण के क्षेत्र में दूसरे नियमित सत्र में ७७ के समूह द्वारा महत्वपूर्ण पहल की गई। इनमें ससाधनों की अतिरिक्तता और तकनीकी सहयोग में वृद्धि पर्यावरण निधि को सुदृढ़ करने, जहरीले उत्पादों और कचरे के लेन-देन तथा परमाणविक कचरे को एकत्रित कर समाप्त करने से संबंधित सकल्प शामिल थे। ७७ के समूह ने स्वयं परिषद को पुनर्जीवित करने के सकल्प के संबंध में बातचीत की पहल की। संयुक्त राज्य अमेरिका द्वारा प्रस्तुत उद्यम संबंधी सकल्प में सावर्जनिक क्षेत्र सहित राष्ट्रीय उद्यमियों को प्रतिबिम्बित करने और रोजगार के अवसर पैदा करने तथा प्रौद्योगिकी प्राप्त करने में उद्यमियों की भूमिका जैसे सशोधन लाने के लिए भारत की भूमिका की सभी प्रतिनिधियों द्वारा प्रशंसा की गई।

अक्टूबर १९८८ में भारत ने नई दिल्ली में नवीन और उच्च प्रौद्योगिकी पर गुटनिरपेक्ष एवं विकासशील देशों के विशेषज्ञों के पहले अर्तशासकीय सलाहकार सम्मेलन की मेजबानी की। यह सहयोग का एक और नया उभरता हुआ क्षेत्र है। इस बैठक में २० विकासशील देशों के विशेषज्ञों ने भाग लिया। सम्मेलन के पांच मुख्य

क्षेत्रों में से प्रत्येक के लिए सहयोग के कार्यक्रम निर्धारित किए गए²³।

जहां तक आठवे गुट निरपेक्ष शिखर सम्मेलन का प्रश्न है पूर्व प्रधानमंत्रियों द्वारा गुट निरपेक्षता की दिशा में किये गये प्रयासों को गति प्रदान करने के लिए श्री राजीव गांधी ने आठवे गुट निरपेक्ष शिखर सम्मेलन में बलपूर्वक इसकी वकालत की। इस बावत उन्होंने लिखा-“मैं १-७ सितम्बर तक हरारे में आयोजित गुट-निरपेक्ष देशों के आठवे शिखर सम्मेलन में शामिल हुआ। यह एक अविस्मरणीय और ऐतिहासिक अवसर था। आन्दोलन की इस २५ वीं वर्षगांठ के अवसर पर एक विशेष स्मारक अधिवेशन का आयोजन किया गया था जिसमें विश्व शान्ति में गुट-निरपेक्ष आन्दोलन के महत्वपूर्ण योगदान का स्मरण किया गया तथा इसके पितामह नेहरू टीटो सुकर्ण एनक्रुमा तथा नासिर द्वारा प्रतिपादित सिद्धान्तों और लक्ष्यों की सतत वैधता की पुनः पुष्टि की गई²⁴।”

इस शिखर सम्मेलन में आन्दोलन की भूतपूर्व अध्यक्षा श्रीमती इन्दिरा गांधी के प्रति भाव-भीनी श्रद्धाजलि अर्पित की गई। इस आन्दोलन की एकता, दृढ़ता और एकजुटता को और अधिक मजबूत करने की दिशा में आन्दोलन के अध्यक्ष की हैसियत से भारत की भूमिका की भूरि-भूरि प्रशंसा की गई। हमारे नेतृत्व में इस आन्दोलन को आन्तरिक तौर पर समरसता और स्थायित्व प्राप्त हुआ है और बाहरी तौर पर दृढ़ता एवं सक्रियता। अपने स्वरूप में अनेकता

और विविधिता किन्तु स्वतन्त्रता शान्ति एव न्याय के प्रति समान प्रतिबद्धता लिए हुए यह आन्दोलन अपने सिद्धान्तों पर सदैव अडिग रहा है।

विश्व पटल पर विभिन्न समस्याओं पर चर्चा करने और समाधान हेतु आयोजित इस शिखर सम्मेलन में श्री राजीव गांधी ने कहा- “हमारे में इस आन्दोलन की अध्यक्षता का दायित्व हमने जिम्बाबे के हाथों सौंप दिया। इस शिखर सम्मेलन में आज के युग के तीन सर्वाधिक महत्वपूर्ण और आधारभूत प्रश्नों पर विचार-विमर्श केन्द्रित रहा। ये प्रश्न थे दक्षिण अफ्रीका में मानवाधिकार नामीबिया की स्वतन्त्रता तथा नाभिकीय विनाश के निरन्तर खतरे से मुक्त होकर एक स्वतन्त्र ससार में सास लेने का समूची मानवता का अधिकार²⁵।”

इस सम्मेलन में दक्षिण अफ्रीका पर एक विशेष घोषणा स्वीकार की गई तथा आक्रमण उपनिवेशवाद तथा जातीयता रंगभेद को रोकने की कार्यवाही के निमित्त एक निधि की स्थापना की गई जिसे अफ्रीका कोष की सजा दी गई है। इस अफ्रीका कोष समिति का अध्यक्ष भारत है और उपाध्यक्ष जाम्बिया। इस कोष की स्थापना हमारे आन्दोलन के इस सकल्प को परिलक्षित करती है कि हम फ्रंटलाइन देशों के अपने भाईयों के साथ तथा दक्षिणी अफ्रीका के मुक्ति आन्दोलनों के साथ अपनी एकजुटता को ठोस रूप देना चाहते हैं। जातीय रंगभेद से जूझने, जातिवादी प्रीटोरिया सरकार के विरुद्ध

प्रतिबन्ध लगाने और सरकार की ओर प्रतिक्रिया स्वरूप की गई कार्रवाइयो से निपटने में उनकी सामर्थ्य को सुदृढ करने के इरादे से हमने फ्रटलाइन देशों के साथ गहन विचार-विमर्श किया।

श्री राजीव गांधी ने आशा व्यक्त की इस महीने के आखिर में लुसाका में इस कोष समिति के वरिष्ठ अधिकारियों की एक बैठक होगी। कोष समिति के सदस्य देशों के राज्याध्यक्षों के शिखर सम्मेलन से पूर्व एक मन्त्री स्तरीय बैठक होगी जिसका आयोजन सम्भवतः दिल्ली में किया जाएगा। मुझे पूरी उम्मीद है कि इस कोष को न सिर्फ गुट निरपेक्ष आन्दोलन के सदस्य तथा गैर सदस्य सरकारों से पूर्ण समर्थन प्राप्त होगा बल्कि उन सभी सासदों स्वैच्छिक संगठनों और व्यक्तियों से भी पूर्ण समर्थन प्राप्त होगा जो दक्षिण अफ्रीका में सभ्यता के बुनियादी मानदण्डों के उल्लंघन से तथा प्रीटीरिया की ओर से आने वाले शान्ति के प्रति खतरे से गम्भीर रूप से चिंतित हैं²⁶ ।

इस आन्दोलन ने फिलिस्तीनियों के हित साधन के प्रति अपना दृढ समर्थन दोहराया तथा गुट-निरपेक्ष देशों की आजादी उनकी स्वाधीनता और प्रभुसत्ता की रक्षा के प्रति अपना सकल्प व्यक्त किया जिन्हें विदेशी दखलन्दाजी की ओर से खतरा है।

हरारे में निरस्त्रीकरण के सबंध में जो अपील सहर्ष स्वीकार की गई वह शान्ति तथा निरस्त्रीकरण के प्रति इस आन्दोलन की प्रतिबद्धता को तथा मानवीय अस्तित्व को बढ़ते हुए खतरे के प्रति

हमारी चिन्ता को परिलक्षित करती है। इस अपील में अमरीका और सोवियत सघ से यह अनुरोध किया गया है कि नाभिकीय युद्ध को भडकने से रोकने के लिए वे तत्काल कदम उठाए तथा एक व्यापक परीक्षण प्रतिबन्ध सन्धि की दिशा में प्रथम चरण के रूप में नाभिकीय परीक्षणों पर एक निश्चित अवधि तक प्रतिबन्ध लगा दे। शिखर सम्मेलन में शान्ति एवं निरस्त्रीकरण की दिशा में छह राष्ट्र पांच महाद्वीपों की पहलकदमी का समर्थन किया गया जिसकी शुरुआत दिल्ली में की गई थी।

आर्थिक स्थिति के बारे में राजीव गांधी ने कहा- “विगत कुछ वर्षों में विश्व की आर्थिक स्थिति कुछ और अधिक बिगड़ी है। हमारे देश में आर्थिक सहयोग के लिए एक सक्रिय कार्यक्रम भी स्वीकार किया गया तथा सार्वभौम तथा आर्थिक मसलों पर की जाने वाली कार्यवाही में एकरूपता तथा तालमेल स्थापित करने के लिए एक समिति भी गठित की गई। एक राजनैतिक घोषणा में आज की दुनिया के सामने पेश अधिकांश कठिन मुद्दों पर आन्दोलन की एक राय लक्षित है।”

उनका दृढ़ मत था कि इस शिखर सम्मेलन ने एक नई दिशा प्रदान की थी। इस आन्दोलन की स्थापना की २५वीं वर्षगांठ के अवसर पर इस शिखर सम्मेलन का आयोजन किया गया था। इस अवसर पर हमने आन्दोलन में अपनी आस्था की पुनः पुष्टि की तथा शांति, निरस्त्रीकरण और विकास के लिए एकजुट हुए विश्व समुदाय

की अपनी परिकल्पना में अपनी आस्था की भी पुनः पुष्टि की। हम प्रधानमंत्री मुगाबे की सफलता की कामना करते हैं कि वह अपने समक्ष आने वाली चुनौतियों का सामना कर सके तथा उन्हें अपना पूर्ण समर्थन और सहयोग देने का वचन देते हैं।

उन्होंने खुशी जाहिर की कि हरारे शिखर सम्मेलन के दौरान मुझे अनेक नेताओं के साथ मिलने का सुअवसर मिला तथा उनसे अपनी मित्रता ताजा करने का भी जिनसे पहले मिलने का सौभाग्य प्राप्त हो चुका था। हमें विभिन्न अन्तर्राष्ट्रीय मसलों पर तथा बहुत से देशों के साथ अपने द्विपक्षीय सम्बन्ध सुदृढ़ करने के सबंध में अत्यन्त लाभप्रद विचार-विमर्श करने का मौका मिला।

अब हम आते हैं राजीव गांधी और राष्ट्रमंडल पर । ब्रिटिश राष्ट्रमंडल को वर्तमान रूप देने में भारत ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है । भारत ने हाल में स्वाधीनता प्राप्त देशों को सीधे और राष्ट्रमंडल जैसे संगठनों के माध्यम से सहायता देकर वहाँ स्थिरता और प्रगति को बढ़ावा देने में रुचि दिखाई । राष्ट्रमंडल से बर्मा के अलग हो जाने के बाद, उसे राष्ट्रमंडल कार्यक्रम के महत ६०,००,००० पौड की सहायता देने का एक अभूतपूर्व मामला विचाराधीन था । फिर भी भारत ने बर्मा की स्वतंत्रता के लिए उसे ऐसी सहायता देने के वास्ते अन्य सदस्य देशों से अनुरोध किया । इस पहल से बाद में कोलम्बो योजना बनाने में मदद मिली। इस योजना ने इस क्षेत्र के आर्थिक विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है।

राष्ट्रमंडल और इसके साथ-साथ विश्व में भारत की भूमिका के फलस्वरूप नई दिल्ली में २३ नवम्बर से २९ नवम्बर १९८३ तक राष्ट्रमंडल के सदस्य देशों के शासनाध्यक्षों की अब तक की सबसे बड़ी बैठक भी हुई। इस शिखर सम्मेलन में जारी अंतिम दस्तावेजों में शांति और विकास से संबंधित मामलों के बारे में दृष्टिकोण की एकता प्रकट हुई। बाद में नासो (NASO) में १६ नवम्बर से २२ नवम्बर १९८५ तक राष्ट्रमंडल सदस्य देशों के शासनाध्यक्षों के सम्मेलन में प्रधानमंत्री राजीव गांधी ने प्रमुख भाषण दिया। उन्हीं के सुझाव पर विश्व व्यवस्था पर घोषणा का प्रस्ताव स्वीकार किया गया²⁷।

भारत ने १९८६ में ३ से ५ अगस्त तक लंदन में राष्ट्रमंडल नेताओं की समीक्षा बैठक दक्षिणी अफ्रीका के बारे में नासो समझौते के अनुसार की गयी थी। इस बैठक में आस्ट्रेलिया, बहामास, कनाडा, भारत, जिम्बाबे और जाम्बिया के नेता इस बात पर सहमत हुए कि दक्षिण अफ्रीकी सरकार पर दबाव डालने के लिए जो उपाय सुझाए गए हैं उनके अतिरिक्त कुछ चुने हुए क्षेत्रों में प्रतिबंध तुरंत लगाए जाएं जिससे कि उस पर दबाव और बढ़ाया जा सके।

२ विश्व की गतिविधियों में राष्ट्रमंडल की भूमिका पर राजीव गांधी के विचार निम्न थे-

बैकूबर में राष्ट्रमंडल शिखर सम्मेलन के लिए जाते समय प्रधानमंत्री नाकासोनी के साथ विचार विमर्श करने के लिए मैं १२

अक्टूबर को थोड़ी देर के लिए टोकियो में रुका था। हमने आपसी हित के मामलों पर चर्चा की। उन्होंने २० करोड़ डॉलर के बराबर राशि का एक आसान और बिना शर्त जापानी ऋण देने की घोषणा की। प्रधानमंत्री ने कहा कि जापान भारत-श्रीलंका समझौते का समर्थन करता है ²⁸ ।

राष्ट्रमण्डल शिखर सम्मेलन १३-१७ अक्टूबर को वेकूवर में सम्पन्न हुआ। वेकूवर शिखर सम्मेलन बढ़ते हुए इस तरह के अनुमानों के बीच आरम्भ हुआ कि राष्ट्रमण्डल दक्षिणी अफ्रीका में जातीय रंगभेद के विरुद्ध अपने अभियान में पीछे रह गया है। यह बात गलत साबित हुई। ब्रिटेन को छोड़कर राष्ट्रमण्डल के सभी देश इस बात के प्रति सहमत थे कि प्रतिबन्धों का इच्छित प्रभाव पड़ना शुरू हो गया है। अतः हमने दबाव को और तेज करने और प्रतिबन्धों के क्षेत्र के विस्तार करने का फैसला किया। हमने राष्ट्रमण्डल के प्रतिबन्धों से संबंधित कार्यक्रम को व्यापक रूप से अन्तर्राष्ट्रीय स्वीकृति दिलाने और बेहतर ढंग से क्रियान्वित करने के लिए काम करने की प्रतिज्ञा ली²⁹।

श्री गांधी का विचार था- “अनेक नये सुझाव, जिनमें हमारे सुझाव भी शामिल थे, स्वीकार किये गये। हम निरन्तरता के आधार पर प्रतिबन्धों के प्रभाव का मूल्यांकन करने पर सहमत हुए। हम इस बात पर भी सहमत हुए कि इन प्रतिबन्धों को निष्क्रिय करने के किसी प्रयास का पता लगाया जाए और इसे प्रकाश में लाया जाए। इस

बात पर सहमत हुए कि प्रीटोरिया जातीय रगभेदवादी शासन के लिए अन्तर्राष्ट्रीय वित्त प्रणाली के साथ प्रीटोरिया के सबधों के निहितार्थों का अध्ययन करने के लिए विशेषज्ञ अध्ययन दल की आवश्यकता पर विचार किया जाना चाहिए। भावी स्थिति के अनुसार हम आगे कार्रवाई करेंगे जिसमें और अधिक प्रतिबन्ध लगाए जाने भी शामिल है। दक्षिण अफ्रीका पर प्रतिबन्धों से सबधित कार्रवाई कार्यक्रम को केवल ब्रिटेन को छोड़कर राष्ट्रमण्डल के अन्य सभी देशों ने स्वीकार किया है³⁰।”

हम सबने फ्रंटलाइन देशों को राष्ट्रमण्डल की समन्वित सहायता के लिए कार्यक्रम प्रस्तुत किए। मोजाम्बिक को तकनीकी सहायता प्रदान करने के लिए एक विशेष कोष की स्थापना की गई। रगभेद के शिकार और उसके विरोधियों को दी जाने वाली राष्ट्रमण्डल की सहायता में वृद्धि की जाएगी। हम इस बात के लिए सहमत हुए कि दक्षिण अफ्रीका में सेन्सरशिप हटाने के लिए किए जा रहे प्रयासों को उच्च प्राथमिकता दी जाए क्योंकि यह ऐसी सेन्सरशिप है जो दुनिया के लोगों से दक्षिणी अफ्रीका के बारे में सच्चाई को छुपाती है। इन उद्देश्यों की उपलब्धि के लिए तेज गति और मार्ग-निर्देश देने के लिए शिखर सम्मेलन ने विदेश मंत्रियों की एक आठ सदस्यीय समिति का गठन किया। समिति की अध्यक्षता कनाडा द्वारा की जाएगी और इसमें भारत को शामिल किया गया है। वेकूवर में फिजी की घटनाओं की प्रमुख रूप से चर्चा हुई। अधिवेशन

के उदघाटन वक्तव्य में मैंने उस देश में हाल में घटी घटनाओं के कारणों में निहित जातीय स्वरूप और लोकतंत्र को कम महत्व दिए जाने के बारे में अपनी गहरी चिन्ता व्यक्त की। फिजी राष्ट्रमण्डल का सदस्य नहीं रहा। शिखर सम्मेलन में यह निर्णय लिया गया कि राष्ट्रमण्डल में फिजी के पुनः प्रवेश पर तभी विचार किया जाएगा जबकि परिस्थितियों को देखते हुए इसकी आवश्यकता समझी जाए। साथ ही इस सन्दर्भ में इस बात को भी ध्यान में रखा जाएगा कि इस पुनः प्रवेश का आधार उन बुनियादी सिद्धान्तों के अनुरूप हो जो इस संगठन के दिशा निर्देश रहे हैं। हम इस बात पर भी सहमत हुए कि राष्ट्रमण्डल फिजी की समस्याओं के निराकरण में सहयोग करने के लिए सदा तत्पर रहेगा।

वेकूवर में जारी की गई राष्ट्रमण्डल विज्ञप्ति में भारत-श्रीलंका समझौते का जोरदार समर्थन किया गया है। इस समझौते को सर्वोच्च राजनेतृत्व की कार्रवाई कहा गया है। शिखर-सम्मेलन की एक महत्वपूर्ण उपलब्धि थी विश्व व्यापार पर वेकूवर घोषणा जिसके अन्तर्गत सभी महाद्वीपों के विकसित और विकासशील देशों के प्रतिनिधियों को एक मंच पर इकट्ठा करने की व्यवस्था है। इस घोषणा में विश्व में बढ़ते हुए संरक्षणवाद की प्रथा के प्रति अपनी चिन्ता व्यक्त की गई है और संरक्षणवादी उपायों के स्टेण्ड स्टिल और रोल बैक पर पुण्टा-डेल-एस्टेट वचनबद्धताओं को पूरा सम्मान दिए जाने की मांग की गई है। इस घोषणा में यह स्वीकार किया

गया है कि अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार के क्षेत्र में विकासशील देशों की स्थिति अलाभकारी है और इस असमानता को देखते हुए उरुग्वे व्यापार वार्ता में इनके हितों पर विशेष ध्यान दिया जाना चाहिए।

हमने सुदूर शिक्षा अर्थात् ज्ञान को अनौपचारिक शिक्षा प्रणाली के माध्यम से अधिकांश लोगों तक पहुंचाने के लिए नई संचार प्रौद्योगिकियों के प्रयोग को प्रोत्साहित करने के लिए राष्ट्रमण्डल कार्यक्रम शुरू किया। भारत इस पहल में और इससे लाभ उठाने में भी पर्याप्त रूप से सक्षम है।

उनका स्पष्ट मत था कि राष्ट्रमण्डल में प्रतिनिधित्व प्राप्त प्रभुसत्ता सम्पन्न सरकारों के भिन्न-भिन्न दृष्टिकोणों की परिधि में बैकूबर शिखर सम्मेलन में हुई सहमतियों में अन्तर्राष्ट्रीय मामलों में इस संगठन की सक्रियता और उपयोगिता की पुष्टि की गई। प्रतिबंधों के सवाल पर एक विपरीत मत की चिन्ता न करते हुए इस शिखर सम्मेलन ने विश्व में शांति और स्थिरता के मुख्य मसलों के बारे में विश्व मत के अधिकांश भाग को एक साथ मिला दिया। कनाडा की सरकार ने इस सम्मेलन के लिए जिस उल्लेखनीय सावधानी के साथ प्रबंध किए उनकी मैं सराहना करना चाहूंगा। इस सम्मेलन को सफल बनाने में प्रधानमंत्री ब्रियान मुलोनी ने जो महत्वपूर्ण और कल्याणपूर्ण भूमिका निभाई है उसकी भी मैं सराहना करना चाहूंगा³¹।

जहाँ तक दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संगठन (सार्क)

का सबध है भारत ने दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग सगठन की स्थापना के समय मे ही इसको बढाने मे सक्रिय भूमिका निभाई है। पहली दक्षिण एशियाई शिखर बैठक दिसम्बर १९८५ मे ढाका मे हुई थी जिसमे दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग सगठन की स्थापना की गई। सार्क का दूसरा शिखर सम्मेलन १५-१७ नवम्बर, १९८६ को बगलूर मे आयोजित किया गया। इस शिखर सम्मेलन मे बगलूर घोषणा सयुक्त प्रेस विज्ञप्ति तथा मन्त्रिपरिषद के दूसरे अधिवेशन की रिपोर्ट को स्वीकार किया गया। विदेश मन्त्रियो ने राष्ट्राध्यक्षो अथवा शासनाध्यक्षो की उपस्थिति मे सार्क सचिवालय की स्थापना करने सबधी एक समझौता-ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए। सार्क सचिवालय को १६ जनवरी १९८७ को काठमाडू नेपाल मे शुरू किया गया³²।

भारत ने नवम्बर मे काठमाडू मे आयोजित तीसरे सार्क शिखर सम्मेलन मे सार्क की अध्यक्षता नेपाल को सौप दी। सार्क द्वारा आयोजित लगभग १०० गतिविधियो मे से ४५ की मेजबानी भारत ने की। तीसरी शिखर बैठक मे महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए जिनका भविष्य मे सार्क के कार्यों पर प्रभाव पड़ेगा। आतकवाद समाप्त करने के लिए एक क्षेत्रीय समझौते पर हस्ताक्षर किए गए। छह अगस्त १९८८ को भारत ने आतकवाद समाप्ति पर हुए सार्क समझौते की पुष्टि की। एक खाद्य सुरक्षा भण्डार की स्थापना का समझौता हुआ, जिसके अतर्गत आपातकाल मे सदस्य देश खाद्य पदार्थ ले सकेगे। अन्य महत्वपूर्ण निर्णय थे- “पर्यावरण पर एक अध्ययन आरम्भ

करना सार्क देशों में व्यक्ति से व्यक्ति के बीच सम्पर्क बढ़ाने के साधनों का विकास करना और योजना के विभिन्न पहलुओं का अध्ययन करना। भारत और बंगला देश में क्रमशः एक मौसम विज्ञान केन्द्र और एक कृषि सूचना केन्द्र स्थापित करने पर समझौता हुआ।” भारत ने १९८८-८९ में सार्क कार्यों के लिए १७५ लाख रुपये के अंशदान की घोषणा की।

प्रधानमन्त्री राजीव गांधी ने चौथे सार्क शिखर सम्मेलन के संबध में २९ से ३१ दिसम्बर १९८८ तक इस्लामाबाद की यात्रा की। शिखर सम्मेलन में १९८८ के दौरान सगठन के कार्यों की पूर्ण समीक्षा की गई। शिखर सम्मेलन में निम्नलिखित प्रमुख निर्णय लिए गए -

- शिक्षा को सहयोग क्षेत्र में शामिल किया जाना।
- प्रत्येक सदस्य देश द्वारा शताब्दी के अंत तक के लिए प्रमुख हित क्षेत्रों जैसे कि खाद्य, कपड़ा मकान शिक्षा प्राथमिक चिकित्सा देखभाल जनसंख्या नियोजन और पर्यावरण की सुरक्षा के लिए निर्धारित विकास लक्ष्यों की सफलता के आधार पर सार्क २००० आधारभूत आवश्यकता सदृश नाम की एक क्षेत्रीय सदृश योजना तैयार करना।
- मानव संसाधन विकास हेतु एक केन्द्र की स्थापना के एक प्रस्ताव की जांच।
- समय समय पर दक्षिण एशियाई उत्सव आयोजित किए जाएंगे ³³।

श्री राजीव गांधी ने सार्क को मजबूती प्रदान करने की आवश्यकता पर जोर देते हुए कहा- “दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग एसोसिएशन का दूसरा शिखर सम्मेलन बगलौर में १६ और १७ नवम्बर को आयोजित हुआ। यह सम्मेलन विश्व के सबसे बड़े और अद्यतन क्षेत्रीय एसोसिएशन के विकास का एक स्पष्ट और महत्वपूर्ण पड़ाव कहा जा सकता है।” कार्तिक-पूणिर्मा और पैगम्बर मोहम्मद और गुरु नानक जयन्ती के पवित्र अवसर पर इसका उद्घाटन हुआ और इसमें ऐसी समस्याओं को जो हम सबकी समस्याएँ हैं मिलजुलकर दूर करके मानवमात्र की भलाई करने में हमारे विश्वास की पुनः पुष्टि हुई। बंगलादेश के नेतृत्व में दक्षिण सहयोग संगठन ने अपने अस्तित्व के पहले वर्ष में विचार के स्तर से आगे बढ़कर एक मूर्त रूप ग्रहण किया है। अपने नेतृत्व काल में एक ओर जहाँ हम पारस्परिक क्रियाकलापों को नई-नई दिशाएँ देने की और अपने सहयोग को नए आयाम प्रदान करने की कोशिश करेंगे वही हमारी यह भी कोशिश होगी कि अब तक हमने जो कुछ प्राप्त किया है, उसकी स्थिति मजबूत करें।

हमने सहयोग के जो क्षेत्र तय किए हैं उनका हमारे ज्यादातर लोगों के जीवन और उनके कल्याण पर सीधा असर पड़ता है। इसमें कृषि वन विकास मौसम विज्ञान, प्राकृतिक विपदाओं से बचने का प्रयास, समूचे नारी समाज की उन्नति और बाल जीवन की रक्षा तथा विकास शामिल हैं। हमने औषधि द्रव्यों का अवैध व्यापार तथा

आतंकवाद की दोहरी और अक्सर एक दूसरे से जुड़ी हुई समस्या का मिलकर मुकाबला करने का भी सकल्प किया है। हमने अपने इस सहयोग को एक सस्थागत रूप देने के उद्देश्य से काठमांडू में एक स्थाई सचिवालय स्थापित करने का भी फैसला किया है, जो हमारे कार्यक्रमों पर निगाह रखेगा और उनके कार्यान्वयन में तालमेल स्थापित करेगा। हम अपने प्रयासों में मुख्य जोर इस बात पर दे रहे हैं कि सभी बाधाओं को पार करके हर स्तर पर जन-जन के बीच सम्पर्कों में वृद्धि की जाये तथा एक दूसरे के प्रति हमारे ज्ञान में जो अन्तर हो उसे समाप्त किया जाये।

नन्दी हिल्स के नेहरू निलय में अपने अवकाश के क्षणों में मैंने अपने साथियों के साथ मिलकर उन अन्य क्षेत्रों को भी तय करने के लिए बातचीत की जिससे जनता की भागीदारी और पारस्परिक कार्यकलाप को और अधिक मजबूत करने के लिए सहयोग करना सम्भव हो सकता हो। इनमें रेडियो और टेलीविजन कार्यक्रम पर्यटन का आदान-प्रदान तथा विद्वानों की आवा-जाही क्षेत्रीय प्रलेखन केन्द्र की स्थापना तथा पड़ोसी देशों में कृषि और वन विकास के विस्तार के कार्यक्रमों द्वारा एक सगठित स्वयंसेवकों का आदान-प्रदान कार्यक्रम भी शामिल है।

उन्होंने दृढ़ता पूर्वक कहा मेरा यह विश्वास है कि इस प्रकार के जन-जन के सम्पर्क से न सिर्फ सरकारों के पारस्परिक प्रयासों को बल मिलेगा, बल्कि सहयोग की क्षमताओं के अनछुए दोनों क्षेत्रों

का भी पता लगेगा। इससे भी महत्वपूर्ण बात यह है कि इस प्रकार के सम्पर्कों से हम एक दूसरे की महत्वाकांक्षाओं को, एक दूसरे की जरूरतों को अच्छी तरह समझ सकेंगे और इस बात को भी अच्छी तरह समझ सकेंगे कि हमारी अर्थव्यवस्था में कौन किसका पूरक हो सकता है। इससे हमारी मित्रता और हमारा पारस्परिक विश्वास मजबूत होगा जिससे सामूहिक आत्मनिर्भरता और पारस्परिक निर्भरता बढ़ाने के लिए वातावरण बनेगा और जब ऐसा होगा तो क्षेत्रीय शांति और स्थायित्व में हमारी सामूहिक जिम्मेदारी अनिवार्यतः बढ़ेगी। शायद यही हमारे लिए औपनिवेशिक विरासत में प्राप्त पुराने ढर्रे को तोड़ने का सबसे निश्चित तरीका है और पारस्परिक सन्देह और विद्वेष निरकुशता को दूर करके क्षेत्रीय सहयोग का एक स्थाई ढांचा तैयार करने का भी तरीका है।

दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संगठन के दूसरे शिखर सम्मेलन में स्वीकृत बगलौर घोषणा और अन्य दस्तावेजों ने इन समान लक्ष्यों को प्राप्त करने की दिशा में महत्वपूर्ण योगदान दिया। दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संगठन एक राजनैतिक संगठन नहीं है। द्विपक्षीय विषय इसकी परिधि से बाहर है।

बगलौर शिखर सम्मेलन में अन्य नेताओं के साथ द्विपक्षीय, क्षेत्रीय तथा अन्तर्राष्ट्रीय मुद्दों पर विचारों के आदान-प्रदान के लिए महत्वपूर्ण अवसर प्राप्त हुआ। मेरी बंगलादेश के राष्ट्रपति, भूटान नरेश मालदीव के राष्ट्रपति, नेपाल नरेश, पाकिस्तान के प्रधानमंत्री

तथा श्रीलंका के राष्ट्रपति के साथ बैठके हुई। सरकार इस सप्ताह के बाद में इन द्विपक्षीय बैठकों के सबंध में एक अलग वक्तव्य देगी। उन्होंने उद्घाटित किया।

हम उससे भी आगे गए यह सोचकर कि कुछ अन्य विषय भी हो सकते हैं जिनकी ओर हम देख सकते हैं, और यदि बगलौर शिखर सम्मेलन तक वे तैयार हो गये तो हम उन्हें स्वीकार करेंगे। इस तरह के दो विषय तैयार थे और हमने उन्हें स्वीकार कर लिया। ये दो क्षेत्र उन दो संस्थाओं के बारे में थे जिनकी स्थापना की जानी है। एक संस्थान भारत में स्थापित किया जाएगा यह मौसम विज्ञान के सबंध में है, और दूसरा संस्थान जो कृषि संबंधी जानकारी के बारे में है बंगला देश में स्थापित किया जाएगा। इसी तरह इन क्षेत्रों पर हम इस वर्ष के दौरान नजर रखेंगे। वे विशेषज्ञों के स्तर पर आरम्भ होंगे और मन्त्रियों के स्तर तक जायेंगे। और काठमाण्डू शिखर सम्मेलन के समय तक यदि उनमें से कोई तैयार हो जाता है तो उन्हें उस शिखर सम्मेलन में अपनाया जा सकेगा और यदि हम महसूस करते हैं कि हमें उन क्षेत्रों को अपनाना चाहिए तो हम उन्हें अपना लेंगे। इस समय व्यापार का प्रश्न सार्क की परिधि के अन्तर्गत नहीं आता है। सचिवालय के लिए वित्त व्यवस्था करने के लिए एक सूत्र तैयार कर लिया गया है। यह एक जटिल और विस्तृत सूत्र है। हमने इन सूत्रों के आधार पर यह निश्चय भी किया है कि हम अन्य वित्तीय संस्थाओं की, जो भी सामने आयेगी वित्त व्यवस्था करेंगे और

जैसे ही अन्य सस्थानों या कार्यों के बारे में निर्णय किया जाता है प्रत्येक क्षेत्र के लिए एक विशेष सूत्र एक विशेष देश की एक विशेष विषय पर दिलचस्पी के आधार पर तैयार किया जाएगा। क्योंकि एक विषय हमारे लिए महत्वपूर्ण हो सकता है लेकिन वह विषय मालदीव या श्रीलंका जैसे देशों के लिए महत्वपूर्ण नहीं हो सकता। अतः इस बात को ध्यान में रखते हुए हम उसी के अनुसार वित्त व्यवस्था का संतुलन करेंगे। आतंकवाद की समस्या से निपटने में एक मुख्य अड़चन यह थी कि इसकी परिभाषा किस तरह की जाए। और इसी कारण जिस समय हमने नशीले द्रव्यों तथा आतंकवाद को एक साथ उठाया तो हमने नशीले द्रव्यों के विषय पर काफी प्रगति की, लेकिन आतंकवाद के विषय पर कम प्रगति हो पाई, क्योंकि इसकी परिभाषा की समस्या एक बाधा थी। लेकिन इस विषय पर अभी भी विचार किया जा रहा है और हम इस पर कार्य कर रहे हैं। मुझे आशा है कि कुछ न कुछ परिणाम अवश्य निकलेगा। मेरा विचार है इसमें वे सभी बहुपक्षीय मामले शामिल हैं, जिन्हें वहां उठाया गया था³⁴ ।

राजीव गांधी का स्पष्ट मत था कि कोई भी हिंसा जो घृणा को बढ़ावा देती है बुद्ध और महात्मा के विचारों के अनुरूप नहीं हो सकती। इसी का पिष्टपेषण करने के लिए उन्होंने विभिन्न अंतर्राष्ट्रीय संगमनों पर भारतीय विदेश नीति की मूल भावना का दिग्दर्शन विश्व के देशों को कराया था।

पाद टिप्पणिया

- 1 Mani Shankar Ayayer Rajiv s Footprints one year in Parliament Page 86
- 2 २०-४-१९८८ की लोकसभा की कार्यवाही से उद्धृत
- 3 २०-४-१९८८ की लोकसभा की कार्यवाही से उद्धृत
- 4 २०-४ १९८८ की लोकसभा की कार्यवाही
- 5 २० ४-१९८८ की लोकसभा की कार्यवाही
- 6 २०-४ १९८८ की लोकसभा की कार्यवाही
- 7 २०-४ १९८८ की लोकसभा की कार्यवाही
- 8 २० ४ १९८८ की लोकसभा की कार्यवाही
- 9 २० ४ १९८८ की लोकसभा की कार्यवाही
- 10 २० ४ १९८८ की लोकसभा की कार्यवाही
- 11 २० ४ १९८८ की लोकसभा की कार्यवाही
- 12 राजीव गाँधी की विदेश निति पर श्री के०आर० नारायणन द्वारा लिखा गया लेख - राजीव गांधी एव
संसद सम्पादक सी०के०जैन महासचिव लोकसभा पृष्ठ-२७
- 13 राजीव गाँधी की विदेश निति पर श्री के०आर० नारायणन द्वारा लिखा गया लेख - राजीव गांधी एव
संसद सम्पादक सी०के०जैन महासचिव लोकसभा पृष्ठ-२७
- 14 Bhawani Sen Gupta Rajiv Gandhi in political study Page 112
- 15 Times of India 7 8 1986
- 16 Harish Chandra Rajiv Gandhi Many Facts Page 136
- 17 Indian Express 23 1 1988
- 18 Hindustan Times 10 6 1988
- 19 Prasad Bimal India s Foreign Policy Studies in Continuity and Change
Page 229
- 20 Patel S R Foreign Policy of India Page 112
- 21 The States man 6th October 1987
- 22 Jain B M South Asian India and United States (Jaipur RB SA 1987)
Page 119
- 23 Mani Shankar Ayayer Rajiv s Footprints one year in Parliament Page 99
- 24 भास्त-१९८८ - सूचना एव प्रकाशन विभाग नई दिल्ली भास्त सरकार ।

- 25 Harish Chandra Rajiv Gandhi Many Facts Page 116
- 26 Somrajan C N ed Formulation and practice of India s Foreign Policy Page 232
- 27 Indian Express – 23 1 1985
- 28 Kacharoo J L India and the Commonwealth Page 136
- 29 The Statesman 18 10 1986
- 30 M C Shah Rajiv Gandhi in Parliament Page 236
- 31 M C Shah Rajiv Gandhi in Parliament Page 236
- 32 भारत १९८८ सूचना एवं प्रकाशन विभाग नई दिल्ली भारत सरकार ।
- 33 Times of India – 1 1 1989
- 34 भारतीय विदेश नीति पर लोकसभा में २० ४ १९८८ को दिया गया वक्तव्य लोकसभा कार्यवाही से ।

अध्याय - ३

श्री राजीव गांधी के प्रधानमंत्रित्व काल में भारत के पड़ोसी देशों से सम्बन्ध के सदर्भ में भारतीय विदेश नीति की पृष्ठभूमि तथा राजीव गांधी के विचारों का विशद विवेचन करने के पश्चात् भारत - चीन सम्बन्धों की दशा एवं दिशा पर इस अध्याय में प्रकाश डालने का प्रयास किया जायेगा । स्वतन्त्रता के बाद भारत और चीन के सम्बन्धों की कहानी भारतीय नेताओं की आदर्शवादिता, स्वप्नदर्शिता और अदूरदर्शिता तथा चीनी विश्वासघात की कहानी है।¹ भारत की चीन सम्बन्धी नीति निम्नलिखित तत्त्वों पर आधारित रही है - **प्रथम** यह विश्वास था कि प्राचीन काल से ही भारत और चीन के मध्य घनिष्ठ सांस्कृतिक और व्यापारिक सम्बन्ध विद्यमान थे । बौद्ध धर्म की जन्मभूमि भारत होने के कारण भारत चीन का एक प्रकार से धर्मगुरु है यह धारणा थी कि और चीन उसका सम्मान करेगा । **दूसरे** चीन को अपनी स्वतन्त्रता और अखण्डता की रक्षा के लिये पाश्चात्य और जापानी साम्राज्यवाद के विरुद्ध एक भीषण और दीर्घ संघर्ष करना पड़ा था । इससे भारत में उसके प्रति गहरी सहानुभूति उत्पन्न हो गयी थी । **तीसरे**, यह माना जाता था कि चीन ने भारत पर कभी आक्रमण नहीं किया है और न कभी करेगा और वह कभी आक्रमण करना चाहेगा तो उत्तर की दुर्गम हिमालय पर्वतमाला उसे कभी ऐसा नहीं करने देगी । **चौथे** भारतीय विदेश नीति के प्रमुख शिल्पी पण्डित नेहरू और उनके विश्वस्त परामर्शदाता रक्षामन्त्री कृष्ण मेनन चीन विशेषतः साम्यवादी चीन के प्रति गहरी सहानुभूति

रखते थे और चीन के साथ मैत्री को असलगता की नीति की आधारशिला मानते थे ।

भारत और चीन न केवल पड़ोसी राष्ट्र हैं। और इतिहास साक्षी है उनमें प्राचीन काल से ही सांस्कृतिक सम्बन्ध चले आ रहे थे । जब दोनों विदेशी आधिपत्य में चले गये तो इनके सम्बन्ध टूट गये । १९४७ में भारत स्वतन्त्र हुआ और उधर १९४९ में कोमिन्ताग सरकार के पतन के बाद चीन साम्यवादी सरकार की स्थापना हुई । साम्यवादी शासन की स्थापना के बाद ही यह महसूस किया गया कि चीन के साथ भारत के मैत्रीपूर्ण सम्बन्धों की स्थापना का मार्ग अनेक कठिनाइयों से भरा हुआ है ^२।

जहाँ तक भारत चीन मैत्री के मार्ग में कठिनाइयों का प्रश्न है इसमें निम्नलिखित कठिनाइयाँ महसूस की गई - प्रथम, भारत की राजनीतिक आर्थिक एवं सामाजिक व्यवस्थाएँ तथा संस्थाएँ चीनी साम्यवादी प्रणाली और उसकी संस्थाओं से भिन्न हैं। द्वितीय, भारत की विदेश नीति शान्तिपूर्ण सह-अस्तित्व एवं पंचशील के सिद्धान्तों पर आधारित है। भारत की नीति साम्राज्यवादी या विस्तारवादी नहीं है। भारत अपनी शक्ति से किसी को आतंकित नहीं करना चाहता । दूसरी ओर साम्यवादी चीन के इरादे आक्रामक साम्राज्यवादी, और विस्तारवादी हैं। इसकी इच्छाएँ एशिया में एकाधिकार की हैं। और उसके साधन तोड़-फोड़ आतंक क्रान्ति कपट और हिंसा हैं। माओ नीति शक्ति को बन्दूक की नली से प्राप्त

करती है। तृतीय एशिया में भारत जनसंख्या शक्ति और प्राकृतिक साधनों में चीन का प्रतिद्वन्दी बनने की क्षमता रखता है। चीन को यह पसन्द नहीं है कि भारत उसका प्रतिद्वन्दी बने। यह दुनिया को यह बताना चाहता है कि भारत एशिया का एक कमजोर देश है। और उसकी स्थिति एक दूसरे दर्जे की है। भारत का शक्ति के रूप में उभरना उसका आर्थिक दृष्टि से सम्पन्न होना और राजनीतिक सुदृढता प्राप्त करना चीन के लिए ईर्ष्या, द्वेष और वैमनस्य का कारण है³।

जहाँ तक भारत चीन सम्बन्धों के इतिहास का प्रश्न है इसे सुविधा की दृष्टि से तीन भागों में बाटा जा सकता है-

- १ प्रमोद काल
- २ टकराव और तनाव काल
- ३ सवाद काल

सर्वप्रथम हम प्रमोद काल (१९४९-५७) को लेते हैं । चीन के प्रति भारत का दृष्टिकोण प्रारम्भ से ही मित्रतापूर्ण रहा है। हमारे स्वतंत्रता संग्राम के दिनों से ही नेहरू भारत और चीन की मित्रता पर बल देते रहे थे। सन १९४२ में च्यांग काई शेक ने भारत की यात्रा की थी, जिससे भारत में चीन के जापानी साम्राज्यवादी के विरुद्ध संघर्ष के प्रति सहानुभूति की एक लहर फैल गई । चीन में साम्यवादी दल की विजय -चीन सम्बन्ध और भी घनिष्ठ हो गये । अक्टूबर १९४९ में चीन में साम्यवादी क्रान्ति का भारत ने

स्वागत किया। गैर-साम्यवादी देशों में भारत ही पहला देश था जिसने चीन को राजनयिक मान्यता प्रदान की। अमेरिका की नाराजगी की कीमत पर भी भारत ने कोरिया युद्ध में चीन का समर्थन किया था। सितम्बर १९५० में सेनफ्रांसिस्को में ४९ राष्ट्रों के साथ होने वाली जापानी सन्धि में भारत इसलिए शामिल नहीं हुआ क्योंकि चीन को उसमें शामिल नहीं किया गया था। संयुक्त राष्ट्र सभ में चीन को मान्यता दिलाने का भारत ने भरसक प्रयत्न किया। भारत ने उस समय भी चीन को मान्यता दिलाने का प्रयास किया जब चीन का भारत के प्रति दृष्टि कोण शत्रुता पूर्ण था। भारत ने अमेरिका की उन नीतियों की सर्वदा आलोचना की जो चीन को अन्तर्राष्ट्रीय सम्मेलनों या संस्थाओं में उचित स्थान दिलाने में बाधा प्रस्तुत करती थी।

सन १९५४-५७ का काल भारत चीन सम्बन्धों में प्रमोद काल कहलाता है। २९ जून, १९५४ को दोनों राष्ट्रों के मध्य एक ८ वर्षीय व्यापारिक समझौता हुआ जिसके अन्तर्गत भारत ने तिब्बत से अपने अतिरिक्त देशीय अधिकारों को चीन को सौंप दिया। इस व्यापारिक समझौते की प्रस्तावना में ही पंचशील के सिद्धान्तों पर जब चीन के तत्कालीन प्रधानमंत्री चाऊ एन लाई भारत आये तो संयुक्त विज्ञप्ति में पंचशील के सिद्धान्तों पर बल दिया गया। अक्टूबर १९५४ में पण्डित नेहरू ने भी चीन की यात्रा की। अप्रैल १९५५ में बाण्डुंग सम्मेलन में नेहरू और चाऊ एन लाई ने पूर्ण सहयोग के साथ कार्य

किया। बाद में गोवा के प्रश्न पर भी चीन ने भारत का साथ दिया और क्यूमाये और मात्सू टापुओं पर भारत ने चीन का समर्थन किया। पामर के शब्दों में साम्यवादी चीन के प्रति नेहरू और उनके सहयोगियों का दृष्टिकोण स्पष्ट रूप से तुष्टिकारी था। विन्सैड शौयब के अनुसार चीनियों के साथ मैत्रीपूर्ण सम्बन्ध कायम करने का जितना प्रयास नेहरू ने किया सम्भवतः विश्व में उतना किसी ने भी नहीं किया। स्वतंत्र भारत में हिन्दी चीनी भाई-भाई का नारा बहुत लोकप्रिय रहा⁴।

अब हम आते हैं टकराव और तनाव काल (१९५७-१९७८) पर पचशील और बाण्डुंग सम्मेलन को भारतीय कूटनीति की महान सफलताएँ माना गया था परन्तु वस्तुतः वे भारतीय कूटनीति की पराजय सिद्ध हुए। तथ्य तो यह है कि भारत की चीन सम्बन्धी नीति जिन धारणाओं पर आधारित थी वे धारणाएँ ही भ्रान्तिपूर्ण सिद्ध हुईं। भारत और चीन के प्राचीन सम्बन्धों की धनिष्ठता को अत्यधिक बढ़ा चढ़ाकर देखा गया था। साम्राज्यवाद के विरुद्ध उसके संघर्ष के प्रति सहानुभूति के प्रवाह में बहकर यह भुला दिया गया था कि चीनी लोग प्राचीन काल से ही चीन को विश्व सभ्यता का केन्द्र मानते आये हैं और एक प्रसारवादी नीति में विश्वास करते रहे हैं। भारत पर उनके भूतकाल में आक्रमण न करने का कारण उनकी शान्तिप्रियता नहीं वरन् हिमालय की दुर्गम पर्वतमालाएँ थीं। परन्तु २०वीं शताब्दी में एक ओर तो विज्ञान की प्रगति ने उनकी अगमता को काफी कम

कर दिया और दूसरी ओर तिब्बत को चीन को सौंप देने की गलती कर भारत ने चीन के हमले को सरल बना दिया^१। इसके अतिरिक्त, भारतीय विदेश नीति के निर्माता यह भूल गये कि द्वितीय विश्व युद्ध के पश्चात् एशिया और अफ्रिका के जागरण से उत्पन्न हुई परिस्थितियों में भारत और चीन के मध्य एशिया और अफ्रीका विशेषतः दक्षिणी पूर्वी एशिया के नेतृत्व के लिए संघर्ष होना अनिवार्य ही था।

जहां तक तिब्बत समस्या का प्रश्न है, तिब्बत भारत का पड़ोसी राज्य है। इसके उत्तर में चीनी सिक्काग स्थित है। भारत को अंग्रेजों से तिब्बत के सम्बन्ध में निम्न अधिकार उत्तराधिकार में मिले -
अ लहासा में एक भारतीय राजनीतिक एजेंट रख सकना
ब ग्यान्तसे गगटोक और यातुग में व्यापारिक एजेंसी स्थापित कर सकना
स ग्यान्तसे के व्यापार मार्ग पर डाक एवं तार के दफ्तर रखना तथा
द ग्यान्तसे में एक छोटा सा सैनिक दस्ता रखना जो व्यापार मार्ग की रक्षा कर सके।

चीन सदियों से तिब्बत पर अपना अधिकार जताता आ रहा था। चीन की नयी साम्यवादी सरकार ने स्थापना के साथ ही तिब्बत पर अपना अधिकार घोषित कर दिया और तिब्बत को अपने राज्य का अंग बताया। १ जनवरी १९५० को चीन सरकार ने तिब्बत को स्वतंत्र कराने की घोषणा कर दी^२। भारत सरकार ने परिवर्तित परिस्थिति में चीन से वार्ता कर लेना ही उचित समझा। दिसम्बर

१९५३ में यह वार्ता प्रारम्भ हुई। पचशील के आधार पर एक समझौता दोनों देशों के बीच कर लिया गया। इसके अन्तर्गत भारत को तिब्बत में व्यापार एजेसिया स्थापित करने का और तीर्थ यात्राओं तथा अन्य नागरिकों द्वारा तिब्बत की यात्रा कर सकना मुख्य रूप से निश्चित किया गया। भारत सरकार यातुग एव ग्यान्तसे अपने सैनिक हटाने के लिए सहमत हो गयी। तिब्बत पर चीन की सार्वभौमिकता स्वीकार करने की भारतीय नीति की ससद में कटु आलोचना हुई जबकि प्रधानमंत्री नेहरू ने इसे पूर्णतया उचित ठहराया। उनके मतानुसार तिब्बत पर पहले से ही चीन का सार्वभौमिक अधिकार था और ब्रिटिश शासन तक ने इसे चुनौती नहीं दी थी। जब तक चीन दुर्बल और अविकसित था तब तक उसने अधिकार का उपयोग नहीं किया पर एक नयी महाशक्ति के रूप में उभरने के पश्चात् वह कैसे किसी अन्य देश भारत की सेनाएँ तिब्बत में रखना सहन कर सकता था। अतएव सम्मानपूर्वक हट जाना ही उचित था।

२५ जून १९५४ को चीन के प्रधानमंत्री जेनेवा से पीकिंग जाते समय भारत पधारे। भारत और चीन के प्रधानमंत्रियों ने अपनी संयुक्त घोषणा में पचशील के प्रति दुबारा अपना विश्वास प्रकट किया⁷।

१८ अक्टूबर, १९५४ को नेहरू पीकिंग की यात्रा पर गये। इसके बाद २८ नवम्बर, १९५६ से १० दिसम्बर, १९५६ तक चाऊ एन लाई ने भारत की यात्रा की। उन्होंने भारतीय ससद को सम्बोधित किया तथा बार बार भारत एव चीन की मित्रता का उल्लेख किया⁸। पुनः एक

बार चीन के प्रधानमन्त्री ने पचशील मे विश्वास प्रकट करने के साथ अन्तर्राष्ट्रीय समस्याओ के समाधान के लिए शक्ति प्रयोग करने की निन्दा की। इस प्रकार १९५६ तक भारत एव चीन के बीच उत्तम राजनीतिक सम्बन्ध थे। इसी वर्ष तिब्बत के खम्पा क्षेत्र मे बड़े पैमाने पर चीनी शासन के विरुद्ध विद्रोह हो गया जो १९५९ तक चलता रहा। इस विद्रोह को दलाईलामा ने ८ व्यक्तियों के दल के साथ भारत मे राजनीतिक शरण ली। इसके पश्चात एक बड़ी संख्या मे तिब्बती शरणार्थी भारत आये। इन सबको मसूरी के पास बसा दिया। चीन की सरकार ने इसे शत्रुतापूर्ण कार्य बताया। वस्तुतः इसी समय से भारत और चीन के सम्बन्ध कुछ कुछ बिगड़ना प्रारम्भ हो गये।

जहा तक भारत चीन सीमा विवाद का सबध है अब तक भारत और चीन के मध्य सीमा को लेकर कटु विवाद प्रारम्भ हो चुका था । १९५०-५१ मे साम्यवादी चीन के नक्शे मे भारत के एक बड़े भाग को चीन का अंग दिखाया गया था। जब भारत सरकार ने चीन का ध्यान इस ओर दिलाया तो यह कहकर मामला टाल दिया गया कि ये नक्शे कोमिन्ताग सरकार के पुराने नक्शे है। चीन की नयी सरकार को इतना समय नहीं मिला है कि वह इनमे उपयुक्त संशोधन कर सके। समय मिलते ही इन नक्शो को ठीक कर दिया जाएगा। जून १९५४ मे भारत एव चीन के मध्य तिब्बत को लेकर समझौता हुआ तब वार्ता हेतु चुने गये विषयो मे सीमा विवाद का कही प्रश्न ही न था। भारत मे यही समझा गया कि समस्त विवाद

हल हो चुके हैं। परन्तु शीघ्र ही १७ जुलाई १९५४ को चीन ने एक पत्र द्वारा भारत पर आरोप लगाया कि भारतीय सेना ने बूजे नामक चीनी स्थान पर अवैध अधिकार कर लिया है। बूजे भारत में बड़ी होती के नाम से प्रसिद्ध था। चीन के विरोध पत्र का उत्तर देते हुए भारत सरकार ने लिख दिया कि यह स्थान भारतीय प्रदेश में है और यहाँ भारतीय सीमा सुरक्षा सेना की चौकी है। १९५४ से ही चीन ने सीमा के विभिन्न भारतीय प्रदेशों में अपने सैनिक दस्ते और टुकड़ियाँ भेजनी आरम्भ की। २३ जनवरी १९५९ के पत्र में चीनी सरकार ने लिखा कि भारत और चीन के मध्य कभी भी सीमाओं का निर्धारण नहीं हुआ है और तथाकथित सीमाएँ चीन के विरुद्ध किये गये साम्राज्यवादी षडयन्त्र मात्र हैं^९।

इधर अक्टूबर १९६२ में भारत पर साम्यवादी चीन ने बड़े पैमाने पर आक्रमण कर दिया। इससे पूर्व १२ जुलाई १९६२ को लद्दाख में गलवान नदी की घाटी की भारतीय चौकी को चीनियों ने अपने घेरे में ले लिया। ८ सितम्बर को चीनी सेनाओं ने मैकमोहन रेखा पार करके भारतीय सीमा में प्रवेश किया। २० अक्टूबर १९६२ को चीनी सेनाओं ने उत्तर पूर्वी सीमान्त तथा लद्दाख के मोर्चे पर एक साथ बड़े पैमाने पर आक्रमण किया^{१०}। टिड्डी दल की भाँति वे भारतीय चौकियों पर टूट पड़े। २१ नवम्बर १९६२ को चीन ने एकाएक अपनी ओर से एकपक्षीय युद्ध विराम की घोषणा कर दी और युद्ध समाप्त हो गया^{११}। चीन ने जीते हुए भारतीय प्रदेशों को भी

खाली करना प्रारम्भ कर दिया और भारत के कुछ सैनिक साजो-समान को भी वापस कर दिया।

जहा तक चीन द्वारा भारत पर आक्रमण के कारणों का सम्बन्ध है डा वी पी दत्त के अनुसार चीन के भारत पर आक्रमण के दो उद्देश्य थे अ अपनी शक्ति का प्रदर्शन करना ब भारत की निर्बलता को प्रदर्शित करना तथा स उसे अन्तर्राष्ट्रीय क्षेत्र में अपमानित करना¹² ।

संक्षेप में चीन द्वारा भारत पर आक्रमण के निम्नलिखित कारण थे-

- १ चीन विस्तारवाद की नीति का प्रदर्शन करना चाहता था।
- २ चीन की इच्छा थी कि वह भारत को लोकतन्त्रात्मक पद्धति से उन्नति करने में सफल न होने दे उस पर युद्ध का बोझ डाल दे।
- ३ तिब्बत के प्रति भारतीय नीति से चीन नाराज था। दलाईलामा को शरण देने के कारण वह रुष्ट था।
- ४ उसका उद्देश्य भारत को बदनाम करना था एशिया में चीन को सर्वोच्च शक्ति बनने की आकांक्षा तथा भारत को नीचा दिखाने की इच्छा थी।

भारत पर चीन का आक्रमण बड़े सुविचारित और क्रूर विचारों से किया गया इसके निम्न उद्देश्य थे-हिमालय में पीकिंग की शक्ति और अधिकार को स्थापित करना, भारत की प्रतिष्ठा को धक्का पहुंचाना नेहरू को नीचा दिखाना चीन को एशिया में बड़ी वास्तविक शक्ति सिद्ध करना, चीनी भाइयों के स्थान पर शक्तियों

को यह सूचना देना कि दुनिया में तब तक शान्ति नहीं रह सकती जब तक कि चीन को महाशक्ति के रूप में स्वीकार न किया जाये और उससे इस तरह का व्यवहार न हो¹³।

चीन को यह आशा थी कि युद्ध की स्थिति में सोवियत साम्यवादी भाई उसका साथ देगा और भारत में आन्तरिक दंगे होंगे। परन्तु चीन की ये कामनाएँ सफल नहीं हो सकीं। अमरीका, ब्रिटेन और उसके बाद फ्रांस पश्चिमी जर्मनी आस्ट्रेलिया और कनाडा ने तेजी से भारत को सैनिक सहायता दी सोवियत संघ प्रायः तटस्थ रहा और उसने चीन पर युद्ध बन्द करने को दबाव डाला। मिश्र यूगोस्लाविया और घाना जैसे गुटनिरपेक्ष राज्यों का दृष्टिकोण बड़ा ही निराशाजनक रहा। आक्रमण की निन्दा करना तो दूर उन्होंने आक्रमण के समय चुप्पी ठान ली। पाकिस्तान ने चीनी आक्रमण का लाभ उठाते हुए भारत की निन्दा करना शुरू कर दिया। पाकिस्तान ने चीनी आक्रमण को सामान्य स्थानीय मामले का रूप देने का प्रयास किया।

जहाँ तक चीन के एक पक्षीय युद्ध विराम के कारणों का सम्बन्ध है, चीन ने एक पक्षीय युद्ध विराम की घोषणा करके सबको स्तब्ध कर दिया। युद्ध बन्द कर देने के कारणों के सम्बन्ध में बड़ा मतभेद है। फिर भी मोटे तौर से निम्नलिखित कारण हो सकते हैं-

- १ चीन अन्तर्राष्ट्रीय क्षेत्र में अपनी सद्भावना प्रकट करना चाहता था कि चीन युद्ध प्रेमी नहीं बल्कि उसे बाध्य होकर लड़ाई लड़नी पड़ी

थी।

- २ चीन को अपने उद्देश्यों की प्राप्ति में सफलता मिल गयी थी। सैनिक दृष्टि से चीन ने भारत को हराकर भारतीय प्रतिष्ठा को धूल में मिला दिया और भारत की निर्बलता जग प्रसिद्ध हो गयी थी।
- ३ सर्दी बढ़ जाने से सैनिकों को सामान पहुँचाने के लम्बे मार्ग पार करना कठिन होता जा रहा था जिससे चीन अधिक समय तक युद्ध जारी नहीं रख सकता था।
- ४ भारत को अमेरिका और ब्रिटेन से भारी मात्रा में सैनिक सहायता तेजी से प्राप्त होने लगी थी।
- ५ सोवियत संघ चीन के इस आक्रमण को उचित नहीं समझता था।
- ६ चीन इस तथ्य से परिचित था कि भारत पर प्रभुत्व जमाना आसान नहीं है। वह केवल अपनी शक्ति प्रदर्शित करके एशिया में अपने नेतृत्व का दावा प्रमाणित करना चाहता था।

अब हम लेते हैं भारत की पराजय के कारणों को । इस युद्ध में भारत की पराजय के निम्नलिखित कारण थे - **अ** भौगोलिक स्थिति चीन के पक्ष में थी। चीनी तिब्बत के ऊँचे पठार तथा चोटियों से आक्रमण करते थे जबकि भारतीयों को निचली घाटियों से हिमालय की ऊँची चोटियों तक चढ़कर अपने मोर्चे की रक्षा करने का कठिन काम करना पड़ा। **ब** चीनियों ने इस युद्ध की तैयारी बहुत समय पूर्व से कर रखी थी जबकि भारत इसके लिए तैयार ही न था¹⁴।

इधर भारत और चीन के युद्ध से एशिया और अफ्रीका के कुछ मित्र राज्यों ने दोनों देशों के सीमा विवाद को हल करवाना चाहा। इन देशों ने श्रीलंका की राजधानी कोलम्बो में १० दिसम्बर से १२ दिसम्बर १९६२ तक एक सम्मेलन किया। इस सम्मेलन में बर्मा, कम्बोडिया, श्रीलंका, थाईलैंड, इण्डोनेशिया तथा संयुक्त अरब गणराज्य के प्रतिनिधियों ने भाग लिया। भारत ने इस प्रस्तावों के बारे में कोई स्पष्ट प्रक्रिया व्यक्त नहीं की। कोलम्बो प्रस्ताव के पांच सूत्र इस प्रकार हैं-

१. वर्तमान नियन्त्रण रेखा भारत-चीन विवाद के समाधान का आधार मानी जाय।
२. अ- पश्चिमी क्षेत्र में चीन वर्तमान रेखा से २० किलोमीटर पीछे अपनी सैनिक चौकियाँ हटा ले, जैसा कि चार्ल्स एन लाई स्वयं श्री नेहरू को अपने २१ तथा २३ नवम्बर के पत्र में लिख चुके हैं। ब- भारत इस क्षेत्र को विसैन्यीकृत रखे और इस क्षेत्र का निरीक्षण दोनों देशों के सैनिक अधिकारी करें।
३. पूर्वी क्षेत्र में वर्तमान नियन्त्रण रेखा को युद्ध विराम रेखा माना जाय।
४. मध्य क्षेत्र में सीमा का निश्चय शान्तिपूर्ण साधनों से किया जाय।
५. इन प्रस्तावों की स्वीकृति से दोनों देशों के बीच परस्पर वार्ता के द्वारा निर्णय ले सकते हैं¹⁵ ।

अब हम आते हैं सवाद काल (१९७८ ९३) पर भारत में जनता सरकार के सत्तारूढ़ होने और चीन में माओत्तर नेताओं द्वारा बागडोर सभाले जाने के बाद दोनों देशों ने विगत बातों को भूलकर नये सिरे से मधुर सम्बन्ध स्थापित करने की दिशा में प्रयास किये। अनेक कूटनीतिक माध्यमों से भारत को पीकिंग से इस बात के सकेत मिले कि वह भारत के साथ सम्बन्ध सुधारने का इच्छुक है¹⁶। १९७५ में टेबिल-टेनिस की प्रतियोगिता कलकत्ता में हुई, जिसमें चीनी खिलाड़ियों के एक दल ने भाग लिया। जनवरी १९७८ में बाग-पिग नान के नेतृत्व में एक उच्च स्तरीय चीनी प्रतिनिधिमण्डल भारत आया। इसके बाद व्यापार-वाणिज्य प्रतिनिधिमण्डलों का दौरा हुआ और दोनों देशों के बीच १९७८ में १ करोड़ २० लाख का व्यापार हुआ। सितम्बर १९७८ में चीन के कृषि वैज्ञानिकों ने भारत की यात्रा की और न्यूयार्क में विदेशमन्त्री अटल बिहारी वाजपेयी ने चीनी विदेश मन्त्री हुआंग हुआ से भेट की। १ अक्टूबर १९७८ को चीन की स्थापना की। २९वीं वर्षगांठ पर उपराष्ट्रपति बी डी जत्ती उपस्थित थे। इसी माह ससद सदस्य सुब्रमण्यम स्वामी तथा मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी के एक प्रतिनिधि मण्डल ने चीन की यात्रा की। नवम्बर १९७८ में मृणालिनी साराभाई के नेतृत्व में भारतीय नेतृत्व मण्डली का चीन में भव्य स्वागत किया गया। १२ फरवरी, १९७९ से प्रारम्भ होने वाली अपनी चीन यात्रा को विदेश मन्त्री अटल बिहारी वाजपेयी ने टोली मिशन की सजा दी थी। उन्होंने कहा कि इससे

एशिया में नये शक्ति सतुलन की शुरुआत हो सकती है। विदेशमन्त्री वाजपेयी के अनुसार उनकी पीकिंग यात्रा का उद्देश्य लेन देन करना नहीं अपितु यह जानना था कि इतने वर्षों के बिगड़े सम्बन्ध के बाद आज चीन में हवा क्या है। वाजपेयी और चीनी विदेशमन्त्री इस बात से सहमत थे कि दोनों देशों को सहयोग के क्षेत्रों का पता लगाने में जुटे रहना चाहिए। दोनों पक्षों में यह आम सहमति थी कि सीमा विवाद देशों के भविष्य में सम्बन्ध का आधार है। वाजपेयी की चीन यात्रा में सीमा विवाद का हल नहीं ढूँढा जा सका, क्योंकि यह पेचीदा मामला था। वाजपेयी को चीन आने का निमन्त्रण देकर चीन ने जहाँ भारत को पुचकारने का प्रयास किया वही यात्रा के समय को वियतनाम पर आक्रमण के लिये चुनकर उसने भारत को परोक्ष धमकी भी दे दी और उसे १९६२ के आक्रमण की याद भी दिला दी । चीन द्वारा १७ फरवरी, १९७९ को वियतनाम पर आक्रमण किये जाने से वाजपेयी अपनी चीन यात्रा को अधूरी छोड़कर स्वदेश आ गये । वाजपेयी की चीन यात्रा से यह स्पष्ट हो गया कि जब तक सीमा सम्बन्धी मामले और कश्मीर से सम्बन्धित कुछ प्रश्नों पर सन्तोषजनक समझौता नहीं हो जाता तब तक चीन के साथ मैत्रीपूर्ण सम्बन्ध स्थापित नहीं हो सकेंगे¹⁷ ।

अन्तर्राष्ट्रीय दृष्टि से भी चीन के साथ फिर से बातचीत शुरू करने के कई कारण दिखायी देते हैं । चीन एक बड़ा पड़ोसी एशियाई देश है । उसके साथ सदा तनाव बने रहने की स्थिति दोनों

देशों के लिये अप्रिय और अहितकर है । अगर दोनों मिल बैठे तो विश्व राजनीति में एशिया का प्रभाव बढ़ना अवश्यम्भावी है । इसके अतिरिक्त तनाव की स्थिति में सैनिक तैयारी पर जो व्यय होता है वह मेल-जोल बढ़ने पर काफी कम हो जायेगा । दूसरी ओर भारत की यह मांग है कि दुनिया में तनाव कम करने की दशा में जो कार्यवाही हो रही है, वह तब तक कारगर नहीं होगी जब तक उसमें चीन जैसे बड़े एशियाई देशों को यथेष्ट स्थान नहीं दिया जायेगा । जब भारत अन्तर्राष्ट्रीय प्रयासों में चीन को यथोचित स्थान दिलाने का पक्षधर है तो उसका स्वयं चीन से मुह फेरे खड़े रहना प्रत्यक्ष असंगत होगा ।

उधर चीन भारत की दोस्ती का हाथ बढ़ाने के लिये आन्तरिक और बाह्य कारणों से विवश है । चीन में ऐसे आसार दिखायी दे रहे हैं कि पुराने माओवादी रवैये से हटकर कुछ नये विकल्पों को आजमाया जाये । इसी सन्दर्भ में चीन ने अपनी विदेश नीति के क्षेत्र में भी पुनर्विचार करना आवश्यक समझा । चीन जानता है कि भारत प्रभाव क्षेत्र की राजनीति और महाशक्तियों के प्रसार का विरोधी है , इसलिये भारत के साथ मिलकर ही एक सक्षम एशियाई व्यक्तित्व का निर्माण हो सकता है जिससे कि एशिया में बड़ी शक्तियों के प्रसार और प्रतिस्पर्धा को रोका जा सकता है । इसलिये भारत के साथ सम्बन्धों को सुधारने की कार्यवाही चीन के राष्ट्रहित में है¹⁸ ।

मार्शल टीटो की अन्त्येष्टि के अवसर पर श्रीमती गांधी ने चीन के विदेश मन्त्री हुआ कुआ फेग से वार्ता की । फेग ने जून १९८१ में भारत की यात्रा की ओर सीमा विवाद सहित सभी प्रकार के सम्बन्धों के सामान्यीकरण हेतु वे वार्ता के लिये राजी हो गये । चीन की सरकार ने भारतीय यात्रियों को मानसरोवर तथा कैलाश पर्वत जाने की अनुमति भी दे दी । भारत और चीन में विवादों के समाधान के लिए १९८२-८७ के मध्य कुल मिलाकर वार्ताओं के आठ दौर हुए । चीन का एक प्रतिनिधि मण्डल श्री फूहाओ के नेतृत्व में भारत चीन सीमा विवाद पर वार्ता के लिए १६ मई १९८२ को नई दिल्ली पहुंचा। दोनों पक्षों में यह विश्वास प्रकट किया कि ४० करोड़ रुपये के आपसी व्यापार में कई गुना वृद्धि की गुंजाइश है। भारत में आयोजित एशियाई खेलों में चीनी दल ने भाग लिया। भारत चीन का तीसरा दौर २९ जनवरी १९८३ में बीजिंग में शुरू हुआ। तीसरी वार्ता की सबसे बड़ी कमजोरी यह थी कि दोनों देश अपने अपने कोई स्पष्ट प्रस्ताव या शर्तें रखने में असफल रहे।

१७ सितम्बर से २२ सितम्बर १९८४ को इस क्रम में प्रारम्भ हुई वार्ता का पांचवा दौर चीन की राजधानी बीजिंग में सम्पन्न हुआ।

१९८० में चीन की ओर से यह बात अवश्य सामने आयी थी कि लद्दाख में अक्साईचिन में चीन द्वारा छीन ली गयी। ३७००० वर्ग किलोमीटर भूमि पर भारत चीन का अधिकार मान ले तो चीन पूर्वी क्षेत्र में मैकमोहन रेखा स्वीकार करने को तैयार है। उसके तत्काल

बाद १९८१ में जब राष्ट्र सघ नियन्त्रित जनसख्या सम्मेलन में भारत के ससदीय प्रतिनिधि मण्डल में अरुणाचल प्रदेश के स्पीकर का नाम शामिल किया गया तो चीन ने इकार कर दिया। बाद में उन्हें वीसा दे दिया गया और उसके बाद भारत चीन वार्ता के पहले और दूसरे दौर सम्पन्न हो गये।¹⁹ लेकिन दिसम्बर १९८२ में नवे एशियाई खेलों के समापन पर चीन ने पुनः तहलका मचाया कि समापन समारोह में अरुणाचल प्रदेश के नर्तक दल क्यों सम्मिलित किये गये। इस बार भारत के विरोध का भी चीन ने कोई सन्तोषजनक उत्तर नहीं दिया। भारत ने इस पर ११ दिसम्बर १९८२ को कोटनीस समारोह में जाने वाले भारतीय प्रतिनिधिमण्डल की यात्रा भी रद्द कर दी।

यहां यह उल्लेखनीय है कि चीन द्वारा पूर्व में मैकमोहन रेखा को स्वीकार करने का मतलब यही निकलता था कि नेफा अर्थात् अरुणाचल में वह भारत के दावे को मानता है। स्मरण रहे कि १९६२ में चीन ने इस क्षेत्र पर आक्रमण किया था व अपना दावा जताया था। भारत ने उसके बाद १९७२ में अरुणाचल को अपने राज्य का दर्जा प्रदान किया था। यदि चीन मैकमोहन रेखा को स्वीकार करने को तैयार है तो अरुणाचल के प्रश्न को लेकर बार - बार क्यों तूफान मचा रहा है।

इधर भारत के लिये स्थिति बुरी थी। १९८२ में प्रकाशित चीनी मानचित्रों में भी उन सभी भारतीय प्रदेशों को चीनी प्रदेश में बताया गया, जिन पर चीन अपना निराधार दावा करता रहा है। इस क्रम में

सिक्किम को भी वह भारतीय प्रदेश नहीं मानता । चीन सिक्किम कश्मीर व सीमा - विवाद पर अपनी पूर्व नीति बदले बिना ही भारत से सम्बन्ध सुधारना चाहता है । वह इस प्रक्रिया में कहीं भी प्रतिबद्ध नहीं होना चाहता है ।

सम्भवतः श्री राजीव गांधी ने अपने अन्य दुस्साहसिक कार्यों की तरह इस दमघोड़ वातावरण को भी मिटाने का सकल्प किया और कूटनीति वार्ताओं के क्रम में दूसरे पक्ष में नियंत्रण पाकर चीन जाने को तैयार हुए- ठीक २६ वर्षों के बाद एक तो पारस्परिक सम्बन्ध चाहे जितने भी बिगड़ गये थे उन्हें सामान्य बनाना ही था, दूसरे उस सीमा विवाद को भी हल करने का रास्ता ढूँढना था जो चीनियों से अधिक भारत के लिये स्थायी सिर-दर्द बन चुका था।

चीन में श्री राजीव गाँधी का अप्रत्याशित रूप से शानदार स्वागत हुआ। वह इस बात का प्रमाण माना जा सकता है कि विगत २६ वर्षों में चीन वालों का भी मन बदल चुका होगा और कहीं न कहीं से वे भी उस अवसर की तलाश में थे जिसे श्री गांधी ने स्वयं आगे बढ़कर उन्हें दे दिया था²⁰ ।

चीन में श्री गांधी ने वैसे तो राजनयिक आवश्यकताओं के अनुरूप अनेक अवसरों पर अनेक वक्तव्य दिये, किन्तु उनका सर्व प्रमुख नीतिगत भाषण वह था जो उन्होंने अपनी यात्रा के पहले ही दिन, अपने और श्रीमती सोनिया गाँधी के सम्मान में, चीन के प्रधान मंत्री श्री ली पेग और श्रीमती पेग द्वारा आयोजित राजकीय भोज के

अवसर पर दिया था।

मानो भगवान बुद्ध का कोई देवदूत दोनो देशो के बीच के भूगोल के उँचे पर्वतो, बीहड वनो भयानक मरुस्थलो और दहाडती नदियो को ही उनके इतिहास को भी अनेक गहरी खाइयो और अनुलघनीय घाटियो को पार करता हुआ आधुनिक चीन मे उतर आया था और नये चीनी समाज को एक बार फिर बुद्ध और गाधी दोनो का सन्देश एक साथ दे रहा था।²¹

श्री गाधी का यह भाषण राजनयिक शिष्टाचार का उत्कृष्टतम नमूना तो था किन्तु उसमे दोनो देशो के लम्बे ऐतिहासिक सम्बन्धो के हर उतार चढाव की सारी वास्तविकताये बिना कुछ भी छुये एक पारदर्शी चित्रावली के समान प्रतिबिम्बित हो गई थी। आखिर वह पूरे २६ वर्षो की अन्यमनस्कता के बाद भारत और चीन का पहला शिखर सवाद जो था।

राजीव गाधी का विचार था कि- “हमारे दोनो देश विश्व की सर्वाधिक उत्कृष्टतम सभ्यताओ का प्रतिनिधित्व करते है। मानव प्रगति के लिये हमारा योगदान महत्वपूर्ण रहा है। हम एक दूसरे को हजारो वर्षो से जानते रहे है। हजारो वर्षो से हमने एक दूसरे से विचारो का आदान प्रदान किया है। हमारे दोनो देश भिन्न-भिन्न कारणो से यूरोपीय शक्तियो के विप्लव के आगे पराभूत हुए। उसके बाद हमदोनो ने अलग-अलग तरीको से पुनः स्वतंत्रता प्राप्त की” ।

हमने उत्तर उपनिवेशवादी एशिया के पुनर्जागरण को मजबूत

करने के लिये साथ-साथ कार्य किये। एशियायी सबध सम्मेलन से लेकर बाडुग सम्मेलन तक हमारी एक आवाज रही जिसमे हमने सभी राष्ट्रों की समानता, सभी लोगो के लिये न्याय तथा स्थायी शान्ति की माग की। हमने शान्तिपूर्ण सह-अस्तित्व के जरिये शान्ति और सुरक्षा की ठोस नींव रखने के लिये मिलकर कार्य किया ताकि भय और आशका के स्थान पर विश्वास की भावना पैदा हो सके।

फिर श्री गांधी ने स्वभावतः उस कटुता की भी चर्चा की जो अचानक दोनों देशों के सबधों में आ गयी।

सामान्य प्रयास के इस चरण के बाद हमारी मैत्री टूटने का एक दौर आया। सीमा पर मतभेदों के कारण दुभाग्यपूर्ण घटनाएँ घटित हुईं, जिनसे हमारे सबधों में तनाव आ गया²²।

उन्होंने आगे कहा- अब अतीत के दायरे से निकलकर बाहर देखने का वक्त आ गया है। अब समय आ गया है जब हमारे देशों के बीच सबध उस स्तर तक बहाल किये जाय, जो हमारे देशों की शताब्दियों की मैत्री के अनुरूप हो। हम दोनों देश मिलकर मानवजाति के एक तिहाई के बराबर हैं। हम मिलजुलकर बहुत कुछ कर सकते हैं²³।

श्री गांधी ने याद दिलाया - १९५४ में भारत और चीन ने शान्तिपूर्ण सह-अस्तित्व के पाँच सिद्धान्तों-पंचशील की घोषणा की थी। हमने इन सिद्धान्तों पर जोर दिया, लेकिन उस समय इनको बहुत कम अंगीकार किया गया। विश्व टकराव के रास्ते पर आगे

बढ़ने के लिये उस समय इतना आमादा था कि वह पचशील के रास्तो का विकल्प ढूढ़ने मे लगा हुआ था। मगर अब तीस वर्षो के दुखद दौर के बाद विश्व-पथ के लिये उन्हे ही अपनाने के प्रयास किये जा रहे है²⁴।

श्री गाधी ने कहा- शान्ति का मार्ग इस मान्यता से आरम्भ होता है कि परमाणु युद्ध कभी जीता नही जा सकता। इसलिये उसे लडा जाना नही चाहिये। परमाणु हथियारो के अनुसधान के बाद से पहली बार हमने न केवल परमाणु हथियारो के नियत्रण बल्कि उनमे कमी लाने की भी प्रक्रिया देखी है। वास्तव मे एक बडी सैनिक शक्ति ने सोवियत सघ की ओर सकेत परम्परागत हथियारो तथा सैनिको की सख्या मे पर्याप्त कमी लाने की घोषणा भी की है। इन कटौतियो से भी ज्यादा महत्वपूर्ण वह भाषा जो अपनाई जा रही है तथा वह तर्क जिसका अनुसरण किया जा रहा है²⁵।

विश्व धीरे-धीरे उन सिद्धान्तो के और करीब पहुचता जा रहा है जिन्हे हम लोगो ने तीन दशक पूर्व सयुक्त रूप से तैयार किया था। भारत और चीन यदि एक दूसरे से अलगाव रखेगे, तो उनके लिये एक साथ मिलकर काम करना मुश्किल होगा। भारत और चीन यदि एक दूसरे के साथ तालमेल रखे तो वे मिलकर कार्य कर सकते है। मै उसी लक्ष्य की दिशा मे तौर तरीको का पता लगाने के लिये आया हूँ।

श्री गाँधी ने पण्डित जवाहर लाल नेहरू की चीन यात्रा के

समय पेड़चिग मे प्रकट किये गये उनके मार्मिक उदगारो की चर्चा की जिसमे श्री नेहरू ने कहा था- हमे यह मानना चाहिये कि इस दुनिया मे रहने का एकमात्र रास्ता सह अस्तित्व और सहयोग तथा प्रत्येक देश को अपनी तरह से जीने का अधिकार को मान्यता देना है। भविष्य मे एक दूसरे के खिलाफ पूर्व और पश्चिम जैसी कोई चीज नही होगी। दुनिया केवल एक होगी जो मानवता की प्रगति के लिये विभिन्न भागो के बीच मैत्री पूर्ण सहयोग के प्रति समर्पित होनी चाहिये।

श्री राजीव गाँधी ने अपील की- शान्तिपूर्ण सह-अस्तित्व के सिद्धान्तो को मानने के लिए विश्व से आग्रह करते समय, हमे अपनी समस्याओ को हल करने मे भी इन सिद्धान्तो का अनुसरण करना चाहिए। सीमा का सवाल एक बड़ी समस्या है। यह हमारी जनता की भावनाओ और सवेदनाओ को स्पर्श करती है। हमे समस्या का स्थायी समाधान ढूढना चाहिए, जो एक दूसरे के दृष्टिकोण की सूझ-बूझ पर आधारित हो। इस समय सीमा-क्षेत्र मे शान्ति की आवश्यकता है। हमे विश्वास है कि सीमा का सवाल सदभावनापूर्ण तरीके से हल कर दिया जायेगा। यह यथार्थवादी समय सीमा के अन्तर्गत हल किया जाना चाहिये। भारत उसके अनुसार आगे बढ़ने के लिये तैयार है।

श्री गाँधी ने कहा- हमारे दोनो देश विकासशील है, और विशाल जनसख्या वाले तथा महाद्वीपीय आकार वाले है दोनो ही अपनी जनता को समानता तथा न्याय के साथ विकास के लाभो तथा

आधुनिकीकरण के लाभो को देना चाहते है। इन कार्यों को पूरा करते समय हम एक दूसरे से बहुत कुछ सीख सकते है²⁶।

चीन ने अपनी अर्थ-व्यवस्था तथा समाज को आधुनिक बनाने के लिये अभिनव उपायो को लागू करने की दिशा में अनेक नई मजिले तय की है। अपने राष्ट्रीय जीवन में आपने जो उल्लेखनीय कार्याकल्प किया है उसके लिये हम आपको बधाई देते है। आपकी कृषि में सफलताये-उत्पादन तथा विविधता दोनों ही दृष्टियों से वास्तव में शानदार है। जल प्रबन्ध बाढ़ नियंत्रण तथा भूमिसुधार के क्षेत्र में आपके कौशल में हमारी खास दिलचस्पी है।

भारत में भी हमने खाद्यान्नों का उत्पादन तिगुना बढ़ा लिया है और दूसरी हरित क्रान्ति लाकर इस शताब्दी के अंत तक इस उत्पादन को दोगुना करना चाहते है। विस्तार तथा गहराई दोनों में हमारे औद्योगिक निर्माताओं तथा स्वदेशी प्रौद्योगिकी ने हमारी आत्मनिर्भरता को लाने की भूमिका निभाई है। जो हमारी आर्थिक दर्शन का सबसे आवश्यक गुण है।

उन्होंने कहा-हमने कुछ क्षेत्रों में अत्यन्त उत्कृष्ट सफलता हासिल की है जबकि आपने भी अन्य क्षेत्रों में उत्कृष्ट सफलताये अर्जित की है। हम उन अवसरों का स्वागत करेंगे, जबकि भारतीय तकनीकी विशेषज्ञों और वैज्ञानिक अब चीनी तकनीकी विशेषज्ञों और वैज्ञानिकों के साथ मिलकर काम करें।

श्री गाँधी ने जोर देते हुए कहा- भारत तथा चीन के स्थायी तथा मैत्रीपूर्ण सम्बन्ध हमारे क्षेत्र के भाग्य का निर्धारण करेंगे। वास्तव में वे विश्व इतिहास की दिशा पर महत्वपूर्ण प्रभाव डालेंगे। विश्व आज मानवता की एकता को मान्यता देने की आवश्यकता महसूस कर रहा है। हमारा स्वप्न एक ऐसे विश्व का है जहाँ टकराव के बजाय बातचीत हो तथा तनाव के बजाय सुलह शान्ति हो। हमारा स्वप्न एक ऐसे विश्व का है जो अहिंसा में विश्वास रखता हो। हम महात्मा गांधी के इस अमर उद्गार में पुनः आस्था व्यक्त करते हैं — यह मेरी दृढ़ आस्था है कि हिंसा से कोई स्थायी चीज नहीं बन सकती ।

अन्त में श्री गाँधी ने कहा -भारत और चीन की मैत्री ऐसी है जो विश्व के लिए बहुत कुछ योगदान कर सकती है। हम सीमा सम्बन्धी अपने मतभेदों का समाधान करने की दिशा में काम करने के वास्ते बचनबद्ध हैं। हमारी यह यात्रा उस सकल्प को गभीरता प्रदान करती है तथा एक नये चरण के सूत्रपात का प्रतीक है। हम विश्व में शान्ति तथा सभी लोगों में समृद्धि के लिए मिलकर खोज फिर शुरू करने की आशा करते हैं²⁷ ।

श्री गाँधी और उनके अष्टमण्डल के सदस्यों ने चीन के बहुत से नेताओं और अधिकारियों से बातें की बहुत से समारोहों में सम्मिलित हुये, चीन की दीवार से लेकर अन्य बहुत से ऐतिहासिक स्थान देखे किन्तु उनकी यात्रा का सर्वाधिक सार्थक और सोद्देश्य

अवसर वह था, जब चीन के सर्वोच्च वयोवृद्ध नेता और चीनी कम्युनिस्ट पार्टी के महामंत्री श्री दग झियाओ पग से श्री गाँधी की मुलाकात हुई। उनकी नब्बे मिनट की बात के बाद श्री पग इतने प्रभावित हुये कि एकाएक कह बैठे- जो गुजर गया उसे भूल जाना बेहतर है। मैं नहीं समझ पा रहा कि विश्व की दो बड़ी सभ्यताये अपनी पुरानी गलतियों से सबक क्यों नहीं हासिल करती।

श्री दग झियाओं पग की बातें इस बात का स्पष्ट संकेत थी कि चीन भी भारत से सम्बन्ध सामान्य बनाने को उत्तना ही उत्सुक है, और पिछली बातें भुलाकर नये सिरे से रिश्ते बनाने का अभिलाषी है। चीन की ओर से दुश्मनी खत्म होने का संकेत तो महामंत्री श्री दग झियाओ पग ने श्री राजीव गाँधी से अपनी वार्ता के अंतिम क्षणों में अपने बूढ़े और कापटे किन्तु अनुभव की ऊर्जा से सर्वशक्तिमान बने हाथों में श्री राजीव गाँधी के युवा किन्तु रोमांचित हो रहे हाथों, को पूरे डेढ़ मिनट तक थामे और हिलाते रहकर यह कहकर दिया था कि- वह अनुभवी नेता अपने विशिष्ट अतिथि पर अपने मार्मिक वचनों के प्रभाव की परख कर लेना कभी नहीं भूला।

श्री राजीव गांधी की यात्रा के दौरान चीन ने यह भी वादा किया था कि वह भविष्य में किसी भारतीय विरोध तत्व को हथियार या प्रशिक्षण नहीं देगा, ताकि उत्तर पूर्व में भारत विरोधी गतिविधियों पर रोक लग सके। इस बात का भी आश्वासन दिया गया कि भविष्य में भारत चीन सीमा की देख रेख पर चीन कम से कम धन व्यय

करेगा। भारत अपनी ओर से भी इस बात पर सहमत हुआ। व्यापार और संस्कृति संबंधी समझौते भी हुये जिनसे यह स्पष्ट हो गया कि दोनों देश १९६२ के पूर्व के माहौल को पुनः नया जीवन देने को तैयार हैं।

श्री राजीव गांधी की चीन-यात्रा उनके शान्ति अभियान के क्रम में एक बहुत बड़ी उपलब्धि थी। श्री राजीव गांधी ने जब चीन जाने का संकल्प लिया था तब जाहिर है कि २६ वर्षों की दुःखद स्मृतियों को भूलकर ही लिया था, और वे १९६२ के क्षुब्ध और आक्रोश से भरे हुए भारत के प्रतिनिधि नहीं थे। चीन जाकर उन्होंने भी देखा कि श्री दग झियाओ पंग की और श्री ली पेग जैसे आज के नेता भी चेयरमैन माओ और प्रधानमंत्री श्री चाउ इन लाई के अलगाववादी और अतिवादीयुग के चीनी समाज के प्रतिनिधि नहीं रह गये थे। वे उस युग की मानसिकता को काफी पीछे छोड़ आये थे।

पाद टिप्पणिया

- 1 Bandyopadhyay, J India China Relation Outlook for the 1980's, Foreign Affairs Reports (New Delhi) Page-87
- 2 Chakravarti, P G Indo China Relations Page-116
- 3 Dutta V P China's Foreign Policy Page-208
- 4 Ismail, M. India and their Neighbours Page-117
- 5 Chopra, S ED, Studies in India's Foreign Policy Page-219
- 6 Times of India 21 1950
- 7 Indian Express 26 6-1954
- 8 Statesman – 11 12 1956
- 9 Government of India White paper on Indo China Relations
- 10 Hindustan Times 21 10 1962
- 11 Times of India – 22-11-1962
- 12 Dutta V P China's Foreign Policy Page-189
- 13 Levi, W Free India in Asia Page-114
- 14 Levis, Martin Deming (Ed) Gandhi Maker of Modern India Page-201
- 15 Times of India – 13 12 1962
- 16 Ramakant, Nepal, China and India Page-119
- 17 Subramanvam, K Our National Security Page-54
- 18 Tharoor, S Reasons of State-Political Development and India Foreign Policy under Indira Gandhi, 1966 1977 Page-112
- 19 Ministry of External Affairs India Foreign Affairs Records
- 20 Kundra J C Indian Foreign Policy Page-89
- २१ सरकार चीन के प्रधानमंत्री द्वारा श्री राजीव गांधी से साथ समारोह के दौरान आयोजित भोज के अवसर पर श्री राजीव गांधी द्वारा दिये गये भाषण से टाइम्स आफ इण्डिया ।
- २२ श्री राजीव गांधी द्वारा चीन यात्रा के दौरान दिये गये भाषण के अंश-राष्ट्र बन्धु राजीव द्वारा श्री जगदीश त्रिगुणायन से उद्धृत
- २३ श्री राजीव गांधी द्वारा चीन यात्रा के दौरान दिये गये भाषण के अंश- राष्ट्र बन्धु राजीव द्वारा श्री जगदीश त्रिगुणायन से उद्धृत
- २४ श्री राजीव गांधी द्वारा चीन यात्रा के दौरान दिये गये भाषण के अंश- राष्ट्र बन्धु राजीव द्वारा श्री जगदीश त्रिगुणायन से उद्धृत
- २५ श्री राजीव गांधी द्वारा चीन यात्रा के दौरान दिये गये भाषण के अंश- राष्ट्र बन्धु राजीव द्वारा श्री जगदीश त्रिगुणायन से उद्धृत
- २६ श्री राजीव गांधी द्वारा चीन यात्रा के दौरान दिये गये भाषण के अंश- राष्ट्र बन्धु राजीव द्वारा श्री जगदीश त्रिगुणायन से उद्धृत
- २७ Bandyopadhyay, J India-China Relation Outlook Page-194

અધ્યાય-૪

नेपाल हिमालय की उपत्यकाओं में बसा हुआ एक छोटा सा देश है। यह भारत और तिब्बत के बीच स्थित है और अब तिब्बत पर चीन के आधिपत्य के बाद भारत और चीन एक बफर स्टेट का कार्य करता है। यह विश्व का एकमात्र हिन्दू राष्ट्र है। इसकी स्थापना पृथ्वी नारायण शाह (१७२३-१७७४) ने १७६९ में की। आधुनिक नेपाल के निर्माता पृथ्वी नारायण शाह ने नेपाल की विदेश नीति का निर्धारण करते हुए कहा था यह देश दो चट्टानों के बीच खिले हुए फूल के समान है। हमें चीनी सम्राट के साथ मैत्रीपूर्ण सम्बन्ध रखने चाहिए तथा हमारे सम्बन्ध दक्षिणी सागरो के सम्राट से भी मधुर होने चाहिए। पर वह बहुत चालाक है। अपने दो पड़ोसियों में से वह भारत को खतरे का अधिक बड़ा स्रोत मानता था। पिछले २०० वर्षों के इतिहास में नेपाल की विदेश नीति की प्रधान विशेषता यह रही है कि दोनों पड़ोसियों में से जो ज्यादा बलवान कहा उसे खुश रखो।

भारत के उत्तर-पूरब में स्थित नेपाल सामरिक दृष्टि से अत्यन्त महत्वपूर्ण है। चीन द्वारा तिब्बत को हस्तगत कर लेने के बाद भारत-चीन सम्बन्धों में नेपाल की सामरिक स्थिति का राजनीतिक महत्व बढ़ गया। उत्तर में भारत की सुरक्षा आज एक बड़ी सीमा तक नेपाल की सुरक्षा पर निर्भर करती है। पं० नेहरू ने १७ मार्च १९५० को कहा था जहां तक कुछ एशियाई गतिविधियों का संबंध है, भारत-नेपाल के बीच किसी प्रकार का सैन्य समझौता नहीं है लेकिन

नेपाल पर किये जाने वाले किसी भी आक्रमण को भारत सहन नहीं कर सकता । नेपाल पर कोई भी सम्भावित आक्रमण निश्चित रूप से भारतीय सुरक्षा के लिए खतरा होगा। अक्टूबर १९५६ में डा० राजेन्द्र प्रसाद ने अपनी नेपाल यात्रा के दौरान कहा था कि नेपाल की शान्ति और सुरक्षा के लिए कोई खतरा भारतीय शान्ति और सुरक्षा के लिए खतरा है । नेपाल के मित्र हमारे मित्र हैं और नेपाल के शत्रु हमारे शत्रु हैं ।

जहा तक भारत नेपाल का सम्बन्ध (१९४७-१९६२) है। भारत में ब्रिटिश शासन के समय यद्यपि नेपाल औपचारिक रूप से एक स्वतंत्र देश था तथापि नेपाल की राजनीति में ब्रिटिश शासकों का हस्तक्षेप बहुत अधिक था । स्वतंत्र भारत सरकार साम्राज्यवादी नीति की पोषक न होने के बावजूद सामरिक महत्व के कारण नेपाल की अवहेलना नहीं कर सकती थी । इसके अतिरिक्त साम्यवादी चीन का तिब्बत में प्रभाव बढ़ जाने से यह प्रारम्भ में ही स्पष्ट हो गया था कि साम्यवादी चीन तिब्बत पर अपना अधिकार जमा लेगा और इस प्रकार नेपाल एवं चीन की सीमाएं बिल्कुल मिल जायगी। संयुक्त राज्य अमेरिका भी इसी कारण नेपाल की राजनीति में रुचि लेने लगा । इस प्रकार नेपाल में बड़ी अन्तराष्ट्रीय शक्तियों के बीच टक्कर होने की स्थिति उत्पन्न हो गयी और ऐसा प्रतीत होने लगा कि नेपाल शीत युद्ध का क्षेत्र बन जायेगा । अपनी सुरक्षा की दृष्टि से भारत सरकार ऐसी स्थिति में नेपाल की राजनीति से उदासीन

नहीं रह सकती थी। अतएव प्रारम्भ से ही भारत सरकार ने नेपाल की राजनीतिक एवं आर्थिक स्थिति को दृढ़ करने की नीति अपनायी¹।

१९४७ में नेपाल के प्रधानमंत्री की मांग पर भारत सरकार में एक वरिष्ठ भारतीय राजनीतिज्ञ श्रीप्रकाश को नेपाल भेजा गया जिससे नेपाल का संविधान तैयार कराने में सहायता दी जा सके। जो संविधान बना यह राजशाही की निरकुशता का अन्त करने वाला था अतएव उसे राजाओं ने कार्यान्वित नहीं होने दिया।

भारत सरकार नेपाल के साथ एक नयी सन्धि भी करना चाहती थी। १९४९ में संधि का एक मसविदा भी तैयार किया गया परन्तु इसका कोई अन्तिम निष्कर्ष नहीं निकला क्योंकि नेपाल सरकार भारत के प्रति सशक्त था। संधि की महत्वपूर्ण शर्त यह थी कि नेपाल में लोकतान्त्रिक प्रणाली स्थापित हो। चूँकि नेपाल के प्रधानमंत्री राणा मोहन शमशेर जग नेपाल के परम्परागत प्रधानमंत्रियों के प्रसिद्ध वंश राणा परिवार के थे और राजा की सम्पूर्ण सत्ता वर्षों से इस राणा परिवार के हाथ में थी, अतएव राणा मोहन शमशेर जग बहादुर लोकतान्त्रिक पद्धति का समर्थन कैसे कर सकते थे।

तिब्बत में चीन की गतिविधियाँ बढ़ने से नेपाल की सुरक्षा के बारे में भारत की चिन्ता बढ़ गयी और १७ मार्च १९५० को प्रधानमंत्री नेहरू ने ससद में कहा कि नेपाल पर कोई भी सम्भावित आक्रमण निश्चित रूप से भारत के लिए खतरा होगा। अप्रैल १९५० में जनरल

विजय शमशेर और एन एम दीक्षित ने नेपाल सरकार के प्रतिनिधि के रूप में भारत की यात्रा की और ३० जुलाई १९५० को दोनों देशों के मध्य एक संधि हुई पर इसी बीच नेपाल में घटित घटनाओं के कारण भारत सरकार और नेपाल की राणा सरकार के सम्बन्धों में तनाव उत्पन्न हो गया ।

इसी समय १९५० के राणाशाही से मुक्ति के लिए प्रयास शुरू हुआ । १६ नवम्बर १९५० को नेपाल के महाराजा त्रिभुवन ने राज परिवार के १४ सदस्यों के साथ अपने राजमहल का परित्याग कर भारत में शरण ली। राजा शमशेर के विरुद्ध गृहयुद्ध शुरू हो गया । यह विद्रोह भारत के भू-भाग से ही संचालित किया गया। भारत के सहयोग से ही नेपाल में राणाशाही का अन्त हुआ और नेपाल के महाराणा वास्तविक शासक बने तथा लोकतंत्र की स्थापना हुई । इस समय पण्डित नेहरू ने कहा था। नेपाल की स्वतंत्रता का सम्मान करते हुए भी हम नेपाल में कोई अव्यवस्था सहन नहीं कर सकते क्योंकि इससे हमारी सीमा सुरक्षा कमजोर हो जाती है । भारत ने बार-बार संयुक्त राष्ट्र सभ में नेपाल की सदस्यता की वकालत की और १९५५ में उसके सदस्य बन जाने पर प्रसन्नता प्रकट की । नेपाल के विदेश मंत्री ने १ फरवरी, १९५५ को एक भाषण में कहा कि नेपाल किसी भी दशा में भारत के विरुद्ध नहीं जायेगा। भारत ने नेपाल को अन्तराष्ट्रीय मानसिक्ता प्राप्त करने में बड़ी सहायता दी है और वह नेपाल का सबसे बड़ा मित्र है^२ । इसके कुछ समय पश्चात

भारत की लोकसभा में बोलते हुए नेहरू ने विदेश नीति पर एक दूसरे से परामर्श करने की उस धारा की पुष्टि की जो भारत-नेपाल की मित्रता सन्धि १९५० में दी गयी थी। उन्होंने यह स्पष्ट कर दिया कि भारत का इरादा नेपाल के आन्तरिक मामलों में हस्तक्षेप करने का नहीं किन्तु नेपाल की घटनाओं का भारत पर महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ता है। अतएव भारत का नेपाल के विषय में चिन्ता करना एवं सतर्क रहना स्वाभाविक है।

अनेक कारणों से १९५३-५४ में भारत के प्रति नेपाली जनता का आक्रोश उभरकर सामने आया। वहाँ के लोगों को यह भ्रम हुआ कि भारत उसके आन्तरिक मामलों में हस्तक्षेप करता है। दूसरा भारत में बहकर आने वाली कोसी नदी पर नेपाली भूमि में बाध बना था। तीसरे भारतीय नदी नेपाल में थी और भारतीय तकनीकी विशेषज्ञ भी वहाँ थे। चौथा व्यापार समझौते में कुछ प्रतिबन्ध भारत की ओर से लगे हुए थे। इन्हीं सब कारणों से १९५४ में जब भारतीय सदभावना मण्डल नेपाल पहुँचा तो कुछ लोगों ने काले झण्डे दिखाकर प्रदर्शन किया था।

नेपाल के प्रधानमंत्री टका प्रसाद ने इसे असन्तुष्ट विरोधी दलों का प्रदर्शन कहते हुए स्पष्ट किया कि नेपाल की अपनी प्रार्थनाओं पर भारतीय सेना आयोग १९५१ में नेपाल की सेना को संगठित करने और प्रशिक्षण देने आया था। नेपाली सेना में कोई भारतीय परामर्शदाता नहीं थे और जो थोड़े से भारतीय परामर्शदाता थे वे भी

तकनीकी सहायता संचालक के अन्तर्गत थे। कोसी बाँध के कारण नेपाल का भी लाभ था और यहाँ भूमि भारत ने क्रय की थी और इससे नेपाल की सार्वभौमिकता पर प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ता था। नेपाल ने स्वयं भी रेलवे के लिये बिहार में भूमि खरीदी थी। स्थिति की ओर भी स्पष्ट करते हुए भारतीय राजदूत ने कहा कि नेपाल की दी जाने वाले भारतीय सहायता में कोई भी शर्त नहीं जोड़ी गयी है और यह सहायता नेपाल सरकार की प्रार्थना पर दी गयी है। भारतीय सैनिक एवं अन्य विशेषज्ञ पूर्ण रूप से परामर्शदाता के रूप में हैं उनकी कोई राजनीतिक स्थिति नहीं है और ये नेपाल से कुछ नहीं लिया है, जबकि नेपाल को इस बाध के कारण बिजली एवं सिंचाई की सुविधा मिलेगी³।

१९५५-५६ के बीच भारत एवं नेपाल के मैत्रीपूर्ण सम्बन्ध नेपाल के महाराजा की भारत यात्रा नवम्बर १९५५ एवं भारतीय राष्ट्रपति की नेपाल यात्रा अक्टूबर १९५६ से और भी घनिष्ठ हो गये। काठमाण्डू लौटकर नेपाल के महाराजा ने एक नागरिक सभा में कहा कि नेहरू को उन्होंने नेपाल का सबसे अच्छा मित्र पाया। भारत के राष्ट्रपति राजेन्द्र प्रसाद ने कहा कि भारत की नेपाल में कोई क्षेत्रीय महत्वाकांक्षाएँ नहीं हैं- हमारे मित्र आपके मित्र हैं और आपके मित्र हमारे।

इधर १९५५ से चीन नेपाल में सक्रिय होने लगा। १९५६ में

नेपाली प्रधानमन्त्री ने चीन की यात्रा की और २० सितम्बर, १९५६ को नेपाल-चीन मैत्री संधि पर हस्ताक्षर हुए। जनवरी १९५७ में चीन के प्रधानमन्त्री चाऊ-एन-लाई नेपाल आये । अपने भाषणों में उन्होंने नेपाल की स्वतन्त्रता और सार्वभौमिकता को अक्षुण्ण बनाये रखने में यथाशक्ति सहायता का आश्वासन ऐसे ढंग से दिया जिससे प्रतीत हुआ कि नेपाल की स्वतन्त्रता को भारत से खतरा है । उन्होंने यह भी कहा कि नेपालियों और चीनियों की एक ही प्रजाति है । चीन नेपाल को ६ करोड़ रूपयों की सहायता देने का भी वचन दिया । नेपाल का चीन के प्रति अधिक झुकाव होना एवं भारत से दूर हटना स्वाभाविक था । १९५९ में नेपाल के प्रधानमन्त्री कोइराला ने चीन की यात्रा की और चाऊ-एन-लाई को पुनः नेपाल आने के लिए आमन्त्रित किया । चीन एवं नेपाल के मध्य एवरेस्ट पर्वत शिखर के बारे में एक समझौता भी हुआ जिसकी भारत में ही कड़ी आलोचना हुई।

कोइराला मन्त्रिमण्डल कुछ ही समय बाद भग कर दिया गया और नेपाली कांग्रेस के अनेक नेताओं को गिरफ्तार कर लिया गया किन्तु इनमें से कुछ व्यक्ति भागकर भारत चले गये और यही से नेपाल में जन आन्दोलन को संचालित करने तथा सफल बनाने का प्रयत्न करने लगे⁴ । नेपाल में यह समझा गया कि भारत द्वारा नेपाल नरेश विरोधी कार्य को प्रश्रय दिया जा रहा है । इससे दोनों देशों के आपसी सम्बन्धों में कटुता आ गयी, जो १९६१ तक बराबर बनी रही।

भारत की अनेक चेतावनियों को अनसुनी करके महाराजा महेन्द्र ने काठमाण्डू-ल्हासा मार्ग बनाने के सम्बन्ध में चीन से समझौता करके भारत के लिए खतरा उत्पन्न कर दिया। महाराजा महेन्द्र चीन यात्रा पर गये। उन्होंने भारत के ऐतिहासिक और अटूट सम्बन्धों का जिक्र किया किन्तु साथ ही चीन के साथ पुरातन सम्बन्धों की चर्चा की जो पुनर्स्थापित हो रहे थे। भारत के प्रति उन्होंने उदासीनता का रुख अपनाया। जब १९६२ में भारत-चीन युद्ध प्रारम्भ हुआ तब नेपाल ने तटस्थता की नीति अपनायी जिसे भारत ने पसन्द नहीं किया।

जहा तक भारत-नेपाल का सम्बन्ध (१९६२-१९७७) है। १९६२ में यद्यपि नेपाल भारत-चीन युद्ध में तटस्थ अवश्य रहा किन्तु चीनी आक्रमण से नेपाल चौकन्ना हो गया। चीनी आक्रमण के बाद भारत के लिए नेपाल में अपनी स्थिति दृढ़ करना भी आवश्यक हो गया। तत्कालीन गृहमंत्री लालबहादुर शास्त्री ने नेपाल की यात्रा की और सरल सौम्य नीति से नेपाल के अनेक सन्देह भी दूर किये। इसके बाद ही नेपाल नरेश १३ दिन की भारत यात्रा पर आये एवं डा० राधाकृष्णन ने नेपाल की यात्रा की। इस समय नेपाल सरकार ने आश्वासन दिया कि नेपाल के मार्ग से भारत पर कोई आक्रमण नहीं हो सकेगा^१।

२३ सितम्बर १९६४ को भारत के विदेशमंत्री सरदार स्वर्णसिंह ने

नेपाल की यात्रा की। इस समय नेपाल और भारत के मध्य एक समझौता हुआ। इसके अनुसार भारत ने नेपाल के लिए ९ करोड़ रूपयों की लागत से सीमावर्ती कस्बे सुगौली और मध्यपूर्वी नेपाल में ओखरा घाटी के बीच १२८ मील लम्बी सड़क बनाने का निश्चय किया। काठमाण्डू से लेकर भारतीय सीमा में रक्सौल को जोड़ने वाली एक अन्य सड़क योजना भी बनी। कोसी योजना पूर्ण करने का निश्चय किया गया। कोसी योजना का उद्देश्य नेपाल की बाढ़ से बचाना बिजली पूर्ति करना एवं सिंचाई में लाभ पहुँचाना था^१।

दिसम्बर १९६५ में नेपाल नरेश ने पुनः भारत की यात्रा की। इस यात्रा के अन्त में भारतीय प्रधानमंत्री लालबहादुर शास्त्री एवं नेपाल नरेश की संयुक्त विज्ञप्ति में नेपाल नरेश ने स्वीकार किया कि भारत की सहायता से नेपाल में चल रहे विकास कार्यों की प्रगति सन्तोषपूर्ण ढंग से हुई। भारतीय प्रधानमंत्री ने विश्वास दिलाया कि नेपाल की पंचवर्षीय योजना में भारत अधिकतम सहयोग देगा।

जनवरी १९६६ में सूर्यबहादुर थापा नेपाल के नये प्रधानमंत्री बने। वे मार्च १९६६ में भारत आये। भारत और नेपाल के सम्बन्धों में इससे कुछ सुधार हुआ परन्तु शीघ्र ही साढ़े चार वर्गमील के सुस्ता क्षेत्र को लेकर दोनों देशों में सीमा-विवाद उठ खड़ा हुआ।

अक्टूबर १९६६ में श्रीमती इन्दिरा गांधी ने नेपाल की यात्रा की

उन्होंने नेपाल के पचायती लोकतंत्र की सराहना की और महाराजा महेन्द्र को दार्शनिक शासक कह कर पुकारा । जून १९६९ में चीन के दबाव में आकर नेपाली प्रधानमंत्री के एन विष्ट ने भारत से नेपाल की उत्तरी सीमा पर काम करने वाले तकनीशियनों को वापस बुलाने और अपनी सैनिक चौकियां हटा लेने की मांग की। इससे भारत में काफी प्रभाव पड़ा । नेपाल ने समझ लिया कि भारत एक दुर्बल पड़ोसी नहीं है⁷ ।

१९७२ में राजा महेन्द्र के निधन के बाद वीरेन्द्र नेपाल के राजा बने। उन्होंने नेपाल के विकास कार्यक्रमों में सहायता देने में भारत की उदारता की सराहना की। १९७४-७५ में सिक्किम के भारत में विलय की घटना की नेपाल में प्रतिक्रिया हुई किन्तु भारत ने इस बात का आश्वासन दिया कि नेपाल और सिक्किम की स्थिति भिन्न है । अक्टूबर १९७५ में महाराजा वीरेन्द्र भारत आये और भारत ने नेपाल को आश्वासन दिया कि वह उसकी पंचवर्षीय योजनाओं में भरपूर सहायता देगा। अप्रैल १९७६ में नेपाल के प्रधानमंत्री तुलसीगिरि भारत आये तो उन्होंने 'समदूरी' सिद्धान्त के तहत भारत और चीन से समदूरी पर बल दिया । लेकिन भारत सरकार इस बात पर बल देती रही कि नेपाल के भारत से विशिष्ट सम्बन्ध हैं अतः उसका समदूरी सिद्धान्त अनुचित है ।

अब हम लेते हैं जनता सरकार के दौरान भारत-नेपाल सम्बन्ध

को जनता पार्टी सरकार ने नेपाल से मधुर सबंध स्थापित करने के लिये पुरजोर प्रयत्न किये । १९७६ से अघर में लटकी हुयी व्यापार और आवागमन संधि को बिल्कुल उसी तरह सम्पन्न किया जैसा कि नेपाल चाहता था⁷ । मार्च १९७८ में एक के बजाय दो संधियां की गयीं। दोनों में रियायतों का अम्बार लगा दिया गया । नेपाली उद्योग के विकास का जिम्मा भारत ने अपने कंधों पर लिया तथा नेपाल द्वारा विनिर्मित लगभग ६० वस्तुओं पर से तटकर हटा लिया। नेपाल को १६ आवश्यक वस्तुएं निर्मित देते रहने का दायित्व भी भारत ने सभाला। पारगमन संधि के अन्तर्गत भूवेष्टित देशों को भी प्राप्त नहीं है । भारत नेपाल सबंधों को सुधारने के लिये विदेश मंत्री ने दो वर्षों में काठमांडू की अनेक यात्रायें कीं। श्री देसाई भी नेपाल गये। इस बीच नेपाल नरेश तथा प्रधानमंत्री भी भारत यात्रा पर आये ।

राजीव गांधी के काल तक भारत-नेपाल के मध्य मतभेद के कई बिन्दु पैदा हो चुके थे। भारत और नेपाल के सुरक्षा सम्बन्धी हित समान होने पर भी उनके सम्बन्धों में अत्यधिक उतार-चढ़ाव रहा है। अनेक बार भारतीय हितों की उपेक्षा करते हुए अर्थात् भारतीय हितों के विरुद्ध नेपाल ने साम्यवादी चीन के साथ समझौते किये। भारत और नेपाल में गलतफहमियां विद्यमान रही हैं और वस्तुओं के लिए पारगमन की सुविधाओं और व्यापार संचालन के सम्बन्ध में मतभेद रहे हैं। नेपाल में चीन की गतिविधियां भारत विरोधी और ध्वसात्मक रही हैं। नेपाल द्वारा काठमाण्डू-ल्हासा सड़क मार्ग बनाने के सबंध में

चीन के साथ समझौता स्पष्टतः भारत विरोधी कदम था। एवरेस्ट पर्वत के सबंध में नेपाल-चीन में प्रारम्भिक समझौता भारत के प्रति विश्वासघात था। आजकल नेपाल का आग्रह है कि नेपाल को शान्ति क्षेत्र घोषित किया जाये⁹। भारत सरकार का दृष्टिकोण यह है कि केवल नेपाल ही क्यों सम्पूर्ण उपमहाद्वीप को शान्ति क्षेत्र घोषित किया जाये। चीन, पाकिस्तान, श्रीलंका और बंगलादेश ने नेपाल के दृष्टिकोण का समर्थन किया है। १९८३ में राष्ट्रपति रीगन ने भी नेपाल को शान्ति क्षेत्र घोषित करने की मांग को समर्थन दिया था। अलोचक इसे भारत विरोधी प्रस्ताव मानते हैं। उनके अनुसार यह अप्रत्यक्ष रूप से भारत पर एक प्रकार का दोषारोपण है कि भारत नेपाल के लिए खतरा है। संभवतः नेपाल को शान्ति क्षेत्र घोषित कराने के पीछे नेपाल का प्रधान उद्देश्य भारत के प्रभाव और विशिष्ट स्थिति को नकारना है जिसे वह अपने राष्ट्रीय व्यक्तित्व की खोज में ही बाधक मानता है। यह उसकी भारत और चीन के मध्य ऐतिहासिक सन्तुलनकारी भूमिका का एक रूप भी हो सकता है। नेपाल इस प्रस्ताव को भारत से अधिकाधिक आर्थिक सहायता पाने के लिए एक सौदेबाजी के आधार के रूप में भी उपयोग करना चाहता है।

भारत के प्रथम युवा प्रधानमंत्री राजीव गांधी की विदेश नीति विषयक समझ ज्यादा वैज्ञानिक और स्थापित अंतर्राष्ट्रीय मानकों के अनुरूप थी¹⁰।

उनके काल में नेपाल के साथ भारत का सहयोग निरन्तर बढ़ता चला गया। सितम्बर, १९८५ में महामहिम नेपाल नरेश ने अपनी दिल्ली यात्रा के दौरान व्यापक विचार - विमर्श किया। नेपाल की विकास परियोजनाओं में भारत की मदद की सराहना की गयी। दोनों देशों के बीच पारगमन संधि को मार्च १९८९ तक बढ़ाया गया। इस संधि से भारत के रास्ते नेपाल को समुद्री मार्ग मिलता है¹¹।

भारत और नेपाल के बीच सभी क्षेत्रों में सबंध सुदृढ़ होते गये हैं। १९८६ में २१ से २५ जुलाई तक भारत के राष्ट्रपति नेपाल की राजकीय यात्रा पर गये । इस दौरान भारत के राष्ट्रपति और नेपाल नरेश के बीच लाभदायक विचार विमर्श हुआ। दोनों पक्षों के बीच आपसी सबंधों के विभिन्न पहलुओं पर अधिकारी स्तर पर विचार विमर्श किया गया¹²। प्रधानमंत्री श्री राजीवगान्धी और नेपाल नरेश के बीच दो बार सितम्बर १९८६ में हरे में और नवम्बर १९८६ में बेगलूर में बातचीत हुयी। इन मुलाकातों से दोनों नेताओं को द्विपक्षीय सबंधों के सभी पहलुओं पर निसकोच और मैत्रीपूर्ण बातचीत करने का मौका मिला¹³।

भारत और नेपाल के बीच परम्परागत मैत्री सबंधों की पुष्टि होती रही। प्रधानमंत्री ने सार्क शिखर सम्मेलन के लिये नवम्बर, १९८७ में काठमांडू की यात्रा की और नेपाल नरेश के साथ विविध मुद्दों पर सफल बातचीत की । भारत नेपाल के बीच गहन आर्थिक सहयोग को जून १९८७ में भारत नेपाल में संयुक्त आयोग की

स्थापना के लिये हस्ताक्षरित समझौते से और भी बल मिला¹⁴।

व्यापार और पारगमन के मामले पर भारत और नेपाल के बीच मतभेद होने के बावजूद दोनों देशों के बीच परस्पर यात्राओं के आदान प्रदान की परम्परा जारी रही। नेपाल के साथ व्यापार और पारगमन की सधियों की अवधि २३ मार्च, १९८९ को समाप्त हो गयी। इस मामले को हल करने के लिये मार्च १९८९ में विदेश मंत्री स्तर की वार्ता हुयी इसके बावजूद मतभेद बने रहे। भारत के विदेश मंत्री ने एक बार फिर अगस्त १९८९ में काठमाण्डू में बातचीत की। महाराजा वीरेन्द्र से भी मिले। कुछ समय बाद नेपाल के महाराजा सितम्बर १९८९ में नौवे गुटनिरपेक्ष शिखर सम्मेलन के दौरान बगलूर में तत्कालीन प्रधानमंत्री राजीवगाँधी से मिले। ये शिखर वार्ता लाभदायक सिद्ध हुयी। मौजूदा मतभेदों को शान्तिपूर्वक ढंग से दूर करने के उद्देश्य से समूचे भारत नेपाल संबंधों की समीक्षा करने के लिये भारत ने हमेशा तत्परता दिखायी है¹⁵।

(क) राजीव गांधी के प्रयासों से ही आगे चलकर भारत नेपाल के आर्थिक-तकनीकी संबंध मजबूत हुए। उनके बाद भी विकास कार्यों में सबसे अधिक धन भारत का ही लगा हुआ है। नेपाल को भारत ने हर तरह का प्रशिक्षण दिया है। भारत ने अनेक नेपाली नागरिकों को प्रशिक्षण किया है। भारत ने नेपाल को जिन परियोजनाओं के लिये सहायता दी है, उनमें प्रमुख हैं।

(क) देवीघाट, त्रिशूल करनाली, पंचेश्वर जल-विद्युत योजनाएँ

- (ख) त्रिभुवन गणपथ काठमाण्डु-त्रिशूली मार्ग त्रिभुवन हवाई अड्डा
- (ग) काठमाण्डु रक्सौल टेलीफोन सयन्त्र
- (घ) चत्र नहर परियोजना कोसी और गडक परियोजना,
- (च) भूवैज्ञानिक अनुसंधान तथा खनिज खोजबीन का काम,
- (छ) वीरगज और हितौदा रेल निर्माण तथा
- (ज) काठमाण्डु घाटी के एक उपनगर पाटन में एक औद्योगिक बस्ती की स्थापना¹⁶ ।

दिसम्बर १९९० में एक द्विपक्षीय करार पर हस्ताक्षर हुए जिसके अन्तर्गत भारत टर्न की और सहायक अनुदान के आधार पर रक्सौल में करोड़ रुपये की लागत से एक नये रोड एव रेल पुल का निर्माण करेगा जो कि भारत-नेपाल से आने-जाने के लिए और माल लाने - ले जाने के लिए सर्वाधिक महत्वपूर्ण सीमा स्थल होगा। दिसम्बर १९९१ में भारत ने नेपाल के महान देश भक्त एव स्वतंत्रता संग्राम सेनानी वी एच कोइराला की पुण्यतिथि में भारत-नेपाल फाउण्डेशन बनाने का प्रस्ताव स्वीकार कर लिया। दोनों ही देश दो-दो करोड़ रुपये के अशदान से स्थापित इस फाउण्डेशन के द्वारा द्विपक्षीय सहयोग को बढ़ावा देगे। वे औद्योगिक क्षेत्र में साझा उद्यम लगाने को भी सहमत हो गये हैं। इसके अन्तर्गत चीनी कागज तथा सीमेन्ट पर विशेष ध्यान दिया जायेगा। नेपाल के आग्रह पर भारत विराट नगर में वी पी कोइराला स्मृति मेडिकल कालेज रंगेली में एक टेलीफोन एक्सचेंज, विराट- नगर -झापा तथा चतरावीपुर मार्ग

के निर्माण जनकपुर-बीजलपुर के रेल लाइन के नवीनीकरण और रक्सौल तक की रेल लाइन को बड़ी लाइन में परिवर्तित करने को राजी हो गया है¹⁷।

भारत भूटान संबंध- भूटान पूर्वी हिमालय में स्थित एक छोटा-सा स्वतंत्र राज्य है। इसके पश्चिम में भारत का सिक्किम प्रान्त तथा बंगाल का दार्जिलिंग जिला इसे नेपाल से अलग करता है। इसकी उत्तरी तथा उत्तर-पूर्वी सीमा पर तिब्बत और इसके पूरब तथा दक्षिण में भारत का असम प्रान्त है।

भूटान एक पर्वतीय राज्य है और पर्वतों के बीच घाटियों में बसा हुआ है। इसका क्षेत्रफल १८ ००० वर्गमील और जनसंख्या लगभग ८ लाख है। यहाँ अधिकतर भूटिया जाति के लोग रहते हैं। भूटान के लोग बौद्ध धर्मावलम्बी हैं।

भारत की प्रतिरक्षा में भूटान का अत्यधिक महत्व है। भारत की उत्तरी प्रतिरक्षा व्यवस्था में भूटान को भेद्योग की सजा दी जाती है। चुम्बी घाटी से चीलन की सीमाएँ केवल ८० मील हैं। यदि चीन विस्तारवादी इरादों से इस क्षेत्र में घुसपैठ करे तो वह न केवल भूटान को बल्कि उत्तरी बंगाल असम और अरुणाचल प्रदेश को भारत से काट सकता है। चीन ने भूटान-तिब्बत की वर्तमान प्राकृतिक सीमाओं को कभी स्वीकार नहीं किया। सौभाग्य से भारत-भूटान सम्बन्ध मित्रतापूर्ण रहे हैं और उनमें कोई प्रमुख समस्या नहीं है।

भारत भूटान को एक स्वतन्त्र देश के रूप में बनाये रखना चाहता है। भारत की पहल पर ही भूटान १९७१ में संयुक्त राष्ट्र सघ का सदस्य बना। १९७३ में वह निर्गुट आन्दोलन में शामिल हुआ १९७७ में भारत ने भूटान के राजदूतावास का नई दिल्ली में दर्जा बढ़ा दिया भूटान सार्क का भी सदस्य है और वह दक्षिण एशिया में डाक सेवाओं में सहयोग सम्बन्धी समिति का अध्यक्ष है।

जहाँ तक भारत भूटान सम्बन्ध के संक्षिप्त इतिहास का प्रश्न है आज से लगभग ५०० वर्ष पूर्व तिब्बत के खामा प्रान्त के लोग यहाँ आकर बस गये और धीरे-धीरे उन्होंने इस पर कब्जा कर लिया। आगे चलकर वर्तमान महाराजा के पूर्वजों ने लामाओं के प्रभुत्व को समाप्त कर दिया और भूटान पर अपना आधिपत्य जमा लिया। भारत-भूटान सम्बन्धों की शुरुआत १८६५ की सन्धि जो कि भारत की ब्रिटिश सरकार और भूटान के मध्य हुई थी, के द्वारा भूटान को भारतीय रियासत का रूप प्रदान किया गया था। उसके बाद १९१० में पुनरवा सन्धि द्वारा इन सम्बन्धों को सुदृढ़ किया गया। इस सन्धि के अन्तर्गत तत्कालीन ब्रिटिश भारत सरकार ने भूटान के आन्तरिक मामलों में हस्तक्षेप न करने और भूटान ने विदेशी मामलों में भारत से निर्देशित होना स्वीकार कर लिया।

अगस्त १९४९ में भूटान सरकार ने स्वतन्त्र भारत की सरकार

से एक नई सन्धि की समे पुनरवा सन्धि की अनेक धाराओ का उल्लेख किया।

इसमे दोनो देशो ने चिरस्थायी शान्ति और मित्रता को सुनिश्चित करने का आश्वासन दिया। इस सन्धि के अनुसार भूटान और भारत का सम्बन्ध पूर्ववत् बनाये रखने का निश्चय किया गया। भारत ने भूटान के आन्तरिक मामलो मे हस्तक्षेप न करने का वचन दिया। सन्धि के अनुच्छेद २ मे कहा गया कि भूटान सरकार विदेशी मामलो मे भारत सरकार की सलाह को मार्गदर्शन के नाते मानने के लिए सहमत है। यह भी व्यवस्था की गयी कि भारत ५ लाख रुपये वार्षिक सहायता देगा। सिक्किम ने सन्धि के जरिये उसका वैदेशिक सम्बन्ध और प्रतिरक्षा का भार भारत को सौंप दिया था। लेकिन भूटान ने इस सन्धि के द्वारा केवल विदेश नीति का भार ही भारत को सौंपा था। भारत चीन युद्ध के बाद भूटान ने प्रतिरक्षा का भार भी भारत को सौंप दिया¹⁸।

नेहरू और श्रीमती इन्दिरा गांधी के प्रधानमन्त्रित्व काल मे भारत और भूटान के सम्बन्ध बहुत मधुर रहे। भारत ने भूटान के विकास मे सक्रिय रुचि ली और उसे आर्थिक सहायता दी ।

३० करोड रुपये की लागत से भारतीय सीमा सडक सगठन ने भूटान मे १००० किलोमीटर लम्बी सडक का निर्माण किया। चीन भूटान के ३०० वर्गमील क्षेत्र पर दावा करता है इस क्षेत्र मे भी एक सडक बनायी गयी। भूटानी विद्यार्थी भारत मे शिक्षा ग्रहण करने आने

लगे। भारत ने भूटान में हवाई पट्टियाँ भी बनायीं जिन पर हेलीकाप्टर उड़ सकते हैं। भारत के सहयोग से ही भूटान की नयी राजधानी थिम्पू का निर्माण किया गया। भूटान के दूसरे महत्वपूर्ण नगर पारो का विकास भी भारत के सहयोग से हुआ। भारत ने भूटान में विद्यालय और अस्पताल बनवाये।

१९७० में भूटान ने संयुक्त राष्ट्र सभा का सदस्य बनने के लिए प्रार्थना-पत्र दिया जिसका भारत ने समर्थन किया। सितम्बर १९७१ में भूटान संयुक्त राष्ट्र सभा का सदस्य बन गया। बंगला देश के सफ़ट के समय भूटान ने भारत को नैतिक समर्थन प्रदान किया तथा भूटान ने भारत के तुरन्त बाद बंगला देश को मान्यता दे दी। १३-१४ अगस्त १९७६ को भूटान नरेश गुटनिरपो राष्ट्रो के शिखर सम्मेलन में भाग लेने जाते हुए दिल्ली रुके। इस गुटनिरपेक्ष सम्मेलन में भूटान ने भारत की अच्छे पड़ोसी की नीति की प्रशंसा की।

सन १९७३ में सिक्किम के भारत विलय की घटना ने भूटान पर गहरा प्रभाव डाला और भूटान ने बड़ी बारीकी के साथ अन्य देशों से मेल-मिलाप बढ़ाने का अभियान छोड़ा। १९७४ में भूटान नरेश के राज्यारोहण के अवसर पर भूटान ने १९४९ की सन्धि की धारा २ की व्याख्या का प्रश्न उठाया। भूटान ने इसकी यह व्याख्या करने का प्रश्न किया कि भूटान वैदेशिक सम्बन्धों के मामले में भारत के परामर्श को मानने के लिए बाध्य नहीं^{१९}।

जहा तक मे जनता पार्टी शासन और भारत भूटान सम्बन्धो का प्रश्न है भारत और भूटान के सम्बन्धो मे प्रकट रूप से कोई तनाव नही था किन्तु जनता पार्टी के शासन के दौरान दो छोटी-छोटी समस्याओ का समाधान हुआ। एक तो १९७२ के व्यापार समझौते की धारा ५ के अनुसार भूटानियो पर भी विदेशी व्यापार के सम्बन्ध मे वे ही कानून-कायदे लागू होते थे जो कि भारतीय व्यापारियो पर होते थे। भूटान की माग थी कि इस अडचन को हटाया जाये। विदेश मन्त्री वाजपेयी की भूटान यात्रा के दौरान इस समस्या का समाधान हुआ। दूसरा भूटान की इस पुरानी माग को भी स्वीकार किया गया कि उसे नई दिल्ली मे राजदूतावास खोलने दिया जाये। जनता शासन ने भूटानी मिशन को न केवल राजदूतावास को दर्जा दिया अपितु उसे बगला देश से भी राजनयिक सम्बन्ध स्थापित करने की सुविधा दी गयी। दोनो देशो के सम्बन्धो को घनिष्ठ बनाने के लिए भूटान के युवा नरेश जिग्मे सिधे वागचुक ने दो बार भारत की यात्रा की तथा भारतीय विदेश मन्त्री वाजपेयी भी एक बार भूटान गये। वाजपेयी ने दावा किया कि भारत और भूटान के सम्बन्ध अत्यन्त उत्तम है तथा जो कुछ छोटी-मोटी अडचने थी उन्हें दूर कर दिया गया है²⁰।

मार्च १९७८ मे भूटान नरेश भारत आये तो भारत ने भूटान को चौथी पंचवर्षीय योजना के लिए ७० करोड रूपये का अनुदान स्वीकार किया। यह योजना कुल ७७ करोड रूपये की थी। इस

अवसर पर भूटान नरेश वागचुक ने कहा था कि भूटान को भारत की मित्रता पर भरोसा है।

जून १९८१ में विदेश मंत्री पी वी नरसिम्हा राव थिम्पू की सदभावना यात्रा पर गये। भारत ने भूटान की पाचवी विकास योजना के लिए १३९ करोड़ रुपये देने का प्रस्ताव किया। भूटान को पारो से कलकत्ता तक अन्तर्राष्ट्रीय विमान सेवा प्रारम्भ करने की अनुमति दी गयी। असम-पश्चिम बंगाल के साथ सीमा निर्धारण के लिए खम्भे लगाये गये और भारत ने भूटान में रहने वाले १५०० तिब्बती शरणार्थियों को लेना स्वीकार कर लिया। भारत और भूटान के बीच १० दिसम्बर, १९८३ को एक व्यापारिक समझौता हुआ। इसमें भारत ने वायदा किया कि भारत भूटान के व्यापार को अन्य बाहरी देशों के साथ बढ़ाने में मदद करेगा। सन १९८४ में भारत और भूटान के बीच दूर संचार और माइक्रोवेव की व्यवस्था की गयी।

जहां तक भारत और भूटान के बीच मतभेद के मुद्दों का प्रश्न है भारत और भूटान के बीच कुछ मनमुटाव १९४९ की भारत-भूटान मैत्री की धारा २ की व्याख्या को लेकर है। इस धारा में कहा गया है कि भारत भूटान के आन्तरिक मामलों में कोई दखल नहीं देगा, लेकिन विदेशी मामलों में भूटान को भारत की सलाह-मशविरा से ही चलना पड़ेगा। भूटान का मत है कि इस धारा की मनचाही व्याख्या नहीं की जा सकती। भारत का मत है कि १९४९ की सन्धि के तहत

भारत भूटान की रक्षा के लिए बाध्य है। भूटान इस प्रकार की व्याख्या का खण्डन करता है। कामचलाऊ सरकार के समय वागचुक ने १९४९ की सन्धि की धारा २ पर पुनर्विचार की बात कही थी²¹।

भारत-भूटान सम्बन्धों में कतिपय गौड़ मुद्दों को लेकर भी उत्तेजना पैदा होती जा रही है। ये हैं - भूटान के आयात-निर्यात पर भारत के कानूनों का लागू होना। १९७२ के व्यापार समझौते की धारा पाच में इसकी व्यवस्था है। नवम्बर १९७७ में भारत के तत्कालीन विदेश मन्त्री अटल बिहारी वाजपेयी ने अपनी भूटान यात्रा के दौरान उसे आश्वासन दिया था कि ये नियम अब भूटान के माल पर लागू नहीं होंगे। पर्यटकों के लिए आन्तरिक रेखा परमिट व्यवस्था। भूटान का मत है कि विदेशी पर्यटकों को भूटान आने में परमिट न मिलने से राजस्व की हानि होती है अतः इसमें भारत को उदार नीति अपनानी चाहिए²²।

विभिन्न अन्तर्राष्ट्रीय मुद्दों पर भी भूटान ने भारतीय दृष्टिकोण से भिन्न नीति अपनायी है। हवाना गुटनिरपेक्ष सम्मेलन १९७९ में जहाँ भारत बहुसंख्यक निर्गुट देशों के साथ कम्पूचिया की सीट को खाली रखने के पक्ष में था वहाँ भूटान ने कम्पूचिया की सीट पोल पोत समूह को देने की वकालत की। भारत जहाँ परमाणु अप्रसार सन्धि को पक्षपातपूर्ण मानता है वहाँ भूटान इस सन्धि के पक्ष में है। जून १९८१ में भूटानी विदेश मंत्री ने राष्ट्रीय असेम्बली में घोषणा की कि भूटान चीन के साथ सीधे द्विपक्षीय वार्ता करना चाहता है ताकि

भूटान-चीन सीमा को चिन्हित किया जा सके।

चीन की भूटान में घुसपैठ निश्चित ही भारत की चिन्ता का कारण है। चीन ने पिछले दिनों में पशुओं को चराने के बहाने भूटान की सीमाओं का अतिक्रमण किया। तिब्बती काफी अन्दर तक भूटान की सीमाओं में चले आये। दूसरा भारत की चिन्ता का कारण भूटान में रह रहे वे ४००० तिब्बती शरणार्थी हैं जो १९५९ से वहाँ रह रहे हैं और जिन्हें भूटान की राष्ट्रीय असेम्बली ने १९७९ में एक प्रस्ताव पास कर कहा है कि वे या तो भूटान की नागरिकता स्वीकार करें और भूटान समाज में घुल-मिल जायें या फिर उन्हें निकाल बाहर किया जाये अर्थात् उन्हें तिब्बत वापस भेज दिया जाये। इस चेतावनी के पीछे चीन का हाथ है जो भारत के राष्ट्रीय हित और आदर्श के विपरीत है। यदि तिब्बती शरणार्थी भूटान नेपाल या भारत की नागरिकता ग्रहण कर लेते हैं तो फिर तिब्बत की स्वाधीनता का मसला ही समाप्त हो जाता है।

समीक्षाधीन वर्ष के दौरान भारत और भूटान के बीच परम्परागत निकट और मैत्रीपूर्ण संबंध और भी मजबूत हुए सितम्बर १९८६ में हरारे में आयोजित नाम शिखर सम्मेलन और १९८६ में १५से१७ नवम्बर तक बंगलूर में सम्पन्न सार्क शिखर सम्मेलन में भूटान नरेश और प्रधानमंत्री श्री राजीवगान्धी को आपसी हितों से संबंधित मामलों पर उच्चतम स्तर पर विचार करने का मौका मिला।

इन दोनों देशों के बीच विद्यमान सहयोग और विश्वास के सबधों को परिलक्षित करती है। भारत और भूटान के परम्परागत रूप से निकट और मैत्रीपूर्ण सबध और सुदृढ़ हुये²³। नवम्बर १९८७ में काठमाण्डू में हुये सार्क शिखर सम्मेलन में भूटान नरेश एव प्रधान मंत्री के बीच आपसी हितों के मामलों पर उच्च स्तर पर बातचीत करने का अवसर प्राप्त हुआ। वार्ताओं में आपसी हित के मामलों पर विशेष रूप से विचारों की सामंजस्यता परिलक्षित हुयी जिससे दो देशों के बीच मौजूदा आपसी विश्वास और सहयोग सबधों का पता चलता है। आर्थिक क्षेत्र में सहयोग बढ़ा है और भारत में विभिन्न क्षेत्रों में भूटान को विशेषज्ञ उपलब्ध कराये हैं²⁴।

भारत और भूटान के बीच परम्परागत घनिष्ठ और मैत्रीपूर्ण सबध और मजबूत हुये। महत्वपूर्ण यात्राओं का आदान प्रदान हुआ। १९८९ में भारत की तरफ से विदेश सचिव तत्कालीन प्रधान मंत्री श्री राजीवगान्धी और राष्ट्रपति श्री आर वेङ्कटरामन ने भूटान की यात्रा की। भूटान से वहाँ के योजना उपमन्त्री श्री दाशो चेक्याब दोरजी और विदेश मंत्री श्री ल्योरो दावा त्सेरिंग ने भारत की यात्रा की। इन यात्राओं के दौरान परस्पर हित के विषयों पर लाभदायक विचार विमर्श किया गया। आर्थिक क्षेत्र के सहयोग में उल्लेखनीय वृद्धि हुयी। अक्टूबर १९८८ में प्रतिष्ठित चुखा पनबिजली परियोजना जो पूरी तरह भारतीय सहायता से बनायी गयी थी का राष्ट्रपति श्री

आर वेक्टरामन और भूटान नरेश ने सयुक्त रूप से उदघाटन किया। भारत भूटान को वानिकी उद्योग, दूरसंचार पनबिजली सर्वेक्षण और शिक्षा आदि जैसे क्षेत्रों में विशेषज्ञों और प्रौद्योगिकविदों की सेवाएँ उपलब्ध कराता रहा है²⁵।

पाद टिप्पणिया

- 1 Mukherjee Dilip Dealing with Nepal (Times of India June 6 1990)
- 2 Ramakant Nepal, China and India Page 84
- 3 Singh, L P India s Foreign Policy – The Shastri Period Page 103
- 4 Prasad Bimal India s Foreign Policy Studies and continuity and Change Page 139
- 5 Ramakant Nepal China and India Page 99
- 6 Times of India- 24 9 1964
- 7 Subramanyam, K Out national Security Page 168
- 8 Tharoor S Reasons of State-Political Development and India s Foreign Policy Under Indira Gandhi, 1966 67 Page 113
- 9 Dutt P V India Foreign Policy Page 169
- 10 Times of India 27 5 1991
- 11 'भारत १९८६' - सूचना एव प्रकाशन विभाग भारत सरकार - पृष्ठ - ७१८ ७१९
- 12 भारत १९८७' सूचना एव प्रकाशन विभाग भारत सरकार पृष्ठ ५१५
- 13 भारत १९८७ - सूचना एव प्रकाशन विभाग भारत सरकार पृष्ठ ५१५
- 14 'भारत १९८८ - सूचना एव प्रकाशन विभाग भारत सरकार पृष्ठ ५५६
- 15 भारत १९९०' सूचना एव प्रकाशन विभाग भारत सरकार पृष्ठ ६४५
- 16 Murty K S India Foreign Policy Page 112
- 17 Appadora, A and Rajan, M S India s Foreign Policy and Relation Page 165
- 18 Prasad Biman India's Foreign Policy Studies and continuity and change Page 239
- 19 Murti, K S India Foreign Policy Page 113
- 20 Appadora A and Rajan, M S India s Foreign Policy and Relation Page 191
- 21 Subramanyam, K. Our national Security Page 107
- 22 Times of India Editorial – 23 11 1977
- २३ 'भारत १९८७' - सूचना एव प्रकाशन विभाग भारत सरकार - पृष्ठ ५१५
- २४ भारत १९८८-८९ - सूचना एव प्रकाशन विभाग भारत सरकार - पृष्ठ - ५५६
- 25 'भारत १९९०' - सूचना एव प्रकाशन विभाग भारत सरकार पृष्ठ - ६४६

અધ્યાય-૫

14 अगस्त, 1947 की आधी रात भारत ब्रिटिश दासता से मुक्त तो हुआ किन्तु वृहत्तर भारत का अविभाज्य अंग पाकिस्तान विभाजित हो गया । समान संस्कृति भाषा बोल-चाल और परम्पराओं के बावजूद भारत के पाकिस्तान से सम्बन्ध विभाजन के समय की गयी भूलों और पाकिस्तानी कटकरता के कारण सदा से ही कटु रहे । इस अध्याय में भारत - पाक सम्बन्धों की पेचीदगियों का विश्लेषण तथा राजीव गांधी के प्रधानमन्त्रित्व काल में किये गये समझौता प्रयासों का विवेचन किया जायेगा ।

एशिया महाद्वीप में ब्रिटिश उपनिवेशवाद की समाप्ति के साथ एक नये संघर्ष की शुरुआत हुई जिसके परिणामस्वरूप इस क्षेत्र से 'शान्ति' शब्द का लोप ही हो गया । यह संघर्ष है दो पड़ोसी देशों का संघर्ष जिसे भारत पाक संघर्ष के नाम से जाना जाता है । भारत विभाजन के समय की घृणा और अविश्वास ने दोनों ही देशों को आज तक युद्ध की तैयारी में लगाये रखा । प्रारम्भ से ही दोनों देशों की सेनाएँ एक दूसरे के आमने सामने न केवल तैनात रही, अपितु तीन बड़े युद्ध हुए और एक छोटी सी चिनगारी से किसी भी दिन चौथा युद्ध शुरू हो जाये तो आश्चर्य नहीं¹ । पाकिस्तान की विदेश नीति का आधार शुरू से ही भारत विरोध रहा है । पाकिस्तान मुस्लिम लीग की हिन्दुओं के प्रति घृणा की नीति का फल है, इसलिए पाकिस्तान के शासकों के लिए यह आवश्यक हो गया कि वे भारत विरोध की नीति अपनाएँ, क्योंकि यदि वे ऐसा नहीं करते हैं

तो उसके जन्म का आधार नष्ट हो जाता है। कश्मीर का प्रश्न इस नीति की प्रमुख अभिव्यक्ति है कश्मीर को प्राप्त करने के लिए कभी अमेरिका और ब्रिटेन का पिछलग्गू बने रहने की नीति तो कभी चीन की चापलूसी यही संकेत देती कि उसका भारत विरोध हमेशा बना रहेगा।

भारत पाक संघर्ष की प्रकृति को सही रूप से समझने के लिये भारत विभाजन में निहित तथ्यों का वस्तुनिष्ठ अध्ययन अपरिहार्य है। विभाजन की घटना ने दो समुदायों के बीच घृणा अविश्वास और वैमनस्य को क्रूरतम ढंग से उजागर किया है। विभाजन के बाद सभी समस्याओं के स्वतः ही सुलझ जाने का सपना देखते वालों ने जब वास्तविकता पर नजर दौड़ाई तो उन्हें घोर निराशा हुई। पाकिस्तान के जन्म से ही समस्याएँ सुलझने की अपेक्षा अधिक उलझती चली गयी और इस महाद्वीप में नये संघर्ष का सूत्रपात हुआ जो अपनी पुष्टि से कहीं अधिक गहरा और पेचीदा था²।

कुलदीप नैयर के शब्दों में 'विभाजन के लिए आप किसी को भी दोषी ठहराये वास्तविकता यह है कि इस पागलपन की दो समुदायों और दो देशों के बीच दो पीढ़ियों से भी अधिक समय तक के लिए सम्बन्धों में कड़वाहट उत्पन्न कर दी। दोनों देशों में हर समय और हर कदम पर मतभेद बढ़ता गया और छोटी से छोटी बात में बड़े विवाद का रूप धारण कर लिया'³ माइकल ग्रेशर ने ठीक ही

लिखा है 'भारत और पाकिस्तान हमेशा अघोषित युद्ध में रहे हैं।' भारत पाक सबंधों की चर्चा करते हुये प० नेहरू ने भारतीय ससद में स्पष्ट कहा कि लोगों में यह भ्रान्ति पूर्ण धारणा है कि कश्मीर विवाद ही दोनों देशों के संघर्ष का कारण है। हमारी मूलभूत विचार धारा ही भिन्न है। हम धर्म निरपेक्षवाद में विश्वास करते हैं। किन्तु पाकिस्तान इस्लामवाद और दुराष्ट्र सिद्धांत में विश्वास करता है। इस सिद्धांत के अनुसार कश्मीर में मुसलमानों का बहुमत पाकिस्तान के लिये एक असहनीय तथ्य है। भारत के प्रति शत्रुता का विचार पाकिस्तान की धार्मिक राजनीति का एक अनिवार्य अंग बन गया है⁴।

जहां तक भारत पाक संबंधों को प्रभावित करने वाली समस्याओं का प्रश्न है भारत पाक संबंधों को प्रभावित करने वाली समस्याएँ मुख्यतः तीन प्रकार की हैं।

विभाजन से उत्पन्न होने वाली समस्याएँ

भारत विरोधी नीति अर्थात् जेहाद (धार्मिक युद्ध) की नीति से

उत्पन्न होने वाली समस्या तथा

पाकिस्तान की सीटों सेण्टों की सदस्यता तथा भारत की किलेबंदी से उत्पन्न होने वाली समस्या।

सर्वप्रथम हम विभाजन से उत्पन्न होने वाली समस्याओं को लेते हैं। भारतीय नेताओं को आशा थी कि देश के विभाजन से शान्ति और आपसी मेल-जोल को बढ़ावा मिलेगा और दोनों देश शान्ति सद्भावना और सहयोग के वातावरण में आर्थिक विकास के

लम्बे और कठिन कार्य में जुट जाएंगे। लेकिन पाकिस्तान के जन्म के साथ ही कुछ ऐसी समस्याएँ उत्पन्न हो गयीं जिनके कारण प्रारम्भ से ही दोनों देशों के मध्य सबंधों में कटुता आ गयी। ये समस्याएँ थीं- क- हैदराबाद विवाद ख- जूनागढ़ विवाद ग- ऋण की अदायगी का प्रश्न घ- नहरी पानी विवाद च- शरणार्थियों का प्रश्न छ-कश्मीर विवाद⁵।

जहाँ तक हैदराबाद विवाद का प्रश्न है हैदराबाद भौगोलिक दृष्टि से भारत के अन्तर्गत मिल सकता था। रियासत के निजाम का रवैया बहुत ही अस्पष्ट और अनिश्चयात्मक था। पाकिस्तान ने हैदराबाद को इस भ्रम में रखा कि मुसीबत के समय वह उसके साथ है। हैदराबाद का निजाम एक स्वतंत्र राज्य स्थापित किये जाने का स्वप्न सजोये था। किन्तु भ्रम बनाये रखने के लिये वह भारत के साथ विलय की बातचीत भी करता रहा। निजाम का मूल लक्ष्य दक्षिणी भारत में मुस्लिम वर्चस्व स्थापित करना था। पाकिस्तान के सहयोग और निजाम के आशीर्वाद से राजकारों ने मारकाट, लूटमार और हत्यारों के माध्यम से इस क्षेत्र में भयावह स्थिति उत्पन्न कर दी। परिणाम स्वरूप भारत को सैनिक कार्यवाही करनी पड़ी। हैदराबाद रियासत को भारत में सम्मिलित कर लिया गया। और निजाम को ५० लाख रुपये प्रिवीपर्स के रूप में देना तय किया। पाकिस्तान ने इस प्रश्न को तीन बार संयुक्त राष्ट्र सभ में उठाया किन्तु अमरीका के सिवाय उसमें किसी ने भी दिलचस्पी नहीं ली।

अब हम लेते हैं जूनागढ़ विवाद को । जूनागढ़ काठियावाड़ की एक छोटी सी रियासत थी जिसका शासक मुस्लिम था । उसने रियासत को पाकिस्तान में सम्मिलित करने की घोषणा कर दी और पाकिस्तान ने उसका सम्मिलन स्वीकार कर लिया जबकि वहाँ की अधिकांश जनसंख्या हिन्दू थी । रियासत की जनता ने नवाब को पाकिस्तान भागने के लिये बाध्य कर दिया और नवम्बर १९४७ में मुस्लिम दीवान को बाध्य होकर भारत सरकार को हस्तक्षेप के लिये आमंत्रित करना पड़ा । लोगों की इच्छा को ध्यान में रखते हुये जनमत संग्रह के बाद जूनागढ़ के मामले को लेकर भारत विरोधी प्रचार किया ।

जहाँ तक ऋण की अदायगी का प्रश्न है विभाजन के उपरान्त भारत और पाकिस्तान के बीच कई आर्थिक समस्याएँ थी । दोनों देशों के आमदनी और कर्ज का बटवारा एवं लागत धन के बीच सतोषजनक बटवारा करना था । मुद्रा के सबंध में निर्णय लेना था । व्यापारिक सबंध में तनावपूर्ण शुरु हुई क्योंकि पाकिस्तान ने तुरन्त ही जूट के निर्यात पर प्रतिबंध लगा दिया । आर्थिक समस्याओं में सबसे कठिन विस्थापितों की सम्पत्ति की समस्या थी । जो हिन्दू शरणार्थी पाकिस्तान में अपनी सम्पत्ति छोड़कर आये थे उसका मूल्य तीन हजार करोड़ रुपये था । जबकि जो मुसलमान भारत में अपनी सम्पत्ति छोड़कर गये थे उसका मूल्य ३०० करोड़ रुपये था । १९५० में नेहरू - लियाकत अली समझौते द्वारा इस समस्या का समाधान

किया गया ।

विभाजन के बाद भारत-पाकिस्तान दोनों सरकारों के दायित्व और लेनदारी को समान अनुपात में बाटा जाना चाहिये था परन्तु सौजन्यवश भारत सरकार ने ब्रिटिश सरकार के सारे ऋण व्यापार को स्वीकार किया । इसके उपलक्ष्य में भारत को ३०० करोड़ रुपया प्रतिवर्ष पाकिस्तान सरकार से मिलना था और यह ५ वर्ष बाद दिया जाना तय हुआ । परन्तु पाकिस्तान सरकार इस ऋण देने में टाल-मटोल करने लगी । दूसरी तरफ भारत को ५५ करोड़ रुपया रक्षा सग्रह का पाकिस्तान को देना था । गांधी जी ने दोनों देशों में मधुर सबंध बनाने हेतु यह रुपया भारत सरकार से पाकिस्तान को दिलवा दिया जब कि नेहरू और पटेल का मत था कि वह रुपया पाकिस्तान को नहीं दिया जाना चाहिये था । उस समय कश्मीर में युद्ध चल रहा था और नेहरू व पटेल का विचार था कि इस धन का उपयोग पाकिस्तान और अधिक हथियार खरीदकर युद्ध तेज करने के लिये करेगा ।

अब हम लेते हैं नहरी पानी विवाद पर । पंजाब के राजनीतिक विभाजन के कारण यह नहरी पानी विवाद उठ खड़ा हुआ । ये नहरे आर्थिक दृष्टिकोण से उस समय बनायी गयी थी जब विभाजन का विचार तक किसी के मस्तिष्क में न था । विभाजन के कारण नहरों के पानी का असंतुलित विभाजन हो गया । पंजाब की पॉंचो नदियों में से सतलज और रावी दोनों देशों के मध्य से बहती हैं । परन्तु

शरणार्थियों का प्रश्न भी महत्वपूर्ण मुद्दा बना रहा । विभाजन के बाद मुस्लिम लीग ने पाकिस्तान में साम्प्रदायिक दंगे करवाये जिससे हजारों के सख्या में शरणार्थी भारत भाग कर आ गये । पाकिस्तान में हिन्दुओं का जीवन और इज्जत सुरक्षित नहीं था । हजारों व्यक्ति वहाँ मौत के घाट उतार दिये गये । हजारों महिलाओं के साथ बलात्कार हुए जिसकी भारत में भी प्रतिक्रिया होना स्वाभाविक था । यहाँ भी कई स्थानों पर दंगे हुए और मुसलमान भागने लगे। भारत की धर्म निरपेक्ष सरकार उनकी रक्षा नहीं करती थी । इसलिये जितनी बड़ी सख्या में विस्थापित पाकिस्तान से आये उतनी बड़ी सख्या में भारत से पाकिस्तान नहीं गये। आज भी हिन्दू शरणार्थियों पर पाकिस्तान में साम्प्रदायिक अत्याचार बदनसूर जारी रहने के कारण हिन्दू अल्पसंख्यक भारत को पलायन करने पर मजबूर हैं ।

सबसे गंभीर मसला कश्मीर विवाद को लेकर है । कश्मीर की समस्या दोनों देशों के बीच एक ऐसे ज्वालामुखी की तरह है जो समय-समय पर लावा उगलती रहती है । अलाप माइकल के शब्दों में, कश्मीर समस्या अनिवार्यतः भूमि या पानी की समस्या नहीं यह लोगों के प्रतिष्ठा की समस्या है ।

कश्मीर की समस्या भारत और पाकिस्तान के बीच सबसे उलझी हुयी समस्या है । स्वतंत्रता के बाद जहाँ भारत और पाकिस्तान दो नये राज्य बने वहाँ देशी रियासते एक प्रकार से स्वतंत्र हो गयी

ब्रिटिश सरकार ने घोषणा कर दी थी कि देशी रियासते अपनी इच्छानुसार भारत अथवा पाकिस्तान में विलय हो सकती हैं। अधिकांश रियासते भारत अथवा पाकिस्तान में मिल गयीं और उनकी कोई समस्या उत्पन्न नहीं हुई। भारत के लिए हैदराबाद और जूनागढ़ ने अवश्य समस्या उत्पन्न कर दी थी परन्तु वह शीघ्र ही हल कर ली गई। कश्मीर की स्थिति कुछ विशेष प्रकार की थी। भारत के उत्तर पश्चिम सीमा पर स्थित यह राज्य भारत अथवा पाकिस्तान दोनों को जोड़ता है। यहाँ की जनसंख्या का बहुसंख्यक भाग मुस्लिमधर्मी था परन्तु यहाँ का आनुवंशिक शासक एक हिन्दू राजा था। अगस्त १९४७ में कश्मीर के शासक ने अपने विलय के विषय में कोई तत्कालीन निर्णय नहीं लिया। पाकिस्तान इसे अपने साथ मिलाना चाहता था। २२ अक्टूबर, १९४७ को उत्तर पश्चिम सीमा प्रान्त के कवालियों ने एक अनेक पाकिस्तानियों ने कश्मीर पर आक्रमण कर दिया। पाकिस्तान ने अपनी सीमा पर भी सेना का जमाव कर लिया। चार दिनों के भीतर ही हमलावर आक्रमणकारी श्रीनगर से २५ मील दूर बारामूला तक जा पहुँचे। २६ अक्टूबर को कश्मीर के शासक ने आक्रमणकारियों से अपने राज्य को बचाने के लिए भारत सरकार से सैनिक सहायता की मांग की और साथ ही कश्मीर को भारत में सम्मिलित करने की प्रार्थना भी की। भारत सरकार ने इस प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया। २७ अक्टूबर को भारतीय सेनाये कश्मीर भेज दी गई तथा युद्ध समाप्ति पर जनमत

संग्रह की शर्त के साथ कश्मीर को भारत का अंग मान लिया गया। भारत द्वारा कश्मीर की सुरक्षा के निर्णय के कारण और उधर पाकिस्तान द्वारा आक्रमणकारियों को सहायता देने की नीति के कारण कश्मीर दोनों राष्ट्रों की बीच युद्ध का क्षेत्र बन गया। प्रारम्भ में भारत सरकार ने पाकिस्तान सरकार से प्रार्थना की कि कबायलियों का मार्ग बन्द कर दे परन्तु जब इस बात के प्रमाण मिलने लगे कि पाकिस्तान सरकार स्वयं इन कबायलियों की सहायता कर रही है तो १ जनवरी १९४८ को भारत सरकार ने सुरक्षा परिषद में यह शिकायत की कि पाकिस्तान से सहायता प्राप्त करके कबायलियों ने भारत के एक अंग कश्मीर पर आक्रमण कर दिया है जिससे अन्तर्राष्ट्रीय शान्ति और सुरक्षा को खतरा है। दूसरी तरफ पाकिस्तान ने भारत पर आरोप लगाया कि कश्मीर का भारत में विलय अवैधानिक है। सुरक्षा परिषद ने इस समस्या का समाधान करने के लिये चेकोस्लोवाकिया, अर्जेन्टाइना, अमेरिका, कोलम्बिया और बेलजियम को सदस्य नियुक्त कर मौके पर स्थिति का अवलोकन करके समझौता कराने के उद्देश्य से संयुक्त राष्ट्र आयोग की नियुक्ति की।

संयुक्त राष्ट्र आयोग ने तुरन्त अपना कार्य प्रारम्भ कर दिया। और मौके पर स्थिति का अध्ययन कर १३ अगस्त १९४८ को दोनों पक्षों से युद्ध बन्द करने और समझौता करने हेतु निम्नांकित आधार प्रस्तुत किये-

- १- पाकिस्तान अपनी सेनाये कश्मीर से हटाने तथा कबायलियो और सामान्य रूप से कश्मीर मे न रहने वाले विदेशियो को भी वहा से हटाने का प्रयत्न करे।
- २- सेनाओ द्वारा खाली किये गये प्रदेश का शासन प्रबन्ध स्थानीय अधिकारी आयोग के निरीक्षण मे करे।
- ३- जब आयोग भारत को पाकिस्तान द्वारा उपर्युक्त वर्णित शर्तो को पूरा करने की सूचना दे तो भास्त भी समझौते के अनुसार अपनी सेनाओ का अधिकाश भाग वहा से हटा ले ।
- ४- समझौता होने तक भारत सरकार युद्धविराम के अन्दर उत्तनी ही सेनाये रखे जितनी की इस प्रदेश मे कानून एव व्यवस्था बनाये रखने के कार्य मे स्थानीय अधिकारियो को सहायता देने के लिए वाछनीय हो।

इस सिद्धान्त के आधार पर दोनो पक्ष एक लम्बी वार्ता के अनुसार १ जनवरी १९४९ को युद्धविराम के लिए सहमत हो गये। कश्मीर के विलय का अन्तिम फैसला जनमत सग्रह के माध्यम से किया जाना था। जनमत सग्रह की शर्तो को पूरा करने के लिए एक अमेरिकी नागरिक एडमिरल चेस्टर निमित्ज को प्रशासक नियुक्त किया गया। उन्होने जनमत सग्रह के सम्बन्ध मे दोनो पक्षो से बातचीत की किन्तु उसका कोई परिणाम नही निकला । अन्तिम मे उन्होने अपने पद से त्यागपत्र दे दिया।

युद्ध विराम रेखा निर्धारित हो जाने पर पाकिस्तान के हाथ मे

कश्मीर का ३२,००० वर्गमील क्षेत्रफल रहा । इसकी जनसंख्या ७ लाख थी । पाकिस्तान ने इस क्षेत्र को आजाद कश्मीर कहा। युद्ध विराम रेखा के इस पार भारत के अधिकार में ५३ ००० वर्गमील क्षेत्रफल था जिसकी जनसंख्या ३३ लाख थी ।

नेहरू जनमत संग्रह के लिये तैयार थे । संयुक्त राष्ट्र ने यह शर्त लगा दी कि पाकिस्तान द्वारा हस्तगत क्षेत्र से जब पाकिस्तानी सेना एवं कबायली पूर्णतया हट जायेगे तभी जनमत संग्रह होगा । पाकिस्तान आजाद कश्मीर से अपनी सेनाये हटाने के लिये तैयार न था । पाकिस्तान ने अमरीका से १९५४ में सैनिक सधि कर ली । वह १९५५ में बगदाद पैक्ट (सेण्टो) का भी सदस्य हो गया। उसने अपने कुछ अड्डे अमरीका को दे दिये। इससे भारत ने खतरा अनुभव किया। भारत का मत था कि पाकिस्तान कश्मीर लेने के लिए अपनी सैनिक शक्ति बढ़ा रहा है। अतः परिवर्तित अन्तराष्ट्रीय परिस्थितियों में जवाहर लाल नेहरू ने अपनी कश्मीर नीति में परिवर्तन कर लिया। उन्होंने निश्चय कर लिया कि कश्मीर में जनमत संग्रह कराना सम्भव नहीं है। इसी समय सोवियत संघ का कश्मीर के प्रश्न पर भारत को समर्थन मिल गया जिससे भारत की स्थिति मजबूत हो गयी। उसका भी अन्तराष्ट्रीय जगत तथा सुरक्षा परिषद में एक शक्तिशाली मित्र हो गया। १९५० में पण्डित नेहरू ने पाकिस्तान से युद्ध वर्जनक सन्धि करने का प्रस्ताव रखा परन्तु पाकिस्तान ने उसे ठुकरा दिया। ६ फरवरी १९५४ को कश्मीर की सविधान सभा ने एक प्रस्ताव पास

कर जम्मू कश्मीर राज्य का विलय भारत में होने की पुष्टि कर दी। भारत सरकार ने भारतीय संविधान में संशोधन कर १४ मई १९५४ को अनुच्छेद ३७० के अन्तर्गत कश्मीर को विशेष दर्जा दे दिया। २६ जनवरी १९५७ को जम्मू कश्मीर का संविधान लागू हो गया। उसके साथ ही जम्मू कश्मीर भारतीय संघ का एक अभिन्न अंग बन गया। इसके बाद भी पाकिस्तान बार-बार कश्मीर का प्रश्न उठाता रहा। २ जनवरी १९५७ को सुरक्षा परिषद में इस प्रश्न को उठाया गया। ब्रिटेन, फ्रांस और अमेरिका ने सुरक्षा परिषद में पाकिस्तान का समर्थन करते हुए कहा कि कश्मीर में संयुक्त राष्ट्र के तत्वावधान में जनमत संग्रह कराया जाय और संयुक्त राष्ट्र संघ की आपात सेना वहां भेजी जाय। भारत ने इस प्रस्ताव का घोर विरोध किया। भारत के समर्थन में सोवियत संघ ने इस प्रस्ताव पर अपने निषेधाधिकार का प्रयोग किया। भारतीय प्रतिनिधि कृष्णा मेनन ने अपने ७ घण्टे ४८ मिनट तक के लम्बे ऐतिहासिक भाषण में कहा कि मूल प्रश्न यह नहीं कि जम्मू कश्मीर में संविधान लागू हो या न हो। मूल समस्या यह है कि जम्मू कश्मीर से पाकिस्तानी सेनाएं अभी तक क्यों नहीं निकलीं। १९६२ में सुरक्षा परिषद में पाकिस्तान ने कश्मीर में आत्म निर्णय की मांग दोहराई। इस प्रस्ताव को सोवियत संघ ने वीटो द्वारा समाप्त कर दिया। जब-जब मौका मिलता है पाकिस्तान कश्मीर के प्रश्न को उठाता रहता है। अप्रैल १९८२ में जनरल जिया-उल-हक ने कहा कि कश्मीर एक अन्तर्राष्ट्रीय मुद्दा है।

मार्च १९८३ में नयी दिल्ली में आयोजित सातवें गुटनिरपेक्ष सम्मेलन में भी जनरल जिया ने कश्मीर को एक विवादास्पद मुद्दा बताया। सितम्बर १९९२ में गुट निरपेक्ष शिखर सम्मेलन (जकार्ता) के पूर्ण अधिवेशन में पाकिस्तानी प्रधानमंत्री नवाज शरीफ ने कश्मीर का मुद्दा फिर से उठाया। पाक प्रधानमंत्री बेनजीर भुट्टो ने संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार सम्मेलन जेनेवा १९९४ में भारत के विरुद्ध आरोप लगाया कि वह कश्मीर में मानवाधिकारों का उल्लंघन कर रहा है।

वस्तुतः भारत और पाकिस्तान के बीच कश्मीर तनाव का मुख्य कारण है। वह कश्मीर को अब भी एक समस्या मानता है। एक पाकिस्तानी पत्रकार के अनुसार हमारी भावनाएँ अब भी कश्मीर के बारे में वैसी ही हैं जैसी कि पहले थीं परन्तु एक बात याद रखनी चाहिए कि हमने १९७२ में शिमला सम्मेलन के दौरान भी कश्मीर देना स्वीकार नहीं किया था। भारत का मत है कि पाकिस्तान कश्मीर तथा अन्य कोई द्विपक्षीय मुद्दा संयुक्त राष्ट्र सभ के मंच से नहीं उठा सकता लेकिन पाकिस्तान इस दृष्टिकोण को स्वीकार नहीं करता।

१९६५ में भारत-पाक युद्ध अप्रैल १९६५ में कच्छ के रन को लेकर भारत एवं पाकिस्तान के बीच संघर्ष हो गया। पाकिस्तानी सेना की दो टुकड़ियाँ भारतीय क्षेत्र में आ घुसी और कच्छ के कई भागों पर अधिकार कर लिया। कच्छ के रन में उत्पात के साथ-साथ पाकिस्तान ने कश्मीर में भी घुसपैठ प्रारम्भ कर दी थी। यह घुसपैठ पूर्ण योजनाबद्ध थी। चीन की सहायता से हजारों पाकिस्तानी सैनिकों

को छापामार युद्ध में प्रशिक्षित किया गया था। योजना के अनुसार छापामार दस्ता शस्त्रों से सज्जित होकर असैनिक वेश में कश्मीर में घुसने वाला था। कश्मीर में आन्तरिक रूप से उपद्रव एवं तोड़-फोड़ द्वारा ऐसी स्थिति उत्पन्न करने की योजना थी जिससे भारतीय सेना को कश्मीर से भागना पड़े। पाकिस्तान का विश्वास था कि कश्मीर की मुस्लिम जनता छापामारों का साथ देगी। किन्तु यह विश्वास अन्त में असत्य प्रमाणित हुआ। ४ तथा ५ अप्रैल, १९६५ को हजारों पाकिस्तानी छापामार सैनिक कश्मीर में घुस आये^७। पाकिस्तानी घुसपैठ को सदैव के लिए रोकने के विचार से भारत सरकार ने उन स्थानों पर अधिकार करने का निर्णय किया जहाँ से होकर पाकिस्तानी घुसपैठिये कश्मीर के भारतीय हिस्से में आते थे। इसी बीच पाकिस्तान की नियमित सेना ने अन्तर्राष्ट्रीय सीमा रेखा को पार करके भारतीय भू-भाग पर आक्रमण कर दिया और पूर्ण रूप से युद्ध आरम्भ हो गया। ४ सितम्बर, १९६५ को सुरक्षा परिषद ने एक प्रस्ताव पास कर भारत और पाकिस्तान दोनों से अपील की कि वे युद्ध विराम करें। २२ सितम्बर १९६५ को दोनों देशों में युद्ध बन्द हो गया^८। भारत को युद्ध में ७५० वर्ग मील भूमि मिली जबकि पाकिस्तान को २१० वर्ग मील भूमि मिली। यह युद्ध भारत-पाकिस्तान के कटु सम्बन्धों की अन्तिम परिणति थी।

ताशकन्द समझौता में सोवियत प्रधानमंत्री ने पाकिस्तान के राष्ट्रपति अयूब खा और भारत के प्रधानमंत्री लालबहादुर शास्त्री को

वार्ता के लिए ताशकन्द में आमन्त्रित किया। ४ जनवरी १९६६ को यह प्रसिद्ध सम्मेलन प्रारम्भ हुआ और सोवियत संघ के प्रयत्नों के परिणामस्वरूप १० जनवरी १९६६ को प्रसिद्ध ताशकन्द सम्मेलन पर हस्ताक्षर हुए। समझौते के अन्तर्गत भारतीय प्रधानमंत्री एवं पाकिस्तान के राष्ट्रपति सहमत हुए कि-

- १ दोनों पक्ष जोरदार प्रयत्न करेंगे कि संयुक्त घोषणा-पत्र के अनुसार भारत और पाकिस्तान में अच्छे पड़ोसियों के सम्बन्ध निर्मित हों। वे राष्ट्र संघ के घोषणा-पत्र के अन्तर्गत पुनः दुहराते हैं कि बल प्रयोग का सहारा न लेंगे और अपने विवाद को शान्तिपूर्ण तरीके से सुलझावेंगे।
- २ दोनों देशों के सभी सशस्त्र सैनिक २५ फरवरी, १९६६ के पूर्व उस स्थान पर वापस चले जायेंगे जहाँ वे ५ अगस्त १९६५ के पूर्व थे और दोनों पक्ष युद्ध विराम की शर्तों का पालन करेंगे।
- ३ दोनों देशों के परस्पर सम्बन्ध एक दूसरे के आन्तरिक मामलों में हस्तक्षेप न करने की नीति पर आधारित रहेंगे।
- ४ दोनों देश एक दूसरे के विरुद्ध होने वाले प्रचार को निरुत्साहित करेंगे और दोनों देशों के मध्य मैत्रीपूर्ण सम्बन्धों की वृद्धि करने वाले प्रचार को प्रोत्साहन देंगे।
- ५ दोनों देशों के मध्य राजनयिक सम्बन्ध पुनः सामान्य रूप से स्थापित किये जायेंगे। दोनों देशों में एक दूसरे के उच्चायुक्त अपने पदों पर वापस जायेंगे।

- ६ दोनो देशो के मध्य आर्थिक एव व्यापारिक सम्बन्ध पुन सामान्य रूप से स्थापित किये जायेगे।
- ७ दोनो देश युद्धबन्दियों का प्रत्यावर्तन करेगे। एक दूसरे की हस्तगत की हुई सम्पत्ति की वापसी पर भी विचार करेगे।
- ८ दोनो देश सन्धि से सम्बन्धित मामलो पर विचार करने के लिए सर्वोच्च स्तर परएव अन्य स्तरों पर आपस में मिलते रहेगे।

यद्यपि इस समझौते के कारण भारत को वह सब प्रदेश पाकिस्तान को वापस देने पडे जो उसने अपार धन एव जन की हानि उठाकर प्राप्त किये थे तथापि यह समझौता निश्चय रूप से भारत और पाकिस्तान के सम्बन्धों में एक शान्तिपूर्ण मोड़ का प्रतीक बन गया¹³।

इधर पूर्वी पाकिस्तान (बंगलादेश) में असन्तोष बढ़ता जा रहा था। शेख मुजीबके नेतृत्व में बंगलादेश में स्वायत्तता का आन्दोलन प्रारम्भ हो गया। पूर्वी पाकिस्तान पूर्णतया मुजीब के साथ था। याहया खा ने बंगालियों पर अत्याचार करने प्रारम्भ कर दिये। पूर्वी बंगाल के घोर अत्याचारों से घबराकर बंगाली घरबार सामान छोड़, जान बचाने हेतु भारत की सीमा में प्रवेश करने लगे। १० हजार शरणार्थी प्रतिदिन भारत आने लगे। शरणार्थियों की संख्या भारत में १ करोड़ तक पहुँच गयी। इसी समय २ दिसम्बर, १९७१ को पाकिस्तानी वायुयानों ने भारत के हवाई अड्डों पर भीषण बमबारी कर दी। ४ दिसम्बर, १९७१ को भारतीय सेना ने जवाबी हमला किया। भारत के विमानों ने पाकिस्तान के महत्वपूर्ण हवाई अड्डों पर बम बर्षा की।

१६ दिसम्बर, १९७१ को ढाका में एक सैनिक समारोह में जनरल नियाजी ने भारत के ले कर्नल जगजीतसिंह अरोरा के सम्मुख आत्म-समर्पण कर दिया। उनके साथ ९३ हजार सैनिकों ने भी हथियार डाल दिये और उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया। बंगलादेश स्वतन्त्र हो गया तथा भारत ने एकतरफा युद्ध विराम कर दिया। भारत ने इस युद्ध में पाकिस्तान की ६ हजार वर्ग मील भूमि पर अधिकार कर लिया। पाकिस्तान में जनरल याहया खा के स्थान पर सत्ता जुल्फिकार अली भुट्टो के हाथ में आ गयी। भुट्टो और श्रीमती गांधी में पत्र व्यवहार हुआ और २८ जून, १९७२ को शिमला में दोनों देशों के मध्य वार्ता होना तय हुआ। ३ जुलाई १९७२ को दोनों देशों के बीच एक समझौता हो गया। इस समझौते के निम्नलिखित मुख्य उपबन्ध थे -

- १ दोनों सरकारों ने यह निश्चय किया कि दोनों देश परस्पर सघर्ष को समाप्त करते हैं जिससे दोनों देशों के सम्बन्धों में बिगाड़ उत्पन्न हुआ था।
- २ दोनों ही सरकारें अपनी सामर्थ्य के अनुसार एक-दूसरे के प्रति घृणित प्रचार नहीं करेंगी।
- ३ आपसी सम्बन्धों में समानता लाने की दृष्टि से - क दोनों राष्ट्रों के बीच डाक-तार सेवा, जल, थल, वायुमार्गों द्वारा पुनः संचार व्यवस्था स्थापित की जायेगी। ख एक-दूसरे देश के नागरिक और निकट आये इसलिए नागरिकों को आने-जाने की सुविधाएँ दी जायेगी।

ग जहा तक सम्भव हो सके व्यापारिक एव आर्थिक मामलो मे सहयोग का सिलसिला जल्द से जल्द शुरू हो। घ विज्ञान एव सांस्कृतिक क्षेत्रो मे आदान-प्रदान बढ़ाया जायेगा।

- ४ स्थायी शांति कायम करने की प्रक्रिया का सिलसिला आरम्भ करने के लिए दोनो सरकारे सहमत है कि क भारत और पाकिस्तान की सेनाये अपनी अन्तराष्ट्रीय सीमा मे लौट जायेगी। ख दोनो देश बिना एक-दूसरे की स्थिति को क्षति पहुचाये जम्मू-कश्मीर मे १७ दिसम्बर, १९७१ को हुए युद्ध विराम के फलस्वरूप नियन्त्रण रेखा को मान्य रखेगे। ग सेनाओं की वापसी इस समझौते के लागू होने के ३० दिन के भीतर पूरी हो जायेगी।

- ५ शिमला समझौते के क्रियान्वयन के लिए दोनो देशो के शासनाध्यक्ष परस्पर मिलते रहेगे ¹⁰।

शिमला समझौते के आलोचको का कहना है कि यह भारत का पाकिस्तान के समक्ष आत्मसमर्पण था। भारत के सैनिको ने जिसे युद्ध के मैदान मे जीता था उसे भारत की कूटनीति ने शिमला मे खो दिया। आलोचको का कहना है कि कश्मीर समस्या का स्थायी हल ढूढे बिना पाकिस्तान के ५,१३९ वर्ग मील क्षेत्र को लौटाना राजनीतिक सफलता नही कहा जा सकता। दूसरे शब्दो मे, आलोचको का कहना है कि शिमला समझौते ने कश्मीर पर पाकिस्तान से सौदेबाजी करने का अवसर हाथ से खो दिया।

२ भारत विरोधी नीति अर्थात् जेहाद (धार्मिक युद्ध) की नीति से उत्पन्न होने वाली समस्याएँ

भारत-पाक सम्बन्धों में कटुता और वैमनस्य कई बार पाकिस्तान के साम्प्रदायिक दृष्टिकोण से उत्पन्न हो जाता है। धार्मिक और साम्प्रदायिक वैमनस्य को पाकिस्तान के शासक जान-बूझकर बनाये रखना चाहते हैं। वे साम्प्रदायिक विष को अन्तर्राष्ट्रीय सम्मेलनों और सगठनों में भी अभिव्यक्त करते रहे। सितम्बर १९६३ में हजारतबल-काण्ड को लेकर पाकिस्तान ने कश्मीर में साम्प्रदायिक दंगे कराने का प्रयास किया। १९६५ में बड़े पैमाने पर कश्मीर में घुसपैठियों को भेजना शुरू कर दिया और विद्रोह भड़काने के लिए साम्प्रदायिक विष का सहारा लिया। १९६९ में रबात मुस्लिम शिखर सम्मेलन के समय तत्कालीन पाकिस्तानी राष्ट्रपति याहया खा ने भारतीय प्रतिनिधिमण्डल के साथ बैठने से इकार कर दिया।

३ पाकिस्तान की सीटों, सेण्टों की सदस्यता तथा भारत की किलेबन्दी से उत्पन्न होने वाली समस्या-

भारत-पाक संबंधों में कटुता पैदा करने वाली एक प्रमुख समस्या पाकिस्तान की गुटीय और शस्त्रों की होड़ की नीति है। वस्तुतः पाकिस्तान ने सीटों १९५५ और सेण्टों १९५५ जैसे सैनिक सगठनों का सदस्य बनकर शीत-युद्ध को भारत के दरवाजे पर लाकर खड़ा कर दिया। दूसरे, पाकिस्तान ने अपनी सैनिक शक्ति बढ़ाने के लिए भारत विरोधी प्रचार का सहारा लेकर, अमरीका से ही नहीं

बल्कि सेण्टो शक्तियो विशेषकर ईरान से प्रचुर मात्रा मे सैनिक सहायता प्राप्त की। भारत-चीन सबधो मे बिगाड आने से पाकिस्तान ने चीन की हमदर्दी प्राप्त करने की कोशिश की और उससे अस्त्र-शस्त्रो को प्राप्त किया। पश्चिमी शक्तिया भी इस उप-महा द्वीप मे पाकिस्तान को भारत के बराबर बनाये रखना चाहती है। वे समझती है कि यदि भारत को शांति का समय मिल गया तो वह महान शक्ति बन जायेगा। अतः अमरीका ने भारत के विरोध पर भी पाकिस्तान को अस्त्र-शस्त्र दिये¹¹।

पाकिस्तान द्वारा आतंकवाद को प्रोत्साहन- दुर्भाग्यवश पाकिस्तान द्वारा पंजाब और जम्मू-कश्मीर मे भारत के विरुद्ध आतंकवाद को लगातार सहायता पहुंचाने और उसे बढ़ावा दिये जाने के कारण दोनो देशो के बीच सबधो मे काफी कटुता उत्पन्न हुई। राजीव गांधी के सत्तासीन होने पर पाकिस्तान द्वारा अपनी प्रतिरक्षा जरूरतो से कही अधिक आधुनिक हथियार हासिल करने और परमाणु बम बनाने के प्रयास की संभावना से भारत को चिन्ता बनी जिससे पाकिस्तान नेताओं द्वारा उच्च स्तर पर दिये गये आश्वासनो के बावजूद सिख उग्रवादियो को सीमा पार से मदद दिया जाना जारी रहना भी भारत के लिए इतनी ही चिन्ता का विषय रहा फिर भी, इन घटनाओ के बावजूद भारत शिमला समझौते की भावना के प्रति अपनी वचनबद्धता के अनुरूप पाकिस्तान के साथ सौहार्दपूर्ण और सहयोगात्मक सबध विकसित करने के अपने प्रयास जारी रखे रहा।

पाकिस्तान के राष्ट्रपति श्री जिया-उल-हक के साथ हुई चार बैठकों के आधार पर वे १७ दिसम्बर १९८५ को नई दिल्ली की यात्रा पर आये जिसमें दोनों पक्षों ने घोषणा की कि वे एक दूसरे के परमाणु प्रतिष्ठानों पर हमला नहीं करेंगे। दोनों पक्षों ने सहयोग के विकास के रास्ते से बाधाओं को दूर करने के लिए द्विपक्षीय बैठकों का कार्यक्रम भी तय किया ¹²। राष्ट्रपति जिया और हमारे प्रधानमंत्री की बैठक के निर्णयों का पालन करते हुए जनवरी १९८६ में भारत के वित्त मंत्री ने पाकिस्तान की यात्रा की और आर्थिक और व्यापारिक सहयोग बढ़ाने पर वार्ता की। दोनों देशों के प्रतिरक्षा सचिव सियाचिन

ग्लेशियर क्षेत्र की स्थिति पर विचार करने के लिए मिले। दोनों देशों के विदेश सचिवों ने स्थाई शांति मैत्री और सहयोग के निर्माण के लिए संधि या समझौते का एक विस्तृत मसौदा तैयार करने के लिए विचार-विमर्श किया। लेकिन कुछ महत्वपूर्ण पहलुओं पर मतभेद बरकरार ¹³ है।

राजीव गांधी के सत्तासीन होने पर पाकिस्तान द्वारा अपनी प्रतिरक्षा जरूरतों से कहीं अधिक आधुनिक हथियार हासिल करने और परमाणु बम बनाने के प्रयास की संभावना से भारत को चिन्ता बनी, जिससे पाकिस्तान नेताओं द्वारा उच्च स्तर पर दिये गये आश्वासनों के बावजूद सिख उग्रवादियों को सीमा पार से मदद दिया जाना जारी रहना भी भारत के लिए इतनी ही चिन्ता का विषय रहा

फिर भी। इन घटनाओं के बावजूद भारत शिमला समझौते की भावना के प्रति अपनी वचनबद्धता के अनुरूप पाकिस्तान के साथ सौहार्दपूर्ण और सहयोगात्मक सबंध विकसित करने के अपने प्रयास जारी रखा। पाकिस्तान के राष्ट्रपति श्री जिया-उल-हक के साथ हुई चार बैठकों के आधार पर वे १७ दिसम्बर १९८५ को नई दिल्ली की यात्रा पर आये जिसमें दोनों पक्षों ने घोषणा की कि वे एक दूसरे के परमाणु प्रतिष्ठानों पर हमला नहीं करेंगे। दोनों पक्षों ने सहयोग के विकास के रास्ते से बाधाओं को दूर करने के लिए द्विपक्षीय बैठकों का कार्यक्रम भी तय किया। राष्ट्रपति जिया और हमारे प्रधानमंत्री की बैठक के निर्णयों का पालन करते हुए, जनवरी, १९८६ में भारत के वित्त मंत्री ने पाकिस्तान की यात्रा की और आर्थिक और व्यापारिक सहयोग बढ़ाने पर वार्ता की। दोनों देशों के प्रतिरक्षा सचिव सियाचिन ग्लेशियर क्षेत्र की स्थिति पर विचार करने के लिए मिले। दोनों देशों के विदेश सचिवों ने स्थाई शांति मैत्री और सहयोग के निर्माण के लिए संधि या समझौते का एक विस्तृत मसौदा तैयार करने के लिए विचार-विमर्श किया। लेकिन कुछ महत्वपूर्ण पहलुओं पर मतभेद बरकरार रहे¹⁴।

वर्ष १९८७ में भारत में आतंकवादियों को निरंतर सहायता देने नाभिकीय अस्त्रों के विकास के कार्यक्रम निरंतर चलते रहने आधुनिकतम हथियारों की निरंतर तलाश में रहने, अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर कश्मीर के सवाल को उठाने की कोशिश तथा भेदभाव रहित

आधार पर व्यापार विकसित करने में झिझक की वजह से पाकिस्तान के साथ सम्बन्ध सुधारने के हमारे प्रयासों पर विपरीत प्रभाव पड़ा¹⁵ । इन दुर्भाग्यपूर्ण बातों के बावजूद, प्रधानमंत्री ने १६ नवम्बर १९८६ को बगलूर में प्रधानमंत्री जुनेजो के साथ हुई मुलाकात में इस बात पर सहमति व्यक्त की कि दिसम्बर १९८६ में हमारे गृह सचिव और विदेश सचिव को पाकिस्तान जाकर सामान्यीकरण की प्रक्रिया को पुनः शुरू करने की सम्भावनाओं का पता लगाना चाहिये¹⁶ । इस समझौते के अनुरूप निश्चित कार्यक्रम के तहत गृह सचिव और विदेश सचिव ने पाकिस्तान की यात्रा की और अपने समकक्ष अधिकारियों से व्यापक बातचीत की । गृह सचिव की यात्रा के दौरान यह फैसला हुआ कि इसके लिए दो समितियाँ गठित की जाएँगी जिनमें एक नए सीमा क्षेत्र नियमों को तैयार करेगी तथा दूसरे नशीले पदार्थों के अवैध व्यापार और तस्करी रोकने के सम्बन्ध में विचार करेगी । लेकिन जनवरी १९८७ में भारत-पाकिस्तानी सीमा पर पाकिस्तानी फौजों के उत्तेजनात्मक और खतरनाक ठिकानों तक आगे बढ़ जाने की वजह से भारत-पाकिस्तान सीमा पर तनाव बढ़ गया¹⁷ । सैनिकों के इस जमाव की वजह से उत्पन्न तनावपूर्ण स्थिति को समाप्त करने के लिए भारत ने अपनी ओर से बातचीत का सिलसिला शुरू किया और सैनिकों की वापसी तथा बातचीत को आगे बढ़ाने के लिये एक समयबद्ध कार्यक्रम तैयार किया गया । इस दौरान भारत बराबर इस बात पर जोर देता रहा है कि सभी मतभेदों

को शांतिपूर्ण बातचीत के द्वारा सुलझाने की जरूरत है¹⁸ ।

राजीव गांधी द्वारा भारत और पाकिस्तान के साथ सम्बन्ध बनाने के प्रयास जारी रखे गए । शिमला समझौते की भावना के पूर्णतः अनुरूप पाकिस्तान के साथ सौहार्दपूर्ण सहयोगपूर्ण और अच्छे पड़ोसी के सम्बन्धों के विकास के प्रति भारत वचनबद्ध है। प्रधानमंत्री और जिया के बीच फरवरी १९८७ में नई दिल्ली में बैठक के अलावा भारत-पाक सीमा पर शांति बनाये रखने और नशीली दवाओं की तस्करी रोकने तथा आर्थिक सहयोग और व्यापार बढ़ाने के उद्देश्य से सचिव स्तर पर अनेक महत्वपूर्ण बैठकें भी हुईं ।

दिसम्बर १९८८ में अपनी यात्रा के दौरान श्री प्रधानमंत्री श्रीमती बेनजीर भुट्टो के साथ द्विपक्षीय और आपसी हित के अन्य मुद्दों पर गहन बातचीत की । इन वार्ताओं के फलस्वरूप पाकिस्तान के साथ निम्नलिखित तीन समझौतों पर हस्ताक्षर किए गये

१ परमाणुविक सस्थापनाओं और सुविधाओं पर अनाक्रमण समझौता,

२ सांस्कृतिक सहयोग समझौता और

३ अंतर्राष्ट्रीय वायु परिवहन से प्राप्त आय पर दोहरे करारोपण से बचाव सम्बन्धी समझौता ¹⁹।

अच्छे सम्बन्धों के प्रति भारत की सच्ची भावनाओं का पाकिस्तान द्वारा सही प्रतिदान नहीं किया गया, जैसा कि उसके द्वारा किए गए अनेक विपरीत कार्यों से स्पष्ट है जिनसे वातावरण

बिगड़ा है और भारत से सम्बन्धों पर बुरा असर पड़ा है। इसमें इसकी हथियारोन्मुख परमाणु नीति इसकी वास्तविक रक्षा आवश्यकताओं से कहीं ऊपर अवाक्स जैसे अत्याधुनिक हथियार प्राप्त करने की इच्छा भारत के विरुद्ध आतंकवादी गतिविधियों में इसके शामिल होने कश्मीर के प्रश्न को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर ले जाने के इसके सघन एवं एकीकृत प्रयास सियाचिन क्षेत्र में इसके द्वारा सेना की आपराधिक कार्रवाई, भारत के साथ गैर-भेदमूलक व्यापार सम्बन्ध स्थापित करने के प्रति इसकी अनिच्छा और व्यक्ति-से-व्यक्ति के सम्बन्धों को बढ़ावा देने के प्रति इसकी ढील आदि शामिल हैं²⁰।

दोनों देशों के द्विपक्षीय संबंधों को बेहतर बनाने के उद्देश्य से पाकिस्तान के साथ लगातार सम्पर्क बनाये रखने के लिये १९८८ और १९८९ के दौरान अधिकारी स्तर पर कई महत्वपूर्ण बैठकें हुईं। भारत ने स्पष्ट किया कि वह पाकिस्तान के सम्बन्धों को तेजी के साथ सामान्य बनाने का इच्छुक है। प्रधानमंत्री श्रीमती बेनजीर भुट्टो का मत था कि पाकिस्तान शिमला समझौते के दायरे में समाधान करना चाहता है।

अंतर्राष्ट्रीय मंच पर राजीव गांधी ने पाकिस्तान के प्रति भारत की नीयत उजागर करते हुए साफ शब्दों में कहा था- “दक्षिण एशिया के सम्बन्ध में हमने कई अवसरों पर पाकिस्तान के साथ मैत्री और मधुर तथा सहयोगपूर्ण सम्बन्धों की बात दोहराई है। हमारे दिलों

मे पाकिस्तान के लोगो के प्रति सदभावनाए है जिनके साथ हमारी भाषा सगीत और साहित्य का साझा है। हमारा इतिहास साझा है। पाकिस्तान के लोगो के प्रति दुर्भावना नही है। हम उनका भला चाहते है और इसीलिए हम लोगो के स्तर पर यात्रियो पर्यटको, छात्रो पत्रकारो श्रमिक नेताओं महिला ग्रुपो के आदान-प्रदान का स्वागत करते है ²²।”

राजीव गांधी ने दोनो देशो के मध्य सम्बन्ध मधुर बनाने के लिए सांस्कृतिक, व्यापारिक, बौद्धिक आदान-प्रदान तथा हित संरक्षण की दिशा मे कई प्रस्ताव पाकिस्तान के समक्ष रखे किन्तु दुर्भाग्यवश पाकिस्तान से अत्यन्त असंतोषजनक प्रत्युत्तर प्राप्त हुआ। इसे स्पष्ट करते हुए श्री राजीव गांधी ने कहा कि “दूसरी ओर पाकिस्तान दोनो देशो के लोगो के बीच इन कार्यक्रमो को रोक रहा था। वह परमाणु हथियार कार्यक्रम पर ही जोर दे रहा था। उन्होंने सियाचिन जैसे क्षेत्रो मे आक्रामक रुख अपना रखा है। वह अपने क्षेत्र मे आतंकवादियो और पृथकवादियो को सहायता और शरण दे रहे है²³।” राजीव गांधी ने पाकिस्तान से कहा था कि हमारी सीमाओ पर आतंकवादी घटनाओ मे हुए अचानक वृद्धि पर बातचीत के लिए भारत तथा पाकिस्तान के गृह सचिवो को बातचीत करनी चाहिए। दोनो देशो के बीच विभिन्न स्तरों पर बेहतर संचार सुविधा होनी चाहिए। सैनिक क्षेत्र मे पहले से ही हाटलाइन है। शायद गृह सचिवो के बीच भी हाटलाइन की जरूरत है ताकि यदि कोई तनाव उत्पन्न

हो तो उसे जितनी जल्दी संभव हो समाप्त किया जा सके।

भारत और पाकिस्तान के विदेश सचिवों के बीच एक हाटलाइन हुआ करती थी। किन्तु पाकिस्तान के अनुरोध पर इसे हटा दिया गया। राजीव गांधी चाहते थे कि इसे बहाल किया जाये ताकि यदि कोई तनाव हो तो उसे तुरन्त कम किया जा सके।

भारत विरोधी प्रचार का सहारा लेकर अमरीका से ही नहीं बल्कि सेण्टो शक्तियों, विशेषकर ईरान से प्रचुर मात्रा में सैनिक सहायता प्राप्त की। भारत-चीन संबंधों में बिगाड़ आने से पाकिस्तान ने चीन की हमदर्दी प्राप्त करने की कोशिश की और उससे अस्त्र-शस्त्रों को प्राप्त किया। पश्चिमी शक्तियाँ भी इस उप-महाद्वीप में पाकिस्तान को भारत के बराबर बनाये रखना चाहती हैं। वे समझती हैं कि यदि भारत को शांति का समय मिल गया तो वह महान शक्ति बन जायेगा। अतः अमरीका ने भारत के विरोध पर भी पाकिस्तान को अस्त्र-शस्त्र दिये।

पाकिस्तान द्वारा आतंकवाद को प्रोत्साहन- दुर्भाग्यवश पाकिस्तान द्वारा पंजाब और जम्मू-कश्मीर में भारत के विरुद्ध आतंकवाद को लगातार सहायता पहुँचाने और उसे बढ़ावा दिये जाने के कारण दोनों देशों के बीच संबंधों में काफी कटुता उत्पन्न हुई²⁴।

पाद टिप्पणिया

- 1 Burk S M Mainsprings of India and Pakistan Foreign Policies Page 37
- 2 Ismil M India and their Neighbours Page 94
- 3 An article on Pakistan by Kuldeep Nayyar
- 4 लोकसभा मे भारत पाक संबधो पर दिये गये वर्ष १९६५ मे प० जवाहरलाल नेहरू के भाषण के अश ।
- 5 Braine B Will India Stay in the Common Wealth ? Page 207
- 6 Panukhr K M India and Indian Ocean Page 114
- 7 Times of India 6 4 1965
- 8 Hindustan Times – 23 9 1965
- 9 Indian Express – 11 1 1966
- 10 Stateman – 4 7 1972
- 11 Prasad Bimal The Origins of Indian Foreign Policy The Indian National Congress and World Affairs 1885-1947 Page 139
- 12 Times of India 18 12 1985
- 13 भारत १९८७ सूचना एव प्रकाशन विभाग पृष्ठ-५१४ ५१५
- 14 भारत १९८७ सूचना एव प्रकाशन विभाग
- 15 भारत १९८८ ८९ - सूचना एव प्रकाशन विभाग पृष्ठ-५५६
- 16 Stateman 17 11 1986
- 17 भारत १९८८ ८९ - सूचना एव प्रकाशन विभाग पृष्ठ-५५६
- 18 Murty K S Indian Foreign Policy Page 113
- 19 भारत १९९० सूचना एव प्रकाशन विभाग पृष्ठ-६४५
- 20 Kundra, J C Indian Foreign Policy Page 133
- 21 भारत १९९० सूचना एव प्रकाशन विभाग पृष्ठ-६४५
- 22 सूचना विदेश मंत्रालय की वर्ष ८८-८९ की अनुदान मागो पर वाद विवाद पर उत्तर देते हुए लोकसभा वाद-विवाद २०४८८ कालम स० २८० से २८७
- 23 विदेश मंत्रालय की वर्ष ८८-८९ की अनुदान मागो पर वाद-विवाद पर उत्तर देते हुए लोकसभा वाद विवाद २०४८८ कालम स० २८० से २८७
- 24 राजीव गांधी एव ससद सम्पादक सी०के०जैन महासचिव लोकसभा पृष्ठ-४७४ ४७५

અધ્યાય-૬

राजीव गांधी के भारत के प्रधानमंत्री के रूप में सत्तारूढ़ होने के समय श्रीलंका भीषण आतंकवाद एवं पृथक्तावाद की धधकती ज्वाला में सुलग रहा था निरीह और निरअपराध लोगों की हत्या की जा रही थी। सरकारी सम्पत्तियों को नुकसान पहुंचाया जा रहा था। श्रीलंका सरकार बेवश और असहाय साबित हो रही थी। ऐसी स्थिति में स्वाभाविक था कि कई देश अपनी राजनीतिक रोटी सेकने के लिये श्रीलंका के आंतरिक मामलों में दखल देने की ताक में थे। राजीव गांधी ने अपनी राजनीतिक सूझबूझ और कूटनीतिक समझ से श्रीलंका से सम्बन्ध बेहतर करने तथा हर संभव सहायता के लिए दोस्ती का हाथ बढ़ाया। इसलिये कि श्रीलंका अहिंसा और प्रेम के मसीहा भगवान बुद्ध के अनुयायियों की धरती है, जहां वहसी हिंसा का ताड़व चल रहा था ¹। इसलिये भी कि अपने पड़ोसी देश में किसी अन्य देश का अड़्डा बने भारत के हित में नहीं था।

श्री लंका भारत के दक्षिण में स्थित एक छोटा द्वीप है जिसका क्षेत्रफल २५,३३२ वर्गमील तथा जनसंख्या १७ १३५ ००० है। सांस्कृतिक दृष्टि से श्रीलंका भारत के साथ जुड़ा है। यहाँ पर रहने वाले भारतीय तमिलनाडु के मूल निवासी हैं। श्रीलंका के अधिकांश निवासी बौद्ध धर्मावलम्बी हैं। हिन्द महासागर में भारत के समीप होने के कारण सैनिक एवं सामरिक दृष्टि से श्रीलंका का भारत के लिए अत्यधिक महत्व है।

भारत और श्रीलका एक दूसरे के पड़ोसी देश है किन्तु उनके सम्बन्ध पड़ोसियों के सम्बन्धों से अधिक गहरे हैं। श्रीलका भारतीय उपमहाद्वीप का ही एक अंग है अतः इसका राजनीतिक महत्व ही नहीं बल्कि औद्योगिक, आर्थिक एवं सांस्कृतिक महत्व भी है। भारत से श्रीलका की दूरी पाक जलडमरूमध्य पार करके बहुत कम समय में तय की जा सकती है। आधा घण्टे से कम की उड़ान में कोई भी भारत से श्रीलका पहुँच सकता है अथवा श्रीलका से भारत आ सकता है। किन्तु वहाँ पहुँचकर उसे ऐसा नहीं लगता कि वह किसी अन्य देश में पहुँच गया है। दक्षिण भारत की जलवायु एवं सांस्कृति की बहुत सी विशेषताएँ वहाँ पर दिखलाई देती हैं। वैसे भी भारत एवं श्रीलका के सम्बन्ध सदियों पुराने हैं। मौर्य सम्राट अशोक के युग में ही श्रीलका और भारत के बीच गहरे सम्बन्ध थे। अशोक ने बौद्ध धर्म का प्रचार करने के लिए अपने ही पुत्र को श्रीलका भेजा था और इसमें कोई सन्देह नहीं कि वह बौद्ध धर्म के अनुयायी है और वे प्राचीन भारत के ऋषियों के कृत्यों से प्रेरणा प्राप्त करते हैं²।

१७ १३ मिलियन जनसंख्या का यह देश भारत से दक्षिण में पाक जलडमरूमध्य से पृथक् होता है इसके पश्चिम में पाक जलडमरूमध्य एवं मन्नार की खाड़ी है। पूरब एवं उत्तर में बंगाल की खाड़ी एवं दक्षिण में हिन्द महासागर है। दुनिया के इस भूभाग के अन्य देशों की तरह श्रीलका भी उपनिवेशीकरण का शिकार हुआ और १५० वर्ष से अधिक समय तक विदेशी शक्तियों के प्रभुत्व में

रहा है। सर्वप्रथम पुर्तगालियों ने इस देश पर अपना अधिकार किया उसके बाद डच लोगो ने किन्तु कालान्तर मे इनका स्थान अंग्रेजो ने ले लिया । अंग्रेजो ने अपनी विश्व प्रसिद्ध नीति ‘फूट डालो और शासन करो’ का यहा भी उपयोग किया और वे श्रीलंका की जनसंख्या के दो बड़े समूहो मे आपस मे वैमनस्य बनाये रखने मे सफल रहे यहा पर बहुमत सिंहली भाषा-भाषियों का है किन्तु तमिल भाषा-भाषी लोग अल्पतम होते हुए भी काफी प्रभाव रखते है ।

अन्तर्राष्ट्रीय राजनीति मे श्रीलंका का विशिष्ट महत्व है । हिन्द महासागर मे से गुजरने वाले सभी जलमार्गों का यह केन्द्र है । इसी सामरिक स्थिति के कारण अंग्रेज इसे छोड़ना नहीं चाहते थे ।

भारत और श्रीलंका औपनिवेशिक दासता के एक लम्बे समय तक शिकार रहे है । दोनो ही देश लगभग साथ-साथ स्वाधीन हुए । श्रीलंका के राष्ट्रीय स्वाधीनता के आन्दोलन को भारत के राष्ट्रीय आन्दोलन से प्रेरणा मिली । श्रीलंका की सरकार ने भी भारत सरकार के समान गुटनिरपेक्षता की नीति को स्वीकार किया । भारत की भाँति श्रीलंका की नीति अन्तर्राष्ट्रीय क्षेत्र मे शान्तिवाद गुटनिरपेक्षता सह-अस्तित्व और दूसरे देशो से मित्रतापूर्ण सम्बन्धो की रही । भारत की भाँति श्रीलंका भी राष्ट्रमण्डल का सदस्य बना । कोलम्बो योजना के अन्तर्गत, जिसकी रचना १९५० मे कोलम्बो मे राष्ट्रमण्डलीय प्रधानमन्त्रियों के सम्मेलन मे की गयी थी दोनो देशो ने आर्थिक क्षेत्र मे पूर्ण सहयोग किया है^३ ।

भारत और श्रीलका मे मैत्रीपूर्ण सम्बन्ध होनेपर भी समय-समय पर कुछ घटनाए घटित होती रही है जिससे दोनो देशो के बीच मतभेद उभरकर सामने आये ।

इनमे भारत प्रवासियो की समस्या प्रमुख रही है । भारत और श्रीलका के मध्य विवाद का प्रमुख मसला भारतीय प्रवासियो को लेकर उत्पन्न हुआ । श्रीलका के अधिकाश भारतीय प्रवासी है। लगभग १० लाख मजदूर चाय और रबड की खेती पर काम करने के लिए लाये गये थे । ये श्रमिक सस्ते थे और इनमे से अधिकाश दक्षिण भारत से ले जाये गये थे । १९४८ मे श्रीलका के स्वतत्र होने तक यह ब्रिटिश नागरिको के रूप मे समान अधिकारो एव मताधिकार का लाभ उठाते थे परन्तु शीघ्र ही १९४८ के सीलोन नागरिकता अधिनियम एव सीलोन संसदीय अधिनियम १९४९ के द्वारा इन्हे मताधिकार से वचित कर दिया गया । नागरिकता प्राप्त करने के लिए उन्हे यह प्रमाणित करना पडता था कि उनके माता-पिता या वे स्वयं श्रीलका मे जन्मे थे और १९३९ से लगातार श्रीलका मे ही निवास कर रहे है । इस प्रकार श्रीलका सरकार का विचार सम्भवतः यह था कि कम से कम भारतीयो को श्रीलका की नागरिकता प्राप्त हो सके ।

इसके पीछे मुख्य कारण ये थे -

- १ बढती हुई जनसख्या के कारण श्रीलका मे आर्थिक दबाव अनुभव होने लगा था और सिंहली लोग चाहते थे कि प्रवासी भारतीय यहा

से चले जाये तो उनको रोजगार के अधिक अवसर प्राप्त होने लगे

- २ प्रवासी भारतीय अपनी कमाई का बड़ा भाग भारत भेज देते थे ।
- ३ श्रीलंका के विदेशी विनिमय पर इसका बुरा प्रभाव पड़ता था ।
भारतीय प्रवासी वर्षों से श्रीलंका में रहने के बाद भी भारत को ही अपना देश मानते थे ।
- ४ प्रवासी भारतीयों की बड़ी संख्या चुनावों को अत्यधिक प्रभावित करती थी । इसीलिए १९४९ के निर्वाचन कानून द्वारा उन्हें मताधिकार से वंचित कर दिया गया^४ ।

उपर्युक्त कारणों के बावजूद भी प्रवासी भारतीयों के प्रति श्रीलंका सरकार का व्यवहार आपत्तिजनक और अन्यायपूर्ण था । प्रवासी भारतीय श्रमिकों को जिनके श्रम से श्रीलंका ने आर्थिक उन्नति का और यूरोपीय पूँजीपतियों के कोष भरे अब श्रीलंका से बहिष्कृत करने का प्रयास किया जा रहा था । समस्या और भी अधिक गम्भीर तब हो गयी जब श्रीलंका सरकार ने प्लान्टेशन लेबर एव विदेशी व्यावसायिक संगठनों का राष्ट्रीकरण करने की नीति प्रकट की। अशिक्षित भारतीय श्रमिकों के साथ यह अन्याय था, अतएव भारत सरकार के लिए हस्तक्षेप करना आवश्यक हो गया ।

इस समस्या के समाधान के लिए भारत सरकार ने श्रीलंका सरकार से वार्ता प्रारम्भ की । लम्बी वार्ता के परिणामस्वरूप जनवरी १९५४ में जान कोटलेवाला नई दिल्ली आये थे और नेहरू के साथ उनका एक समझौता हुआ, जिसे नेहरू-कोटलेवाला समझौता कहते हैं।

इसकी शर्तें निम्न प्रकार थी -

- १ श्रीलंका की सरकार उन सभी भारतीय मूल के लोगो के नाम रजिस्टर करेगी जो श्रीलंका में स्थायी रूप से रहने के इच्छुक हैं ।
- २ जो श्रीलंका की नागरिकता नहीं चाहते उन्हें भारत वापस भेज दिया जायेगा ।
- ३ भारत से श्रीलंका को अवैध अप्रवास सख्तीपूर्वक रोका जायेगा ।
- ४ नागरिकता प्राप्त करने के लिए दो वर्षों से जो आवेदन पत्र पड़े हैं उनका निर्णय सरकार शीघ्र करेगी ।
- ५ भारतीयों के लिए श्रीलंका में एक अलग चुनाव रजिस्टर बनेगा जिसके आधार पर वे निश्चित सख्या में अपने प्रतिनिधि चुनेगे ।
- ६ जिन भारतवासियों को श्रीलंका में नागरिकता नहीं दी जा सकेगी उन्हें विदेशी के रूप में रहने की सुविधा दी जाएगी^१ ।

श्रीलंका की सरकार ने इस समझौते का इमानदारी से पालन नहीं किया भारतीय मूल के बहुत सारे ब्यक्तियों को नागरिकताविहीन बना दिया । मार्च १९५४ में श्रीलंका सरकार ने भारतीय मूल के नागरिकों के निवास आज्ञा पत्रों (रेजीडेन्सी) का नवीनीकरण स्थगित करने की आज्ञा दे दी और इस प्रकार श्रीलंका में वर्षों से बसे हुए नागरिकों को अवैध निवासी बना दिया । यह सब दिल्ली समझौते की भावना के विरुद्ध था । इसके पूर्व वीसा प्राप्त करना आवश्यक नहीं था । भारत सरकार की ओर से भारतीय उच्चायुक्त ने श्रीलंका को चेतावनी दी कि भारत सरकार केवल

उन्ही व्यक्तियों को भारतीय नागरिकों के रूप में स्वीकार करेगी जिन्होंने स्वेच्छा से इसके लिए आवेदन किया है और ऐसे व्यक्तियों को फिर श्रीलंका के बगीचों एवं अन्य खेतियों पर भी काम करने की अनुमति नहीं दी जायेगी।

राज्यविहीन नागरिकों की स्थिति पर दोनों सरकारों में मूलभूत अंतर था । श्रीलंका सरकार उन्हें तब तक भारतीय नागरिक कहती थी जब तक वह उन्हें अपना नागरिक न मान ले। भारत सरकार के दृष्टिकोण से केवल वे ही व्यक्ति भारतीय नागरिक थे जिनके पास सदैव से भारतीय पासपोर्ट अथवा अनुमति पत्र थे और जिन्होंने भारतीय उच्चायुक्त के आफिस में अपने को पंजीकृत करा लिया था । शेष व्यक्ति राज्यविहीन थे । इसी प्रकार बड़ी संख्या में राज्यविहीन व्यक्तियों की समस्या उत्पन्न हो गयी । इससे भारत और श्रीलंका के सम्बन्धों में कटुता उत्पन्न हो गयी । १९५६ के भाषा विवाद से यह कटुता और बढ़ गयी । श्रीलंका सरकार ने यह आरोप लगाया कि इन दंगों के पीछे भारत का हाथ था । परन्तु भण्डारनायक के प्रधानमन्त्रित्व (१९५६-५९) काल में भारत और श्रीलंका सम्बन्धों में सुधार हुआ । भण्डारनायक नेहरू के प्रशंसक और मित्र थे, वे गुटनिरपेक्षता की नीति में विश्वास करते थे और भारत को श्रीलंका का एक बड़ा मित्र-राष्ट्र मानते थे^६ । उनकी हत्या के बाद श्रीमती भण्डारनायक १९६०-७७ के कार्यकाल में भी भारत- श्रीलंका सम्बन्ध मधुर रहे । इसी कारण अक्टूबर १९६४ में भारतीय प्रधानमंत्री

लालबहादुर शास्त्री और श्रीमती भण्डारनायक के बीच एक समझौता हुआ जिसमें निम्न बातें मुख्य थी-

- १ श्रीलंका में रह रहे वे सभी भारतीय नागरिक जो अभी तक किसी भी देशों के नागरिक नहीं हैं वे भारत या श्रीलंका में से किसी भी देश की नागरिक नहीं हैं वे भारत या श्रीलंका में से किसी भी देश की नागरिकता अपनाये।
- २ यह अनुमान था कि श्रीलंका में ऐसे ९७५००० व्यक्ति हैं जो राष्ट्रियताविहीन हैं। समझौते के अनुसार यह तय किया गया कि इनमें से ५,२५,००० व्यक्तियों को भारत और ३ ०० ००० व्यक्तियों को श्रीलंका अपनी नागरिकता प्रदान करे और १ ५०,००० व्यक्तियों की नागरिकता की समस्या को एक अन्य समझौते द्वारा सुलझा दिया जायेगा।
- ३ आने वाले १५ वर्षों में यह कार्य पूरा कर लिया जाये।
- ४ भारत आने वाले प्रवासियों को वे सभी सुविधाएँ प्राप्त होंगी जो किसी भी अन्य विदेशी को प्राप्त होती हैं लेकिन उन्हें विदेशों में धन भेजने की सुविधा नहीं होगी।
- ५ भारतीय अपने कमाई हुई पूँजी को भारत ले जा सकेंगे लेकिन उसकी सीमा चार हजार से कम नहीं होनी चाहिए^१।

इस समझौते में एक कमी यह रह गयी कि १,५०,००० राष्ट्रियताविहीन व्यक्तियों की नागरिकता का सतोषपूर्ण फैसला नहीं हो पाया। लेकिन जनवरी १९७४ में जब श्रीलंका की प्रधानमंत्री

श्रीमती भण्डारनायके भारत आयी तो शेष १ ५० ००० राष्ट्रीयताविहीन व्यक्तियों की नागरिकता का भी फैसला हो गया । एक समझौते के अनुसार दोनों देशों ने आधे-आधे यानी ७५-७५ हजार व्यक्तियों को अपनी-अपनी नागरिकता देना स्वीकार कर लिया ।

विवाद का दूसरा बिन्दु है कच्छदीप टापू का मसला । भारत-श्रीलंका के बीच दूसरा मसला कच्छदीप से सम्बन्धित रहा है । कच्छदीप भारत और श्रीलंका के समुद्री तटों के बीच २०० एकड़ का एक छोटा सा द्वीप है जिसमें नागफनी के अतिरिक्त और कुछ नहीं उगता । यहाँ आबादी नहीं के बराबर है और आस-पास मछुवारे मछली जरूर पकड़ते हैं दोनों देश इस भूखण्ड पर अपना आधिपत्य जताते थे । विवाद इसलिए और भी बढ़ गया क्योंकि इस द्वीप के आस-पास तेल के काफी बड़े भण्डार होने की आशा की जाती थी । भारत ने एक महान पड़ोसी देश की परम्परा का निर्वाह करते हुए इस छोटे से द्वीप के कारण दोनों देशों के बीच विवाद को लम्बा खींचना उपयुक्त नहीं समझा । २८ जून १९७४ को दोनों देशों में एक समझौता हुआ, जिसके अनुसार कच्छदीप टापू पर भारत ने श्रीलंका की प्रभुसत्ता को स्वीकार कर लिया ।

जनता सरकार ने श्रीलंका से सम्बन्ध बढ़ाने के लिए ईमानदारी भरा प्रयत्न किया। श्रीलंका के विदेशमंत्री हमीद अग्रैल, १९७८ में भारत आये और उसके बाद अक्टूबर १९७८ में जयवर्द्धने ने स्वयं भारत की यात्रा की । उन्होंने प्रवासी भारतीयों की समस्या शीघ्र

सुलझाने का आश्वासन दिया किन्तु ३५ करोड़ रुपये के भुगतान-असन्तुलन पर चिन्ता भी व्यक्त की। उन्होंने भारतीय पूँजी के विनियोग का स्वागत किया तथा दोनो देशो के सर्वविध आर्थिक सहयोग की कामना की। मुक्त व्यापार क्षेत्र स्थापित करने के प्रस्ताव पर भी ध्यान दिया गया। दोनो देशो की विदेश नीति का विश्व मामलो के बारे मे लगभग समान दृष्टिकोण था हालाकि कैम्प डेविड समझौते के बारे मे जयवर्द्धने सरकार का रुख भारत की तरह आलोचनात्मक नहीं था^४। फरवरी, १९७८ मे मोरारजी देसाई ने श्रीलंका की यात्रा की तथा प्रवासी भारतीयो की नागरिकता से सम्बन्धित प्रक्रिया की स्वयं जाकर देखभाल की। मोरारजी की इस श्रीलंका यात्रा से दोनो देशो मे मधुरता का संचार हुआ इसमे सदेह नहीं है। किन्तु श्रीलंका के तमिलो की समस्या के बारे मे कटुता ज्यो की त्यो बनी रही। मोरारजी ने श्रीलंका के तमिलो को यह सलाह दी कि वे अलगाववाद को छोड़े और सिंहलियो के साथ मिल-जुलकर रहे। जनता सरकार की इतनी बड़ी उदारता के बाद भी संयुक्त राष्ट्र महासभा मे श्रीलंका का वोट पाकिस्तान के परमाणु मुक्त क्षेत्र प्रस्ताव के पक्ष मे पड़ा।

१९८२-८८ मे भारत श्रीलंका सम्बन्धो को प्रभावित करने वाला मुख्य मुद्दा श्रीलंका का तमिल अल्पसंख्यक समुदाय है। श्रीलंका की १७ १३ मिलियन की आबादी मे ७४ प्रतिशत सिंहली १३ प्रतिशत श्रीलंका के तमिल, ६ प्रतिशत भारत मूल के तमिल और शेष अन्य

लोग हैं। तमिल श्रीलका के उत्तर में जाफना जिले में रहते हैं। तमिल लोग धर्म से हिन्दू कहलाते हैं और सिंहली बौद्ध^१।

अनेक कारणों से श्रीलका के तमिलों में असुरक्षा अविश्वास और आतंक की भावना विद्यमान रही है। जयवर्द्धने की सरकार ने तमिलों के विरुद्ध घोर भेदभावपूर्ण नीतियाँ अपनायीं। आतंकवादियों के दमन के नाम पर निर्दोष लोगों की हत्या की जाने लगी। १९७७ के बाद चार बड़े दंगे एवं १९८३-८५ का दमन नरसंहार आदि ने तमिल नृवशियों को बाध्य कर दिया कि या तो वे समुद्र में कूद पड़े या समुद्र पार कर भारत आ जायें।

श्रीलका के तमिलों के वर्तमान आन्दोलन का मूल कारण बहुसंख्यक सिंहलियों द्वारा की गयी भेदभाव की नीति है। एक तरफ देश के आर्थिक, सामाजिक और राजनयिक क्षेत्रों में सिंहली शासक वर्ग का एकाधिकार है और दूसरी तरफ बौद्ध धर्म को देश का राष्ट्रीय भाषा का दर्जा दिया गया है दूसरी तरफ तमिलों की निम्नलिखित शिकायतें हैं।

- १ सरकारी नौकरियों में भर्ती के वक्त तथा विश्वविद्यालयों में प्रवेश के वक्त उनके साथ भेदभाव किया जाता है।
- २ सरकार तमिल इलाकों में सिंहली किसानों को जानबूझकर बसा रही है, ताकि तमिल लोग 'घर' में ही अल्पसंख्यक हो जायें।
- ३ तमिलों के संगठन की शक्ति को तोड़ने के लिए सरकार तमिल अल्पसंख्यक को देश के दूसरे हिस्सों में जबरदस्ती बिखेर रही है

- ४ उग्रवादियों का सफाया करने के बहाने जयवर्द्धने सरकार सरकारी आतंकवाद फैला रही है¹⁰ ।

श्रीलंका के तमिल समुदाय ने अपने आपको 'तमिल यूनाइटेड लिबरेशन फ्रन्ट' नाम के राजनीतिक संगठन में संगठित कर रखा है और इसके माध्यम से समय-पर वह अपने असन्तोष को अभिव्यक्त भी करता रहता है । तमिलों के कुछ उग्रवादी संगठन तमिल ईलम नाम के एक पृथक राष्ट्र के निर्माण की बात करते हैं परन्तु तमिलों का प्रमुख संगठन तुल्फ (TULF) स्वायत्तता की ही मांग करता है । यह संगठन श्रीलंका को विभाजित नहीं करना चाहता है परन्तु यह तमिलों के लिए एक स्वतंत्र देश के नागरिकों की तरह सम्मानित जीवन अवश्य प्राप्त करना चाहता है । यही मुद्दा तमिल आन्दोलन का मूल आधार है ।

श्रीलंका के तमिल अल्पसंख्यक समुदाय की समस्या उसका आन्तरिक मामला है और भारत श्रीलंका के आन्तरिक मामले में हस्तक्षेप नहीं करना चाहता । भारत ईलम पृथक तमिल राज्य की धारणा^{का} समर्थक नहीं है। वह संगठित और अखण्ड श्रीलंका ही बनाये रखना चाहता है तथापि अनेक कारणों से वहाँ पर होने वाली घटनाओं के प्रति भारत का चिन्तित होना स्वाभाविक है¹¹ । भारत की श्रीलंका के प्रति तब चिन्तित होता है जब -

- १ श्रीलंका की घटनाएँ तथा तमिलों पर अत्याचार भारत के तमिल समुदाय दक्षिणी राज्यों को उत्तेजित करते हैं ।

- २ भारत का उन घटनाओं से चिन्तित होना स्वाभाविक है जब सिंहली बहुसंख्यक समुदाय श्रीलंका के तमिल अल्पसंख्यक समुदाय की आर्थिक और व्यापारिक सम्पन्नता को नष्ट-भ्रष्ट कर उन्हें विपन्न बनाने का प्रयास करता है।
- ३ जब नरसंहार से बचने के लिए एक लाख शरणार्थी भारत से शरण लेते हैं।
- ४ जब जयवर्द्धने सरकार तमिल समस्या को अलस्टर पंजाब या कश्मीर समस्याओं से जोड़ने का प्रयास करती है।
- ५ जब श्रीलंका सरकार तमिल उग्रवादियों को सबक सिखाने के लिए इजरायल की खुफिया संस्थाओं -शिनबेत और मौसाद को श्रीलंका की सेनाओं और पुलिस को प्रशिक्षण देने के लिए भाड़े पर रखती है।
- ६ जब श्रीलंका सरकार निर्गुट नीति को ताक पर रखकर अमेरिका को प्रसन्न करने के इजरायल से राजनयिक सम्बन्ध स्थापित करती है।
- ७ जब श्रीलंका सरकार भारत को डराने के लिए त्रिकोमल्ली बन्दरगाह में अमेरिका नौसेना जहाजों और युद्धपोतों को सुविधाएँ देने के लिए वार्ताएँ करती है।

जयवर्द्धने की सरकार ने तमिलों के विरुद्ध घोर भेदभावपूर्ण नीतियाँ अपनाया आतंकवादियों के दमन के नाम पर निर्दोष लोगों की सामूहिक हत्या की जाने लगी। जुलाई १९८३ में तमिल आतंकवादियों ने १३ सैनिक मार डाले¹²। इस पर श्रीलंका की सिंहली सेना पागल हो उठी और सैकड़ों निर्दोष तमिलों को गोलियों

से भून डाला। सरकारी जेलों में बन्दी तमिलों की नृशंस हत्या कर दी गयी। उनके घर और दुकानें जला दी गयी। श्रीलंका के ये अत्याचार इतने भयंकर थे कि स्वयं श्रीलंका को यह आशंका होने लगी कि भारत उस पर आक्रमण कर सकता है। उसने भारत विरुद्ध अमेरिका ब्रिटेन पाकिस्तान और बंगलादेश से सैनिक सहायता का आश्वासन मांगा। जबकि भारत की इस प्रकार की कोई कार्यवाही करने की इच्छा नहीं रही¹³। श्रीमती इन्दिरा गांधी ने तो श्रीलंका से दूर रहने का सिद्धान्त प्रतिपादित किया था।

जहाँ तक तमिल समस्या के समाधान में भारतीय सहयोग का प्रश्न है तमिल समस्या का समाधान करने हेतु भारत शुरू से ही बातचीत का रास्ता अपनाता रहा है। जुलाई १९८३ से जी पार्थसारथी भारतीय प्रधानमंत्री के विशेष दूत के रूप में कोलम्बो में बातचीत करते रहे हैं। श्रीलंका के राष्ट्रपति जयवर्द्धने की जून १९८४ और जून १९८५ में दिल्ली में भारतीय प्रधानमंत्री के साथ शिखर वार्ताएं आयोजित की गयी। भूटान की राजधानी थिम्पू में श्रीलंका की समस्या के शान्तिमय हल के लिए पहली बार ८ जुलाई से और पुनः १२ अगस्त से वार्ताएं हुईं¹⁴। परन्तु ये वार्ताएं विफल रहीं।

श्रीलंका सरकार समस्या का समाधान सैनिक शक्ति के बल पर निकालने का प्रयत्न करती रही है, जबकि भारत बातचीत के जरिये समस्या का हल करने की सलाह देता रहा है। श्रीलंका ने

भारत पर यह भी आरोप लगाया कि आतंकवादी चुनौती तमिलनाडु सरकार द्वारा समर्थित आन्दोलन से शुरू होती है। इससे सद्भाव कमजोर होते हैं और विश्वसनीयता घटती है।

तमिलनाडु के मुख्यमंत्री, श्री एम जी रामचन्द्रन के नेतृत्व में एक सर्वदलीय प्रतिनिधि मंडली २३ अप्रैल १९८५ को राजीव गांधी से मिला था और उन्होंने श्रीलंका में हाल की स्थिति के बारे में एक ज्ञापन दिया था¹⁵।

प्रतिनिधि मंडल को आश्वासन देते हुए राजीव गांधी ने कहा था कि भारत सरकार श्रीलंका की स्थिति पर नजर रखे हुए है और उससे भारत पर पड़ने वाले प्रभाव से हम चिंतित हैं। श्रीलंका सरकार के साथ सामान्य श्रोतों तथा विशेष यात्राओं के माध्यम से निरन्तर सम्पर्क बनाए हुए है¹⁶।

राजीव गांधी ने स्पष्ट किया -“वर्तमान स्थिति को ध्यान में रखते हुए मैं राष्ट्रपति जयबर्द्धन को अपने दुःख और चिंता के बारे में अवगत कराऊंगा और सभी संबंधित पक्षों को मान्य राजनीतिक आधार पर इस समस्या को तुरन्त हल किए जाने की आवश्यकता के बारे में बताऊंगा। स्थिति की गम्भीरता को देखते हुए मैंने इस समस्या के समाधान के लिए प्रयास जारी रखने हेतु एक विशेष सलाहकार दल का गठन किया है”¹⁷

भारत श्रीलंका समझौता श्रीलंका की यात्रा से लौटने के बाद राजीव गांधी ने सदन को अवगत कराया था- “मैं इस

यात्रा को इसलिए महत्वपूर्ण मानता हूँ कि श्रीलंका के महामान्य राष्ट्रपति ने और मैंने कल २९ जुलाई को एक करार पर हस्ताक्षर किए जिसका उद्देश्य उस कठिन संघर्ष को समाप्त करवाना है जो वर्षों से हमारे मित्र पड़ोसी श्रीलंका को दुखी करता आया है। सदन श्रीलंका के नागरिकों के बीच के जातीय संघर्ष की पृष्ठभूमि से परिचित है जिसकी जड़े वहाँ के जटिल ऐतिहासिक और आर्थिक सामाजिक कारणों में निहित हैं। इस संघर्ष ने पिछले चार वर्षों में बहुत गंभीर रूप ले लिया था जिसके कारण श्रीलंका के स्थायित्व और उसकी एकता और अखण्डता के लिए खतरा पैदा हो गया था।

१९८३ में तमिलों के विरुद्ध अभूतपूर्व हिंसा के साथ तो हालात बहुत ही अधिक बिगड़ गए। मैं बड़े पैमाने पर हुई हत्याओं और उन व्यापक दुख पीड़ाओं के बारे में नहीं जाना चाहता जो श्रीलंका के लोगों को सहनी पड़ी। जुलाई १९८३ और मई १९८७ के बीच की अवधि विशेष रूप से श्रीलंका के इतिहास का दुखद अध्याय है। हजारों नागरिकों की हत्या हुई जिनमें तमिल, सिंहली और ते और बच्चे यहाँ तक कि भिक्षु और पुजारी भी शामिल हैं। हजारों लोग बेघर होकर खुद अपने ही देश श्रीलंका में शरणार्थी बन गए, और करीब १,५०,००० श्रीलंकाई तमिल शरणार्थी भारत आ गए। ”

श्रीलंका के राष्ट्रपति के साथ हुए समझौते के बारे में उन्होंने भारतीय संसद को अवगत कराते हुए कहा था- “हमने श्रीलंका की

जातीय समस्या के स्थायी समाधान की एक रूपरेखा तैयार की। इस समझौते से वे बुनियादी आकांक्षाएँ पूरी होती हैं जो तमिल संघर्ष का मूल कारण हैं यानी उनकी यह इच्छा कि उनकी स्पष्ट जातीय अस्मिता को स्वीकार किया जाए अपने राजनैतिक भविष्य के प्रबन्ध के लिए उन्हें राजनैतिक स्वायत्तता मिले इस लक्ष्य की पूर्ति के लिए उन्हें समुचित राजकीय सत्ता प्राप्त हो श्रीलंका के उत्तरी और पूर्वी प्रान्तों को तमिलों के ऐतिहासिक निवास के क्षेत्रों के रूप में स्वीकृति मिले तथा तमिल को श्रीलंका लोकतांत्रिक समाजवादी गणराज्य की एक राजभाषा माना जाए¹⁹। ”

इस करार में श्रीलंका के पूर्वी और उत्तरी प्रान्तों को एक प्रशासनिक ईकाई बना दिया गया है, जिसकी अपनी एक निर्वाचित प्रान्तीय परिषद होगी और एक मुख्यमंत्री होगा। मई से दिसम्बर १९८६ के बीच जिन प्रस्तावों को अंतिम रूप दिया था, उनकी रूपरेखा के अन्तर्गत प्रान्तीय परिषद को अधिकार दिए जाएंगे, ताकि श्रीलंका के प्रान्तों को पूर्ण रूप से स्वायत्तता का सुनिश्चय हो सके। श्रीलंका में आपातकालीन स्थिति निकट भविष्य में हटा ली जायेगी। लड़ाई बन्दी और शस्त्र समर्पण एक निश्चित समयावधि में किया जाएगा। सभी उग्रवादी वर्गों को आम माफी दी जाएगी। तीन माह के भीतर प्रान्तीय परिषदों के चुनाव करा लिये जायेंगे। इस करार में उत्तरी और पूर्वी प्रान्तों के बीच सम्पर्क के बुनियादी मुद्दे पर १९८८ के अतः तक जनमत संग्रह का सुझाव है, जिसे स्थगित करने का

राष्ट्रपति को विवेकाधिकार होगा²⁰।

श्री राजीव गांधी ने समझौते पर प्रकाश डालते हुए ससद में कहा कि “ सिंहल आतंकवादी संगठन जे०वी०पी० ने सन १९७१ में श्रीलंका में बड़े पैमाने पर विद्रोह करवाया था। इस विद्रोह को दबाने के लिए तत्कालीन प्रधानमंत्री श्रीमती भण्डारनायके ने भारत से सहायता मांगी थी और तत्काल पूरी सहायता की थी।

राष्ट्रपति जयवर्द्धने के नेतृत्व में श्रीलंका की सरकार ने भारत से समुचित सैनिक सहायता के लिए औपचारिक अनुरोध किया ताकि जाफना प्रायद्वीप में लडाई-बन्दी और शस्त्र समर्पण, और अगर जरूरत पड़े तो पूर्वी प्रान्त में भी सुनिश्चित हो सके। उन्होंने श्रीलंका के कुछ सैनिकों को जाफना से दक्षिण में कुछ स्थानों पर ले जाने के लिए सैनिक परिवहन के लिए भी अनुरोध किया।

श्रीलंका की सरकार के इस औपचारिक अनुरोध के उत्तर में तथा हाल ही में सम्पन्न भारत-श्रीलंका करार के अन्तर्गत अपने दायित्वों के अनुरूप भारत की सशस्त्र सेना जाफना प्रायद्वीप में पहुँच गयी। सैनिक श्रीलंका में श्रीलंका की सरकार के विशिष्ट और औपचारिक अनुरोध पर वहाँ उतरे, जिन्होंने भारत-श्रीलंका करार के अन्तर्गत भारत के दायित्वों और वायदों का हवाला दिया था।

श्रीलंका के हाल के इतिहास का एक दुखद अध्याय समाप्त हो जायेगा है और भारत-श्रीलंका संबंधों का एक नया अध्याय शुरू होगा ।

इस कणर से अतीत का तनाव और अविश्वास दूर हो जाएगा तथा श्रीलका और भारत के लोगो के बीच की मित्रता और अधिक सुदृढ होगी जो २५०० वर्ष से ज्यादा पुरानी है और जिनका इतिहास सास्कृतिक परम्परा एक रही है²¹। ”

भारत - श्रीलका समझौते के कार्यान्वयन पर प्रकाश डालते हुए श्री राजीव गांधी ने लोक सभा में कहा कि इस समझौते की विश्व भर में प्रशंसा की गई । इस बात को सभी मानते हैं कि समझौते को पूरी तरह से क्रियान्वित करना सभी के हित में होगा। तमिल आकाक्षाएं पूरी होंगी। श्रीलका की एकता और अखण्डता बनाए रखी जाएगी तथा क्षेत्र में शांति और स्थिरता को बहाल किया जा सकेगा।

समझौते पर हस्ताक्षर होने के बाद श्रीलका के सुरक्षा कर्मी अपनी बैरको में ही रहे पूर्वी प्रान्त में होम गार्डों से शस्त्र ले लिए गए और स्पेशल टास्क फोर्स को अधिकांश रूप से हटा लिया। सर्वक्षमा के अंतर्गत ३३०० से भी अधिक तमिल बन्दियों को रिहा किया गया तथा यदि सामान्य स्थिति बनाने में लिट्टे ने अडचन नहीं डाली होती तो बाकी बन्दियों को भी छोड़ दिया जाता ।

उत्तरी और पूर्वी प्रान्तों में सिविल प्रशासन की रूपरेखा उसी आधार पर तैयार की जा रही थी जिसका सुझाव लिट्टे से लेकर तुल्फ तक के तमिल प्रतिनिधियों ने दिया था। अंतरिम प्रशासनिक परिषद घोषित कर दी गई थी जिसमें लिट्टे को सबसे अधिक

निर्णायक हिस्सा दिया गया था। भारत से शरणार्थियों की वापसी की योजना श्रीलंका सरकार के परामर्श से बनाई गई थी। हमने भारत द्वारा घोषित २५ करोड़ रुपये के अनुदान के माध्यम से वित्त पोषित किए जाने वाले पुर्नवास के प्राथमिकता क्षेत्रों का पता लगा लिया था। श्रीलंका के उत्तरी और पूर्वी प्रान्तों में शांति स्थापित हो गई थी। सामान्य स्थिति की बहाली नजदीक ही थी कि लिट्टे अपने वचन से मुकर कर करारा आघात किया।

लिट्टे ने जानबूझकर समझौते को असफल बनाने के प्रयास किए क्योंकि वे उग्रवाद से लोकतांत्रिक राजनैतिक प्रक्रिया में आने में या तो असमर्थ थे या अनिच्छुक। लिट्टे को राजनैतिक मुख्यधारा में शामिल होने के लिए और यहां तक कि इस प्रक्रिया में प्रमुख भूमिका निभाने के लिए भी हर संभव प्रोत्साहन तथा अवसर दिया गया। लिट्टे के नेतृत्व को जिन्होंने ६०० से अधिक विरोधी तमिल उग्रवादियों को मरवा दिया था अपनी सुरक्षा के लिए व्यक्तिगत शस्त्र रखने की अनुमति दे दी थी। उन्हें अपने हथियार स्वयं उनकी सुविधा के अनुसार समर्पित करने की अनुमति दी थी, हालांकि इससे कुछ प्रेरित पार्टियों ने समझौते को क्रियान्वित करने की हमारी मशा पर शक किया था। लिट्टे अपनी बात से पीछे हट गए और हिंसा का रास्ता अख्तियार करने का फैसला किया। एक ओर तो इसने भारत के समझौते के प्रति अपना समर्थन देने का वचन दिया लेकिन इसी ओर इसने सेमिनारों के माध्यम से हिंसा अपनी गैर-कानूनी

प्रसारण सुविधाओं के माध्यम से भारत और इस समझौते के विरुद्ध एक प्रचार अभियान शुरू कर दिया। इसने जाफना में गडबड़िया फैलानी शुरू कर दी सामान्य जन-जीवन तथा पुननिर्माण और पुर्नवास की प्रक्रिया में बाधा पहुंचाई उन्होंने तमिल भावनाओं को भड़काने का प्रयास किया। यह अनशन उन रियायतों की मांग के लिए किया गया था जिनके बारे में पहले से ही बातचीत चल रही थी और जिनहे मान लिया गया था तथा उन्होंने उस पर सन्तोष व्यक्त किया था।

दुर्भाग्यवश इसी समय लिट्टे के १२ सदस्यों ने आत्महत्या की। भारतीय शांति सेनाओं को निर्देश दिए गए थे कि वे ऐसे किसी भी आदमी को पकड़ ले जो हथियार लेकर चल रहा हो अथवा असैनिक लोगों को मारने के काम में लगा हो। इस मौके पर लिट्टे ने भारतीय शांति सेनाओं पर हमले आरंभ कर दिए। तब इस बात के सिवाय कोई और विकल्प नहीं था कि लिट्टे को निशस्त्र कर दिया जाए। शान्ति सेना को ऐसे तरीके अपनाने अथवा हथियारों का प्रयोग न करने के कड़े अनुदेश दिए गए थे जिसके कारण जाफना के नागरिक जो लिट्टे के बन्धक बने हुए थे भारी संख्या में हताहत न हो। भारतीय सेना ने अत्याधिक अनुशासन और साहस के साथ इन अनुदेशों का पालन किया है और तमिल नागरिकों को बचाने की इस प्रक्रिया में बहुत कुर्बानी दी है।

इन कार्रवाइयों को करते समय भारत ने इस तथ्य को नहीं भुलाया कि भारत का अंतिम उद्देश्य सत्ता का शीघ्र तथा उपयुक्त रूप से हस्तांतरण सुनिश्चित करना है ताकि तमिलों की न्यायसंगत आकांक्षाएँ पूरी हो सकें और वे सुरक्षापूर्वक श्रीलंका में अन्य नागरिकों के साथ सम्मान से रह सकें। लिट्टे द्वारा की जा रही हिंसा पर नियन्त्रण करने की कोशिश करते हुए भी भारत ने श्रीलंका के तमिल शरणार्थियों की शीघ्र वापसी का सुनिश्चय करने की जरूरत की तमिल क्षेत्रों पर नये उपनिवेश न बनने देने का सुनिश्चय करने की आवश्यकता को हमेशा ध्यान में रखा ।

श्रीलंका में तमिलों की न्यायसंगत आकांक्षाओं को पूरा करने का भारत ने पूरा प्रयास किया। राष्ट्रहित में यह आवश्यक हो गया था कि भारत श्रीलंका के आंतरिक मामलों में दखल दे अन्यथा सामरिक दृष्टि से महत्वपूर्ण भारत का यह पड़ोसी देश ऐसे देशों का अड़्डा बन जाता जो भारत में आतंकवादी गतिविधियों को बढ़ावा दे रहे थे तथा अभी तक प्रकाश में आये कई आतंकवादी संगठनों का संचालन कर रहे थे । राजीव गांधी ने वक्त की नजाकत को समझा तथा भारतीय जनता और जनप्रतिनिधियों को विश्वास में लेकर श्रीलंका में शांति वार्ताओं के माध्यम से तथा सैनिक बल पर भी शांति कायम करने की कोशिश की । यद्यपि इसके लिये भारत^{का} काफी धन-जन इसमें स्वाहा हो गया²²।

- 1 Appadorai A Domestic Roots of India s Foreign Policy Page 162
- 2 अशोक और मौर्या साम्राज्य का पतन रोमिला थापर, पृष्ठ १२२
- 3 Ismail M India and their Neighbours
- 4 Ismail M India and their Neighbours
- 5 Gunther J Inside Asia Page 99
- 6 Madan Gopal India as a World Power
- 7 Murty K S India Foreign Policy Page – 114
- 8 Murty K S India Foreign Policy Page – 114
- 9 नव भारत टाइम्स-३९ १९८५ में प्रकाशित डा० वेद प्रताप वैदिक का लेख ।
- 10 Mishra K P Ed Studies in Indian Foreign Policy Page 225
- 11 Kachroo J L India and Common Wealth
- 12 Indian Express 28 7 1983
- 13 Barman, Chandra R The Asean and India, India Quarterly Page-112
- 14 Indian Express – 9 7 1985
- 15 Times of India – 24 4 1985
- 16 Indian Express – 24 4 1985
- 17 श्रीलंका की स्थिति के बारे में वक्तव्य लोकसभा वाद विवाद २५ ४ १९८५ पृष्ठ-१६० १६१
- 18 भारत श्रीलंका समझौते के बारे में वक्तव्य लो०स०वा०वि० ३० ०७ १९८७ पृष्ठ-२१६ २१८
- 19 भारत श्रीलंका समझौते के बारे में वक्तव्य लो०स०वा०वि० ३० ०७ १९८७ पृष्ठ-२१६ २१८
- 20 जनसत्ता ३० ०७ १९८५
- 21 भारत श्रीलंका समझौते के बारे में वक्तव्य लो०स०वा०वि० ३० ०७ १९८७-पृष्ठ-२१६ २१८
- 22 भारत श्रीलंका में स्थिति के बारे में वक्तव्य लो०स०वा०वि० १ ११ १९८७ पृष्ठ ३१३ से ३१७

અધ્યાય-૭

वर्ष के दौरान मालदीव और बर्मा के साथ भी सबंध सुदृढ हुये जो कि फरवरी, १९८५ में मालदीव के राष्ट्रपति श्री गयूम की यात्रा और प्रधानमंत्री की हाल ही की माले की यात्रा से रेखांकित होता है। विदेश राज्य मंत्री ने भी वर्ष के दौरान रगून की यात्रा की ^१।

विदेशमंत्री श्री नारायणदत्त तिवारी १९८६ में बर्मा की राजकीय यात्रा की उनकी इस यात्रा के दौरान अडमान सागर के कोको चैनल तथा बंगाल की खाड़ी में समुद्री सीमा के परिसीमन के सबंध में एक करार पर हस्ताक्षर हुए जिसकी वजह से दोनों देशों के बीच विद्यमान मैत्रीपूर्ण और सौहार्दपूर्ण सबंध और सुदृढ हुए हैं ^२।

बर्मा के साथ मौजूदा सौहार्दपूर्ण सबंध सुदृढ हुये हैं। सितम्बर १९८७ में बर्मा के विदेश मंत्री श्री यू ये गोउग की भारत यात्रा के दौरान रगून में दिसम्बर १९८६ में हुये समुद्री सीमा करार की पुष्टि के प्रलेखों का आदान प्रदान किया गया। इसी के साथ भारत बर्मा के बीच समुद्री सीमा के सबंध में परिसीमन सन्धि लागू हो गयी प्रधानमंत्री राजीवगान्धी ने दिसम्बर १९८७ में बर्मा की यात्रा की ओर बर्मा की सोशलिस्ट प्रोग्राम पार्टी के अध्यक्ष श्री यू ने विन राष्ट्रपति श्री ऊ सान यू और बर्मा के प्रधानमंत्री के साथ गहन बातचीत की इन वार्ताओं में दोनों देशों के बीच विद्यमान मैत्री सबंधों को बढ़ाने और मजबूत करने के उपायों पर जोर दिया गया। द्विपक्षीय सबंधों को प्रोत्साहित करने के लिये अनेक निर्णय लिये गये ^३।

बर्मा भारत का एक निकट का पड़ोसी देश है जिसकी भारत

के साथ एक लम्बी और सवेदनशील सीमा लगती है। दोनो देशो के बीच परम्परागत रूप से मैत्रीपूर्ण सबध रहे है और दोनो के बीच कोई समस्या नहीं रही। ऐसी स्थिति मे जब १९८८ मे वहाँ गम्भीर असतोष भडक उठा तो भारत को उस पर चिन्ता हुयी । यह बर्मा का आन्तरिक मामला था, लेकिन भारत के नेताओ ने उस समय जो वक्तव्य दिये उनमे बर्मा की जनता की लोकतात्रिक आकाक्षाओं के प्रति भारत की सहानुभूति स्पष्ट नजर आती थी। भारत की सीमाओ पर शरण लेने आये भारत के लोगो को मिजोरम और अरुणाचल प्रदेश के शिविरो मे रहने की अनुमति दी गयी⁴।

जहा तक हिन्द महासागर का सबध है राजीव गाधी ने भी माना कि हिन्द महासागर मे बडी शक्तियो की सैनिक उपस्थिति मे विस्तार और इस क्षेत्र मे बढता हुआ तनाव चिन्ता का विषय बना हुआ है । भारत इस बात के लिए दृढ रूप से वचनबद्ध है कि हिन्द महासागर क्षेत्र से विदेशी सैनिक उपस्थिति पूरी तरह समाप्त होनी चाहिए और इस क्षेत्र मे बाहरी शक्तियो द्वारा प्रयुक्त सैनिक अड्डो और अन्य सुविधाओ को पूरी तरह समाप्त किया जाना चाहिए । भारत ने यथाशीघ्र १९९० से पूर्व कोलम्बो मे हिन्द महासागर के सबध मे एक सम्मेलन बुलाए जाने की माग का समर्थन किया है ।⁵

हिन्द महासागर और बडी ताकतें तथा भारत की नीति राजीव गाधी के इस क्षेत्र में विचार को जानने के लिए महत्वपूर्ण है । हिन्दमहासागर के आस-पास के देशो ने बड़ी ताकतो से अनेक बार

अनुरोध किया है कि वे इस क्षेत्र को अपने षड्यंत्रों का केंद्र न बनाएँ और इसे शान्ति-क्षेत्र बना रहने दें। लेकिन ये बड़ी ताकतें अपना-अपना प्रभाव क्षेत्र बढ़ाने की होड़ में बार-बार इस अनुरोध को ठुकरा कर अपना उल्लू सीधा करने की कोशिश करती रही। भारत ने हिन्द महासागर में महाशक्तियों की सैन्य उपस्थिति तथा सैनिक अड्डों की स्थापना का सदैव ही विरोध किया है। उनकी मान्यता है कि ऐसा करने से उसके पड़ोस में नए संघर्ष उत्पन्न होते हैं और उसकी शान्ति तथा स्थायित्व के लिए खतरा उत्पन्न हो जाता है। हिन्द महासागर को शान्ति का क्षेत्र बनाने के सम्बन्ध में १९७१ की घोषणा को शीघ्र क्रियान्वित कराने की दिशा में भारत गुट-निरपेक्ष राष्ट्रों तथा तटवर्ती राज्यों के साथ मिलकर कार्य कर रहा है।

“भारत की हमेशा यह मान्यता रही है कि हिन्द महासागर में इस प्रकार की स्थिति का अस्थिरकारी प्रभाव पड़ता है। और एक शक्ति की उपस्थिति से निश्चय ही दूसरी शक्तियाँ भी आकर्षित होती हैं जिसके परिणामस्वरूप संघर्ष का वातावरण पैदा होता है। हालांकि हिन्द महासागर में बड़ी शक्तियों की सैनिक उपस्थिति को न्यायोचित ठहराने के लिए तरह-तरह की बातें कही गईं जैसे तेल की निरन्तर सप्लाई का आश्वासन, संचार साधन का कायम रखा जाना सुरक्षा और क्षेत्रीय स्थायित्व। लेकिन भारत का यह पक्का विश्वास है कि इस तरह के रवैये से न तो क्षेत्र की सुरक्षा को ही योगदान मिल सकता है और न इसके स्थायित्व में। इसके विपरीत

इससे समस्या और अधिक भडकती ही है । इस क्षेत्र में सेना को बढ़ते हुए जमाव से भारत और हिन्द महासागर के क्षेत्र को शान्ति का क्षेत्र बनाया जाना चाहिए ⁶।”

हिन्द महासागर ससार की नौसेनाओं का अखाड़ा बन गया है। यह परमाणु हथियारों का अड्डा बन चुका है । हम हिन्द महासागर को शांति क्षेत्र बनाये रखने के लिये पूरी तरह वचनबद्ध हैं और हम इस लक्ष्य की पूर्ति के लिये प्रयास करेंगे । हिन्द महासागर में बड़ी ताकतों की उपस्थिति से सभी तटवर्ती राष्ट्रों को खतरा है । दियोगो गार्शिया का लगातार सैनिकीकरण हमारे लिये गंभीर चिंता का विषय है । हम चाहते हैं कि हिन्द महासागर महाशक्तियों की शत्रुता और उनके आपसी तनावों से मुक्त रहे । संयुक्त राष्ट्रसंघ में हिन्द महासागर सम्बन्धी समिति में हमारा प्रतिनिधि सक्रिय रूप से भाग लेता है । हम कार्यवाही के बारे में अन्य देशों के साथ बहुत निकट से सम्पर्क बनाये हुए हैं जो कि संयुक्त राष्ट्र संघ की साधारण सभा के निर्णयों को असली जामा पहनाने के लिये की जा सकती है । हमें तटवर्ती शक्तियों के सहयोग की जरूरत है और हमें उम्मीद है कि हमें उनका सहयोग अवश्य मिलेगा ⁷ ।

पाद टिप्पणिया

- 1 भारत १९८६-सूचना एव प्रकाशन विभाग । पृष्ठ ७१९
- 2 भारत १९८७-सूचना एव प्रकाशन विभाग । पृष्ठ ५१५
- 3 भारत १९८८-८९ -सूचना एव प्रकाशन विभाग । पृष्ठ ५५७
- 4 भारत १९९०-सूचना एव प्रकाशन विभाग। पृष्ठ ६४६
- 5 भारत १९८६-सूचना एव प्रकाशन विभाग।
- 6 Madan Gopal India as a World Power Page 127
- 7 Ministry of External Affairs India and Foreign Affairs Records

અધ્યાય-૮

बंगला देश के उद्भव के समय अन्तराष्ट्रीय राजनीति में विकसित अमरीकी-चीन नितान्त ने भारत के समक्ष बड़ी समस्या उत्पन्न कर दी थी। एक ओर पाकिस्तान चीन और अमरीका की साठगाठ से दक्षिण एशिया में शक्ति सन्तुलन अस्त-व्यस्त हो रहा था तो दूसरी ओर पाकिस्तान के दो सम्भागों के बीच झगड़े का सीधा प्रभाव भारत पर आ पड़ा था¹। पूर्वी बंगाल में पाकिस्तान की सैनिक कार्यवाही के परिणामस्वरूप लाखों लोगों को अपना वतन छोड़कर भारत आना पड़ा। धीरे-धीरे शरणार्थियों की संख्या बढ़कर एक करोड़ हो गयी। संसार में इतनी बड़ी जनसंख्या का दूसरे देश में आगमन पहली घटना थी। इस विशाल जनसमुदाय के खान-पान, रहन-सहन और स्वास्थ्य सम्बन्धी देखभाल का भार भारत पर था। इससे भी अधिक महत्वपूर्ण बात भारत की सुरक्षा अखण्डता और सार्वभौमिकता को अक्षुण्ण बनाये रखने की थी। विश्व के अधिकांश देश इस प्रसंग पर तटस्थ थे क्योंकि वे इस आग की लपट से बहुत दूर थे। किन्तु पूर्वी बंगाल में जो कुछ भी घटित हो रहा था उसे देखते हुए भारत न तो तटस्थ दृष्टा रह सकता था और न विरक्त ही। देश की संसद अखबार राजनीतिक दल और प्रबुद्ध जन सभी बंगला देश की जनता और उसके नेताओं को समर्थन देने की मांग कर रहे थे। भूतपूर्व विदेश मंत्री एम सी छागला का कहना था राजनैतिक, वैधानिक और नैतिकता की दृष्टि से बंगला देश को मान्यता देना न्यायोचित है²। भारतीय हितों के परिप्रेक्ष्य में विवेचना

दरवाजे पर दस्तक दे रहा था। निक्सन माओ से मिलने जा रहे थे और भारत यह समझने लगा कि दो शक्तियों का मिलन भारत के लिये खतरनाक हो सकता है। जब ३ दिसम्बर १९७१ को पाकिस्तान ने पठानकोट, अमृतसर जोधपुर आगरा और श्रीनगर पर बमबारी कर इस उपमहाद्वीप में युद्ध छेड़ दिया⁴ तो दो सप्ताह की घमासान लड़ाई के बाद बंगलादेश की मुक्तिवाहिनी और भारतीय सेना के समक्ष पाकिस्तान को शस्त्र डालने पड़े। बंगलादेश आजाद हुआ और शेख मुजीबुर्रहमान रिहा कर दिये गये। अपनी रिहाई के बाद ढाका जाते समय वे भारत रुके। उनके स्वागत समारोह में भारत की भूमिका को दोहराते हुए प्रधानमंत्री श्रीमती इन्दिरा गांधी ने जो कहा वह उल्लेखनीय है

मैंने कहा था कि ये शरणार्थी अपने घर पुन लौटेंगे। हम मुक्तिवाहिनी और बंगलाजन की हर तरह से सहायता करेंगे। हमने शेख साहब को भी मुक्त कराने का व्रत लिया था। ये तीनों वादे पूरे कर दिये गये हैं।

संक्षेप में बंगलादेश के निर्माण में भारत की महत्वपूर्ण भूमिका रही है। बंगलादेश का निर्माण भारत-पाक युद्ध के दौरान १६ दिसम्बर, १९७१ को हुआ। भारत ही सबसे पहला देश है जिसने ६ दिसम्बर, १९७१ को बंगलादेश को मान्यता दे दी। भारत की सेनाओं ने बंगलादेश की मुक्तिवाहिनी से मिलकर १६ दिसम्बर, १९७१ को स्वतन्त्र बंगला देश की स्थापना करायी⁵।

६ दिसम्बर १९७१ को भारत ने बंगलादेश को मान्यता दे दी । १० दिसम्बर १९७१ को प्रधानमन्त्री श्रीमती इन्दिरा गांधी और बंगलादेश के तत्कालीन कार्यवाहक राष्ट्रपति नजरुल इस्लाम के मध्य एक सन्धि हुयी, जिसके अनुसार भारतीय सेनापति की अध्यक्षता मे एक संयुक्त कमान का निर्माण किया गया । जब १६ दिसम्बर, १९७१ को बंगलादेश मे पाकिस्तानी सेना के कमान्डर जनरल नियाजी ने हथियार डाल दिये तो स्वतन्त्र बंगलादेश का निर्माण हो गया । भारत के प्रयासो से ९ जनवरी १९७२ को भारत पहुचने पर शेख ने भारत के प्रति अपने आभार को व्यक्त किया ^६। शेख मुजीब ने कहा भारत-बंगला देश एक असीम भाई-चारे मे बंध गये है उनका कृतज्ञ राष्ट्र भारत की सहायता भुला नहीं सकेगा ।

स्वतन्त्र बंगलादेश के निर्माण के समय से लेकर १९७५ तक भारत-बंगला देश सम्बन्ध घनिष्ठ मित्रता के रहे । अन्तराष्ट्रीय समस्याओ के प्रति दोनो ही देश धर्मनिरपेक्षता पचशील और गुटनिरपेक्षता की नीति मे विश्वास करते रहे । दोनो हिन्द महासागर को शान्ति का क्षेत्र बनाये रखना चाहते थे। बंगला देश को मान्यता दिलाने मे भारत की कूटनीति अत्याधिक सक्रिय रही ।

शेख मुजीब के कार्यकाल मे भारत और बंगलादेश के बीच मैत्रीपूर्ण सम्बन्धो को सुदृढ करने के लिये निम्नलिखित सन्धिया और समझौते किये गये ।

फरवरी, १९७२ में शेख मुजीब भारत की यात्रा पर आये और मार्च १९७२ में श्रीमती गांधी बंगला देश गयीं ।

१९ मार्च १९७२ को भारत और बंगला देश के बीच एक मैत्री सन्धि हुई जिसकी अवधि २५ वर्ष की थी । इस सन्धि के द्वारा दोनों देशों ने एक-दूसरे के आन्तरिक मामलों में हस्तक्षेप न करने एक-दूसरे की सीमाओं का आदर करने एक-दूसरे के विरुद्ध किसी अन्य देश की सहायता नहीं करने विश्व-शान्ति और सुरक्षा को दृढ़ बनाने आदि का सकल्प किया । सन्धि में यह भी व्यवस्था की गयी कि यदि दोनों देशों में कोई मतभेद हो जायेगा तो उसे आपसी बातचीत द्वारा हल करने की कोशिश करेंगे⁷ ।

भारत-बंगला देश के बीच २५ मार्च १९७२ को एक व्यापार समझौता हुआ जिसके अनुसार सीमाओं के १६ - १६ कि०मी० तक स्वतन्त्र व्यापार की व्यवस्था थी । इसमें आयात-निर्यात और विनिमय सम्बन्धी कोई नियन्त्रण नहीं था ।

बंगला देश के आर्थिक पुनर्निर्माण के लिए भारत ने २५ करोड़ रुपये मूल्य का माल और सेवाएँ प्रदान करने का वचन दिया । भारत ने बंगला देश को ५० लाख पौण्ड की विदेशी मुद्रा का ऋण देने का भी निश्चय किया ।

३० सितम्बर, १९७२ को दोनों देशों के बीच एक सांस्कृतिक समझौता हुआ जिसने दोनों के सम्बन्धों को और भी मजबूत किया ।

पाकिस्तान के साथ ३ जुलाई, १९७२ को शिमला समझौता

और १८ अगस्त को युद्धबन्दी समझौता करने समय भी भारत ने बगला देश से परामर्श किया । अप्रैल १९७४ में भारत पाकिस्तान और बगला देश के मध्य एक त्रिपक्षीय समझौता हुआ जिसके अनुसार सभी पाकिस्तानी युद्धबंदी मुक्त कर दिये गये । मई १९७४ में बगला देश और भारत के बीच सीमाकन सबंधी समझौता हुआ जिसके अनुसार भारत ने दाहग्राम और अमरकोट का क्षेत्र बगला देश को दे दिया और बगला देश ने बरूबाडी पर भारतीय अधिकार स्वीकार कर लिया । मई १९७४ में भारत ने बगला देश को ४० करोड़ रुपये का ऋण देना भी स्वीकार किया^१। इस ऋण का उपयोग बगला देश रेल के डिब्बे और अन्य उपकरण सीमेण्ट मशीने, तथा कृषि उपकरण खरीदने के लिये करेगा।

संक्षेप में शेख मुजीब के कार्यकाल में भारत-बंगलादेश सम्बन्ध मधुर रहे।

जहाँ तक शेख मुजीब के बाद भारत बंगलादेश सम्बन्ध का प्रश्न है

१५ अगस्त १९७५ को शेख मुजीब की हत्या कर दी गयी^२। पहले मुश्ताक अहमद और फिर ६ नवम्बर, १९७६ को जस्टिस आबू सादात सयाम राष्ट्रपति बने। ३० जनवरी, १९७६ को मेजर जनरल जिया उर रहमान ने मुख्य मार्शल लॉ प्रशासक बनकर सत्ता पर अधिकार कर लिया। मई, १९८१ में जिया उर रहमान की हत्या कर दी गयी। २४ मार्च, १९८२ को राष्ट्रपति अब्दुल सत्तार के असैनिक शासन का तख्ता पलट कर लेफ्टिनेंट जनरल एच एम इरशाद मुख्य

मार्शल लॉ प्रशासक बन गये।

शेख मुजीब की हत्या के बाद बंगलादेश के शासको ने भारत विरोधी और पाक समर्थक नीति अपनायी। यद्यपि इरशाद के काल १९८२ में भारत विरोधी स्वर कुछ हल्का पड़ा परन्तु फिर भी भारत-बंगलादेश में उतने ^{सम्बन्ध} मधुर नहीं कहे जा सकते जितने शेख मुजीब के युग में थे। वस्तुतः शेख मुजीब की हत्या के बाद बंगलादेश में जो नयी सरकारें बनी उनका भारत के प्रति कठोर रुख था।

१९७५-१९८२ की कालावधि में भारत बंगला देश के मध्य सम्बन्धों को प्रभावित करने वाले जो निम्नलिखित मुद्दे प्रमुख थे।

इनमें फरक्का समस्या प्रमुख है। बंगलादेश ने गंगा के पानी के बटवारे की समस्या फरक्का विवाद को अन्तराष्ट्रीय रूप देने का प्रयत्न किया और संयुक्त राष्ट्र सचय व अन्तराष्ट्रीय मंचों पर उछालने का प्रयास किया। भारत ने बंगला देश को इस जलविवाद को अन्तराष्ट्रीय रूप न देने के लिये सहमत कर लिया और ढाका तथा दिल्ली में वार्ताओं के बाद दोनों देशों ने २६ सितम्बर १९७७ को एक समझौता किया। यही समझौता फरक्का समझौता कहलाता है।

फरक्का समझौता ५ नवम्बर, १९७७ को लागू हुआ। इसमें दो व्यवस्थाएँ की गयीं -

अल्पकालीन व्यवस्था के अनुसार १२ अप्रैल से ३० अप्रैल तक जबकि पानी की बहुत कमी रहती है भारत को २०,८०० क्यूसेक और बंगलादेश को ३४,७०० क्यूसेक पानी मिलेगा और इसके तुरन्त

बाद भारत को मिलने वाले पानी की मात्रा बढ़ती जायेगी और जल्दी ही ४० ००० क्यूसेक तक पहुच जायेगी। अल्पकालीन व्यवस्था मे यह बात भी रखी गयी कि यह समझौता ५ वर्ष के लिये है और ३ वर्ष बाद इस पर पुनर्विचार किया जायेगा।

दीर्घकालीन व्यवस्था के अन्तर्गत दोनो देशो ने अपने ऊपर गंगा के प्रवाह को तेज करने की जिम्मेदारी ली और १९७२ मे स्थापित संयुक्त आयोग इस सम्बन्ध मे दोनो पक्षो के प्रस्तावो की जाच करके यह बतायेगा कि उनके प्रस्ताव व्यवहारिक और मितव्ययी है या नही और ये सिफारिशे दोनो को लगभग पाच वर्ष के भीतर विचार के लिये मिल जायेगी।

भारत मे इस समझौते पर तीखी प्रतिक्रियाए हुई। आलोचको के अनुसार गंगा मुख्य रूप से भारतीय नदी है क्योकि इसकी ८० प्रतिशत धारा भारत मे है। दूसरा ४० ००० क्यूसेक से कम पानी मिलने पर कलकत्ता की हालत खराब होने का अदेशा था जबकि फरक्का का निर्माण कलकत्ता बन्दरगाह के लिए ही हुआ था। तीसरा पानी की कमी के समय भारत को केवल २०,८०० क्यूसेक पानी ही मिलेगा जो इसकी आवश्यकता से लगभग २०,००० क्यूसेक कम होगा और बंगला देश को अपनी आवश्यकता से ५,००० क्यूसेक अधिक पानी मिलेगा। वस्तुतः बंगाल और त्रिपुरा की जनता को नाराज करके फरक्का समझौता किया गया। डा वेद प्रताप वैदिक के अनुसार, फरक्का समझौते के अन्तर्गत बंगला देश को रियायते

देने के लिये जनता सरकार ने भारत द्वारा प्रस्तुत पुराने सभी तर्कों को दरकिनार कर दिया। हो सकता है कि कांग्रेस सरकार कलकत्ता बन्दरगाह को बचाने के नाम पर जरूरत से ज्यादा पानी मागने की बात करती रही हो और जनता सरकार ने उचित उदारता का परिचय दिया हो किन्तु उसका नतीजा क्या हुआ?, उदारता बाझ ही साबित हुई। फरक्का समझौता गंगा के पानी के बटवारे की समस्या का स्थायी समाधान नहीं था। अतः इसे १९८२ के समझौते स्मरण पत्र द्वारा रद्द कर दिया गया^१।

गंगा के पानी के बटवारे की समस्या को हल करने के लिए भारत ने सितम्बर १९७७ में अपने हितों को अनदेखा करते हुए बंगला देश के साथ इसलिए फरक्का समझौता किया था कि इससे गंगा के प्रवाह को तेज किया जा सकेगा और दोनों देशों की वार्ताओं से समस्या का स्थायी समाधान हो सकेगा। लेकिन बंगला देश १९७७ के अन्तरिम समझौते को अन्तिम समझौता मानता रहा और उसके द्वारा प्राप्त रियायतों को निरन्तर बनाये रखना चाहता है। इस प्रकार यह कहा जा सकता है कि बंगला देश फरक्का समझौते से केवल प्रारम्भिक लाभ उठाना चाहता है, वह इसके स्थायी समाधान के प्रति बिल्कुल उत्सुक नहीं है^{१०}।

बंगला देश ने गंगा जल वितरण की समस्या को, जो द्विपक्षीय समस्या है, बहुपक्षीय एवं अन्तराष्ट्रीय दिशा देने का प्रयास किया। बंगलादेश ने नेपाल, चीन, भूटान और विश्व बैंक को भी इस समस्या

मे घसीटने का प्रयास किया⁸।

बगला देश के हिन्दू और बिहारी मुसलमान अपने आपको सुरक्षित महसूस नहीं करते परिणामस्वरूप वे अवैध रूप से भारत में आते हैं जिससे भारत के सीमावर्ती प्रदेशों - त्रिपुरा असम बंगाल मिजोरम आदि में स्थिति बिगड़ जाती है।

१९७४ को समझौते के अनुसार मुहरी नदी के पानी की मध्य रेखा ही भारत-बंगला देश की सीमा रेखा है। बंगला देश रायफल के अधिकारियों ने इस समझौते की उल्लंघन करके १९७९ में भारतीय जमीन पर अपना दावा पेश किया और भारतीय किसानों पर गोलिया चलायीं। यह विवाद ४४-४५ एकड़ जमीन के बारे में है जो त्रिपुरा राज्य के बेलोनिया कस्बे के पास मुहरी नदी के भारतीय तट पर है।

नवमूर द्वीप बंगाल की खाड़ी में उभरा एक नया सा द्वीप है। इसका क्षेत्रफल केवल १२ वर्गकिलोमीटर है। बंगला देश इसे दक्षिण तलपती कहता है और भारत इसे पुरबाशा की सजा देता है। यह द्वीप भारतीय सीमाओं में है फिर भी बंगला देश इस पर अपना दावा करता है। अगस्त, १९८१ में बंगलादेश के आठ युद्धपोतों ने इस पर कब्जा करने का विफल प्रयास किया। वर्तमान में यह द्वीप भारत के अधिकार में है। बंगला देश इस मामले को भी अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर लाना चाहता है।

चकमा शरणार्थियों की समस्या ने भी दोनों देशों में उत्तेजना पैदा की। यद्यपि बंगला देश ने चकमा शरणार्थियों को वापस लेने

का वायदा किया, परन्तु भय के कारण चकमा शरणार्थी बगला देश जाना नहीं चाहते।

अब हम उपरोक्त समस्याओं के परिपेक्ष्य में राजीव गांधी के काल में भारत बगला देश सम्बन्ध पर दृष्टिपात करेंगे ।

उपरोक्त पृष्ठ भूमि राजीव गाँधी ने बगला देश के साथ संबंधों को गम्भीरता से लिया ¹¹। नैसाऊ में राष्ट्रमंडल शिखर बैठक के दौरान प्रधानमंत्री ने बगला देश के राष्ट्रपति से बातचीत की । यह फैसला किया गया कि गंगा के पानी के पानी की लम्बे समय से चली आ रही समस्या के समाधान का रास्ता ढूँढने के लिये दोनों देशों के सिचाई मंत्री की नयी दिल्ली यात्रा का परिणाम था कि सहमति के ज्ञापन पर हस्ताक्षर किये गये जिसके अन्तर्गत जल ससाधन मंत्रियों को दोनों देशों में उपलब्ध साझे जल ससाधनों का संयुक्त अध्ययन करना था इससे फरक्का गंगा में पानी का बहाव बढ़ाने की समस्या का दोनों देश समाधान निकाल पाते। ज्ञापन में ये भी प्राविधान था कि इसकी वैधताके तीन वर्षों के दौरान, १९८२ में हस्ताक्षर किये गये सहमति के ज्ञापन की शर्तों व नियमों के अनुसार फरक्का में गंगा के पानी का बटवारा होगा। दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग एसोसिएशन के दिसम्बर, १९८५ में हुये शिखर सम्मेलन के समय प्रधान मंत्री पुन राष्ट्रपति इरशाद से मिले। इससे पहले वे जून में भी उनसे मिले थे जब वे तूफान पीड़ितों के प्रति सहानुभूति व्यक्त करने के लिये श्री लंका के राष्ट्रपति जयवर्धने के साथ ढाका

और आपसी हित के मामलो पर राष्ट्रपति इरशाद के साथ गहन बातचीत की। इस यात्रा के दौरान इस बात के महत्व पर जोर दिया गया कि अप्रैल १९८६ के बाद बंगलादेश से भारत में प्रवेश करने वाले ४९००० से अधिक चकमा अप्रवासियों को बंगलादेश वापिस ले लें। दुर्भाग्य से, बंगलादेश के साथ बार-बार इस बारे में बातचीत किए जाने के बावजूद समस्या बनी हुई है और चकमा आप्रवासी भारत में ही रह रहे हैं तथा वे तब तक लौटने को तैयार नहीं हैं जब तक कि बंगलादेश सरकार उनकी सुरक्षा के लिए निश्चित गारंटी न ले। नदी जल के सामान्य बँटवारे के प्रश्न पर इस विषय के अध्ययन के लिये गठित विशेषज्ञों की संयुक्त समिति का कार्यकाल दो बार पहले मई १९८७ में पुनः नवम्बर १९८७ में बढ़ाया गया था।

बंगलादेश के साथ मैत्रीपूर्ण संबंधों को बेहतर बनाने के प्रयास जारी रहे। सितम्बर १९८८ में वहाँ विनाशकारी बाढ़ बड़े पैमाने पर आई। एक पड़ोसी मित्र की जिम्मेदारियों के अनुरूप बंगलादेश द्वारा सहायता के लिये की गयी अपील के जवाब में वहाँ राहत सहायता पहुँचाने वाला भारत पहला देश था¹⁴।

भारत बंगलादेश से ब्रह्मपुत्र नदी की विनाशकारी बाढ़ क्षमता पर नियंत्रण करने के लिये उसे उपयोगी बनाने और इसकी प्रचुर जलराशि को दोनों देशों लिए इस्तेमाल करने में सहयोग करने पर बल देता रहा है। भारत द्वारा १९७८ में रखा गया पहला विस्तृत प्रस्ताव दोबारा राष्ट्रपति श्री इरशाद के सम्मुख २९ सितम्बर, १९८८ को

उस समय रखा गया जब वे भारत की यात्रा में आये थे¹⁵। बाढ़ प्रवध के लिये सम्भावित सहयोग के बारे में विचार-विमर्श करने के लिये जल ससाधन विशेषज्ञों के एक संयुक्त कार्यदल का गठन किया गया।

लगभग तीन वर्ष पहले बांग्लादेश के करीब ४५,००० चकमा शरणार्थी भारत आये थे और वे अभी तक यहाँ बसे हुये हैं। भारत बांग्लादेश से लगातार ये आग्रह करता है कि वह अपने यहाँ ऐसी परिस्थितियाँ पैदा करे जिससे इन शरणार्थीयों में विश्वास पैदा हो और वे अपने घर लौट जायें¹⁶।

इस प्रकार हम देखते हैं कि अपने पूरे प्रधानमन्त्रित्व काल में श्री राजीव गांधी बांग्लादेश के साथ भारत के संबंधों को सुधारने के कार्य में लगे रहे हैं।

पाद टिप्पणिया

- 1 Ismail M India and their Neighbours Page 179
- 2 Ministry of External Affairs India and Foreign Affairs Records
- 3 An article by Ajit Bhattacharya on Bangladesh crises
- 4 Times of India – 4 12 1971
- 5 Indian Express – 7 12 1971
- 6 Hindustan Times 10 1 1972
- 7 Hindustan Times 20 5 1972
- 8 Times of India – 16 8 1975
- 9 Chopra s Ed Studies in India s Foreign Policy Page 161
- 10 Subramanyam K Our National Security Page –149
- 11 Harish Chandra Rajiv Gandhi many facts Page 173
- 12 भारत १९८६ सूचना एव प्रकाश विभाग नयी दिल्ली पृष्ठ-७१८
- 13 भारत १९८७ सूचना एव प्रकाश विभाग नयी दिल्ली-पृष्ठ-५१५
- 14 भारत १९८८-८९ सूचना एव प्रकाश विभाग नयी दिल्ली पृष्ठ-५५६
- 15 Times of India 30 09 1988
- 16 भारत १९९०-सूचना एवं प्रकाश विभाग पृष्ठ-६४५

अध्याय-९

उपसंहार

राजीव गांधी के प्रधानमंत्रित्वकाल में भारत का पड़ोसी देशों से सम्बन्ध विषयक विशद विवेचन के पश्चात् हम इस निष्कर्ष पर पहुँचे हैं कि राजीव गांधी की वैज्ञानिक सोच, नवोन्मेषक विचार और आधुनिक अवधारणा ने भारतीय विदेश नीति को एक नयी दिशा दी है। आज ग्लोबलाइजेशन और लिबरलाइजेशन के इस दौर में जब दुनिया के सभी देश अपने सर्वांगीण विकास के लिये एक दूसरे पर निर्भर हैं कोई भी राष्ट्र अपने को विश्व समुदाय से अलग नहीं रह सकता है। ऐसी स्थिति में यह आवश्यक हो गया है कि प्रत्येक राष्ट्र अपने पड़ोसी देशों से बेहतर सम्बन्ध कायम करे। इनफोरमेशन टेक्नोलॉजी का जो विस्फोट आज हमारे सामने दिखायी दे रहा है वह राजीव गांधी की दूरदृष्टि ने बहुत पहले ही देख लिया था। इक्कीसवीं शताब्दी को कम्प्यूटर युग में ले जाने का उनका सपना था।

भारतीय विदेश नीति के मौलिक सिद्धांतों जैसे असलग्नता साधनों की पवित्रता उपनिवेशवाद तथा साम्राज्यवाद विरोधी सिद्धान्त, जातिवाद एवं नस्लवाद विरोधी सिद्धांत एवं पंचशील के महत्वपूर्ण सिद्धांतों के आलोक में भारतीय राजनीतिज्ञों द्वारा अंतर्राष्ट्रीय रंगमंच पर किये गये निर्णयों, क्रियान्वयनों तथा अदा की गयी भूमिका का वृहद वर्णन करने के पश्चात् राजीव गांधी के काल में अंतर्राष्ट्रीय संगठनों में भारतीय योगदान की चर्चा की गयी। भारत के प्रथम प्रधानमंत्री पं० जवाहर लाल नेहरू से लेकर राजीव

गांधी के प्रधानमंत्रित्व काल तक भारत-चीन भारत-भूटान भारत-पाकिस्तान भारत-श्रीलंका, भारत-बंगलादेश सम्बन्धों का मूल्यांकन वर्तमान परिप्रेक्ष्य में किया गया।

किसी भी देश की विदेश नीति वहाँ के राष्ट्रीय आंदोलन ऐतिहासिक पृष्ठभूमि सांस्कृतिक मूल्यों राजनीतिक परिस्थितियों स्थानीय विशेषताओं नेतृत्व व्यक्तित्व भौगोलिक एवं अंतरराष्ट्रीय व्यवस्थाओं से प्रभावित रहती है। भारत जैसे धर्म जाति, संस्कृति, परम्परा की विविधतापूर्वक देश में, जहाँ धर्म निरपेक्षता एवं समाजवाद पर लोकतंत्र की आधारशिला रखी गयी है विदेश नीति का निर्माण या निर्धारण एक जटिल कार्य है। महात्मा गांधी के शब्दों में 'भारत इस पृथ्वी के एशियाई एवं अन्य गैर-यूरोपीय जातियों के खोज की कुंजी है' (Collected Work of Mahatma Gandhi (New Delhi, 1969, vol 35, P 457)

जवाहरलाल नेहरू से लेकर इंदिरागांधी तक भारत के पड़ोसी देशों से कैसे सम्बन्ध रहे, तुलनात्मक विवेचन करते हुए राजीव गांधी के प्रधानमंत्रित्व काल में पड़ोसी देशों से सम्बन्धों का मूल्यांकन किया गया। राजीव गांधी की नई सोच, नई दिशा और नवोन्मेषक विचारों^{का} प्रस्फुटन उनकी पड़ोसी देशों की यात्राओं, समझौता वार्ताओं और विभिन्न अंतरराष्ट्रीय मंचों पर व्यक्त विचारों से होता है। अग्रिम दो अनुच्छेदों में राजीव गांधी के पड़ोसी देशों के सम्बन्धों का सार संक्षेप प्रस्तुत करेंगे।

5 जनवरी १९८५ को प्रधानमंत्री का पद ग्रहण करने के बाद प्रधान मंत्री का पद ग्रहण करने के बाद प्रधानमंत्री राजीव गांधी ने पड़ोसी देशों के साथ में मैत्रीपूर्ण सम्बन्ध स्थापित करने के लिये व्याहारिकता पर बल दिया। अप्रैल, १९८५ में उनकी ढाका यात्रा से भारत व बांग्लादेश के सम्बन्धों में सुधार की प्रक्रिया शुरू हुई । १९८५ में भारतीय प्रधानमंत्री राजीव गांधी ने बांग्लादेश के राष्ट्रपति इरशाद से राष्ट्रमंडल के नसाऊ (Nasau) सम्मेलन में मुलाकात की । इस अवसर पर दोनों देशों के सिंचाई मंत्रियों ने एक समझौते पर हस्ताक्षर किये जिसमें कि गंगा के परनी के बटवारे की समस्या का समाधान निकाला जा सके । नवम्बर १९८५ में भारत व बांग्लादेश में एम० ओ० यू० पर तीन साल के लिये हस्ताक्षर किये जिसके अंतर्गत प्राप्य पानी के ससाधनों का संयुक्त अध्ययन शुरू किया जा सके ताकि फरक्का बाँध में गंगा के पानी में बढ़ोत्तरी की समस्या का समाधान निकाला जा सके । यह एक महत्वपूर्ण कदम था ।

पड़ोसी देशों से बेहतर सम्बन्ध बनाने के उद्देश्य से राजीव गांधी दिसम्बर १९८५ में सार्क के प्रथम शिखर सम्मेलन के दौरान राष्ट्रपति इरशाद से मुलाकात की । इस मुलाकात के दौरान द्विपक्षीय सम्बन्धों को सुधारने के दिशा में तीन बीघा गलियारे पर समझौते को शीघ्र लागू करने की वचनबद्धता दोहरायी गयी । कानूनी अडचनों के बावजूद भी तत्कालीन सरकार ने दहाग्राम व अगारपोटा, बंगलादेश

को प्रवेश की सुविधा प्रदान करना प्रस्तावित किया। इतने सबके के बावजूद भारत-बंगलादेश के बीच तनाव का मुख्य कारण बंगलादेश के गैर कानूनी बंगलादेशियों का भारत में प्रवेश बरकरार रहा। ४५ ००० चकमा शरणार्थियों को भारत से बंगलादेश वापस करने के सदर्भ में बातचीत का नया सिलसिला शुरू हुआ।

राजीव गांधी के प्रधानमंत्रित्व काल में भारत के मैत्रीपूर्ण सम्बन्ध रहे। ३ नवम्बर 1988 को जब भाडे के विदेशी सैनिकों ने माले पर आक्रमण किया तो माले सरकार के अनुरोध पर भारतीय सैनिकों ने स्थिति पर काबू कर माले की स्वतन्त्रता व सम्प्रभुता की रक्षा की। राष्ट्रपति गयूम 7 व 8 दिसम्बर को भारत यात्रा पर आये और माले की सम्प्रभुता की रक्षा के लिये भारत के प्रति आभार प्रकट किया।

भारत-पाकिस्तान विभाजन के समय से ही दोनों देशों के मध्य तनाव बढ़ता गया। विभिन्न सरकारों ने इस खाई को पाटने की कोशिश की, किन्तु जब भारत में युवा और वैज्ञानिक सोच सम्पन्न प्रधानमंत्री राजीव गांधी सत्ता में आये तो इस दिशा में प्रयास तेज हो गया। इसका एक प्रमुख कारण यह भी था कि भारत की ही तरह पाकिस्तान की सत्ता भी जुल्फिकार अली भुट्टो की बेटी बेनजीर के युवा हाथों में थी। सार्क के चौथे शिखर सम्मेलन (दिसम्बर, 1988) इस्लामाबाद में राजीव गांधी ने बेनजीर भुट्टो के साथ द्विपक्षीय एवं अन्य समझौतों पर खुल कर बातचीत की, जिसके परिणाम स्वरूप

तीन महत्वपूर्ण समझौते पर हस्ताक्षर किये गये

- १ दोनों देश एक-दूसरे के आणविक प्रतिष्ठानों पर आक्रमण नहीं करेंगे।
- २ सांस्कृतिक सहयोग
- ३ अन्तर्राष्ट्रीय वायु परिवहन में प्राप्त आय के दोहरे करारान का परिहार।

भारत और पाकिस्तान दोनों देशों के प्रधानमंत्रियों ने शिमला समझौते की बात दोहरायी। बेनजीर भुट्टो ने इस समझौते को करीबी से देखा था जिसका वर्णन उन्होंने अपनी आत्मकथा ' पूरब की बेटी ' में किया है । किन्तु उनके सामने घरेलू उलझने थी सैनिक समुदाय में कटुता पैदा होने का भय था या उसके अभिन्न मित्र अमरीका तथा चीन के सैनिक एवं सामरिक हितों पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ने की आशका थी। इन परिस्थितियों में बेनजीर भुट्टो शिमला समझौते को जोखिम नहीं उठा पाई।

पूर्व प्रधानमंत्रियों के विपरीत राजीव गांधी और बेनजीर भुट्टो एक दूसरे के खिलाफ बयानबाजी से परहेज करते रहे। मुद्दों का निपटारा करने के लिये तथा भारत के साथ सम्बन्ध सामान्य बनाने के लिये सावधानीपूर्ण साहस तथा इच्छा शक्ति की आवश्यकता थी । बेनजीर अपने वालिद द्वारा किये गये शिमला समझौते की दुहाई तो देती रहीं लेकिन लागू करने में राजनीतिक मनोबल नहीं जुटा पाई । यही वजह थी कि सियाचीन ग्लैसियर, आणविक शस्त्रों की होड़ और कश्मीर समस्या जैसे मुद्दे अछूते रह गये ।

लाहौर में २६ दिसम्बर, १९८८ को बरिष्ठ सम्पादकों को

सम्बोधित करते हुए बेनजीर भुट्टो से स्पष्ट किया था कि कश्मीर समस्या का समाधान भारतीय उपमहाद्वीप की शांति के लिए बहुत आवश्यक है।

सियाचीन के मामले पर रक्षा सचिव स्तर पर मई व दिसम्बर १९८८ में वार्ता शुरू हुई परन्तु पाकिस्तान द्वारा आतंकवादियों को भौतिक व नैतिक समर्थन देना जारी रहने के कारण सम्बन्ध सामान्य नहीं हो सके और यह मसला लटका रह गया।

राजीव गांधी के प्रधान मंत्रित्व काल में पड़ोसी देशों के साथ सम्बन्धों का विश्लेषण करने पर स्पष्ट हो जाता है कि इस दौरान भारत की विदेश नीति में जहाँ युवा प्रधानमंत्री की नवोन्मेषक दृष्टि थी वही परम्परा का अपेक्षित निर्वाह भी था। समय की मांग को दृष्टिगत रखते हुए राष्ट्रहित में राजीव गांधी ने अमरीका के साथ तकनीक, प्रतिरक्षा एवं आर्थिक सहयोग को बढ़ावा देने में रचनात्मक भूमिका निभाई। इसके अतिरिक्त सोवियत संघ के साथ विशेष सामरिक सम्बन्धों की निरन्तरता बनाये रखकर महाशक्तियों के साथ सम्बन्धों में बेहतर तालमेल बनाये रखा। इस काल में असलग्न आंदोलन को गतिशीलता प्रदान की गयी। सार्क संगठन को और अधिक मजबूत बनाकर इसे गति दिशा एवं शक्ति सम्पन्न बनाने में भारत का सक्रिय सहयोग रहा। अन्तर्राष्ट्रीय क्षेत्र में आणविक रासायनिक एवं जैविक हथियारों पर प्रतिबन्ध लगाने की दिशा में विभिन्न मंचों के माध्यम से भारत ने प्रभावशाली भूमिका निभाई।

परन्तु राजीव गांधी के प्रधानमंत्रित्व काल में समान संस्कृति धर्म परम्परा और रीति-रिवाज वाले राष्ट्र नेपाल के साथ मधुर सम्बन्ध नहीं स्थापित हो सके। चीन के साथ सम्बन्धों को सामान्य बनाने एवं भविष्य के लिये अपेक्षित सामंजस्य बनाये रखने के लिये राजीव गांधी की दिसम्बर १९८८ की चीन यात्रा मील का पत्थर साबित हुई। निकटतम पड़ोसी देशों से तमाम वार्ताओं समझौतों व अन्य सार्थक प्रयासों के बावजूद सम्बन्ध सामान्य नहीं बन सके। निष्कर्षतः यह कहा जा सकता है कि कुछ गम्भीर त्रुटियों के बावजूद भी राजीव गांधी की विदेश नीति सफल कही जा सकती है।

BOOKS

- 1 Appadorai Domestic Roots of India's Foreign Policy
- 2 Anthony H Richmond The colour Problem
- 3 Appadorai and M S Rajan India's Foreign Policy and Relations
- 4 Appadorai India's Foreign Policy
- 5 Kapur India's Nuclear Option Atomic Diplomacy and Decision Making
- 6 Braine India Stay in the Common Wealth
- 7 Bimal Prasad India's Foreign Policy Studies in Continuity and change
- 8 Jain South Asian India and United States
- 9 Bhawani Sen Gupta Rajiv Gandhi a Political Study
- 10 Bimal Prasad The Origins of Indian Foreign Policy The Indian National Congress and World Affairs
- 11 Nanda Ed Indian Foreign Policy The Nehru years
- 12 Chandra R Barman The Asean and India India Quarterly
- 13 C Ned Somvajan Formulation and Practice of India's Foreign Policy
- 14 Levy straus Race and History
- 15 Carrasmary Indira Gandhi In the Crucible of leadership
- 16 Chester Bowles The New Dimension of Peace
- 17 Durgadas India and the World
- 18 Dilip Mukherjee Dealing with Nepal (Times of India, June 6 1990)

- 19 Dom Moraes Mr Gandhi
- 20 Drieberg Indira Gandhi
- 21 Defence of India ed Chanchal Sarkar Press Institute of India
- 22 Devendra Khanna Mother and Son
- 23 Mankekar Twenty two Fateful Days
- 24 Frank Moraes Jawahar Lal Nehru
- 25 Gopal Krishna (One Prety to minance) Development and trends
- 26 Jansen Afro Asia and Non alignment
- 27 Telang Indo China Dispute
- 28 Government of India White Paper on Indo China Relations
- 29 Mirchandani India's Nuclear Diploma
- 30 Hans J Morenthau Dilemmas of Politics
- 31 Harish Chandra Rajiv Gandhi Many Facts
- 32 Henry Kissinger The White House Years
- 33 Healy Kathleen Rajiv Gaandhi The Year of Power
- 34 James N Rosenau (ed) International Politics and Foreign Policy A
Reader in Research and Theory
- 35 Kacharoo India and the Commonwealth
- 36 Bandyopaadhyay India China Relation Out look for the 1980
Foreign Affairs Reports (New Delhi)
- 37 J C Kundra Indian Foreign Policy
- 38 Gunther Inside Asia
- 39 Keith Horsefield The real cost of the War
- 40 Bains India's International Dispute

- 41 Jawaharlal Nehru (1) India's Foreign Policy (2) The Discovery of India
- 42 Subramanyam Our National Security
- 43 Panikar India and the Indian Ocean
- 44 Murty Indian Foreign Policy
- 45 Mishra Ed Studies in Indian Foreign Policy
- 46 Mishra Ed Janta's Foreign Policy
- 47 Krishna Kant "Border Security Belt A Must" The Hindustan Times August
- 48 Rustamji Closing in on Terrorists 'August 19 1986
- 49 Mishra Ed Jantaa's Foreign Policy
- 50 Karunakar Gupta India's Foreign Policy
- 51 Karunakaran ed Outside the Contest A Study of Non alignment and the Foreign Policies of Some Non aligned countries
- 52 Karunakaran India in the World Affairs (2 vols)
- 53 Mishra Ed Non Alignment Frontiers and Dynamics
- 54 Singh India's Foreign Policy The Shastri Period
- 55 Marguard The Peoples and Policies of South Africa
- 56 Natrajan The American Shadow Over India
- 57 Mani Sankar Ayayer Rajiv's Footprints one year in Parliament
- 58 Shah Rajiv Gandhi in Parliament
- 59 Ismail India and their Neighbours
- 60 Madan Gopal India as a world Power
- 61 Martin Deming Levis (Ed) Gandhi Maker of Modern India

- 62 Michael Brecher Nehru A Political Biography
- 63 Mohammad Yunus Persons Passions and Politics
- 64 Morarjee Desai The story of my life
- 65 Mrs Vijay Laxmi Pandit The Scope of Happiness A personal
Memoir
- 66 M V Kamath India at the United Nations
- 67 Madan Gopal Gupta International Relations since 1919 Three
parts
- 68 Nehru Independence and After
- 69 Nicholas Nagent Rajiv Gandhi's son of a Dynasty
- 70 Oxford Illustrated Encyclopedia The Physical World Editor Sir
Vivian Fuch 1985
- 71 Rao Defence Without Drift
- 72 Chakravarti India China Relations
- 73 Rajni Kothari "The Congress System in India" from Party System
and Election Studies
- 74 Berkes and M S Bedi The Diplomacy of India Indian Foreign
Policy in the United Nations
- 75 Rama Kant Nepal China and India
- 76 Richard Attenborough In Search of Gandhi, 1982
- 77 Reader's Digest Great Events of the 20th Century How they
change our lives
- 78 Karanjia The Mid of Mr Nehru 1960

- 79 Raj Mohan Gandhi Will the Real Rajiv Stand Up ? Indian Express Delhi 12 August 1986
- 80 Raj Mohan Sri Lanka the Fractured Island Penguin 1989
- 81 Horn "Afghanistan and the Soviet Indian Influence Friendship Asian Survey
- 82 Arora American Foreign Policy Towards India
- 83 Suffinal Dutt With Nehru in the Foreign Policy
- 84 Burke Mainspring of India and Pakistan Foreign Policy
- 85 Tharoor Reasons of State Political Development and Foreign Policy Under Indira Gandhi
- 86 Patel Foreign Policy of India
- 87 Chopra Ed Studies in India's Foreign Policy
- 88 Swaraj Paul Indira Gandhi 1985
- 89 Mulgaokar A Question of Rights 'Indian Express Delhi" August 1986
- 90 Seventh Conference of heads of State or Government of Nonaligned Countries New Delhi 1983
- 91 Khera India's Defence Problem
- 92 Sir Anthony Eden The memoirs of Full circle
- 93 Sumer Kaul Reagan's Spots and Stripes " In Indian Express 26 July 1986
- 94 Simi Garewal India's Rajiv
- 95 Mukherjee India's Role in World Peace
- 96 Dutt India Foreign Policy

- 97 Dutt China's Foreign Policy
- 98 Chipman India's Foreign Policy
- 99 Levi Free India in Asia
- 100 Wayland Young Strategy for survival